(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तांत

अंक 7] विधान सभा के सप्तम् सत्र का बीसवां दिवस [संख्या 16

शनिवार

8 मार्च, 1975

विधान सभा की बैठक म.पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन) ।

अध्यक्षीय सूचना
राज्यपाल महोदय से प्राप्त संदेश

श्री अध्यक्ष : राज्यपाल महोदय से प्राप्त संदेश के बारे में सूचना ।

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि धन्यवाद प्रस्ताव के उत्तर में निम्नांकित सन्देश राज्यपाल महोदय से प्राप्त हुआ है :

"सं. 1390 मार्च 7, 1975

प्रिय अध्यक्ष महोदय,

आपका 21 फरवरी का पत्र क्रमांक प. शा. पत्र सं-पत्र 10 (4) सदन।वि. स.। 75।6171 मिला । इस कृतज्ञता संदेश के लिए माननीय सदस्यों का आभारी हूं । आप कृपया उनके पास तक मेरे कृतज्ञता ज्ञापन को पहुंचाने का कष्ट करें ।

भवदीय,
जोगेन्द्रसिंह"

श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : हमारा संदेश भी रुग्णता के आधार पर उन तक पहुंचा दें ।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

1. श्री भानुकुमार शास्त्री, सदस्य विधान सभा की ओर से दिनांक 1 मार्च, 1975 से श्री ज्ञानसिंह केशियर, सी.आई.डी., जयपुर द्वारा सरकारी कागजात आदि के साथ अपहरण या हत्या के कारणों का पता नहीं चला सकने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में । इस प्रश्न पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा ।

2. श्री गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य विधान सभा की ओर से स्वतंत्रता सेनानियों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा देने की घोषणा के उपरांत उन्हें चिकित्सा सुविधा न देने से उत्पन्न स्थिति के विषय में । यह प्रश्न का विषय है । यदि माननीय सदस्य चाहें तो इस सम्बन्ध में चिकित्सा सम्बन्धी मांग के समय इस पर चर्चा उठा सकते हैं, और चूंकि यह अविलम्बनीय लोक महत्व का

(श्री अध्यक्ष)

विषय नहीं है । अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं ।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से मैं यह ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ज्ञानसिंह जो केशियर सी.आई.डी., जयपुर था दिनांक 1-3-75 की शाम से गायब है । आज 8 तारीख है किसी भी पुलिस कर्मचारी को वेतन नहीं मिला है, क्योंकि केशियर नहीं है और उनकी पत्नी ने पुलिस थाने पर आकर यह रिपोर्ट डलवा दी है कि मेरे पतिदेव एक महात्माजी के यहाँ आया जाया करते थे और ऐसा अन्दाजा लगाया जा सकता है कि उनकी वहां हत्या हो गई है । अगर हत्या हो गई तो बड़ा खेद का विषय है । यहां की पुलिस, यहां की सरकार उसको ट्रेस आउट नहीं कर सकी । ट्रेस आउट करके राज्य कर्मचारी, पुलिस के अधिकारी या कर्मचारी जो भी हैं उनके वेतन की व्यवस्था करें क्योंकि इसके अभाव में उनमें काफी असन्तोष फैल रहा है ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवा महल): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव महत्वपूर्ण इसलिए है कि जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई में भाग लिया और 25 वर्ष पश्चात् भारत सरकार ने इस बात की महत्ता को समझ कर उनको ताम्रपत्र प्रदान किये । उसके बाद राजस्थान की सरकार ने एक आदेश निकाला 4 अक्टूबर, 74 को, क्रमांक एफ. 13।3।सहा।बी।स्वायत्त शासन विभाग।74।ग्रुप 2 द्वारा कि स्वतंत्रता सेनानियों को निःशुल्क चिकित्सा की सुविधा दी जायगी । यह राज्यपाल महोदय की नियमों की स्वीकृति से स्वतंत्रता सेनानियों को स्वयं की बीमारी के सिलसिले में सभी प्रकार की चिकित्सा सुविधा राजकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क प्रदान की जाय, एतद्द्वारा आज्ञा प्रदान की जाती है । आज्ञा से, ओ.पी. जोशी, सहायक सचिव । इस लेटर की प्रतिलिपि समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को भेजी गई, सभी प्रभारी चिकित्साधिकारियों को भेजी गई और समस्त प्रशासनिक अधिकारियों को भेजी गई और आज्ञा पत्रावली में भेजी गई । इसके बाद नियम भी बनाए । नियम, बन जाने के बाद आज की तारीख तक 4 अक्टूबर, 1974 की आज्ञा के उपरान्त भी कोई भी स्वतंत्रता सेनानी किसी भी अस्पताल में जाता है तो वहां के अधिकारी कह देते हैं कि इस प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी जा सकती । इसके नियम बन चुके हैं । अब मैं यह निवेदन करूंगा कि राज्यपाल महोदय की आज्ञा से जो नियम निकाले गए उसमें लिखा गया कि राज्यपाल महोदय ने नियमों की शिथिलता करते हुए ये शिथिलता शब्द होने से शिथिलता का उपयोग हो रहा है कि राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानियों को चिकित्सा सुविधा नहीं दी जाय । एक बार सरकार ने घोषणा कर दी और घोषणा करने के बाद भी ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों का इस प्रकार से उपहास हो, इस प्रकार का मजाक हो तो मैं समझता हूं कि जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई में इस प्रकार की कुर्बानियां कीं उन सब के साथ ऐसा उपहास किया जाय, मैं समझता हूं कि यह कदापि सहनीय नहीं है । इसलिए मेरा निवेदन है कि इन स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में निःशुल्क चिकित्सा की जो घोषणा की है राज्य सरकार से उसका पालन करवाया जाय, यही मेरा निवेदन है ।

Page No 3

(3)

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखा जाने वाला पत्र।

सदन की मेज पर रखा गया पत्र

अधिसूचना

श्री खेतसिंह (मुख्य मंत्री की ओर से) : अध्यक्ष महोदय, मैं कार्मिक विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. 8 (17) कार्मिक। क।2।73, दिनांक 11 मई, 1974 सदन की मेज पर रखता हूं।

अध्यक्षीय सूचना

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का स्थगन

श्री अध्यक्ष : ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। इसमें मैं निवेदन कर दूं कि माननीय मंत्री महोदय की अनुपस्थिति की वजह से इसको 13 तारीख के लिए स्थगित किया जाता है।

आधा घण्टे की चर्चा

स्कन्ध सहायकों की नियुक्ति

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न सं. 93(3 भे.मं.) के उत्तर में तारीख 24 फरवरी, 1975 को ...

श्री अध्यक्ष : मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि आधा घण्टे का डिस्कशन रूल 49 में होता है उसमें सिर्फ इतना ही किया जा सकता है कि जो उत्तर गयी दफा आया है उसके अन्दर स्पष्टीकरण की कोई बात हो वह आप पूछ सकते हैं और सारा क्वेश्चन नहीं दोहराया जा सकता। कहीं, आपको कोई संदेह रह गया हो या कोई एम्बीगुटी हो वही आप रख सकते हैं।

श्री मूलचन्द सामरिया : इस बारे में जो उत्तर दिया गया है वह अपने आप में ऐसा था कि भेड़ व ऊन विभाग में असिस्टेंट स्टाकमैन (स्कन्ध सहायक) के पदों पर जो नियुक्तियां की जाती थीं उनका तरीका यह होता था कि श्रीमान पहले उनको ट्रेनिंग दी जाती है करीब दस माह की। उस ट्रेनिंग में किसी को लेने से पूर्व बहुत सी पत्र पत्रिकाओं में उनका एडवरटाइजमेंट दिया जाता है और उस एडवरटाइजमेंट के आधार पर और एम्पलॉयमेंट एक्सचेंज से सूची देने के बाद फिर सिलेक्शन बोर्ड अथवा डायरेक्टर और उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति उनको ट्रेनीज़ को भर्ती करते हैं।

श्री अध्यक्ष : आप सीधा सवाल पूछ लीजिये स्पष्टीकरण के लिए।

श्री मूलचन्द सामरिया : मैं प्रश्न की पृष्ठभूमि रख रहा हूं। वह लोग 5–7 जगह डिवीजनल हैड क्वार्टर पर जाकर वहां इण्टरव्यू लेते हैं और फिर इण्टरव्यू के आधार पर जिस तरह के नतीजे पर पहुंचते हैं उसके मुताबिक उन ट्रेनीज का सिलेक्शन होता है ट्रेनिंग के लिए। उस सिलेक्शन के समय यह भी ध्यान में रखा जाता है कि यह उनका धन्धा है. जिन लोगों का यह धन्धा है उनमें अधिकतर खटीक, गूजर, मीणा आदि जातियों के सम्बन्धित लोग ही अधिकतर होते हैं इसलिये, इसमें 28 परसेंट की जगह बहुत ज्यादा तादाद में सुरक्षित स्थानों पर शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को लिया जाता है। इसमें जो नियुक्तियां की गई उनमें किन किन पत्र-पत्रिकाओं में एड,

(श्री मूलचन्द सामरिया)
वरटाइजमेंट किया गया, एक यह मेरा प्रश्न है। इसका कोई भी जवाब नहीं दिया गया है और न किसी पत्र-पत्रिका का हवाला ही दिया गया है। किस तारीख को किस पत्र पत्रिका में एडवरटाइजमेंट निकाला गया यह भी नहीं बताया गया है। श्रीमन्, इसके अलावा किसी एम्पलॉयमेंट एक्सचेंज से कोई सूची आई या नहीं इसकी भी कोई जानकारी मेरे प्रश्न के जवाब में नहीं दी गई। इसके अलावा सिलेक्शन के लिए किस अधिकारी ने किस किस स्थान पर जाकर चयन किया यह भी प्रश्न के जवाब में नहीं बतलाया गया। इसकी तरफ भी विभाग से उत्तर नहीं दिया गया कि किस किस स्थान पर सिलेक्शन के लिए इण्टरव्यू लिए गए। इसका भी जवाब नहीं दिया गया कि किस किस तारीख को इन्टरव्यू लिया गया और इसमें सबसे गम्भीर मामला, अध्यक्ष महोदय, यह है कि किसी भी व्यक्ति को ट्रेनिंग देने के लिए अथवा सिलेक्शन के लिए बजट का प्रावधान होना जरूरी है और बजट में भी इस पर्टीक्यूलर काम के लिए स्वीकृति है या नहीं, इसी तरह की वित्तीय स्वीकृति है या नहीं, यह नहीं देखा गया है। कोई स्वीकृति नहीं है। और जब प्रश्न पूछा गया तो यह जवाब दिया गया है, यह सदन को गुमराह करने वाला है।

श्री अध्यक्ष: आप स्पष्टीकरण चाह लें, स्पीच न दें।

श्री मूलचन्द सामरिया: इसका जवाब नहीं दिया गया है।

श्री अध्यक्ष: आप डाइरेक्ट पूछ लें। एडवरटाइजमेण्ट हुआ है या नहीं, एम्पलॉयमेन्ट एक्सचेन्ज से पूछा गया है या नहीं, यह सीधे प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

श्री मूलचन्द सामरिया: पहली अनियमितता तो यह हुई कि सिलेक्शन कर लिया गया, वित्तीय स्वीकृति नहीं थी और यह फर्मा दिया गया कि स्वेच्छा से ट्रेनिंग ले रहे हैं। इस ओर मंत्री महोदय को ध्यान देना चाहिए था। यह 15 दिन की ट्रेनिंग है। किस तरह से स्टाक असिस्टेन्ट के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। भेड़-पालकों को यह ट्रेनिंग है—जिन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है उनको नौकरियां दी जाती हैं। भेड़ पालकों की ट्रेनिंग के लिए 8 रोज या 15 रोज होते हैं। भेड़ पालकों की ट्रेनिंग के लिए ग्रेजुएट और मैट्रिक होना कोई जरूरी नहीं होता है। उसकी क्वालिफिकेशन है भेड़ों को चराना और उनकी देखभाल करना। इस लिए यह जवाब में स्पष्ट करें कि वे किस तरह से भेड़ पालक हो सकते हैं। उनका धंधा भेड़ पालने का नहीं है। ये लोग भेड़ों के हाथ लगाना अच्छा भी नहीं समझते हैं और भेड़ पालना उनके परिवार में अच्छा भी नहीं समझते हैं। इसके अलावा मंत्री महोदय ने यह फर्मा दिया कि चार, पांच जगह और है और यह जगह शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लिए रखी गयी है। जो ट्रेनिंग दी जा रही है उसमें 28 पर्सेन्ट के हिसाब से देखें शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग और होने चाहिए जबकि कम हैं और यह धंधा विशेषतः उन्हीं का है। चार जगह बाद में भरेंगे। यह जो जवाब मंत्री महोदय ने दिया है, इसके सम्बन्ध में उनका स्पष्टीकरण चाहूंगा? इस ट्रेनिंग का पीरियड कितना है दस महीने का है? कितने महीने की ट्रेनिंग वे ले चुके हैं? इस बारे में ऐसे कोई नियम

(श्री मूलचन्द सामरिया)
हैं ? इस बारे में मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि अधिकारी ने यह लिखा है कि यह कैसे संभव हो सकता है । कैसे ट्रेनिंग हो सकती है ? इसके लिए मंत्री महोदय का स्पष्टीकरण चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछ लीजिए । यह तो स्पीच हो रही है ।

श्री मूलचन्द सामरिया : जो वित्तीय स्वीकृति है उसके लिए कौन से आदेश हैं जिसके अन्तर्गत यह प्रशिक्षण दिया जा रहा है । क्या इन ट्रेनीज को स्टाइपेन्ड मिल रहा है ? इस अनियमित कार्यवाही में प्रशिक्षण कब खत्म होगा और जो बकाया चार लोग हैं उनको कब लिया जाएगा ? वे कब इसके लिए काबिल होंगे ? कुछ लोगों को पक्षपात कर के लिया गया है और राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों से लोगों को लिया गया है । इन सारी परिस्थितियों के ऊपर, वित्तीय स्वीकृति न होने, सिलेक्शन कमेटी द्वारा इनका सिलेक्शन न किया जाना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे में इनको लिया जाना, ये सब अपने आप में गंभीर बातें हैं और खुद मिनिस्टर महोदय ने इनकी सूची बनायी है, इन लोगों की काबलियत नहीं देखी गयी है । एडवरटाइजमेन्ट नहीं किया गया है । इन सब बातों से मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि यह सारी कार्यवाही [× × ×]

श्री निरंजननाथ आचार्य : आम ए पाइन्ट आफ आर्डर सर ।

अनियमितता हो जाना एक अलग प्रश्न है । ऐलीगेशन लगाना एक अलग से प्रश्न है । कल ही लोकसभा में माननीय अध्यक्ष की एक रूलिंग का आपने मुलाहिजा किया होगा । श्री जय प्रकाश नारायण के सम्बन्ध में जो कहा गया, इट वाज मेड टू विद्ड्रा । यह व्यवस्था की हुई है कि जो ऐलीगेशन लगाये जाएं नोटिस टू दी हाउस, दि परमीशन आफ दी स्पीकर लिया जाना चाहिए । कोई माननीय सदस्य किसी अनियमितताओं के सम्बन्ध में बोलना चाहें, ऐलीगेशन लगाना चाहें तो वह बिना नोटिस के नहीं होता है और यदि कोई ऐलीगेशन बिना नोटिस के लगाये जाते हैं तो मैं अध्यक्ष महोदय से मांग करूंगा कि ऐसे ऐलीगेशन को एक्सपंज किया जाए ।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर) **:** मैं भी निवेदन करूंगा· · · ·

श्री अध्यक्ष : मैं व्यवस्था दे रहा हूं ।

आपने जो प्रश्न उठाया है, कि किसी माननीय सदस्य के खिलाफ कोई डिफेमेटरी क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, ऐलीगेशन लगा सकते हैं । इसके सम्बन्ध में हमारे नियम बहुत ही स्पष्ट हैं । नियम 273 इस सम्बन्ध में है । नियम 273 के तहत कोई भी माननीय सदस्य, दूसरे माननीय सदस्य के प्रति ऐलीगेशन लगाना चाहते हैं, तो उस ऐलीगेशन की सूचना उस माननीय सदस्य को देनी पड़ती है और स्पीकर स्वीकृति दे देता है, उसके बाद ही ऐलीगेशन सदन में लगा सकते हैं । इस प्रकार का कोई नोटिस मुझ को प्राप्त नहीं हुआ है । दूसरा यह है कि यह हाफ ऐन आवर डिस्कशन है । इसको किसी प्रकार से ऐलीगेशन का माध्यम नहीं बनाया

× × × यह शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेश से निकाले गये ।

(श्री अध्यक्ष)

जा सकता है। आधे घंटे की चर्चा इस विषय पर केवल इतनी ही हो सकती है कि जो स्पष्ट नहीं है, कोई एम्बीगुइटी रह गई हो तो उसको क्लेरिफाई कराया जाय, वह करा सकते हैं। हाफ एन अवर के माध्यम से डिफेमेट्री स्टेटमेन्ट नहीं हो सकता, यह ऐलीगेशन लगाने का माध्यम नहीं हो सकता। इसके लिए जो प्रोसीजर है, उसको एडाप्ट करना होगा। इसलिए इस प्रकार के ऐलीगेशन के लिए मैं हाफ एन अवर डिसक्शन में इजाजत नहीं दे सकता।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : यह एक्सपंज होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : इसको एक्सपंज किया जाए।

श्री राम किशन (भरतपुर)**: अध्यक्ष** महोदय, यह मामला इतना गंभीर है कि इसको इतने हल्के ढंग से नहीं लिया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : नियमानुकूल लिया जाना चाहिए।

श्री रामकिशन : नियमानुकूल हो हो, इसके लिए निवेदन करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, ट्रेनिंग के लिए रूल्स बने हुए हैं, इसका एक मेन्युअल है। उसमें साफ लिखा हुआ है कि जब भी कोई वेकेन्सी होगी डाईरेक्टर एडवटाईजमेन्ट करेगा। इसमें एडवटाईजमेन्ट नहीं किया गया है। एम्पलॉयमेन्ट एक्सचेन्ज से भी नाम नहीं मांगे गये हैं। इसके लिए एक कमेटी बनानी पड़ती है। वह कमेटी भी नहीं बनायी गयी है। यह भी लिखा गया है कि यह कमेटी जगह जगह जाकर इन्टरव्यू लेगी। यह भी नहीं किया गया है। जब ये सारी बातें नहीं हुई हैं तो मंत्री महोदय के पास सीधे प्रार्थना-पत्र किस तरह से आ गये? कोई ऐलीगेशन-लगाने का सवाल नहीं है। प्रार्थना-पत्र अलग अलग जिलों से आये हैं। प्रार्थना-पत्र लेने की क्या पद्धति है? यह सारी बातें जवाब में नहीं बतायी गयी हैं। स्टाक असिस्टेन्ट और वूल ग्रेडर के लिए प्रार्थना-पत्र लिये गये हैं, यह सब किस ऑथोरिटी ने असेस किया था कि इन पोस्टों के लिए ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी? तो फिर आपने ट्रेनिंग किस आधार पर दिलाई है? इन ट्रेनीज को आप कहा पर खपाएंगे? नियमों में ट्रेनीज को खपाने के लिए गारन्टी दी हुई है। मैन्युअल में लिखा हुआ है कि उनको बोंड भरना पड़ेगा। दो साल के भीतर भीतर उनको बुला सकते हैं। विभाग खुद लगायेगा। यह कहना कि हमने प्रिन्सीपल से पूछ लिया। सलाह ले ली। इसमें कमेटी का नियम है। इस नियम के अन्तर्गत कमेटी नहीं बनी है। मैंने इस संबंध में मुख्य मंत्री महोदय को लिखा था और यह लिखा था कि इस मामले में साफ तौर से नियमों का उल्लंघन किया गया है। मैंने मुख्य मंत्री को लिखे पत्र में यह साफ लिखा था कि इस तरह से जो स्टाक असिस्टेन्ट और वूल ग्रेडर को लिया गया है उस सम्बन्ध में यह आम चर्चा है कि मंत्री महोदय ने दो हजार, तीन हजार रुपये रिश्वत के लिए हैं। मुख्य मंत्री ने इसका जवाब दिया है कि इसकी जल्दी ही जांच करूंगा और आपको सूचित करूंगा। अब तक मुख्य मंत्री महोदय ने इसकी कोई सूचना नहीं दी है। तो इसका सीधा ही मतलब है कि हमारी मंशा किसी को बदनाम करने की नहीं है। जो सदन के नेता

(श्री रामकिशन)

हैं, उनको पहले ही इसकी सूचना दे दी है। उन्होंने इसकी जांच का आश्वासन दिया है। वह जांच कब होगी ? निश्चित तौर पर इसमें नियमों का उल्लंघन हुआ है। नियमों का उल्लंघन बिना किसी कारण के नहीं हो सकता है। इसमें रुपया या रिश्वत नहीं ली गयी हो, यह मानने के लिए मैं तैयार नहीं हूं।

इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, आप और देखेंगे कि भेड़ का जो काम है यह आम तौर पर जैसलमेर, बाड़मेर इन जगहों पर चलता है, और इसमें जिन लोगों को रिक्रूट किया गया है, जिन लोगों को लिया गया है वह खास तौर से भरतपुर और अलवर की तरफ के लोग हैं। इसको आप क्या कहेंगे ? जो धन्धा वह करते हैं और जिनको लेना चाहिए था उनको नहीं लिया गया और भरतपुर, बस्सी और दौसा के आसपास के लोगों को लिया है तो मैं समझता हूं कि स्पष्ट नियमों का उल्लघंन है। नियमों के तहत बहस करें वह ठीक है लेकिन यह करप्शन का बड़ा गम्भीर मामला है। सरकार की इसका जवाब देते वक्त खाली मंत्री को बचाने की दृष्टि नहीं होना चाहिए। मैं मिसाल देना चाहता हूं कि पश्चिमी बंगाल में दो मिनिस्टरों को निकाला गया है। वहां पर भी कांग्रेस सरकार है। किस बात पर निकाला गया आप जांच करिये। केवल इस बात के लिए निकाला गया कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों को नियमों के विरुद्ध नौकरियों पर लगाया था। एक एलिगेशन था और पश्चिमी बंगाल में दो मिनिस्टरों को सदन से निकाला गया है और उनको कांग्रेस से अलग किया गया है। यहां पर 25 आदमियों का नियमों के विरुद्ध रिक्रूटमेन्ट हुआ है, उसके बाद पैसे लेकर करना बहुत गम्भीर है। मंत्री महोदय इन 4–5 मामलों को–कमेटी का मामला, एडवर्टाइजमेन्ट का मामला, साथ ही साथ एसेसमेन्ट नहीं किया गया, आगे जैसलमेर बाड़मेर के लोगों को नहीं लिया गया और भरतपुर के लोगों को लिया गया है, यह अपने आप में बहुत गम्भीर मामला है। माननीय मंत्री महोदय जवाब दें।

श्री अध्यक्ष : मैं यह 11 बजकर 35 मिनिट पर बन्द कर दूंगा।

श्री रामकिशन : ऐसे मामलों में, अध्यक्ष महोदय, रिजिड नहीं हो सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोग कभी भी नहीं कहते हैं लेकिन कभी ऐसे गम्भीर मामले आ जायं और उसमें नियमों की कठोरता की पालना की गई तो फिर हमारी भी सीमा है।

श्री अध्यक्ष : आपकी भी सीमा है और मेरी भी सीमा है। मेरी जो सीमा है उसको पढ़कर सुना दूं।

श्री रामकिशन : नियमों की पालना आज तक कठोरता से नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष : हमेशा हाफ एन आवर डिस्कशन 30 मिनिट में खत्म हुआ है।

श्री रामकिशन : कई बार ऐसा मौका आया है....

श्री अध्यक्ष : आप कोई मिसाल रखें।

श्री रामकिशन : वह आ जायेगी।

श्री अध्यक्ष : जब आप घन्टा दो घन्टा बोले हों। हाफ एन अवर डिस्कशन के मतलब से आप स्वयं वाकिफ हैं। उसका अर्थ यह है कि हाफ एन अवर में खत्म हो।

श्री भानुकुमार शास्त्री : यह बहुत गम्भीर मामला है इसमें आप नियमों को कुछ रिलेक्स कर सकते हैं। यह एक गम्भीर मामला है।

श्री अध्यक्ष : डेफिनिट प्रोवीजन भी हो। जिस मामले में यह है उन मंत्रीजी का उत्तर भी हो जाय इस बात का ध्यान रखें।

श्री भानुकुमार शास्त्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पार्लियामेंट में जो यह रखने नहीं दिया इसका एक मात्र कारण यह था कि वह व्यक्ति जिन्होंने रखा था वह उसका उत्तरदायित्व लेने को तैयार नहीं थे। हमारे माननीय सदस्य तैयार हैं। उसका उत्तरदायित्व उनके ऊपर है। वह प्रमाणित करायेंगे कि इस प्रकार भ्रष्टाचार हुआ है।

श्री अध्यक्ष : नोटिस दे दें।

श्री भानुकुमार शास्त्री : यह क्वेश्चन अवर में प्रश्न आ चुका है। माननीय सदस्य ने मंत्री पर आरोप उस समय भी लगाया था इसलिए गवर्नमेंट का इन्ट्रेस्ट इसमें है कि वह इसकी एन्क्वायरी करे। मेरा यह कहना है कि माननीय मंत्री महोदय ने जिस ढंग से यहां पर सिलेक्शन किया है क्या यह बता सकते हैं कि यह नियमो के अनुसार हुआ है? इस सारी सूची पर मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि इस पर दस्तखत किसने किये? किसके माध्यम से भिजवा दी, और 25 लोगों की दूसरी सूची जो है वह स्वयं ने दस्तखत करके भिजवा दी जिसमें किसी प्रकार से नियमों की पालना नहीं हुई है। तो साधारणतया हर व्यक्ति इस प्रकार से पैसा निकालने के लिए मजबूर हो जाता है। कहीं न कहीं कोई गड़बड़ है, भ्रष्टाचार का सवाल है। यह सुना जाता है कि इस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ है। मैं यह चाहूंगा कि इस मामले में सारी स्पष्ट बात करें कि सिलेक्शन कमेटी द्वारा सिलेक्शन न होकर या किसी दूसरी संस्था द्वारा न होकर अपने इन्ट्रेस्टेड लोगों को भिजवाने का कष्ट और कृपा आपने क्यों की?

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी।

श्री मन्नीलाल महावर (राज्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, दौसा से आने वाले माननीय सदस्य, उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य, और गंगानगर जिले से आने वाले माननीय सदस्यों ने प्रश्न संख्या 93 पर आधा घण्टे की चर्चा के कारण बतलाते हुए कुछ मुद्दे सदन में बतलाये।

दिनांक 24–2–75 को पूर्ण जानकारी नहीं होने के कारण और माननीय सदस्यों के बार बार पूछे जाने व व्यवधान के कारण जवाब पूर्ण सन्तुष्टि के साथ नहीं दे पाया। लेकिन अब मैं पूर्ण जानकारी के साथ जो कि प्रश्न उठाये गये हैं उनका पूर्ण रूप से जवाब देने के लिए आपके समक्ष निवेदन कर रहा हूं कि हमारे यहां माह मई, 1974 में नियमित रूप से प्रशिक्षण का सत्र चालू हो गया था उसके बाद कुछ प्रार्थना-पत्र विभिन्न जिलों से यानि भरतपुर, बाड़मेर, जोधपुर, बांसवाड़ा, अलवर, अजमेर व जयपुर से बेरोजगार नव-

(श्री मुन्शीलाल महावर)

युवकों, जो कमजोर वर्ग के हैं, ऐसे लोगों की काफी तादाद में प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए। इस पर विचार करने के लिए सचिवालय में निदेशक, उपनिदेशक, सहायक निदेशक एवं प्रधानाचार्य, भेड़ व ऊन विभाग आदि की मीटिंग बुलाई गई और इस विषय पर चर्चा की गई और यह निश्चय किया गया कि प्रशिक्षण योग्यता के आधार पर डी.पी. ए.पी. योजना की सफलता के लिए भी आवश्यक था कि कुछ और अधिक प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति हों तो उक्त कार्यक्रम पूर्णरूप से सफल हो सकता है, वर्ना कार्य में व्यवधान पैदा होने की सम्भावना थी। निदेशक, भेड़ व ऊन विभाग के अपने पत्र के द्वारा प्रशिक्षणार्थियों की आवश्यकता हेतु लिखा था। अतः उक्त विषय पर दो-तीन बार विचार-विमर्श किया गया, जिसमें निदेशक उपनिदेशक, प्रधानाचार्य भेड़ व ऊन विभाग की सहमति से यह निश्चय किया गया कि प्रशिक्षण का सत्र चालू हो गया है और आगे प्रशिक्षण का सत्र आने में काफी समय है और विशेष आवश्यकता को देखते हुए प्रशिक्षणार्थियों की योग्यता के आधार पर लगभग 25 केन्डीडेट्स को प्रशिक्षण दे दिया जावे जिसमें राज्य सरकार का अतिरिक्त व्यय नहीं होगा। प्रशिक्षणार्थियों को स्वयं के खर्चे पर प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।

मैं, भेड़ व ऊन प्रशिक्षण संस्थान पर जब गया उस समय यह जानकारी प्राप्त हुई कि प्रशिक्षण केन्द्र पर 46 प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं एवं राज्य सरकार की ओर से प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को 30) रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति दी जाती है। चूंकि डी.पी. ए. पी. प्रोग्राम की योजना प्रान्त में शीघ्र चालू होने वाली है एवं विभाग स्कन्ध सहायकों की आवश्यकता होगी इस वास्तविकता को मद्दे नजर रखते हुए यह विचार विमर्श किया गया कि कुछ और व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जावे। इसमें उन व्यक्तियों को लिया जावे जो कि गरीब वर्ग के हों एवं प्रशिक्षण के अन्तर्गत राज्य सरकार कोई भी खर्चा वहन न करे। इन प्रशिक्षणार्थियों को स्पेशल बैंच के तौर पर लिया जावे क्योंकि ये प्रशिक्षणार्थी मध्यम प्रशिक्षण के लिए लिये गये हैं। इस अतिरिक्त प्रशिक्षण के लिये राज्य सरकार का कोई आर्थिक खर्चा नहीं होगा एवं न अधिक कर्मचारियों को वहां पर लगाना पड़ेगा।

अतः यह सुझाव दिया गया है कि निदेशक, भेड़ व ऊन विभाग को इस तरह का प्रशिक्षण चालू करने का निर्देश दे दिया जावे। अतः यह सूची निदेशक, भेड़ व ऊन विभाग को 6-12-74 को भेजी। इस सूची को प्रधानाचार्य एवं व्याख्याताओं ने प्रमाण-पत्र इत्यादि को देखते हुए प्रशिक्षण के लिए प्रवेश दिया। इन प्रशिक्षणार्थियों में से 8 प्रशिक्षणार्थी स्कन्ध सहायक के प्रशिक्षण में लिए गये व 13 व्यक्ति ऊन वर्गीकरण प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त पाये गये। इनके आदेश में यह स्पष्ट सूचित कर दिया गया था कि राज्य सरकार इन प्रशिक्षणार्थियों के लिए किसी भी प्रकार का आर्थिक खर्च वहन नहीं करेगी। इसके अतिरिक्त मैं सदन को यह भी सूचित करना चाहूँगा कि इनको किसी प्रकार की नौकरी का आश्वासन नहीं दिया गया था।

निदेशक महोदय ने अपने पत्र संख्या एफ 11 (3)–4।संस्था।ब।51295–322,

(श्री मुन्शीलाल महावर)

दिनांक 10–12–74 द्वारा प्रधानाचार्य, भेड़ व ऊन प्रशिक्षण संस्थान को आदेश दिये गये कि इन 25 व्यक्तियों को भी प्रशिक्षण के लिए उनकी योग्यता, जन्म-तिथि, स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र आदि प्राप्त कर यदि इनमें कोई अनियमितता पाई जाती है तो तुरन्त निदेशालय को सूचित करें। अतः 25 में से केवल 21 प्रशिक्षण में उनके स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र, शिक्षा प्रमाण-पत्र, इत्यादि के आधार पर लिये गये एवं उनका प्रशिक्षण 15-12-74 से आरम्भ किया गया।

उपरोक्त स्थिति से सदन में माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं कि इन व्यक्तियों के प्रशिक्षण में डी. पी. ए. पी. कार्यक्रम की सफलता के लिए एक विशिष्ठ प्रशिक्षण बैंच लगाया गया जिसमें उक्त कार्यवाही में विचार विमर्श किया गया, विचार विमर्श विभागीय अधिकारियों के साथ हुआ। जहां तक चयन समिति का प्रश्न है वहां निदेशक महोदय के निर्देशानुसार प्रधानाचार्य और व्याख्याताओं के द्वारा जांच की गई। इस चयन समिति में प्रिंसिपल एम. वी. सप्रे तथा प्रकाश जी. राय एवं जसवीरसिंह व्याख्याता थे। तत्पश्चात् ही इस प्रशिक्षण हेतु चयन कर प्रवेश दिया गया। इन व्यक्तियों के प्रशिक्षण हेतु चयनित प्रशिक्षणार्थियों के चयन में विभागीय तथा मन्त्री की अव्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता। यह प्रशिक्षण नियमानुसार ही योग्यता, स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र, सामान्य ज्ञान, भेड़ पालन में रुचि रखने वाले आदि बातों को मद्देनजर रखते हुये विशिष्ठ बैंच में प्रवेश दिया गया अतः जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है वह नियमानुसार ही किया जा रहा है।

इन प्रशिक्षणार्थियों को किसी भी तरह की छात्रवृत्ति नहीं दी जावेगी एवं इन्हें किसी प्रकार के निःशुल्क निवास की व्यवस्था उपलब्ध कराई जावेगी। इसके अतिरिक्त इन प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण के अन्तर्गत दौरे भी करने पड़ेंगे जिसका खर्चा वे स्वयं वहन करेंगे।

इस चयन में वित्तीय स्वीकृत भी नहीं ली गई और मन्त्री स्वयं ने इसका उल्लंघन कर जनहित की घोर अवहेलना की है, इस आरोप के सम्बन्ध में निवेदन है कि विभाग को किसी भी प्रकार अतिरिक्त व्यय नहीं उठना पड़ा, बल्कि विभाग की डी. पी. ए. पी. योजना को सुचारु रूप से समय पर प्रशिक्षित व्यक्ति उपलब्ध हो सकेंगे, इसका लाभ मिले और सूखाग्रस्त क्षेत्रों में भेड़ पालकों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। उसमें राज्य सरकार की और मेरी कहीं भी व्यक्तिगत स्वार्थ की बात नहीं आती है बल्कि जो कुछ भी किया गया है वह राज्य के प्रजावर्ग के हित एवं प्रदेश के विकास में किया गया है। माननीय सदस्य ने जो ++ आरोप लगाया है वह बिल्कुल तथ्यहीन, निराधार व झूठ से प्रेरित है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : ये जो आरोप हट गये हैं, उनको क्यों जिन्दा कर रहे हैं।

श्री भानुकुमार शास्त्री : वह बता रहे हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : एक्सपंज हो गये थे। फिर क्यों लगा रहे हैं?

++ये शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेश से निकाले गये।

श्री भानुकुमार शास्त्री : एक्सपंज तो अध्यक्ष महोदय ने किये हैं ।

श्री मुंशीलाल महावर : ऐसे आरोप लगाये थे ।

श्री मूलचन्द सामरिया : अध्यक्ष महोदय पहले वाले में भी × × थे ।

(शोरगुल–व्यवधान–अश्रव्य)

श्री भानुकुमार शास्त्री : ग्रॉन ए प्वाइण्ट आफ ऑर्डर, सर। अध्यक्ष महोदय, यह विषय नहीं है । आप व्यवस्था दीजिए । चोरी करने का कोई आरोप ही नहीं है ।

श्री अध्यक्ष: जिन प्वाइण्ट्स पर देना चाहते है उसी पर स्पष्टीकरण देकर समाप्त कीजिये ।

एक माननीय सदस्य : वह तो हो गया है ।

श्री मुंशोलाल महावर : स्पष्टीकरण हो गया ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपने अपने स्पष्टीकरण में जो आरोप की बात कही है, वह एक्सपंज की जाय ।

श्री मूलचन्द सामरिया : अध्यक्ष महोदय, इसको एक्सपंज किया जाये नहीं तो मैंने जो कुछ कहा है, वह भी सही है ।

श्री अध्यक्ष : आज के परिप्रेक्ष्य में नहीं होगा ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : रिप्लाई ठीक ढंग से देना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : इन्होंने एलीगेशन की बात विथड्रा की है ।

श्री मूलचन्द सामरिया : इन्होंने नहीं की है ।

श्री अध्यक्ष : आपके बारे में मैं पहले ही कह चुका हूं कि एक्सपंज होनी चाहिये ।

श्री मोहम्मद गफ़्फार अली : अध्यक्ष महोदय, आपका जो एक्सप्लेनेशन है, उसमें से भी विथड्रा होनी चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : वह हो गया, कह दिया ।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, आपने कहा है कि कमेटी बनाई है । क्या वह बनाई थी ? अध्यक्ष महोदय, मैं लम्बा नहीं खींचना चाहूंगा । सवाल यह है कि मैन्युअल के अनुसार कमेटी बनाई है ।

श्री अध्यक्ष : इनका उत्तर दे दीजिये ।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, कमेटी मेम्बर्स के नाम बताइये । मेन्यूअल के अनुसार सरकार ने कमेटी बनाई है ?

श्री अध्यक्ष : आपका प्रश्न है, क्या कमेटी बनाई है ?

श्री मुंशोलाल महावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है कि कमेटी बनी है, कमेटी मिनिस्टर नहीं बनाते हैं ।

××ये शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार से निकाले गये ।

Page No 12

(12)

श्री अध्यक्ष : यह किसने पूछा है कि मिनिस्टर बनाता है ?

श्री मुंशीलाल महावर : अपने आप ही वह बनती है। अपने आप ही वह सारा काम होता है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : अपने आप ही ?

श्री मूलचन्द सामरिया : आप क्या मजाक कर रहे हैं ?

(व्यवधान–शोरगुल)

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मारफत यह कहता हूं कि हाउस को गुमराह करने का दूसरा मोशन दे दिया जायेगा। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या मैन्युअल के अनुसार कमेटी बनी या नहीं ?

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अध्यक्ष महोदय, मैं एक आज्ञा चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री मुंशीलाल महावर : उसमें प्रिंसिपल और दो लेक्चरार थे।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : माननीय मन्त्री महोदय ने जो जवाब दिया है, कमेटी बनी हुई है। मीटिंग होती रही है। भले ही वह मैन्युअल के आधार पर नहीं हो। तो माननीय सदस्य रामकिशन जी से पूछना चाहता हूं। कमेटी से उनका क्या मतलब है ? कमेटी का और क्या काम है ? यह आप ही बताइये।

श्री रामकिशन : देखिये, आप इसमें घपला कर रहे हैं। डिप्टी सेक्रेटरी का आदेश गया है। गवर्नमेंट को लिखा है। वूल ग्रेडर का असेसमेण्ट किस ने किया है। वह कहीं लगा नहीं सकते हैं। आपने खेतसिंह जी के कहने से जवाब दिया है। आप जवाब दीजिये नहीं तो दूसरा प्रिविलेज मोशन आ जायेगा।

श्री भानुकुमार शास्त्री : एक और बता दीजिये, क्या सेंक्शन दी है।

श्री मुंशीलाल महावर : अध्यक्ष महोदय भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने··

श्री भानुकुमार शास्त्री : क्या फाइनेंस की सेंक्शन दी या नहीं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : हमने आपकी प्रसन्न मुद्रा की बड़ी तारीफ की है। इसलिये आप धैर्य से जवाब दीजिये।

श्री मुंशीलाल महावर : अध्यक्ष महोदय, जो सेक्रेटरी के बारे में कहा है, सचिवालय में डी. पी. ए. पी. प्रोग्राम की मिटिंग हुई है। लड़कों को लिया जाना चाहिये, उसकी मिनिट्स भेजी हैं। उन्होंने यह लिखा है कि हम मिनिट्स भेज रहे हैं। जिनमें से प्रेजेन्ट टर्म के अनुसार सिलेक्शन किया गया है। 7–12–74 को। डायरेक्टर साहब ने आदेश दिये हैं। उनके सार्टिफिकेट्स में किसी प्रकार कमी हो या अनियमितता हो तो हम को सूचित करें। मैं निवेदन करना चाहता हूं आप जिस पार्टी में हैं, तो हमारा फर्ज हो जाता है कि हम भरतपुर में जाकर प्रचार करते। आप होशहवास की बात करते हैं, मैं अपनी पार्टी के प्रति वफादार हूं। अगर जरा सा भी भ्रष्टाचार सिद्ध कर देते हैं तो मैं सदन से त्यागपत्र दे सकता हूं।

(शोरगुल–व्यवधान)

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : यह चैलेंज कर रहे हैं। ××× रहने भी दो।

श्री निरंजननाथ आचार्य : ××× नहीं है। इस शब्द को भी वापिस ले लें।

(शोरगुल–अश्रव्य)

श्री भानुकुमार शास्त्री : अच्छी वकालत के लिए धन्यवाद !

अध्यक्षीय व्यवस्था

कटौती प्रस्तावों पर चर्चा की प्रक्रिया

श्री अध्यक्ष : अनुदानों की मांगों एवं कटौती प्रस्तावों पर वाद-विवाद के सम्बन्ध में प्रक्रिया।

अनुदानों की मांगों पर विचार करने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस सम्बन्ध में गत कुछ वर्षों से अपनाई जाने वाली पद्धति की ओर आकर्षित करना चाहूंगा।

जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित होगा, मांगें समूह में प्रस्तुत की जावेंगी। मांगों पर कटौती प्रस्तावों की संख्या काफी होती है और समयाभाव के कारण यह सम्भव नहीं होगा कि कटौती प्रस्तावों की सूचना देने वाले सभी माननीय सदस्यों को विचार व्यक्त करने का अवसर दिया जा सके।

जैसा कि पिछले वर्षों में परिपाटी रही है सभी मांगों पर दिये गये कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत किये हुए समझा जाय और उन्हें सदन में पृथक् से प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। जिन माननीय सदस्यों के नाम पुकारे जायें वे अपने सारे कटौती प्रस्तावों पर एक साथ उसी समय बोलने की कृपा करें। किसी पार्टी के माननीय नेता या अन्य प्रमुख सदस्य, जो उनकी पार्टी की ओर से बोलना चाहें वे अपने विचार व्यक्त कर सकेंगे किन्तु वे अपनी पार्टी के समय के भीतर ही बोल सकेंगे।

माननीय सदस्यों को यह भी ज्ञात होगा कि मांगों पर होने वाली बहस के दौरान उठाये गये प्रश्नों के उत्तर मन्त्री महोदय द्वारा उसी दिन दिये जायेंगे और उसके बाद उन मांगों पर मतदान होगा। जिन कटौती प्रस्तावों के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों को समयाभाव के कारण उत्तर न मिल सके तो उनके आग्रह पर सरकार की ओर से सम्बन्धित माननीय सदस्यों को लिखित उत्तर मिल जायें, ऐसा मेरा निवेदन है।

श्री किशन मोटवानी : अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। जैसा देखा गया है···

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था पर फर्मा रहे हैं।

श्री किशन मोटवानी : आपने व्यवस्था दी है उस पर निवेदन है कि जिन सदस्यों को राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका नहीं मिला···

श्री अध्यक्ष : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं।

श्री किशन मोटवानी : व्यवस्था के लिए निवेदन कर रहा हूं, उस रूप में व्यवस्था हो सकती है कि जिन माननीय सदस्यों को

×××ये शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेश से निकाले गये।

Page No 14

(१४)

(श्री किशन मोटवानी)
न बजट भाषण पर मौका मिला, न राज्यपाल महोदय के भाषण पर मौका मिला, उनको इन कटौती प्रस्ताव के माध्यम से प्रॉयोरिटी देकर बोलने का मौका दिया जाय।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मुख्य सचेतक का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : मुख्य सचेतक का है। मेरा इसमें इतना है, जो कटौती प्रस्ताव सचिवालय में आये हैं, विधान सभा में उसी प्रॉयोरिटी के रूप में लेकर, उसी प्रॉयोरिटी के रूप में नाम बोलते जायेंगे। यह व्यवस्था हो सकेगी। परन्तु जिनके नाम नहीं आये हैं या बहुत देरी से आये हैं, किस को कम करूं··

श्री किशन मोटवानी : नाम आये हैं।

श्री अध्यक्ष : और कम करने के बाद जिस आर्डर में आये हैं, उस आर्डर में नहीं बोले जायं। यह उचित नहीं है। उसी आर्डर में नाम बोले जायेंगे और समय का खुद ध्यान रखें। 250 कटौती प्रस्ताव एज्यूकेशन पर हैं। दूसरी और हैं। आप सोच सकते हैं, 250 कटौती प्रस्ताव जिस पर है, उस पर कितना समय लग सकता है।

श्री खेतसिंह

श्री खेत सिंह (शिक्षा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या··

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अध्यक्ष महोदय, टाइम का निर्धारण नहीं किया है, किस प्रकार··

श्री अध्यक्ष : जान बूझ कर नहीं किया है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : ठीक है।

श्री अध्यक्ष : वैसे सुना दूं, आप चाहें ?

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : नहीं, हमें हर्ज नहीं है। सीमा थोड़ी आप निश्चित करवाइये।

श्री फूलचन्द जैन : आपने उठा दिया है सवाल। आप बोल दें।

एक माननीय सदस्य : आपने ध्यान आकर्षित कर दिया है···

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मेरा निवेदन है कांग्रेस को अलग समय दिया जाय और बाकी विरोधी पक्ष विशुद्ध है उसको अधिक समय दिया जाय।

श्री श्रीराम गोटेवाला : विशुद्ध कब हो गये ?

श्री अध्यक्ष : मांगों पर विचार व्यक्त करने के लिये मोटे तौर पर सरकारी पक्ष को तीन घण्टे का समय दिया जायगा जिसमें मंत्रियों द्वारा उत्तर दिये जाने का समय भी सम्मिलित होगा। अन्य दलों के लिए निम्न प्रकार होगा :—

— स्वतंत्र दल	पैंतीस मिनिट
— जनसंघ दल	तीस मिनिट
— संसोपा	बीस मिनिट
— सी.पी.आई.	बीस मिनिट
— सी.पी एम.	दस मिनिट
— निर्दलीय	पांच से दस मिनिट प्रति वक्ता।

श्री **रामकिशन** : निर्दलीय कहां रहे ?

श्री **अध्यक्ष** : आवश्यकता हुई तो कमी-वेशी हो सकती है।

श्री रामकिशन : निर्दलीय कहां रहे ?

श्री अध्यक्ष : जो कुछ रहे हैं ।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : आचार्य जी हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आचार्य जी विराजे हुए हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : इतनी आपस में चर्चा करने पर भी विषय उठाते हैं।

आय-व्ययक (बजट), 1975–76
द्वितीय अवस्था

अनुदान की मांगें : मांग संख्या 24 व मांग संख्या 17

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 24 के सम्बन्ध में 31 मार्च 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 74,04,17,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाय ।

श्री अध्यक्ष : दूसरी डिमाण्ड भी मूव कर दीजिये ।

श्री रामकिशन : शिक्षा और जेल का खूब मेल किया है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : शिक्षा जेल में दे रहे हैं ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : राठौड़ी का अधिकार मत दो ।

श्री भानुकुमार शास्त्री : राठौड़ी राज्य में शिक्षा जेल में होती है ।

श्री बनवारीलाल (राज्य मंत्री, कारागृह) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 17 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,22,15,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाय ।

मांग सं. 24 व 17 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल, जयपुर),

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा),

श्री मनोहरलाल (कामां),

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर),

श्री मीठालाल मीणा (लालसोट):—

1. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में माण्टेसरी प्रशिक्षित अध्यापकों की राज्य सेवा में नियुक्ति न किये जाने पर चर्चा के लिए) ।

2. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (संस्कृत प्राध्यापकों तथा अन्य प्राध्यापकों के वेतनमान में भेदभाव व असमानता पर चर्चा के लिये) ।

3. **श्री गिरधारीलाल भार्गव** (हवामहल जयपुर) :—मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 256 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
दिया जाय (जेल में बन्दियों को अच्छा भोजन दिये जाने हेतु चर्चा के लिए)।

4. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 256 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जेल व्यवस्था में सुधार किये जाने हेतु चर्चा के लिए)।

5. श्री शंकरसिंह रावत (नसीराबाद): मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अध्यापकों के स्थानान्तरण सत्र के बीच में न कर सत्र समाप्ति पर किये जाने हेतु चर्चा के लिए)।

6. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्राथमिक शालाओं को उच्च प्राथमिक शालाओं में क्रमोन्नत न कर छात्रों के आधार पर ही कक्षायें खोलने पर चर्चा के लिये)।

7. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय। राजकीय शिक्षण संस्थाओं की दयनीय स्थिति एवं पूरे वर्ष अध्यापकों के स्थानान्तरण से शिक्षा में कमी पर चर्चा के लिये)।

8. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अजमेर में लड़कियों का पृथक कालेज खोलने पर चर्चा के लिए)।

9. श्री जयकिशन तोसावड़ा (फागी): मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में महिला शिक्षा का उचित प्रसार न होने पर चर्चा के लिये)।

10. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार न होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

11. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (फागी एवं चाकसू तहसील में महिला शिक्षा के प्रसार हेतु चर्चा के लिये)।

12 मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चाकसू एवं फागी तहसील में प्रौढ़ शिक्षा की उचित व्यवस्था न होने पर चर्चा के लिये)।

13. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (फागी हायर सैकेण्डरी स्कूल में बायलोजी की कक्षा खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

14. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चाकसू कस्बे में हायर सैकण्डरी स्कूल खोलने हेतु चर्चा के लिये)।

15. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 256 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में जेलियों की दशा सुधारने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

Page No 17

(17)

(श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा)

16. मांग संख्या 17 मुख्य शीर्षक 256 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में जेलों को खुले रूप में बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

17. श्री झाबरमल सुण्डा (फतेहपुर): मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाठ्य पुस्तकें समय पर विद्यार्थियों को उपलब्ध न कराये जाने पर चर्चा के लिए)।

18. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (फतेहपुर–शेखावाटी क्षेत्र में प्राथमिक शालायें खोलने में हुई अनियमितता पर चर्चा के लिये)।

19. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आदर्श गांधी विद्या मंदिर रामगढ़ शेखावाटी को टेक-ओवर करने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये)।

20. श्री दीपंकर (लाडनूं): मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शहरों और गांवों के अध्यापकों को समान सुविधा उपलब्ध कराने पर चर्चा के लिये)।

21. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 256 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बंदियों के भोजन की अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

22. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 256 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जेलों में जेलियों के व्यवहार सुधारने पर चर्चा के लिये)।

23. श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर): मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अल्पवेतनभोगी अध्यापकों का उनके होम डिस्ट्रिक्ट से दूर स्थानान्तरण करने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये)।

24. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 256 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जेल के अधिकारियों को पुलिस अधिकारियों के समान वेतन किये जाने पर चर्चा के लिये)।

25. श्री ओंकारलाल चौहान (डग): मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अधिक हायर सैकण्डरी स्कूल्स एण्ड कालेजेज खोलने हेतु चर्चा के लिये)।

26. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा के क्षेत्र में उचित विकास नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

27. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटा में एल. एल. एम. कालेज खुलवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

Page No 18

(18)

(श्री ओंकार लाल चौहान)

28. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा नीति में परिवर्तन किया जाय इस पर चर्चा के लिये)।

29. श्री बनवारीलाल (धौलपुर) : मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (धौलपुर सब-डिवीजन में शिक्षा का उचित प्रसार कराने के बाबत चर्चा के लिये)।

30. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम ससीया में सैकण्डरी स्कूल खोलने के बाबत चर्चा के लिये)।

31. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (धौलपुर कालेज में पोस्ट ग्रेजुएट कक्षायें खोलने के बाबत चर्चा के लिये)।

32. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (धौलपुर कालेज में ला-क्लासेज खोलने के बाबत चर्चा के लिये)।

33. श्री भुवनेश चतुर्वेदी (कोटा) : मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं को दिये जाने वाले अनुदान में होने वाली अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

34. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजकीय शिक्षण संस्थाओं में अध्यापकों के अभाव पर चर्चा के लिए)।

35. श्रीमती निर्मला कुमारी (चित्तौड़गढ़): मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वर्तमान शिक्षा की उपयोगिता समाप्त हो जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

36. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में व्यवसायिक शिक्षा के महत्व को बढ़ावा नहीं दिये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

37. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 256 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में जेल की वर्तमान व्यवस्था दोष पूर्ण होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

38. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 256 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में जेलों में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

39. श्री चुन्नीलाल इंदलिया (नोखा): मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में मिडिल स्कूलों को हायर सैकण्ड्री स्कूलों में क्रमोन्नत करने में सरकार द्वारा पूरा सहयोग नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिए)।

40. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)
कम कर दिया जाय (नोखा मंडी, बीकानेर की 70 हजार की आबादी व 11,00,000 रुपये की लागत का भवन बनाने पर भी कालेज नहीं खोलने पर चर्चा के लिये)।

41. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बीकानेर के कस्बा नोखा मण्डी में गट्टाणी गर्ल्स मिडिल स्कूल को सैकेण्डरी में क्रमोन्नत करवाने हेतु चर्चा के लिये)।

42. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील नोखा के ग्राम काकड़ा सैकेण्डरी पाठशाला में ऑप्शनल विषय विज्ञान व वाणिज्य चालू करवाने व सैकण्डरी से हायर सैकेण्डरी में क्रमोन्नत करवाने पर चर्चा के लिये)।

43. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील नोखा के ग्राम भामरसर व सुरपुरा मिडिल स्कूलों में पाठ्य पुस्तकों की कमी व विद्यार्थियों की संख्या अधिक होते हुए भी अध्यापकों की कोई सन्तोषजनक व्यवस्था नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

44. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील नोखा के ग्राम जसरासर के मिडिल स्कूल को हायर सैकण्डरी में क्रमोन्नत करने हेतु चर्चा के लिये)।

45. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील कोलायत के ग्राम झझू के मिडिल स्कूल को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करवाने हेतु चर्चा के लिये)।

46. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील कोलायत के ग्राम दासूड़ी व गिरराजसर मिडिल स्कूलों में अध्यापकों की सन्तोषजनक व्यवस्था नहीं की गयी इस पर चर्चा के लिये)।

47. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम कूदसू तहसील नोखा की मिडिल स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या अधिक होते भी अध्यापकों की पूरी व्यवस्था नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

48. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील नोखा के ग्राम कक्कू की प्राथमिक पाठशाला को उच्च प्राथमिक पाठशाला में क्रमोन्नत कराने हेतु चर्चा के लिये)।

49. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील नोखा के बन्धड़ा मिडिल स्कूल को क्रमोन्नत करवाने पर चर्चा के लिये)।

50. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति नोखा क्षेत्र के अधीनस्थ ग्राम साधूणा की मिडिल स्कूल

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)
में अध्यापकों की पूरी संख्या व उचित व्यवस्था नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

51. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील नोखा के ग्राम सारूंडा एक बहुत बड़ी आबादी वाला ग्रामीण व ढाणियों का क्षेत्र है, विद्यार्थियों की अधिक संख्या से मिडिल स्कूल खुलवाने के लिये चर्चा के लिये)।

52. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील नोखा के ग्राम भाडूसर व ग्राम पंचायत व पंचायत समिति द्वारा कई प्रस्ताव भेजने के बावजूद मिडिल स्कूल नहीं खोले जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

53. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बीकानेर तहसील नोखा ग्राम देशलसर को मिडिल स्कूल विद्यार्थियों की संख्या अधिक होते हुए भी हायर सैकण्डरी में क्रमोन्नत नहीं किया गया, इस पर चर्चा के लिये)।

54. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम पांचू तहसील नोखा के मिडिल स्कूल को हायर सैकण्डरी में क्रमोन्नत नहीं किया गया है जब कि लगभग 50 हजार की आबादी के ग्रामीण क्षेत्र में कई सैकण्डरी स्कूल हैं, इस पर चर्चा के लिये)।

55. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील नोखा के ग्राम घरनोक में दो बार मिडिल स्कूल की स्वीकृति दिये जाने के बावजूद भी स्कूल नहीं चालू किया गया इस पर चर्चा के लिये)।

56. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील नोखा के ग्राम जयसिंह देसर, मगरा व पीथरासर सिर्फ आधा मील की दूरी पर दो मिडिल स्कूल हैं तथा विद्यार्थियों की संख्या बहुत अधिक होते हुए भी हायर सैकण्डरी नहीं खोले जाने पर चर्चा के लिये)।

57. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील नोखा ग्राम जांगलू मिडिल स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या अधिक होते हुए भी अध्यापकों की सम्पूर्ण व्यवस्था आज तक नहीं की गयी है इस पर चर्चा के लिये)।

58. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील नोखा के ग्राम साधासर के मिडिल स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या अधिक होते हुए भी अध्यापकों की पूर्ण रूप से व्यवस्था नहीं है, इस पर चर्चा के लिये)।

59. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)
दिया जाय (तहसील नोखा के ग्राम बेरासर व ग्राम गजरूप देसर मिडिल स्कूल में अध्यापकों की कमी पर चर्चा के लिये)।

60. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील नोखा के ग्राम सारवरिया के मिडिल स्कूल में अध्यापकों की कमी की पूर्ति करवाने पर चर्चा के लिये)।

61. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील नोखा के ग्राम कूचौर अगूणी व आथूणी के मिडिल स्कूलों में फर्नीचर, दरियों व पाठ्य पुस्तकों के अभाव को दूर करवाने हेतु चर्चा के लिये)।

62. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील नोखा के ग्राम बादनू की मिडिल स्कूल में अध्यापकों की व्यवस्था करवाने पर चर्चा के लिये)।

63. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील कोलायत के ग्राम अमासर के मिडिल स्कूल को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करवाने हेतु चर्चा के लिये)।

64. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील नोखा के ग्राम हिमरसर के मिडिल स्कूल को सैकेन्डरी में क्रमोन्नत करवाने हेतु चर्चा के लिये)।

65. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 256 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य की जेलों में रहने वाले कैदियों को पेट भर खाना व अन्य सामग्री उपलब्ध करवाने पर चर्चा के लिये)।

66. श्री सांवरमल मीर (श्री माधोपुर): मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षालयों में समय पर अध्यापक न भेजने पर चर्चा के लिये)।

67. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 256 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जेल में कैदियों को अच्छा खाना तथा अच्छे आचरण के कैदियों को अधिक सुविधा देने पर चर्चा के लिये)।

68. श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर): मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजकीय कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय, लूणकरनसर व कालू को माध्यमिक स्तर तक क्रमोन्नत कराने पर चर्चा के लिये)।

69. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर क्षेत्र की छतरगढ़ कालोनी में उच्च कन्या प्राथमिक विद्यालय खुलाने हेतु चर्चा के लिये)।

70. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लूणकनरसर तहसील मुख्यालय के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में कृषि एवं पशुपालन विज्ञान के अतिरिक्त विषय के अध्यापन की व्यवस्था नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

(श्री भीमसेन चौधरी)

71. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महा विद्यालय बीकानेर के छात्रों एवं छात्राओं के लिए छात्रावास सुविधाओं की विभाग द्वारा व्यवस्था नहीं कराये जाने पर चर्चा के लिये)।

72. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर के ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिये छात्रावास सुविधा के अभाव पर चर्चा के लिये)।

73. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अभावग्रस्त क्षेत्रों के विद्यार्थियों को अभाव स्थिति के दौरान आर्थिक सहायता दी जाये-इस पर चर्चा के लिये)।

74. श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा) : मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान के पोलीटेक्निक विद्यालयों में डिमांस्ट्रेटर्स के ग्रेड व तरक्की एवं नये कोर्सेज के चालू कराने के लिए चर्चा के लिए)।

75. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अध्यापकों के स्थानान्तरण की राज्य सरकार की नीति को दृढ़ता से लागू करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

76. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उम्मेद कन्या माध्यमिक विद्यालय एवं दयानन्द कन्या माध्यमिक विद्यालय, जोधपुर को माध्यमिक स्तर का अनुदान न मिलने के विषय में चर्चा के लिए)।

77. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजकीय मोंटेसरी पाठशाला, जोधपुर के नये भवन को जो पिछले आठ वर्षों से अधूरा पड़ा है, विभाग द्वारा पूर्ण करने के लिए चर्चा के लिए)।

78. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के एडहाक ग्रान्ट इन एड स्वीकार करने के लिए राज्य सरकार द्वारा स्पष्ट नीति-निर्धारण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

79. मांग संख्या 24 मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार के पत्र संख्या प.स. 29/(44)शिक्षा–5/73 दिनांक 29-6-1973 द्वारा श्री सुमेर हायर सैकेण्डरी स्कूल, जोधपुर को रुपये 50 हजार का तदर्थ अनुदान स्वीकृत का अभी तक भुगतान न होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

80. श्री रामगोपाल (किशनगंज) : मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बारां मिडिल स्कूल व कालेज को क्रमोन्नत करने पर चर्चा के लिए)।

(श्री रामगोपाल)

81. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बरोनी प्राथमिक विद्यालय तहसील किशनगंज को क्रमोन्नत कराने हेतु चर्चा के लिए)।

82. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटा जिले में शिक्षण संस्थाओं के भवनों का निर्माण एवं मरम्मत कराने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिए)।

83. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटा जिले की शिक्षा समस्याओं का निराकरण नहीं किये जाने पर चर्चा के लिए)।

84. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 256 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बोरखेड़ा जिला कोटा में आदर्श जेल (खुला शिविर) (ओपन एयर कैम्प) स्थापित करने पर चर्चा के लिए)।

85. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 256 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान की जेलों में कैदियों को उचित सुविधा प्राप्त नहीं होने पर चर्चा के लिए)।

86. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 256 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भटरू में जेल भवन निर्माण कराने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिए)।

87. श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा): मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वर्तमान शिक्षा प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

88. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा प्रणाली को अधिकाधिक जनोपयोगी बनाने के बारे में चर्चा के लिए)।

89. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 256 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जेल को मानव की अपराध वृत्ति को शमन करने का स्थान बनवाने हेतु चर्चा के लिए)।

90. श्री केदारनाथ (गंगानगर): मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा विभाग में बड़े अधिकारियों के पद कई महिनों से रिक्त पड़े हैं, इससे उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

91. मांग संख्या 24 मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार पंचायत समिति के अतिरिक्त (सरप्लस) स्टाफ को शिक्षा विभाग में एडजस्ट करने में असमर्थ रही इस पर चर्चा के लिये)।

92. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगानगर जिले में विद्यालय निरीक्षक का पद दिनांक 7-1-1975 से खाली पड़ा है, इससे उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

(श्री केदार नाथ)

93. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार विघटित नगरपालिका के अध्यापकों के मामले निपटाने में असमर्थ रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

94. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार विघटित जिला बोर्ड के अध्यापकों के बकाया मामले निपटाने में असमर्थ रही, इस पर चर्चा के लिये)।

95. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार पब्लिक स्कूलों को बन्द करने में अयोग्य साबित हुई, इस पर चर्चा के लिये)।

96. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार निजी संस्थाओं का राष्ट्रीयकरण करने में असमर्थ रही, इस पर चर्चा के लिये)।

97. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार तृतीय वेतन श्रृंखला के अध्यापकों का ग्रेड, रनिंग करने में असमर्थ रही, इस पर चर्चा के लिये)।

98. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार अभी तक प्राइवेट स्कूल व विद्यालयों के अध्यापकों की सेवा सुरक्षा की व्यवस्था नहीं कर पाई, इस पर चर्चा के लिये)।

99. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार के वरिष्ठ अध्यापकों के वेतनमान सुधारने की सिफारिश लगभग एक वर्ष पूर्व सरकार को पेश करने के उपरांत भी लागू नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

100. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बी.एड. प्रशिक्षण के लिये पहले डिग्री में न्यूनतम अंक का कोई प्रावधान नहीं था। राजस्थान में प्रशिक्षित स्नातकों की बहुत कमी है। और अध्यापक प्रशिक्षण में जाना चाहते हैं परन्तु विश्वविद्यालय न्यूनतम 40% अंक की रोक लगाकर 10 वर्ष की सेवा से ऊपर वाले अध्यापकों को प्रशिक्षण से वंचित कर रहा है। अतः न्यूनतम अंकों की रोक हटायी जावे अथवा 10 वर्ष से ऊपर के अध्यापकों को प्रशिक्षित माना जावे या 50% स्थान रिजर्व किया जावे, इस पर चर्चा के लिये)।

101. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनुदान एवं मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के अध्यापकों की सेवा सुरक्षा के लिए शिक्षा नियम प्रकाशित एवं लागू नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

102. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय शहरों में आवश्यकता से अधिक स्टाफ है, जबकि ग्रामीण कन्या विद्यालयों में जैसे गंगूवाला, भूकरका,

(श्री केदार नाथ)
रिड़, फ्लाचर आदि में स्टाफ की कमी पर चर्चा के लिए)।

103. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शालाओं में आवश्यकता के सामान की कमी रहती है, जैसे टाटपट्टी, ब्लैक बोर्ड आदि जबकि प्राइवेट संस्थाओं में आवश्यकता से अधिक अनुदान दिया जाता है इस पर चर्चा के लिये)।

104. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लगातार 10 वर्ष के सेवा काल के बाद मैट्रिक, हायर सैकण्ड्री अध्यापकों को ट्रेन्ड मान लिया जाता है, परन्तु लगातार 10 वर्ष के सेवाकाल के बाद भी बी.ए. पास अध्यापकों को बी.एड. नहीं मानने पर चर्चा के लिए)।

105. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (परियोजना क्षेत्र में परियोजना भत्ता दिया जाता है. परन्तु परियोजना क्षेत्र में कार्यरत अध्यापकों को परियोजना भत्ता देने में सरकार असमर्थ रही इस पर चर्चा के लिए)।

106. मांग संख्या 24 मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार श्रीमाली आयोग की सिफारिशों को लागू करने में असमर्थ रही, पर चर्चा के लिये)।

107. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा प्रधानाध्यापक सैकण्डरी स्कूल के पद के लिए चयनित सिलेक्टेड 324 व्यक्तियों में से अभी तक 200 अध्यापकों को पद स्थापन करवाने में असमर्थ रही, पर चर्चा के लिये)।

108. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 256 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार जेलों में भोजन व रहने की व्यवस्था करने में असमर्थ रही, पर चर्चा के लिये)।

109. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 256 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया (उदयपुर के केन्द्रीय कारागृह को सुधारने में सरकार असमर्थ रही, इस पर चर्चा के लिये)।

110. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 256 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार जेल के अन्दर जन आन्दोलनों के तहत गिरफ्तार किये व्यक्तियों से राजनैतिक कैदी के रूप में व्यवहार करने में असफल रही, इस पर चर्चा के लिये)।

111. श्री गुरदयालसिंह संधु (करणपुर): मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चक 33 बी–बी तहसील पदमपुर में कन्या माध्यमिक पाठशाला खुलाने पर चर्चा के लिये)।

112. मांग संख्या 24 मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पदमपुर, जिला गंगानगर, में महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

(श्री गुरदयालसिंह संधु)

113. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (स्कूलों में पंजाबी भाषा (गुरमुखी लिपि में) न पढ़ाये जाने के बारे में चर्चा के लिये)।

114. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तामकोट उच्च माध्यमिक पाठशाला में कृषि वैकल्पिक विषय पढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

115. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम विडिंग, तहसील करनपुर, में उच्च माध्यमिक विद्यालय खुलवाये जाने पर चर्चा के लिये)।

116. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम माणकसर, तहसील करणपुर, जिला गंगानगर, में उच्च माध्यमिक विद्यालय खुलवाये जाने पर चर्चा के लिये)।

117. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चक 4 जे–जे तहसील पदमपुर, जिला गंगानगर, में उच्च माध्यमिक विद्यालय खुलवाये जाने हेतु चर्चा के लिये)।

118. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पदमपुर, जिला गंगानगर, में कला महाविद्यालय (पुरुषों के लिये) खोलने हेतु चर्चा के लिये)।

119. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम गमूढ़वाली जिला गंगानगर में उच्च माध्यमिक विद्यालय खुलवाने हेतु चर्चा के लिये)।

120. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम तामकोट तहसील पदमपुर के उच्च माध्यमिक विद्यालय में कृषि व विज्ञान की शिक्षा शुरू कराने हेतु चर्चा के लिये)।

121. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चक 3 ओ तहसील करनपुर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में भूगोल का ऐच्छिक विषय शुरू कराने हेतु चर्चा के लिये)।

122. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 256 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जेल में राजनैतिक बन्दियों के साथ आम केदियों जैसा व्यवहार किया जाना और 'सी' श्रेणी में रखा जाने पर चर्चा के लिये)।

123. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 256 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर जेल में जनवरी, 1975 में चूरू के सत्याग्रहियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया इस पर चर्चा के लिये)।

124. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 256 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (करणपुर जेल की

(श्री गुरदयालसिंह संधु)

चिन्ताजनक स्थिति को सुधारने पर चर्चा के लिये)।

125. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर गर्ल्स सेकेण्डरी स्कूल को हायर सेकेण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत करने में शिक्षा विभाग की उपेक्षा पर चर्चा के लिये)।

126. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा की नीति में आमूल–चूल परिवर्तन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

127. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय। (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालय एवं कालेज के प्राध्यापकों के वेतनमानों में वृद्धि की सिफारिश को राज्य सरकार द्वारा मान्यता देने में उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

128. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान प्रान्त के पिछड़े हुये जैसलमेर, बाड़मेर एवं जालोर जिलों में, जिलों के मुख्यालयों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों के भवनों के निर्माण एवं उनके मरम्मत की ओर विभागीय उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

129. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय बाड़मेर जिले की राणी गांव, बंसाला, बाटाडू एवं रामसर मिडिल स्कूलों को सेकेण्ड्री स्कूलों में क्रमोन्नत करने में उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

130. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले के मुख्यालय बाड़मेर नगर में राजकीय महाविद्यालय में राजकीय छात्रावास के भवन निर्माण के लिये महाविद्यालय के प्रांगण में गत साल एक लाख रुपये स्वीकृत करने की घोषणा की थी, जिसके क्रियान्वयन न होने से महाविद्यालय के विद्यार्थियों में घोर असन्तोष के विषय पर चर्चा के लिये)।

131. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले के मुख्यालय बाड़मेर नगर में राजकीय महाविद्यालय में रसायन विभाग की एग्जास्ट फैन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

132. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 256 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जेलों में सुधारों की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

133. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 256 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले के मुख्यालय बाड़मेर सब–जेल में पानी की सुचारु रूप से व्यवस्था न होने पर चर्चा के लिये)।

134. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 256 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर सब–जेल के भवन

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)
में मरम्मत करने के लिये विभाग द्वारा व्यवस्था न करने पर चर्चा के लिये)।

135. **श्री नन्दलाल बैरवा** (पाटन) : मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 256 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान की जेलों में भोजन आदि की उचित व्यवस्था नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

136. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 256 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान के कारागृहों में व्यवस्था अच्छी नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

137. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (केशवराय पाटन सेकेण्डरी स्कूल में वाणिज्य विषय अभी तक नहीं खोले जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

138. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामों में शिक्षा में विशेष व्यवस्था नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

139. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में महिला शिक्षा पर विशेष कार्यक्रम नहीं बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

140. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये (जिला बून्दी की तहसील केशवराय पाटन की सैकेण्डरी स्कूल को हाई सैकेण्डरी में क्रमोन्नत नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

141. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बून्दी में विधि कक्षायें नहीं खोले जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

142. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बून्दी कालेज में राजकीय छात्रावास नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

143. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में शिक्षा की उचित व्यवस्था नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

144. **श्री गोपीलाल** (पीपल्दा) : मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (स्कूलों में अध्यापकों की समय पर नियुक्ति न होने पर चर्चा के लिये)।

145. **श्री लूणाराम** (डूंगरपुर) : मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भवन बनाने के लिये दिये जाने वाले अनुदान में विभाग द्वारा अनियमितता करने पर चर्चा के लिये)।

146. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर

(श्री लूणाराम)

दिया जाय (मान्यता प्राप्त शालाओं को समय पर अनुदान न देने पर चर्चा के लिये)।

147. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अध्यापकों के गलत स्थानान्तरणों से बढ़ने वाले अधिभार पर चर्चा के लिये)।

148. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मान्यता प्राप्त एडहॉक स्कूलों को दी जाने वाली राशि के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये)।

149. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा घटिया फर्नीचर खरीदने पर चचा के लिये)।

150. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाठ्य पुस्तकों के मूल्य व छपाई में हुई गड़बड़ी से समय पर पुस्तक न मिलने पर चर्चा के लिये)।

151. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (श्री डूंगरगढ़ कन्या सेकेण्ड्री स्कूलों को क्रमोन्नत किये जाने के बारे में चर्चा के लिये)।

152. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अधिक प्राथमिक पाठशालाओं की स्थापना का प्रावधान बजट में न करने के बारे में चर्चा के लिये)।

153. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सेकेण्डरी शालाओं में कामर्स एवं साईन्स की कक्षायें खुलवाने के बारे में चर्चा के लिये)।

154. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सोनियासर व आढ़सर उच्च प्राथमिक शालाओं को क्रमोन्नत किये जाने पर चर्चा के लिये)।

155. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्राथमिक शाला बेलवान, उदरासर, धनेरु वापेऊ, वार्ड नम्बर 3 डूंगरगढ़, रुपलीसर, बजरंगसर, जेतसीसर, बाडलियों को क्रमोन्नत कराने हेतु चर्चा के लिये)।

156. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बालिकाओं के लिये आढ़सर, तेऊ में प्राथमिक शालायें स्थापित कराने हेतु चर्चा के लिये)।

157. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 256 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बन्दी लोगों को उनके भरण पोषण पर होने वाले खर्च के अनुपात से सुविधा न पहुंचाने पर चर्चा के लिये)।

158. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 256 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सब–जेल में पाक बन्दी लोगों को काम देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

159. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन) : मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (झालरापाटन शहर में कन्या मिडिल स्कूल में प्रधानाध्यापिका एवं स्टाफ न भेजने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

160. मांग संख्या 24 मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झालावाड़ में कन्या हायर सैकेण्डरी व झालरापाटन में छात्रों का हायर सैकेण्डरी स्कूल न खोले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

161. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झालावाड़ के महाविद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएट कक्षायें चालू कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

162. **श्री करनसिंह** (डीग) : मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

163. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 256 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जेल व्यवस्था में सुधार हेतु चर्चा के लिये)।

164. **श्री भैरूलाल** (अकलेरा) : मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकलेरा माध्यमिक विद्यालय में वाणिज्य कक्षा कायम कराये जाने हेतु चर्चा के लिये)।

165. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकलेरा कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत कराने हेतु चर्चा के लिये)।

166. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मनोहर थाना उच्च माध्यमिक विद्यालय में यन्त्र विज्ञान का विषय खुलाने हेतु चर्चा के लिये)।

167. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकलेरा माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किये जाने हेतु चर्चा के लिये)।

168. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मनोहरथाना कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किये जाने हेतु चर्चा के लिये)।

169. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नये उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों व कक्षाओं के कमरों के अभाव से, छात्रों में उत्पन्न असंतोष पर चर्चा के लिये)।

170. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों का स्थानान्तरण राजनैतिक दृष्टिकोण अपना कर करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

(श्री भैरू लाल)

171. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गत तीन वर्षों में कायम हुए उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भवनों के अभाव से छात्रों को परेशानी पर चर्चा के लिये।

172. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 256 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जेलों में प्रशिक्षण संस्थाओं की कमी पर चर्चा के लिये)।

173. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 256 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकलेरा सब जेल पर तैनात प्रहरियों की पदोन्नति में बरते गये भेद-भाव पर चर्चा के लिये)।

174. श्री नारायणसिंह चौधरी (दांता-रामगढ़) : मांग संख्या 24 मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शालाओं में अध्यापकों की कमी से होने वाली अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

175. श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर) : मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा पद्धति में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

176. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अध्यापकों की नियुक्तियों में हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

177. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 256 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जेलों में सुधार की आवश्यकता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

178. श्री रतीराम यादव (तिजारा) : मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान शिक्षक संघ के मांग पत्र को सरकार द्वारा स्वीकार नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

179. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अध्यापकों के तबादलों के सम्बन्ध में सरकार की वर्तमान नीति के बारे में चर्चा के लिये)।

180. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (निजी शिक्षण संस्थाओं के राष्ट्रीयकरण न करने के कारण शिक्षकों की सर्विस में असुरक्षा व्याप्त है इस पर चर्चा के लिये)।

181. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजकीय प्राथमिक शालाओं के अध्यापकों के मेडीकल पुनर्भुगतान हेतु राजकीय कोष से व्यवस्था कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

182. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान के अध्यापकों के वेतन स्तर को केन्द्र के अध्यापकों के वेतन स्तर के फर्क की समाप्ति करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

(श्री रतीराम यादव)

183. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजकीय महाविद्यालयों में हिन्दी के अध्यापकों के साथ पक्षपात पूर्ण वर्ताव करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

184. श्री केशरीमल (व्यावर) : मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (निजी शिक्षण संस्थाओं के राष्ट्रीयकरण न करने के कारण शिक्षकों की सर्विस में असुरक्षा व्याप्त है, इस पर चर्चा के लिये)।

185. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वर्तमान शिक्षा पद्धति में उपयुक्त परिवर्तन करने में सरकार असफल रही है इस सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

186. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजकीय प्राथमिक शालाओं के अध्यापकों को मेडीकल पुनर्भुगतान हेतु राजकीय कोष से व्यवस्था कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

187. मांग संख्या 24 मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान के अध्यापकों के वेतन स्तर को केन्द्र के अध्यापकों के वेतन स्तर के फर्क को समाप्त करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

188. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान शिक्षक संघ के मांग-पत्र को सरकार द्वारा स्वीकार नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

189. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वर्नाक्यूलर व अन्य प्रमाण-पत्र प्राप्त सिंध से आये अध्यापक व अध्यापिकायें जो सेवा में हैं, इन्हें अभी तक भी मान्यता नहीं देने पर चर्चा के लिये)।

190. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ब्यावर में गर्ल्स कालेज नहीं खोले जाने पर चर्चा के लिये)।

191. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ब्यावर में मिल एरिया लेबर कालोनी में विभाग द्वारा शाला भवन नहीं बनवाने पर चर्चा के लिये)।

192. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अध्यापकों के स्थानान्तरण की कोई नीति नहीं अपनाने पर चर्चा के लिये)।

193. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (देवखेड़ा ग्राम की प्राथमिक शाला को सेकेन्डरी में क्रमोन्नत कराने हेतु चर्चा के लिये)।

Page No 33

(33)

(श्री केशरी मल)

194. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बराखन मे प्राथमिक शाला को सेकेण्डरी शाला में क्रमोन्नत कराने पर चर्चा के लिए)।

195. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लबूरी गांव बामनहेड़ा पंचायत क्षेत्र में प्राथमिक शाला खुलवाने पर चर्चा के लिए)।

196. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शहरों में शाला भवनों के लिये सरकार द्वारा राशि न दिये जाने पर चर्चा के लिए)।

197. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 256 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जेलों में अखबार व पुस्तकों की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

198. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 256 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जेल के कैदियों को काम सीख लेने के बाद उनसे लिये गये कार्य के भुगतान की राशि बढ़ाने के बारे मे चर्चा के लिये)।

199. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 256 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जेलों में कैदियों को अच्छे और साबुत कम्बलों की व्यवस्था कराने हेतु चर्चा के लिये)।

200. श्री अजीतसिंह (टोंक): मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण सेकेण्डरी स्कूलों में कृषि व विज्ञान की कक्षायें अनिवार्य रूप से खुलाये जाने हेतु चर्चा के लिए)।

201. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा को जीविका अर्जित करने योग्य बनाने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिए)।

202. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (टोंक कालेज में पोस्ट ग्रेजुएट कक्षायें खुलवाने हेतु चर्चा के लिये)।

203. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (टोंक में राजकीय कन्या छात्रावास खुलवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

204. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 256 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (टोंक जेल में पेड़ काट कर बेच देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए)।

205. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 256 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जेल में कैदियों को पूरा राशन प्राप्त न होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

206. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 256 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया

(श्री अजीत सिंह)
कम कर दिया जाय (टोंक जेल में उद्योग स्थापित करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

207. श्री भोपालसिंह (जैसलमेर): मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा के विस्तार व गुणात्मक पहलुओं में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता तथा उसको व्यवसायोन्मुख बनाने की दिशा में प्रभावशाली कदम समय रहते उठाना वांछित है इस पर चर्चा के लिये)।

208. श्री चेतराम (टोडाभीम): मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान प्रान्त में शिक्षा प्रणाली पर सुधार व सवाई माधोपुर जिले की शिक्षा समस्याओं पर चर्चा के लिये)।

209. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 256 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर जिले की जेलों में बन्दियों को पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराने पर चर्चा के लिये)।

210. श्री उम्मेदीलाल (हिन्डौन): मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 256 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जेलों के सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

211. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रौढ़ शिक्षा के विस्तार पर चर्चा के लिये)।

212. श्री चिरमनसिंह भाटी (भीम): मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा विभाग में ब्यावर सीनियर डिप्टी इन्सपेक्टर द्वारा मनमानी करने व नियमों का उल्लंघन करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

213. श्री विजयसिंह राठोड़ (माडल): मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ग्रामों में शालाओं के भवनों की कमी दूर करने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

214. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत माग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (व्यवसायोन्मुख शिक्षा पर अधिक बल देने हेतु चर्चा के लिये)।

215. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा पद्धति में परिवर्तन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

216 मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षण संस्थाओं को साधन सम्पन्न बनाने हेतु चर्चा के लिये)।

217. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 256 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जेलों में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं पक्षपात पर चर्चा के लिये)।

218. श्री मानालाल (राजसमंद) मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्त-

(श्री नाथालाल)

र्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्राथमिक शालाओं में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों व छात्रों के बैठने की सुविधा के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

219. श्री रामलाल बाड़ी (वाड़ी) : मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भरतपुर जिले में शिक्षण संस्थाओं में सुधार करने पर चर्चा के लिये)।

220. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 256 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (धौलपुर जेल में सुधार करने पर चर्चा के लिये)।

221. श्री गोपाल जोशी (बीकानेर) : मांग संख्या 24 मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में शिक्षा के सम्बन्ध में आवश्यक सुधार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

222. मांग संख्या 24. मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर में विश्वविद्यालय का अभाव है इसको दूर करने पर चर्चा के लिये)।

223. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये)।

224. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 256 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर जेल में कैदियों को समय पर उचित मात्रा में खाद्य सामग्री उपलब्ध नहीं कराने पर चर्चा के लिये)।

225. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 256 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जोधपुर जेल में कैदियों के साथ अच्छा व्यवहार न करने व उनकी समस्याओं का समाधान करने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

226. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 256 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटा जेल में कैदियों के साथ अच्छा व्यवहार न करने व उनकी समस्याओं का विभाग द्वारा समाधान न करने पर चर्चा के लिये)।

227. श्री जगमोहनसिंह (छबड़ा) : मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (छबड़ा सैकेण्डरी स्कूल में कृषि विषय खोले जाने बाबत चर्चा के लिये)।

228. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (छीपाबड़ोद कन्या मिडिल स्कूल को सैकेण्डरी में क्रमोन्नत किए जाने हेतु चर्चा के लिये)।

229. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (छबड़ा सेकेण्डरी स्कूल को हायर सेकेण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत किए जाने हेतु चर्चा के लिये)।

230. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया

(श्री जगमोहन सिंह)
कम कर दिया जाय (हाड़ौती विश्वविद्यालय कोटा में खोले जाने पर चर्चा के लिए)।

231. श्री देवीलाल (सराड़ा) : मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला उदयपुर तहसील सराड़ा गांव देवपुरा में सेकेण्ड्री स्कूल खुलवाने हेतु चर्चा के लिये)।

232. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील सराड़ा के गांव जावद में प्राथमिक विद्यालय खुलवाने पर चर्चा के लिये)।

233. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील सराड़ा के गांव बलुवा, पिलाधर, सिगटवाड़ा, मलाड़ा में प्राथमिक विद्यालय खुलवाने हेतु चर्चा के लिये)।

234. श्री भगराज चौधरी (रानीवाड़ा): मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जालौर जिले की पंचायत समिति क्षेत्र में जसवंतपुरा एवं रानीवाड़ा में माध्यमिक शालायें खुलवाने हेतु चर्चा के लिए)।

235. श्री हनुमानसहाय (बैराठ) : मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मिडिल एवं सेकेण्ड्री स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के अभाव पर चर्चा के लिये)।

236. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा विभाग द्वारा द्वितीय ग्रेड के अध्यापकों के अनावश्यक स्थानान्तरणों पर चर्चा के लिये)।

237. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शाहपुरा में कालेज स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

238. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (स्कूल भवनों को पूर्ण कराये जाने हेतु ग्रान्ट-इन-एड की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

239. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में संस्कृत शिक्षा के विकास किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

240. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सेकेण्डरी स्कूलों में वाणिज्य एवं विज्ञान विषय तथा कृषि विषय चालू किये जाने हेतु चर्चा के लिए)।

241. मांग संख्या 24 मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्राथमिक शालाओं में अध्यापकों की कमी के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

242. श्री मोहनराज (बाली): मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के

(श्री मोहन राज)

अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाली क्षेत्र क आदिवासी इलाके में कार्यरत अध्यापकों को विशेष सेवा–सुविधा, अलाउन्स, आवास सुविधा न दिये जाने के फलस्वरूप स्कूलें बन्द रहने के विषय पर चर्चा के लिए)।

243. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा में आवश्यक सुधार कर उसे श्रम–प्रधान एवं व्यवसाय मूलक बनाने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये)।

244. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम मुंडारा, बीजापुर व लूनावा (बाली क्षेत्र) में सेकेण्डरी कक्षाओं के अभी तक न खोलने के कारण व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिए)।

245. श्रीमती उषा प्रकाश (बैर) : मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये (अनुदान प्राप्त संस्थाओं में कार्यरत अध्यापक प्राध्यापक की दयनीय स्थिति पर चर्चा के लिये)।

246. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (महिला शिक्षा की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

247. श्री किशन मोटवानी (अजमेर): मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अजमेर राजकीय बी. एड कालेज में एम. एड की कक्षायें खुलवाने के औचित्य पर चर्चा के लिये)।

248. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अजमेर राजकीय महाविद्यालय में एल.एल.एम. की कक्षा व लेबर ला कोर्स चालू न करने के कारण से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

249. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अजमेर में लड़कियों के लिये अलग राजकीय महाविद्यालय के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

250. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अजमेर राजकीय महाविद्यालय में सिंधी विषय पढ़ाने के लिये प्राध्यापक के अभाव पर चर्चा के लिये)।

251. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग मे से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा स्कूलों में बच्चों के बैठने के लिए उचित सामग्री व भवन के अभाव की व्यवस्था न करने पर चर्चा के लिये)।

252. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अल्प भाषा के अध्यापक जिन्होंने उर्दू या सिंधी सब्जेक्ट के साथ बी. ए. कर लिया है उनको सैकिण्ड ग्रेड अध्यापक बनाने के बारे में चर्चा के लिये)।

(श्री किशन मोटवानी)

253. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अल्प भाषा के एस. टी. सी. प्रशिक्षणार्थियों को छात्रवृत्ति बन्द करने से उत्पन्न दयनीय स्थिति पर चर्चा के लिये)।

254. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नियूजी प्राइमरी टीचर्स जो 1952 से पहले नियुक्त किये गये थे उनकी 55 वर्ष से 58 वर्ष तक एक्सटेन्शन व 58 से 60 तक-री-एम्पलाइमेन्ट की पालिसी में सम्भव तबदीली लाने व एक्सटेन्शन व री-एम्पलाइमेन्ट के केसों को अकारण रद्द कर देने व साल साल भर तक उन अध्यापकों को तनख्वाह से वंचित रखने पर चर्चा के लिये)।

255. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के अध्यापकों को राजकीय अध्यापक के समानान्तर गृह भत्ता, मेडिकल भुगतान व अन्य सुविधायें न प्रदान करने पर चर्चा के लिये)।

256. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 256 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जेल में सामान्य सुख सुविधा के अभाव पर चर्चा के लिये)।

257. सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव (आमेर) : मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष होने पर भी इस वर्ष शिक्षा के क्षेत्र में महिला शिक्षा के लिये सरकार द्वारा कोई उत्साहवर्धक कार्य नहीं किए जाने पर चर्चा के लिये)।

258. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 256 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जेल में वार्डरों व अधिकारियों को समय पर पदोन्नतियां नहीं मिलने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये)।

259. श्री गोकुलचन्द (कठूमर) : मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकारी आदेशों की अनुपालना समय पर न किये जाने सम्बन्धी विभागीय लापरवाही पर चर्चा के लिये)।

260. श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर) : मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा प्रणाली में आवश्यक सुधार लाने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये)।

261. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा विभाग में व्याप्त अव्यवस्था से सरकारी आदेशों का समय पर पालन नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

262. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक प्रगति के लिये योगिक-क्रियाओं के अध्ययन व अध्यापन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

263. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : मांग संख्या 24 मुख्य शीर्षक 277 के अन्तगत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मरुधर बालिका विद्यापीठ एवं अन्य बालिका विद्यापीठों को अनुदान 90 प्रतिशत दिलाने के बारे में चर्चा के लिये)।

264. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (एस. टी सी. ट्रेनिंग सेन्ट्रों में शिक्षार्थियों को भर्ती करने के आधारों के बारे में चर्चा के लिये)।

265. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उच्च माध्यमिक पाठशालाओं के छात्रों को स्कोलरशिप देने के सरकार के आधारों के बारे में चर्चा के लिये)।

266. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षणालयों में एवं विश्वविद्यालयों में बढ़ती हुई विद्यार्थियों की अनुशासनहीनता एवं उनमें सुधार के बारे में चर्चा के लिये)।

267. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा प्रणाली में आमूल चूल सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

268. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के स्तर में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

269. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय भवनों में छात्रावास खोलने के बारे में चर्चा के लिये)।

270. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भीनमाल एवं जालोर कालेजों के भवनों के विकास के बारे में चर्चा के लिये)।

271. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उच्च माध्यमिक पाठशाला सांचोर के सार्वजनिक छात्रावास को अनुदान नहीं दिये जाने के बारे में चर्चा के लिये)।

272. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर में शिक्षण संस्थाओं के भवन के अभाव पर चर्चा के लिये)।

273. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति, सांचोर में माध्यमिक स्कूल, उच्च माध्यमिक स्कूल, सांचोर एवं प्राथमिक पाठशालाओं में पूरे शिक्षक लगाने के बारे में चर्चा के लिये)।

274. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर में उच्च प्राथमिक पाठशालाओं में शिक्षकों की कमी को दूर करने के बारे में चर्चा के लिये)।

275. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर में प्राथमिक पाठशालाओं के शिक्षकों की कमी दूर करने के बारे में चर्चा के लिये)।

276. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा के सुधार के बारे में चर्चा के लिये)।

277. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य रूप से लागू कराने हेतु चर्चा के लिये)।

278. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षणालय भवनों के निर्माण एवं अन्य कार्यों में अनुदान दिलाने के बारे में चर्चा के लिये)।

279. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 256 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में जेल सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

280. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 256 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लम्बी सजा वाले बंदियों को कृषि फार्मों पर रखने के बारे में चर्चा के लिये)।

281. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 256 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (न्यायिक पृथकता के बाद जेलों की व्यवस्था में परिवर्तन के बारे में चर्चा के लिये)।

282. **श्री शंकर लाल (पाली):** मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाली में पोस्ट ग्रेजुएट कक्षाएं प्रारम्भ कराने हेतु चर्चा के लिये)।

283. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मौजूदा शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकता के बारे में चर्चा के लिये)।

284. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 256 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय टोंक के जेल अधिकारियों द्वारा खेती की जमीन को विवादास्पद बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

285. **श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर):** मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी को रोकने के लिये स्कूलों में कुटीर उद्योगों से सम्बन्धित प्रशिक्षण देने हेतु कक्षाएं चलाने पर चर्चा के लिये)।

Page No 41

(५१)

(श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल)

286. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम कैमला, पिलौदा, छोटी उदेई एवम् सेवा ग्राम टोक्सी, तलावड़ा के स्कूलों को सैकण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत करने के लिये चर्चा के लिये)।

287. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सैकण्डरी स्कूल ग्राम वजीरपुर में विज्ञान कक्षाएं खोलने एवम् हायर सैकेण्डरी स्कूल गंगापुर सिटी में शार्ट हैण्ड की कक्षाएं खोलने हेतु चर्चा के लिये)।

288. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगापुर सिटी में महाविद्यालय खोलने हेतु चर्चा के लिये)।

289. **श्री गोपाल सिंह** (खण्डेला): मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (स्त्री शिक्षा तथा व्यवसायोन्मुखी शिक्षा की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

290. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 256 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जेलों में शिक्षा के जरिए सुधार तथा जेलों की गिरी हुई हालत को सुधारने के बारे में चर्चा के लिये)।

291. **श्री रमेशचन्द्र सैनिक** (हिण्डौली): मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बून्दी कालेज को पोस्ट ग्रेजुएट में क्रमोन्नत करने पर चर्चा के लिये)।

292. **श्री सुरेशचन्द्र** (कोटपूतली): मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटपूतली तहसील के ग्राम प्रागपुरा, छारदड़ा, बडनगर, पाछोडाला में सैकेण्डरी स्कूल स्वीकृत कराने हेतु चर्चा के लिये)।

293. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटपूतली राजकीय महाविद्यालय को क्रमोन्नत कर पोस्ट ग्रेजुएट कक्षा शुरू कराने हेतु चर्चा के लिये)।

294. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटपूतली तहसील में सैकेण्डरी स्कूल नारेहड़ा व सदरपुरा में वाणिज्य विषय खुलवाने हेतु चर्चा के लिये)।

295. **श्री प्रतापसिंह** (किशनगढ़): मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (किशनगढ़ महाविद्यालय को क्रमोन्नत कर पोस्ट ग्रेजुएट कक्षा शुरू कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

296. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजकीय कन्या शाला किशनगढ़ में टैम्पो की व्यवस्था कराने हेतु चर्चा के लिये)।

297. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मदनगंज किशनगढ़ की शादुल उच्च प्राथमिक शाला को क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

298. **श्री नारायणसिंह मसूदा** (मसूदा): मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा पद्धति में परिवर्तन एवं युवा छात्र की समस्या पर चर्चा के लिये)।

299. **श्री मनोहरलाल** (कामां): मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कामां–डीग में कालेज खुलवाने हेतु चर्चा के लिये)।

300. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कामां में संस्कृत विद्यालय खुलवाने हेतु चर्चा के लिये)।

301. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डीग के अध्यापकों के स्थिरीकरण के मामले निपटाने में विलम्ब होने पर चर्चा के लिये)।

302. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कामां उच्च माध्यमिक विद्यालय में बायलोजी, नागरिक शास्त्र व अर्थशास्त्र की कक्षाएँ खुलवाने हेतु चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 24 व 17 पर विचार एवं पारण

श्री अध्यक्ष: श्री गिरधारीलाल भार्गव!

श्री गिरधारी लाल भार्गव (हवा महल, जयपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा विभाग के बारे में सर्वप्रथम अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा। माननीय शिक्षा मंत्री जी, आपने यहां पर राजस्थान की राज्य भाषा हिन्दी के बारे में आपने भी और मुख्य मंत्री जी ने भी इस सदन में कई घोषणायें समय समय पर की हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा, आपके अन्तर्गत जो भाषा विभाग है, उसमें यह बात समझ में आती है कि विधि विभाग, वित्त विभाग में किन्हीं कठिनाइयों के आधार पर हिन्दी का प्रयोग न कर सकें, लेकिन अन्य विभाग हैं उनमें भी हिन्दी में कार्य नहीं होता, चाहे मुख्य मंत्री कार्यालय हो, चाहे भाषा विभाग हो, चाहे स्वयं मंत्री महोदय का भाषा विभाग का कार्यालय हो, सामान्य प्रशासन विभाग हो। यही नहीं, राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर गजट नोटिफिकेशन किये जाते हैं, वह भी माननीय अध्यक्ष महोदय, अंग्रेजी में किये जाते हैं और अनुवाद हिन्दी में किया जाता है। जब कि होना यह चाहिए कि मूल बजट हिन्दी में हो और उसका अनुवाद अंग्रेजी में हो। मैं निवेदन करना चाहूंगा, पिछले साल रिक्शा चालक कानून बना, रिक्शा चालक अंग्रेजी नहीं जानते, लेकिन वह अंग्रेजी में था। मंत्रियों की यात्रा के रूल्स हैं उनको सरकार अंग्रेजी में निकालती है। यह खेद की बात है। मुंशीलाल महावर का जिक्र हो रहा था, उनका कार्यक्रम अंग्रेजी में निकलता है, हिन्दी में नहीं निकलता, मुंशी महाराज! मैं निवेदन करना चाहूंगा, स्वास्थ्य विभाग मोहनलाल छंगाणी के अन्तर्गत है, इस विभाग में अंग्रेजी में कार्य होता है। मुख्य सचिव कार्यालय में अंग्रेजी में कार्य करते हैं। और राज्य सरकार के आदेश प्रसारित होते हैं, नोटिफिकेशन होते है, वह अंग्रेजी में होते हैं। मैं निवेदन करना

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

चाहूंगा, जो भाषा विभाग मूलतः आपका स्वयं का, शिक्षा विभाग में है, उसमें अंग्रेजी में काम करते हैं। भाषा विभाग हिन्दी भाषा की बात करता है, लेकिन वह अंग्रेजी में काम करता है। भाषा विभाग के मंत्री कौन हैं, फारुक हसन भाषा विभाग के मंत्री भाषा विभाग का निरीक्षण करने जाते हैं या स्वयं सचिवालय, जहां पर बैठ कर राज्य करते हैं, वहां घोर उपेक्षा हिन्दी की किस प्रकार हो रही है वह आप स्वयं देख लीजिये। यह बाहर के अधिकारी हैं, चाहे मद्रास के हों या दूसरे प्रान्तों के हों वह हिन्दी में लिखने का प्रयास करेंगे लेकिन राजस्थान के अधिकारी हैं, वह अधिकारी अंग्रेजी में लिखने का प्रयास करेंगे. अंग्रेजी में लिखेंगे। वह सोचते हैं कि हिन्दी में लिखेंगे तो तौहीन होगी। राजस्थान सचिवालय...

श्री अध्यक्ष : एक नम्र निवेदन कर रहा था, आपके चार कटौती प्रस्ताव हैं।

श्री भानुकुमार शास्त्री : सब पर बोल देंगे।

श्री अध्यक्ष : सब पर बोल दें। 30 मिनिट आपके हिस्से में हैं, आपके दल के में, आप कितना बोलना चाहेंगे, आप देख लीजिये।

श्री भानुकुमार शास्त्री : 30 मिनिट हैं।

श्री अध्यक्ष : जो भी मैंने कहा।

श्री भानुकुमार शास्त्री : 20 मिनिट कहा।

श्री अध्यक्ष : 30 मिनिट हैं तो तीस हैं। आपका उद्देश्य पूरा हो जाय, वह कह लें। इससे समय की पाबन्दी भी हो जायगी। बहुत साधारण सी बात है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सचिवालय में पोस्टर लगे हुए हैं, हिन्दी निज अधिकार मांगती ! सबसे सच्चा प्यार मांगती ! सचिवालय में हिन्दी अपना अधिकार मांग रही है, सबसे प्यार मांग रही है। यह पोस्टर लगे हुए हैं। दूसरे राजस्थान एक हिन्दी भाषी प्रान्त है। लेकिन आप सचिवालय में देख लीजिये। मेरा निवेदन है कि सम्पूर्ण राजस्थान का काम, सचिवालय का काम हिन्दी में हो। यह मेरा पहला निवेदन है।

दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहूंगा, पब्लिक सर्विस कमीशन कई स्थानों के लिए प्राध्यापकों और प्रधान अध्यापकों की लिस्ट निकालती है, लेकिन लिस्ट निकालने के बाद भी आज तक उनका पोस्टिंग नहीं किया गया है। आज कई प्रधान अध्यापकों के स्थान रिक्त पड़े हैं, जब कि कई अध्यापकों का दूर प्रदेश बाड़मेर, जैसलमेर में ट्रान्सफर कर दिया। मुझे जानकारी है, आपके अभी तक सूद, जो शिक्षा सचिव थे, शिक्षा कमिश्नर थे, उनसे बात न बनने के कारण विधान सभा का सत्र जब चल रहा है, सत्रावधि में सूद को हटा कर आहूजा को विराजमान किया है।

दूसरा प्रश्न हिन्दी ग्रन्थ अकादमी के बारे में है। पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज के लिए किताबें छापने का इस हिन्दी ग्रन्थ अकादमी का काम है। लेकिन इस अकादमी के जो माननीय सदस्य हैं, वह अपनी खुद की किताब छापते हैं। जो विद्यार्थी शोध कार्य कर रहे हैं, उनसे लिखवायेंगे और उन्हीं से प्रूफ रीडिंग करवायेंगे और हजारों

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

रुपये लेकर कुछ विद्यार्थियों को बांट देंगे। इस प्रकार किताबें लिखने का काम ठेके के आधार पर हो रहा है। ठेके के आधार पर जो काम होता है वह गलत है और जो पुस्तकें छपाते हैं वह पाठ्य-क्रम के अनुसार नहीं हैं। मेरे पास पुस्तकें मौजूद हैं। हिन्दी विषय में जो पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं, उन्हीं पर केवल किताबें छपवानी चाहिए। राजस्थान के जो तीनों विश्वविद्यालय हैं उन्हीं से जानकारी प्राप्त करनी चाहिए।

खेल-कूद परिषद् के बारे में निवेदन है कि राजस्थान में स्कूलों में खेल-कूद प्रशिक्षण की अलग से व्यवस्था होनी चाहिए परन्तु आपने सारे का सारा काम स्पोर्टस् परिषद् को दे दिया। स्पोर्टस् काऊंसिल को वास्तव में अच्छे खिलाड़ियों का चयन करना था। भारत सरकार ने डेप्यूटेशन पर 105 डेमोंन्स्ट्रेटर्स पी. टी. आई. के यहां पर भेजे हैं उनकी उपयोगिता राजस्थान में नहीं रही। स्कूलों की व्यवस्था अलग से हो, खेलकूद के मैदानों की व्यवस्था अलग से हो लेकिन माउन्ट आबू में आपने निर्णय लिया। आपका इस वर्ष का जो बजट है उसमें खेलकूद का कोई प्रावधान नहीं किया। माउंट आबू में, 1974–75 में निर्णय लिया, वह काला वर्ष आपके लिए साबित हुआ। राजस्थान स्कूल्स की टीम अब आगरा गई नवम्बर 1974 में। अन्तर्राज्यीय प्रतियोगिता में एक भी मैडल आपको प्राप्त नहीं हुआ। नागालैंड में तीन दिन प्रतियोगिता हुई उसमें केवल तीन मैडल प्राप्त हुए। अफसोस इस बात का है कि इसी प्रतियोगिता में राजस्थान के खिलाड़ी पहले 20 मैडल लेकर आये थे, इस स्थिति के लिए आप ही जिम्मेदार हैं। 12–13 लाख रुपये स्पोर्टस् काउंसिल को प्रतिवर्ष आप प्रशिक्षण केन्द्र के लिए देते हैं और उन केन्द्रों में वहां क्या होता है? माऊंट आबू में साल में केवल एक बार शिविर लगता है उसी में ही आप 12–13 लाख खर्च करते हैं। इसलिए मेरी मांग है कि माउन्ट आबू में जो प्रति वर्ष आप प्रशिक्षण केन्द्र लगाते हैं उनको बंद करें और जो कैम्पस हैं उनको जिला स्तर पर आयोजित करके विभिन्न प्रकार के खेलों का वर्गीकरण करके अलग अलग जिलों में ट्रेनिंग दे दी जाए। सारे के सारे कैम्पस जैसे पहले प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में करते थे उसी आधार पर चलें और कोचिंग मशीनरी राजस्थान में खड़ी करें तो राजस्थान के खिलाड़ियों की प्रगति होगी। आपने बीकानेर में केवल एक स्कूल खोल रखा है, जो अपर्याप्त है। इसके अलावा प्रत्येक जिले में स्टेडियम बनायें, उनका कार्यभार जो वहां स्कूलों के हैडक्वाटर्स हैं उनको सुपुर्द करें, सही काम होगा।

आप स्पोर्ट्स काउंसिल को काम न देकर जो भारत सरकार से डेमोन्सट्रेटर्स आये हैं और खेलकूद जगत में महत्व रखते हैं, उस पर ध्यान देंगे।

राजस्थान में नेहरू युवक केन्द्र हैं जिनको भारत सरकार द्वारा पैसा मिलता है। उनमें भली प्रकार के खेलकूद और भली प्रकार की नौकरी की व्यवस्था का प्रावधान है। ये इसी उद्देश्य से खोले गए, वे बढिया हैं लेकिन राजस्थान का शिक्षा विभाग उन्हें कन्ट्रोल करता है। जयपुर में भी केन्द्र है। जितने माननीय सदस्य बैठे हैं, मैं चुनौती

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

देकर पूछना चाहता हूं शायद आपको स्वयं को भी मालूम नहीं होगा कि जयपुर में नेहरू युवक केंद्र कहां पर हैं। यदि आप उनको अच्छी तरह से नहीं चला सकते तो अपनी असमर्थता भारत सरकार को प्रकट कर दें। भारत सरकार जिन जिन बातों के लिए राज्य सरकार को पैसा देना चाहती है, उनके प्रति सरकार उपेक्षा का व्यवहार करके उनको पूरा नहीं करती। आप वहां जायेंगे भाषण देंगे और कहेंगे कि राजस्थान में खेलकूदों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, कलाकारों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। लेकिन वास्तव में या तो किसी खिलाड़ी को राजस्थान में नौकरी नहीं मिलेगी, वह राजस्थान से बाहर चला जाएगा तो फिर राजस्थान का खिलाड़ी जिस पर आपने खर्च किया वह बाहर चला गया और नौकरी देंगे तो भी जैसलमेर या बाड़मेर में देंगे, तो इस तरह वह खिलाड़ी बेकार हो जाएगा। यही कलाकारों के क्षेत्र में है। उनको आप नौकरी नहीं देते, कोई प्रोत्साहन नहीं देते। इसके बाद में राजस्थान संगीत संस्थान·····

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरा समय बाकी है।

श्री अध्यक्ष : 15 मिनट आपको बोलते हुए हो गए, 15 मिनट और बोल लीजिए मुझे आपत्ति नहीं है। लेकिन इससे आपके दल के और सदस्यों को नुकसान पहुंचेगा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : राजस्थान संगीत संस्थान एक मात्र संस्थान है कोटा में वहां जितने अध्यापक हैं उनमें से आधे विद्यार्थी हैं। जयपुर में भी एक संस्थान चलता है अजबघर किशनपोल बाजार में, वहां एक ओर तबला एक ओर हारमोनियम, एक ओर सितार बज रही है, पर्दा डालकर घुंघुरू पहन कर डांस हो रही है, बीच में बच्चों को ट्रेनिंग देना चाहते हैं तो यह मखौल है संगीत की····

श्री खेतसिंह (शिक्षा मंत्री) : वहां तो तबला और हारमोनियम ही मिलेगा। क्या आप झुंझुना बजाना चाहते हैं?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : वहां जिस प्रकार के अध्यापक होने चाहिए वह नहीं हैं। इसके लिए उपयुक्त भवन तलाश करें और अच्छे अध्यापक रखें। कथक सिखाने के लिए एक भी अध्यापक नहीं है। जयपुर का नाम कथक शैली से जुड़ा हुआ है। लखनऊ में भी कथक कालेज है। राजस्थान के व्यक्ति बम्बई, कलकत्ता, लखनऊ कथक सीखने जाते हैं लेकिन राजस्थान में कथक का कालेज नहीं है। इसलिए मेरी मांग है कि जयपुर में भी कथक केन्द्र की स्थापना करें।

श्री अध्यक्ष : कितना बाकी बोलना है?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : प्रौढ़ शिक्षा के बारे में निवेदन करना है कि बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता। आप लोगों को ग्रोबलाइज करने के लिए किताबें दे देते हैं। पुरातत्व विभाग आपके नीचे है। म्यूजियम का हाल देखिए। वहां लाइट की व्यवस्था नहीं, हवा महल पर रोशनी का प्रबंध नहीं, जन्तर मन्तर पर रोशनी का प्रबंध नहीं, सफाई की व्यवस्था नहीं। आमेर का भी यही हाल है, गलते का भी यही हाल है। आप लिफ्ट लगा

Page No 46

(46)

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

हैं लोग वहां पर जायं। ऊपर चले जायं, नीचे आ जायं, खर्चा आपको जरूर लगेगा लेकिन लोगों से आप यदि एक-एक दो-दो रुपए भी लेंगे तो भी लोग जायेंगे। इसी प्रकार आप नाहरगढ़ की उपेक्षा कर रहे हैं...

श्री अध्यक्ष : आपके दल के और लोग भी हैं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : दो चार मिनट और बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष : You have already taken 15 minutes.

श्री गिरधारीलाल भार्गव : 30 मिनट मेरे दल के हैं।

श्री अध्यक्ष : तो फिर आपके दल के दूसरे सदस्यों के लिए समय नहीं बचेगा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : दो तीन बार टोकाटा की हुई है इसमें भी समय लग गया है, वैसे तो आप मेरे प्रति दयावान हैं।

श्री अध्यक्ष : मेरी वजह से आपका एक मिनट गया है सो मैं बढ़ा दूंगा।

श्री निरंजननाथ आचार्य : इसके बाद भी आप सहृदय उनके प्रति रहें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आपने कलाकारों का निर्माण नहीं किया। इतना भारी खर्चा करने के बाद भी कलाकारों का निर्माण नहीं हुआ। क्यों नहीं? मैं अब मूल समस्या पर आ रहा हूं कि कलाकारों को पनपाने के लिये क्या किया गया। यहां का जो सांस्कृतिक रविन्द्र मंच है उसकी आज क्या हालत हो गई है। वह जमीन में खिसकता जा रहा है, उसकी छतें बेकार हो गई हैं, जगह-जगह उसमें दीमक हो गये हैं और कितनी बुरी हालत है। ऐसी हालत हो गई है कि लोग कहा करेंगे कि यहां पर किसी जमाने में एक सांस्कृतिक केन्द्र था जहां पर सांस्कृतिक गतिविधियां चला करती थीं। अध्यक्ष महोदय, आप भी कई बार इसमें गये होंगे। 13 अप्रेल, सन् 74 से बन्द पड़ा हुआ है। एक साल से भी अधिक हो गया इसको बन्द हुए। पहले इसकी व्यवस्था संगीत नाटक अकादमी के पास थी। उस समय जो व्यवस्थापक थे उन्होंने कई प्रकार के गबन, घोटाले किये। हिसाब का ऑडिट किया गया। ऑडिट रिपोर्ट में कई गलतियां पायी गई, परन्तु उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई उसकी ऑडिट रिपोर्ट की प्रति मेरे पास भी है मैं उसको दिखाने को तैयार हूं। उसी आदमी को आप अधिकार देने जा रहे हैं। उसके खिलाफ संगीत नाटक अकादमी में कई बार हटाने का प्रस्ताव भी पास हुआ फिर भी उसको नहीं हटाया गया। इसके बाद इसका चार्ज ललित कला अकादमी को एक वर्ष के लिये दिया गया। उसमें भटनागर साहब थे उन्होंने कई गड़बड़–घोटाले किये। उन्होंने भी कोई काम नहीं किया और रविन्द्र मंच को बिलकुल बिठा दिया। उनके खिलाफ भी जांच बैठायी गयी। जांच रिपोर्ट में उनके खिलाफ कई चार्ज लगाये गये और अब वह जांच रिपोर्ट दबाई जा रही है क्योंकि वे रामनिवास मिर्धा के चाहेते थे, उनके दबाव में आकर उस रिपोर्ट को दबाया जा रहा है। लेकिन बहुत अफसोस की बात है, अध्यक्ष महोदय भी घोषणा करते हैं फिर भी आठ–आठ महीने हो गये और आपने कहा था कि मार्च में पूरा हो जायगा लेकिन मुझे तो इसके अभी मरम्मत के भी आसार नजर नहीं आ रहे हैं,

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

इसलिए धन्यवाद के पात्र हैं। पांच हजार रुपये मरम्मत के लिये दे दिये परन्तु फिर भी इसकी मरम्मत की गति अभी बहुत धीमी है। पचास हजार रुपये भुगतान करने के लिये दे दिया। बिजली के लिये दे दिया, पानी के लिए दे दिया लेकिन आपने राज्य कर्मचारियों को भुगतान नहीं किया। आपने घोषणा की कि हम लोगों को नौकरी से निकालना नहीं चाहते हैं। उन लोगों को आप वापिस लेना चाहते हैं तो ऐसी कौनसी आवश्यकता आ गई उनको निकालने की। एक स्वायत्त शासन संस्था में राज्य सरकार ने किस प्रकार से हस्तक्षेप किया, अब आप उनको नोटिस दिये जा रहे हैं, उनको नौकरी से निकाल रहे हैं। आपने यह भी घोषणा की थी कि हम संगीत नाटक अकादमी, ललित कला अकादमी और साहित्य अकादमी का पुनर्गठन करेंगे। मेघराज मुकुल को आपने बिठा रखा है वर्षों से, वह क्या करता है केवल कविताएं बनाता है इन्दिराजी आ गई तो कविता बोल दी, सुखाड़ियाजी आ गये तो कविता लिख दी, केवल यह काम है उसका और कुछ वह कर नहीं सकता। कविता पाठ करता रहता है। इसी तरह से कई अफसर हैं। अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि रविन्द्र मन्च का अनुशासन ठीक किया जाय। इसमें कलाकारों को प्रतिनिधित्व दिया जाये और सरकार का और जनता के आदमियों का भी इसमें प्रतिनिधित्व हो और इस संस्थान का जो राजस्थान की सांस्कृतिक गतिविधियों का एक केन्द्र है, इसकी शीघ्र व्यवस्था को सुधारा जाय। इसके कर्मचारियों का वेतन दिलाया जाय जिससे व्यवस्था ठीक हो। मुझे तो आशा नहीं है कि शिक्षा मन्त्रीजी इसकी व्यवस्था सुधार सकेंगे, राजस्थान की सांस्कृतिक गतिविधियों का जो ह्रास हो रहा है उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे।

(समय–समाप्ति सूचक घंटी)

अध्यक्ष महोदय, अभी समाप्त कर रहा हूं। इसके लिये एक बोर्ड बनाया जाय उसका एक कार्यालय हो और वहां उसकी व्यवस्था हो जाय। मेरी मांग है कि शिक्षा मन्त्रीजी इस प्रकार के गंभीर घोटालों की तरफ ध्यान देंगे नहीं तो राजस्थान की जनता आवाज उठायेगी और आपके लिये मुश्किल हो जायेगी इसलिए आप कर्मचारियों का वेतन दिलाइये और घोटालों की जांच कराइये। अन्त में मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि जेलों के सम्बन्ध में, वहां पर कैदी हड़ताल पर बैठे हैं उनका क्या किया आपने। जेल सुधार के लिये जेल रिफार्म्स कमीशन ने आपको बढ़िया-बढ़िया सुझाव दिये हैं, अच्छे-अच्छे कामों के लिए, उनको काम सिखाने के लिये और अनुशासन में रहने के लिए जिससे वह बाहर आवें तो शरीफों की तरह रह सकें और अपना जीवन सुधार सकें मैं समझता हूं मैंने जो विचार व्यक्त किये हैं, माननीय शिक्षा मन्त्री महोदय और जेल मन्त्रीजी उन सारी बातों का उत्तर अपने जवाब में देने की कृपा करेंगे।

श्री निरंजननाथ आचार्य : ठेका आपको देने का प्रश्न महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष : श्री सामरिया !

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब कभी शिक्षा के

(श्री मूलचन्द मामरिया)

बारे में कोई मीटिंग होती है, या कोई सम्मेलन होता है तो प्रधान मन्त्री से लेकर राष्ट्रपति तक और केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री तथा राज्यों के मन्त्री से राठौर साहब तक सभी इस बात पर गौर करते हैं कि शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन होना चाहिए । लेकिन मैं यह नहीं समझ सका कि शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन शुरू करने का कार्य करेगा कौन, आखिर इस काम की जिम्मेदारी किस पर है । इस शिक्षा में डिफेक्ट्स हैं और आज बेरोजगारों की संख्या इस शिक्षा से बढ़ती जाती है, आखिर इसको दूर करने की जिम्मेदारी किस पर है, यह दायित्व कोई भी व्यक्ति अपने ऊपर लेने को तैयार नहीं है और जब कभी भाषण होंगे, या कोई मीटिंग होगी तो यह कह दिया जायगा कि शिक्षा में परिवर्तन होना चाहिए, इस तरह से विकास होना चाहिए, शिक्षा के साथ उद्योग धन्धे जोड़े जाने चाहिए, इस तरह की शिक्षा होनी चाहिए जिससे आगे चलकर जीवन में कुछ काम आ सके । मान्यवर, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आज हमारे सामने यह है कि खास तौर से इस प्रान्त में शिक्षित बेरोजगारों की सूची के बारे में अथवा उनकी संख्या के बारे में सरकार से पूछा जाता है तो अनभिज्ञता प्रकट करते हैं । मैं यह पूछना चाहता हूं कि हमारे प्रान्त में कितने शिक्षित बेरोजगार हैं और किस-किस प्रकार के हैं तो उनको इस बात की कोई खबर ही नहीं है । इस मामले में सरकार बेखबर रही है कि शिक्षित और अशिक्षित बेरोजगार हमारे प्रान्त में कितनी संख्या में हैं। मैं समझता हूं कि सरकार की जो अरुचि इस ओर रही है उनको धन्धा लगाने के बारे में, यह उनकी अकर्मण्यता का द्योतक है । अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में और खास तौर से हमारे प्रदेश में जो बेरोजगारी है शिक्षित लोगों की और अशिक्षित लोगों की वह इतनी भयंकर है कि आज जयप्रकाशजी आन्दोलन करते हैं कि हमारी शिक्षा पद्धति में सुधार होना चाहिए, शिक्षा को इस तरह का बनाया जाना चाहिए कि पढ़ने के बाद वह जीवन में उपयोगी साबित हो सके । यह सही है कि हमारे देश में आज बहुत से अधिकांश विद्यार्थी ऐसे हैं जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए कालेज में जाते है, उनमें से बहुत से गरीबों के बच्चे होते हैं जो अपना सब कुछ बेचकर, अपने बर्तन और जेवर बेचकर कई तरह की मुसीबतों को उठाकर अपने बच्चों को पढ़ने के लिये भेज पाते हैं ।

अध्यक्ष महोदय, जब वह बच्चे स्कूल और कालेजों में पढ़ते हैं तो उनको आशायें होती हैं । उनके सरक्षकों को व उनके माता पिता को भी आशायें होती हैं कि जब हमारे बच्चे पढ़ लिखकर आयेंगे तो हमें कुछ कमा कर देंगे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, आज जब बच्चे ग्रेजुएशेन, पोस्ट ग्रेजुएशन, साईन्स और आर्ट्स में अथवा मेडीकल में या इन्जीनियरिंग करके कालेज से बाहर आते हैं तो उन्हें ऐसा महसूस होता है कि मानों वह आकाश से गिरकर जमीन पर फेंक दिये हों। उनके मन की स्थिति ऐसी अजीबो गरीब हो जाती है कि वह बयान नहीं की जा सकती है। कहां तो अध्यक्ष महोदय, कालेज में पढ़ते समय उनके मन में यह होता है कि हम हमारी पढ़ाई समाप्त होने के बाद अच्छे अच्छे पदों पर काम करेंगे हमारे देश

(श्री मूलचन्द सामरिया)

की सेवा करेंगे। कोई डाक्टरी पढ़ता है तो वह सोचता है कि गरीब लोगों की सेवा करेंगे, इन्जीनियरिंग पढ़ने वाला सोचता है कि हम देश के निर्माण में कुछ काम करेंगे। कोई सोचता है कि हम लेक्चरार बनेंगे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, जब वह कालेज के बाहर निकलते हैं तो अपने आपको बेबस पाते हैं। जब उन लोगों का भविष्य अन्धकारमय वह लोग देखते हैं तो वह लोग बेचारे मजबूर होकर मन्त्रियों के और नेताओं के यहां पर नौकरियों के लिये चक्कर काटते हैं। अध्यक्ष महोदय, इससे जब उनका काम नहीं होता है तो उनके स्वाभिमान को ठेस पहुँचती है और स्वाभिमान के ठेस पहुँचने के कारण वह बेरोजगार लोग इकट्ठे होते हैं और फिर आन्दोलित होकर वह लोग सड़कों पर फैसला करने की सोचते हैं। अध्यक्ष महोदय, आज यह शिक्षा पद्धति जो हमारे देश में चल रही है वही बेरोजगारी को जन्म देने वाली है और आन्दोलन को जन्म देने वाली भी वही दूषित शिक्षा पद्धति है और अगर यही हालत शिक्षा पद्धति की रही तो हमारे यहां पर आन्दोलन होते ही रहेंगे और उनका परिणाम देश के लिये अच्छा नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय, यह तो ठीक है कि हमारे यहां पर साक्षरता की बहुत ही कमी है अगर सभी व्यक्ति यहां पर साक्षर हों तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा अध्यक्ष महोदय कि हमारे यहां पर बेरोजगारों का प्रतिशत 80 प्रतिशत होगा। हमारे यहां पर 80 प्रतिशत लोग बेरोजगार होंगे। इसलिये मेरा सुझाव है कि शिक्षा पद्धति में परिवर्तन किया जाय। अध्यक्ष महोदय हमारे यहां पर ऐसी पद्धति शिक्षा के लिये हो कि प्राथमिक शिक्षा से मैट्रिक की शिक्षा तक बच्चे को उसके साथ-साथ छोटी मोटी ट्रेनिंग उद्योग धन्धों की दी जानी चाहिये और जिस समय वह बच्चा मैट्रिक पास करके निकले उस वक्त जब उसको मैट्रिक का सर्टिफिकेट दिया जाता है तब उसको जिस उद्योग धन्धे में उसने ट्रेनिंग ली है उसको सर्टिफिकेट और औजार वगैरह भी राज्य सरकार से दिया जावे तथा कुछ धनराशि भी उसे दी जावे। ताकि वह अपना रोजगार कमा सके। उसके बाद भी पढ़ाई के लिये आपको चाहिये कि उन्हीं लोगों को पढ़ने का मौका दिया जावे जो कि काबिल हों उसके लिये उनको चाहिये कि आप टेस्ट वगैरह लेकर पढ़ने का मौका दें। इसमें जो डफर हो उनको मौका नहीं दिया जाना चाहिये। ऐसा नहीं हो किसी मन्त्री का बेटा अगर डफर हो या कोई बड़े आफिसर या बड़े सेठ साहूकार का लड़का डफर हो तो भी आप उसे पढ़ने के लिये एडमिशन दे दें।

श्री रामकिशन : अरे, मन्त्री का बेटा कभी डफर होता है क्या ?

श्री मूलचन्द सामरिया : होता क्यों नहीं है, हो भी सकता है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मन्त्री का बेटा डफर नहीं हो सकता क्योंकि शेर का बच्चा शेर होता है।

श्री मूलचन्द सामरिया : तो अध्यक्ष महोदय मेरा निवेदन है कि मैट्रिक के आगे अगर पढ़ाई में एडमीशन देने की बात हो तो उसमें सिफारिश से एडमीशन नहीं देकर उसे उसके रिकार्ड के अनुसार एडमी-

(श्री मूलचन्द सामरिया)
शन दिया जाना चाहिये जिससे कि भविष्य में अच्छे अच्छे लोग पढ़ लिखकर आगे निकलें। इसमें बेरोजगारों की संख्या भी कम होगी और ज्यादा आन्दोलन भी नहीं होंगे। लेकिन अगर आपने इस तरह की कार्यवाही नहीं की तो आप इन बेरोजगारों के आन्दोलन को कभी भी नहीं दबा सकेंगे।

(व्यवस्था–सूचक–घन्टी)

अध्यक्ष महोदय, मैं अब दो शब्द दौसा में जो कालेज है उसके बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, दौसा में विद्यार्थियों की तो कालेज में संख्या ज्यादा है और वहां पर कालेज में कमरे की व्यवस्था कम है जिससे कि बच्चों को बाहर बैठना पड़ता है उसके लिये भी व्यवस्था राज्य सरकार को जल्दी से जल्दी करानी चाहिए इसके अलावा अध्यक्ष महोदय वहां पर जो गर्ल्स स्कूल है वह भी ऐसी जगह है कि जहां पर चारों ओर गन्दगी ही गन्दगी है। लेकिन वहा पर दूसरी व्यवस्था नहीं होने के कारण उन लड़कियों को वहां पर मजबूरी की हालत में बैठ कर पढ़ना पड़ता है। इसके लिये मेरा निवेदन है कि उनके लिये अच्छी व्यवस्था की जावे। इसके अलावा थोड़ा मैं संस्कृत कालेज के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, उस कालेज में बच्चों की संख्या ज्यादा है और कमरे कम होने के कारण काफी बच्चों को दिक्कत होती है इसलिये मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार को उनके लिये उचित व्यवस्था करनी चाहिये।

एक माननीय सदस्य : आप मन्त्रियों की XXX करो। तो हो सकती है।

श्री मूलचन्द सामरिया : मैं मन्त्रियों की XXX क्यों करूंगा साहब ? वहां की जनता करेगी। अब अध्यक्ष महोदय, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं एक दो शब्द कारागृह के बारे में भी निवेदन कर दूं। एक दो महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आपका कोई कट मोशन है क्या ?

श्री मूलचन्द सामरिया : कटमोशन तो मेरा नहीं है लेकिन मैं एक मिनट कारागृह के बारे में भी आपकी आज्ञा हो तो बोल लूं।

श्री अध्यक्ष : अगर कटमोशन नहीं है तो आप नहीं बोल सकते हैं।

श्री मूलचन्द सामरिया : तो फिर ठीक है, साहब।

श्री अध्यक्ष : श्री मनोहरलाल (अनुपस्थित)।

श्री भानुकुमार शास्त्री

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं सीमित समय के अन्दर ही अपने विचार व्यक्त करने का प्रयास करूंगा। अध्यक्ष महोदय जब श्री खेतसिंह जी शिक्षा मंत्री बने थे, जब उन्होंने शिक्षा विभाग सम्भाला था तो मैं आशा करता था कि अब शिक्षा पद्धति में आमूलचूल परिवर्तन आयेंगे और शिक्षा पद्धति में ऐसा सुधार होगा कि हमारे यहां की आने वाली भावी पीढ़ी में अच्छे नागरिक पढ़ लिखकर तैयार होंगे और आगे जाकर वह लोग समाज के लिये उपयोगी सिद्ध होंगे। लेकिन मुझे खेद के

XXX ये शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेश से कार्य विवरण से निकाले गये।

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

साथ कहना पड़ता है कि उन्होंने शिक्षा के माध्यम में कोई परिवर्तन नहीं किया और आज काफी समय गुजर गया है। इसके विपरीत मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि शिक्षा मंत्री के पद के लिये यह पूर्णतया असफल रहे हैं। मैं तो यह कहूंगा न सिर्फ असफल ही बल्कि उन्होंने शिक्षा की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। इसलिये मैं इनको शिक्षा मंत्री नहीं कह कर अगर उनको स्थानान्तरण मंत्री कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उन्होंने सिवाय ट्रान्सफर्स आर्डर्स निकालने के कुछ नहीं किया। आये दिन सचिवालय से ट्रान्सफर्स लिस्ट निकलती रहती है। अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी कल ही एक प्रश्न काल के समय प्रश्न पूछा था जिसका कि मुझे लिखित उत्तर मिला वह आदेश राज्य सरकार ने एक हायर सेकेण्डरी स्कूल के सीनियर टीचर श्री बजरंगलाल के बारे में निकाले थे मैं उसको सदन के सामने पढ़कर सुनता हूं :

"The Government agrees with your view that suspension of Shri Bajrang Lal Dhabhai, Senior Teacher, by the institution was irregular. The institution should be asked to withdraw their order regarding suspension of the teacher, take him back in service immediately. If the institution does not do so within a period of fifteen days, the facts may be reported to Government for further necessary orders.

अध्यक्ष महोदय, इसमें लास्ट में वार्निग है कि 15 दिन के अन्दर यह किया जाय।

श्री खेतसिंह : यह कौनसा आर्डर आप बता रहे हैं। मण्डावा की ऐडड स्कूल के सीनियर टीचर के बारे में फरमा रहे हैं क्या ?

श्री भानुकुमार शास्त्री : आपने आर्डर किये हैं। आपने दस दिन के भीतर आर्डर की पालना के लिये कहा है। फिर उसी व्यक्ति के लिये सचिवालय से दूसरे आदेश जाते हैं कि पहले वाले आर्डर को विथड्रा किया जाता है। यह आपने क्या किया आपने पहले आडर वैसा और दूसरा आर्डर इस प्रकार का क्यों निकाला। कुछ समझ में नहीं आता है। इसी प्रकार जयपुर शहर के अन्दर सिर्फ 12 व्यक्तियों की ट्रान्सफर करने के लिये जो कि उनके कृपा पात्र हैं आपने 115 अध्यापकों की लिस्ट ट्रान्सफर्स की निकाल दी अब वह बेचारे चक्कर काट रहे हैं। मेरे पास लिस्ट है लेकिन मैं उसको पढ़कर नहीं सुनाऊंगा। ऐसे तो आपने सैंकड़ों आडर कर दिये हैं। तो मेरा निवेदन है कि आपको यह रवैया बदलना चाहिये। एक सत्र के बीच में आपको लोगों के ट्रान्सफर नहीं करने चाहिये क्योंकि लोगों के बाल बच्चे पढ़ते हैं। आप उनको जब चाहे सत्र के बीच में बाड़मेर, जैसलमेर, पूर्व से उत्तर और दक्षिण से पूर्व बदलते हैं। तो आप सोचिये सत्र के बीच में एक व्यक्ति अपने बच्चों को जो पढ़ रहे हैं कहां, वह अपने बच्चों को छोड़कर जायेगा और कहां वह जायेगा। यह क्या है। यह आपको नहीं करना चाहिये। एक व्यक्ति को आप साल भर बाद में छः महीने बाद में और दो साल में कभी भी हटादें और उसके विपरीत आपने, अपने कृपा पात्रों को दस साल से जो व्यक्ति

(श्री भानु कुमार शास्त्री)
आज जयपुर में जमे हुए हैं नहीं हटाया है। ऐसे एक नहीं सैंकड़ों हैं राजस्थान में जो दस वर्षों से एक ही स्कूल में जमे हुए हैं। जयपुर में कुछ लोगों के नाम तो मैं आपके सामने बताऊं। श्री आर. एस. गोयल, श्री गंगासहाय, श्री महेशचन्द्र शर्मा। यह तीनों व्यक्ति अध्यक्ष महोदय, दस-दस साल से एक ही स्कूल में हैं। इसके अलावा कुछ टीचर्स ऐसे हैं, अध्यक्ष महोदय, कि जो ट्रान्सफर तो हो गये थे लेकिन चार, पांच महीने या छः महीने बाद वापिस घूम फिर कर वहीं पर आ गये।

इसके अलावा एक उदाहरण मैं ऐसा अध्यक्ष महोदय, आपको दूंगा जिसमें कि एक गणित के एम.एस सी. टीचर को आपने ऐसी स्कूल में स्थानान्तरण कर दिया जहां कि मेथेमेटिक्स सबजेक्ट नहीं है। उसने जब कहा कि साहब यहां तो मेथेमेटिक्स सबजेक्ट नहीं है तो उसको कहा गया है कि आप हिन्दी पढ़ाइये। अब जिस व्यक्ति ने हिन्दी साहित्य नहीं पढ़ा वह कैसे पढ़ा सकता है लेकिन उसे कहा कि अगर आप नहीं पढ़ाना चाहते हैं तो आप बैठे रहिये। अध्यक्ष महोदय, वह मेरा मित्र है मेरे पास पत्र आया है कि यहां मैं ऐसी स्कूल में हूं जहां पर मेथेमेटिक्स सबजेक्ट ही नहीं है। यहां मेरा रहना ठीक नहीं। अध्यक्ष महोदय, एम. एस. सी. जो व्यक्ति मेथेमेटिक्स में हो उसे तो वहां भेजा जाना चाहिये जहां कि मेथेमेटिक्स सबजेक्ट तो हो। अन्यथा उसका वहां रहने से क्या फायदा ?

अध्यक्ष महोदय, एक बात और मैं निवेदन करना चाहूंगा थोड़े समय पहले हमारे शिक्षा मन्त्रीजी के जो निजी सचिव थे उनके बारे में। अध्यक्ष महोदय मन्त्री महोदय के निजी सचिव भ्रष्टाचार के कारनामों से दुखित होकर टीचर्स ने उनको पीटा। ऐसा मैंने टाइम्स आफ इन्डिया के अखबार में पढ़ा था। अध्यक्ष महोदय, जिस निजी सचिव को मन्त्री महोदय के सामने पीटा गया उसको वहां से हटा तो दिया गया लेकिन उन्हें पारितोषिक दिया गया। वह पारितोषिक उसे यह मिला कि उसे किसी अच्छे पद पर लगा दिया गया। उसको भ्रष्टाचार में पिटाई करने का रिवार्ड मिला कि उसे कोई दूसरे ऊंची जगह पर सर्विस दिला दी गयी। अध्यक्ष महोदय, जो आदमी भ्रष्टाचार के लिये पीटा जावे और उसको दूसरी अच्छी जगह नौकरी दी जावे इससे ज्यादा दुख की बात क्या हो सकती है ? अध्यक्ष महोदय ताज्जुब की बात तो यह है कि जिस समय उस निजी सचिव को पीटा गया उस वक्त स्वयं शिक्षा मन्त्रीजी उसके साथ थे पर उन्होंने उसके लिये कोई कार्यवाही नहीं की। यदि गलत तरीके से पीटा है तो उनके खिलाफ केस रजिस्टर कराना चाहिए था। उन्होंने वह नहीं किया। अध्यापक मन्त्रीजी के पास पहुंचे कि आपके विभाग में पैसा मांगा जाता है। मन्त्रीजी ने कहा कि पैसे मांगें तो जूते उड़ाओ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : बड़ी कार्यवाही की।

श्री भानुकुमार शास्त्री : इस कार्यवाही को इतिहास नहीं भूलेगा। मन्त्री महोदय, वहां से बाहर निकले उससे पहले उनके निजी सचिव की पूजा प्रतिष्ठा हो गई। लेकिन

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

आपने उनको पारितोषिक क्या दिया ? चालान कराते। लेकिन आपने उसको और पारितोषिक दे दिया। मैं पूछता हूं कि क्या ऐसे भ्रष्ट आदमी को विभाग में रखना चाहिये शिक्षा मन्त्रीजी ?

यह सरकार गरीबों को, अनुसूचित जाति और जन जाति के लोगों को पट्टे बांटने और उनके विकास में लगी है। धन्यवाद देता हूं उसके लिये। अच्छा काम कोई करेगा तो उसके लिए हम प्रसन्न होंगे। लेकिन आज हमारे सत्ताधारी दल के लोग अनुसूचित जाति और जन-जाति के लोगों के ठेकेदार बन बैठे हैं। बड़े बड़े छात्रावास अनुसूचित जाति और जन-जाति के बच्चों के लिए खोल रखे हैं। उनमें क्या हो रहा है ? मन्त्रीजी ध्यान नहीं देते। सुबह से शाम तक उनके यहां पर भीड़ लगी रहती है इसी स्थानान्तरण को लेकर। उदयपुर में जो वनवासी छात्रावास है उस ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कौन उसको चलाते हैं और कौन नहीं मैं इस पर नहीं जाना चाहूंगा। किन्तु मैं एक ही बात कहना चाहता हूं वनवासियों के छात्रावास के लिए आपने उनको भूमि दे दी। आपने वह बच्चों के छात्रावास के लिए दी। लेकिन उस भूमि के प्लाट बना कर प्राइवेट लोगों को बेच दिया गया। मकान खड़े हुए हैं वहां पर। एक पोर्शन सेंट पाल को बेच दिया गया। मकान खड़े कर लिये गये। वनवासियों के छात्रावास के विकास के लिए दी गयी जमीन को बेच दिया गया और आपके पास शिकायतें आयीं और आपने कुछ नहीं किया। आपको चाहिये था कि आप उसको रोकते। मैं कहना चाहूंगा कि जहां-जहां भी वनवासी छात्रावास हैं वनवासियों की ही एक कमेटी बनायें जो उनको सम्हालें। भारत की प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी बांसवाड़ा आयीं और छात्रावासों से लड़कियों को भेजा गया। जायें मुझे कोई आपत्ति नहीं। सारा खर्चा एक ने किया। लेकिन इन्चार्ज ने एक एक लड़की से दस दस रुपये लिए, उन्होंने आस पास के अपने भाइयों से लिया लेकिन जिनके पास पढ़ने के लिए नहीं उनसे इस प्रकार लिया गया। सरकार ने वाहवाही लूटने के लिये छात्रवृत्ति के सम्बन्ध में घोषणा करदी लेकिन वह मिली नहीं अब तक। आज भी लोग रोज दरवाजे खटखटाते फिर रहे हैं। छात्रवृत्ति आपने दी नहीं। आप असफल रहे। मैं दूसरी बात न कहूं कर इतनी ही बात जरूर कहूंगा कि इस प्रकार के वनवासी छात्रावासों में फैले हुए भ्रष्टाचार के बारे में जांच बिठायें और अपने हाथ में लेकर अनुसूचित जाति और जन-जाति के अच्छे लोगों के हाथों में सौंप दें।

दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि कभी तो यह बात मान लीजिए, मुझे यह आश्चर्य है, बिना कान जब भगवान सुन लेता है तो आपके तो कान हैं, फिर भी आप न सुनें। तथ्य सामने आ जायं, फाइन्डिंग्स सामने आ जायं कम से कम उस पर इन्क्वायरी कमेटी तो इन्स्टीट्यूट करिये, जांच तो बिठाइये।

जयपुर के लालबहादुर शास्त्री कालेज पर भार्गव कमेटी बिठायी। आपने आज तक हमारे सामने सदन में रिपोर्ट नहीं दी।

(श्री भानुकुमार शास्त्री)
इसके लिए गत वर्ष भी निवेदन किया गया था। उस रिपोर्ट में गम्भीर आरोप लगाये गये हैं। भाई भतीजावाद, कुनबा परस्ती पर लगाये हैं। कुछ तो करिये।

मैं उदयपुर की विद्या भवन संस्था के बारे में कहना चाहता हूं। प्राइवेट संस्था है। उदयपुर के लिए एक असेट है। अच्छी शिक्षण संस्था है। लेकिन वहां पर शिक्षकों के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है उस ओर तो ध्यान दीजिए। आज जो विद्या भवन में शिक्षक हैं उनको तनख्वाह नहीं मिलती है। स्थगन प्रस्ताव की भी सूचना दी। सन् 56 से रूरल इन्स्टीट्यूट बना हुआ है। भारत सरकार ने पैसा दिया। सैंट परसेन्ट पैसा, 90 परसेन्ट भी नहीं। और भूमि दी। मैं समझता हूं, दो सौ ढाई सौ, बीघा जमीन स्वावलम्बी इसको बनाने के लिए दी। उसको विद्या भवन इन्स्टीट्यूशन ने आधी अपनी सोसाइटी के नाम पर कर लिया, इस मतलब से कि उसको टेक ओवर करें तो हमारे हाथ से न जायें। 250 बीघा की आमदनी का कोई लेखा जोखा नहीं। उपकरणों के बारे में, नये सिस्टम के बारे में 20 लाख रुपया भारत सरकार ने अनुदान के रूप में दिया। विद्या भवन इन्स्टीट्यूशन उसका उपयोग नहीं कर सकी और वह लैप्स हो गया मनो। उसको उपयोग में राजस्थान के नागरिक नहीं ले पाये। उन्हें नहीं लेना था तो दूसरी संस्था ले लेती और नयी शिक्षण प्रणाली का लाभ अन्य स्कूल ले सकते थे।

प्रोविडेन्ड फण्ड्स जो टीचर्स से लिया जाता है, आडिट रिपोर्ट आपके पास आती हैं, मेरे पास भी कापी है, उसके अन्दर अध्यापकों का जो पैसा काटा गया है वह जमा नहीं है। कहां गया? मैंने कहा था सारे पैसे का एम्बेजेलमेन्ट हो गया, गबन हो गया। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो पैसा जमा है वह एक कन्सोलिडेटेड अमाउन्ट है। एक एक अध्यापक का पैसा गिनवाइये। इन्टरनल आडिट रिपोर्ट ने यह संकेत किया है कि पैसा नहीं है, गबन हो गया है और जमा नहीं है।

शिक्षा के अन्दर आपके मंत्री होते हुए अव्यवस्था हो रही है। आज विद्या भवन में डा. मेहता जैसा चाहें वैसा करते हैं। योग्यता हो या न हो अध्यापकों को रख लेते हैं। शतप्रतिशत अनुदान देने की बात है इस प्रकार कोई सलेक्ट कमेटी विश्वविद्यालय का मैनेजमेन्ट में कोई हाथ हो जिससे प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं में फैली हुई अव्यवस्था से बचा जा सके।

रूरल इन्स्टीट्यूशन बन्द कर रखी है। आपके यहां से पैसा मिलता नहीं और अध्यापकों को रख रखा है। इसके सम्बन्ध में एक प्रशासक नियुक्त कर दीजिये।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

अध्यक्ष महोदय, मैं जल्दी ही समाप्त करूंगा।

श्री अध्यक्ष: आपका ध्यान दिलाया है।

श्री भानुकुमार शास्त्री: अध्यापकों ने इस सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र भी दे रखा है। इन सारी बातों की ओर संकेत करते हुए कहूंगा कि उदयपुर में एक नहीं अनेक संस्थाओं में अव्यवस्था के सम्बन्ध में प्रश्नों के

(श्री भानुकुमार शास्त्री)
माध्यम से, बजट में कट मोशन देकर और हर माध्यम से ध्यान आकर्षित करता रहा हूँ लेकिन आप उस सम्बन्ध में जांच करने के लिये तैयार नहीं हैं। सत्र विधान सभा का समाप्त हो जायगा। मंत्रीजी और कामों में लग जावेंगे। वही सिलसिला शुरू हो जायगा।

उदयपुर राजस्थान महिला विद्यालय को एक लाख रुपये का सामान आपने दिया। डामेस्टिक साइन्स की दृष्टि से आपने क्लासेस बन्द कर दी हैं। क्या राज्य सरकार उनसे सामान नहीं ले सकती है, युनिवर्सिटी को सामान दे दीजिये। वहां पर 1964 से लेकर 1968 तक का प्रोविडेन्ट फन्ड का कोई हिसाब नहीं हैं। अध्यापकों को पैसा मिलता नहीं है। अध्यापक आते हैं और आप उनको कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं देते हैं। जहां हमारी शिक्षण संस्थायें चलती हों वहां इस प्रकार की अव्यवस्था हो यह अवांछनीय है।

मैं बात एक और कहना चाहता हूं आपकी जो अनुदान प्राप्त संस्थायें हैं कितना पैसा लेप्स हो रहा है। आपने कई संस्थाओं को 68–69 की अनुदान प्राप्त करने वाली सूची में ले लिया है लेकिन आज तक कुछ नहीं मिला जबकि उसके बाद 69–70 की संस्थाओं को भी अनुदान प्राप्त हो जाना चाहिये था। किस प्रकार का आपका रिकोगनिशन है किस प्रकार का आपका प्लान है कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है इसके आधार स्तम्भ आप देखते नहीं हैं।

मुझे कुछ साहित्य अकादमी के बारे में भी निवेदन करना है। आपने राजस्थान साहित्य अकादमी के बारे में जो जल्दबाजी में डाइरेक्टर की नियुक्ति कर दी वह बिलकुल गलत है। एक सही तरीका सलेक्शन कमेटी के जरिये है, डी. पी. सी. के माध्यम से है, किसी कमेटी के माध्यम से एडवरटाइजमेंट निकाल कर डाइरेक्टर जैसी पोस्ट को एडवरटाइज नहीं करते और उसको अपनी इच्छा से थोप देते हैं। आज आधे से ज्यादा उसके कर्मचारी सस्पेन्डेड हैं। मैं समझता हूं माननीय मंत्री जी विशेष ध्यान देंगे। मन में कोई वाइसनेस है उसको निकाल देंगे और योग्य व्यक्ति को रखेंगे चाहे वह कोई व्यक्ति हो। आज इसमें कोई व्यवस्था रखें लेकिन यह नहीं होना चाहिये कि शिक्षा विभाग में अन्धेरगर्दी हो। मैंने एक पत्र भी माननीय मंत्री जी को लिखा था सेन्ट्रल परचेज के बारे में। आपने मुझे उत्तर भी जल्दी भेजा, शायद उसमें कुछ घंटे भी नहीं लगे····

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपके लिये है यह दूसरों के लिये नहीं है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मेरे पास जवाब आ जाता है लेकिन जवाब सही है या क्या लिखा है सेण्ट्रल परचेज नहीं की गई और अखबारों में यह समाचार है, कहां तक सही है लेकिन आपने एक ज्वलन्त उदाहरण राजस्थान के प्रमुख साहित्यकार की पुस्तक पर जब वे जीवित थे उनको आप सहायता नहीं दे पाये। उनके मरने के बाद उनकी किताब पर उनके घर वालों को नहीं देकर पब्लिशर को 7) रु. की किताब के एक लाख की परचेज का आर्डर किया। एक पब्लिशर को लाभ देने के लिए आपने एक लाख की परचेज की। उनके घरवालों को बेचारों को क्या मिला, कुछ नहीं मिला

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

इसी प्रकार एक किताब की जिसकी कीमत 45 रु. है 20 हजार की खरीद की। मैं अन्त में एक बात कहना चाहता हूं आपने जो मुझे...

श्री खेतसिंह (शिक्षा मंत्री) : 45 रुपये किताब का नाम क्या है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : हृदय के उद्गार।

श्री भानुकुमार शास्त्री : नाम मैं बता दूंगा। आपके वार्षिक प्रगति विवरण में विस्तृत सुझाव है। अब मैं एक बात कहूंगा कि आपने पाठ्य पुस्तक मण्डल में छापी, किताब खोलकर पढ़िए तो एक लाइन भी आपको सही नहीं मिलेगी। आपने सिंधी की एक किताब छापी उसमें भी एक एक पंक्ति में दो-दो अशुद्धियां। मैं पढ़ नहीं सकता उसको...

श्री निरंजननाथ आचार्य : पर शिक्षा मंत्री जी पढ़ सकते हैं क्या ?

श्री भानुकुमार शास्त्री : वे पढ़ाने की व्यवस्था करा सकते हैं, उसमें शुद्धि करा सकते हैं उसको सही छपवा सकते हैं। मेरा निवेदन है कि किताबों की शुद्ध छपाई की ओर भी ध्यान दें क्योंकि किताबें छपाने में काफी पैसा लगता हैं और उसको ठीक प्रकार पढ़ नहीं पाये तो वह बेकार है।

अब मैं संस्कृत शिक्षा की उपेक्षा के बारे में दो शब्द कहना चाहता हूं। मैं तो यह कहूंगा जिस प्रकार अंग्रेजों के जमाने में साइन्स के अध्यापक मिलते थे उसी प्रकार आज के युग में आपको संस्कृत के अध्यापक मिलेंगे। उसका कारण सरकार की गलत प्रणाली। आज परीक्षाओं में संस्कृत के विषय को अनिवार्य नहीं रखा गया है उसके लिये 20 या 25 प्रतिशत मार्क रखे हैं। जब मैं अध्यापक था तब मालूम था आज नहीं है तो उसके प्राप्तांकों को डिविजन में जोड़ा नहीं जायगा। कम्पलसरी विषय है लेकिन उसके पूर्णांक जुड़ेंगे नहीं। यह मखौल हो गया है। यदि आपने विषय अनिवार्य रखा है तो उसके अंक डिविजन में जुड़ने चाहिए तब तो विद्यार्थी में उत्साह बढ़ेगा अन्यथा संस्कृत के प्रति विद्यार्थियों में कोई रुचि नहीं रहेगी। मैं इस विषय पर अधिक नहीं कहता हुआ अन्त में एक बात कहते हुए शिक्षा मंत्रालय, राजस्थान के अन्दर शिक्षा की आने वाली पीढ़ी को एक प्रजातन्त्रीय प्रणाली में जीवन के मूल्यों को जोड़कर कुछ ध्यान देगा तब तो मैं समझूंगा आगे जाकर कुछ निर्माण कर सकेंगे अन्यथा शिक्षा पर किये जाने वाला व्यय अपव्यय हो जायगा, इस पर मंत्रीजी ध्यान दें।

श्री अध्यक्ष : श्री मीठालाल।

(अनुपस्थित)

श्री शंकरलाल (अनुपस्थित)

श्री जयकिशनलाल।

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा (फागी) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के ऊपर जो आज मांग प्रसारित की जा रही है उसके ऊपर मैं अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। शिक्षा मनुष्य के जीवन का एक अंग है...

(1.37 म. प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष पीठासीन)

Page No 57

(57)

(श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा)

और जब तक मनुष्य शिक्षा ग्रहण नहीं करता वास्तव में उसका जीवन सफल नहीं हो सकता है। इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब तक शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ा सकते हैं तब तक हमारी समाज का पूर्ण रूप से भला नहीं हो सकता है। मेरा निवेदन है राजस्थान में जो शिक्षा प्रणाली है वह पूर्ण रूप से दोषी है। आज का विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् अन्धेरे में रहता है और वह यह नहीं सोच पाता है कि जिस प्रकार प्रति वर्ष डिग्री ग्रहण करता जा रहा है उसका सही उपयोग होगा या नहीं होगा। इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप अखबारों में देखते हैं इस प्रकार की घटनायें आये दिन होती रहती हैं कि शिक्षितों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। आज का शिक्षित वर्ग किसी भी डिग्री को प्राप्त करके एक दूसरे के दरवाजे पर भटकता फिरता है और जब सही रूप से उसको नौकरी नहीं मिलती है तो आत्म हत्या करनी पड़ती है। इसलिए मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन यह करना चाहता हूं राजस्थान में शिक्षा के अन्दर किसी न किसी प्रकार की नई योजना लाकर, शिक्षा में आमूल-चूल परिवर्तन करके नई पद्धति बना देनी चाहिए जिससे आने वाले विद्यार्थी का पूर्ण रूप से लाभ हो सके और किसी प्रकार उसकी सही धारणा बन सके। मान लें आज शिक्षा की अवधि के अन्दर अपने जीवन में कुछ न कुछ कार्य विद्यालय या विश्वविद्यालय से प्रस्थान करने से पहले उसके विचारों में यह धारणा आ जानी चाहिए कि मैं बेरोजगार नहीं रहूंगा। मेरी शिक्षा में वह प्रणाली है जो भविष्य के लिये मेरे गुरुजनों ने और सरकार ने आयोजन बना दिया है उसको लेकर मैं सफल हो सकूंगा। इस प्रकार की योजना हमको बैठ कर बनानी चाहिए। यदि इस प्रकार की योजना बना दें तो समाज की जो आने वाली पीढ़ी है, जो आने वाले नवयुवक हैं वे पूर्ण रूप से इस जीवन को सफल बनाकर जीवन-यापन कर सकते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्राथमिक शालाओं के स्तर के बारे में इस प्रकार अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। यदि हम जानते हैं कि प्राथमिक शालाओं में स्तर ठीक नहीं है और यदि हम ग्रामीण स्थानों पर जाकर देखें तो हमें मालूम पड़ेगा नन्हें मुन्हें बच्चे जो हमारे भारत के कर्णधार हैं उनको बैठने के लिये स्थान नहीं है। सर्दी, गर्मी, बरसात में किस प्रकार वे अपना विद्याध्ययन करें इस प्रकार की व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं है इसलिए मेरा निवेदन है और माननीय मुख्य मन्त्रीजी से मैं पूर्ण रूप से निवेदन कर देना चाहता हूं कि इस प्रकार प्रत्येक जिला स्तर पर एक कमेटी बना दी जाय और इस कमेटी का कार्य सही हो, क्योंकि आज तक देखा यह गया है कि जिस प्रकार की भी कोई कमेटी बनती है उसे राज्य सरकार से किसी प्रकार का अनुदान नहीं मिलता है इसलिए वह कमेटी हर गांव, हर तहसील और हर पंचायत समिति में भ्रमण करे और वहां जाकर पूर्ण रूप से शिक्षा की गतिविधियों का अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट आपको प्रस्तुत करे तो उस क्षेत्र का शिक्षा के माने में पूर्ण रूप से भला हो सकता है। आप प्राथमिक शिक्षा के बारे में इस प्रकार की कमेटी गठित कर दें और उसकी व्यवस्था सरकार अपनी तरफ से पूर्ण कर दे तो हमारी शिक्षा की व्यवस्था सुधर सकती है।

(श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा)

इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि किताबों की व्यवस्था विद्यार्थियों के लिए समय पर नहीं होती और विद्यार्थियों को अध्यापक परेशान करते हैं और माता पिता परेशान करते हैं इसलिए किताबें समय पर नहीं पहुंचती। कभी प्रेस में पड़ी रहती हैं तो कभी कहीं पड़ी रहती हैं। तो इसके लिए उपभोक्ता भण्डार जिला स्तर पर खोल दिये जायें या और भी उपकरण जो कि शिक्षा से संबंधित होते हैं उनकी व्यवस्था भी इस प्रकार से कर दी जाये तो हमारी प्राथमिक शिक्षा का स्तर पूर्ण रूप से सुधर सकता है।

इसके साथ ही माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि भवन निर्माण के लिए अनुदान दे दिया जाये तो सारी व्यवस्था सुधर सकती है। साथ ही निवेदन यह है कि कई प्राथमिक स्कूलों के अन्दर कहीं चपरासी की व्यवस्था नहीं है और बच्चे कभी पानी पीने को भटक रहे हैं तो कभी कहीं जाने के लिए भटक रहे हैं। इसलिए मेरा कहना है कि जिस पाठशाला में 100 विद्यार्थी से अधिक हों वहां एक चपरासी कम से कम अवश्य नियुक्त कर दें तो उस स्कूल का पूर्ण रूप से भला हो सकता है। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की व्यवस्था कर दी जाये। पेयजल की व्यवस्था भी बहुत आवश्यक है और चपरासी नहीं होने के कारण विद्यार्थियों को पास में किसी कुए पर भेज दिया जाता है और ऐसे स्थानों पर ऐसी घटनायें भी हो गयी हैं कि विद्यार्थी कुओं में गिर गये हैं। इसलिए यह व्यवस्था स्कूलों के अन्दर अवश्य होनी चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में जब तक शिक्षा का सुधार नहीं करेंगे तब तक हमारी जनता अपने जीवन के वास्तविक मूल्य को नहीं समझ सकती। हम चाहे प्रजातंत्र की दुहाई दें, घोषणायें करते रहें, समाजवाद की घोषणा करते रहें लेकिन मेरा निवेदन यह है कि जब तक प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा और जब तक वह शिक्षा ग्रहण करके अपने देश के प्रति उसका क्या उत्तरदायित्व है, अपने स्वयं के प्रति क्या उत्तरदायित्व है और अपने क्या अधिकार और कर्त्तव्य हैं–जब तक एक व्यक्ति यह सब नहीं समझ पाता तब तक सरकार की रीति नीति भी उसके समझ में नहीं आ सकती। इसलिए मेरा निवेदन है कि यदि आप प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित नहीं कर दें तब तक वास्तव में आज का जो हमारा समाज है वह गलत रास्ते पर जा रहा है और इसलिए गलत रास्ते पर जा रहा है कि देश की वास्तविक गतिविधियों का ध्यान नहीं होता और भविष्य के बारे में जो डांवाडोल परिस्थिति रही है, जब तक हम वास्तविक शिक्षा देकर और वास्तविक जीवनयापन करने की सुविधा नहीं देंगे तब तक वह गुमराह होता है और वह हमारे प्रजातंत्र के विरुद्ध देश में आन्दोलन उपस्थित कर रहा है। यदि हम शिक्षा की समस्त गतिविधियां शुरू कर दें, चाहे मजदूर वर्ग हो, चाहे किसान वर्ग हो यदि वह शिक्षित है और सब प्रकार की शिक्षा उसको दे दी जाय तो वह गुमराह नहीं हो सकेगा और अपने सही रास्ते को नहीं भूल सकता।

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, अभी तो केवल पांच, छः मिनट ही हुये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : यह आ का डिस्कीशन नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय की यही व्यवस्था है।

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : दूसरे आपको प्रौढ़ शिक्षा और महिला शिक्षा के बारे में प्रगति करनी चाहिये। जब तक इस दिशा में हम प्रगति नहीं लायेंगे तब तक हम उन्नति नहीं कर सकते। यदि हम जो निरक्षर भट्टाचार्य हैं उनको साक्षर कर देंगे तो वह अपने जीवन को समझेंगे। साथ ही साथ महिला शिक्षा के बारे में निवेदन है कि महिलायें हमारे समाज का अंग हैं और उस महिला वर्ग को जब तक हम शिक्षा नहीं देंगे तब तक अपने परिवार की ठीक प्रकार की वह व्यवस्था नहीं कर पायेंगी। क्योंकि पुरुष वर्ग केवल मात्र व्यापार करने, या नौकरी करने या खेती करने के कार्य करता है लेकिन घर की व्यवस्था पूर्ण रूप से महिलाओं पर आधारित है। इसलिए जब तक महिला वर्ग शिक्षित नहीं होगा तब तक हमारे समाज का ढांचा ठीक ढंग से नहीं सुधर सकता और यह वर्ष वैसे भी महिला वर्ष है इसलिए विशेष प्रकार की इनको सुविधायें देनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य आपस में बात न करें।

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अब अपने क्षेत्र की बात और बता देना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र के अन्दर चाकसू ऐसा कस्बा है कि पिछले 15–20 साल से वहां पर सेकेण्डरी स्कूल है लेकिन वह आज तक हायर सेकेन्डरी नहीं बना इसलिए मैं शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन कर देना चाहता हूं कि कम से कम उसे हायर सेकेंडरी स्कूल में तो परिवर्तित कर दें...

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : आपका फागी कहां है ?

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : फागी और चाकसू मिला हुआ है। फागी का नाम इसलिए लेता हूं कि वह मेरी जन्मभूमि है। मुझे तो मेरी जन्मभूमि से मोह है। आपको मोह नहीं है तो आप बैठे रहिये...

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मैंने आपको याद दिलाया है।

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : और वहीं से जीतकर आया हूं इसलिए वहां की जनता की सब गतिविधियों की मुझे चिन्ता है, आपकी तरह निश्चिन्त नहीं हूं।

इसलिए मैंने निवेदन किया है कि वह म्यूनिसिपेलिटी एरिया है और वहां के विद्यार्थी दूसरी जगह भटकते रहें यह ठीक नहीं है। हमने कल, परसों अखबार में पढ़ा था कि अब हम हायर सेकेन्डरी की प्रणाली को हटाकर फिर से इन्टरमीडियेट वाली प्रणाली को हम लागू करना चाहते हैं। तो यह तो बहुत अच्छा है लेकिन अभी जहां सेकेन्डरी स्कूल हैं उनको हायर सेकेन्डरी स्कूल में परिवर्तित कर दें तो वास्तव में ग्रामीण जनता की अच्छी तरह से भलाई हो सकती है।

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

एक दो मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये।

(समय–समाप्ति–सूचक घंण्टी)

आप विराजिये।

श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा : जब भी मैं बोलता हूं पता नहीं आपके दिल में मेरे साथ ये ××× क्यों है। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, तीन वर्ष हो गए।

श्री उपाध्यक्ष : आप तशरीफ रखिये। आर्डर प्लीज।

श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा : मैं कोई गलत नहीं बोल रहा हूं। मेरे मुंह से गलत शब्द नहीं निकल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अभी माननीय अध्यक्ष महोदय ने यह व्यवस्था दी थी कि 7 मिनट से अधिक किसी को भी समय नहीं दिया जायेगा।

श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा : 10 मिनट के लिए कहा है और फिर भी कह रहा हूं आप प्रासीडिंग्स देख लें। उसमें आगे भी कहा है उसमें कमीबेशी की जा सकती है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : माननीय सदस्य ने यह लफ्ज कहे हैं कि ××× है इनको एक्सपन्ज किया जाये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने सुने नहीं।

श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा : यह ××× शब्द हैं मैं स्वयं ही विथड्रा करता हूं। मैं शब्दों की गतिविधियों को अच्छी तरह से जानता हूं। 5 मिनट का समय मुझे दे दें।

श्री उपाध्यक्ष : केवल 2 मिनट।

श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा : 5 मिनट। तो मेरा ऐसा निवेदन है कि मैं शिक्षा के बारे में बता रहा था। अब मैं क्रीडा परिषद् के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। क्रीड़ा परिषद् इस प्रकार की है कि यदि हम इसकी व्यवस्था ठीक कर दें तो काफी फायदा हो सकता है। क्योंकि यह परिषद् केवल मात्र शिक्षण संस्थाओं के अन्दर ही चलती है। बाहर जब शिक्षा ग्रहण करने के बाद व्यक्ति निकलता है तो उसका जीवन सांसारिक गतिविधियों से जुड़ जाता है। इसलिए उसको समय नहीं मिल पाता है और समय विद्यार्थी जीवन में ही मिल पाता है इसलिए मेरा यह निवेदन है कि इस प्रकार की परिषद् की व्यवस्था ठीक कर दें, सरकार की ओर से सारी व्यवस्था ठीक करें, इनको किसी प्रकार का अनुदान दें या जो इसके अन्दर किसी प्रकार के उपकरण या सामग्री या सामान दें और अच्छी तरह से योग्यता रखने वाले जो अच्छे खेल के अन्दर प्रशिक्षित व्यक्ति हैं उन्हें यदि हम चयन करें तो यह परिषद् या इसके अन्दर आने वाले सदस्य या खिलाड़ी हमारे देश में पूर्ण रूप से एक ऊंचा स्थान बना सकते हैं और प्रान्त के लोग भी ऊंचा स्थान बना सकते हैं।

साथ ही यूथ बोर्ड की ओर भी मैं विशेष रूप से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यूथ को यदि हम किसी प्रकार से आगे लायेंगे तो वह कन्धे से कन्धा मिला कर हमारे देश की गतिविधियों के अन्दर हाथ बटायेगा और यूथ बोर्ड की स्थापना की दो तीन वर्ष से लगातार इसके बारे में घोषणा की जा रही है। इसलिए मेरा निवेदन

××× ये शब्द माननीय सदस्य द्वारा वापिस लिये गये।

(श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा)

है, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्रीजी से और माननीय मुख्य मंत्री महोदय से कि जल्दी से जल्दी इस बोर्ड की यदि हम घोषणा कर दें तो वास्तव में कई विद्यार्थी हैं, युवक हैं, नवयुवक वर्ग है उनको शान्ति मिल सकती है, उनका आक्रोश शान्त हो सकता है।

दूसरा मेरा निवेदन है उपाध्यक्ष महोदय कि छात्र वर्ग में या शिक्षा संस्थाओं के अन्दर चिकित्सा सम्बन्धी सुविधा भी कर दें यदि तो वहां के छात्रों को जो इधर उधर मारे मारे फिरना पड़ता है, कभी किस डाक्टर के कभी किस डाक्टर के पास जाकर चिकित्सा करानी पड़ती है, यदि इस प्रकार की व्यवस्था महाविद्यालियों में, सेकेन्ड्री स्कूल, हायर सेकेन्ड्री स्कूल और प्राथमिक पाठशालाओं में कुछ स्थानों पर किसी प्रकार की व्यवस्था कर दें तो यह सारी की सारी स्थिति हो सकती है। (व्यवधान–अश्रव्य)। यह बढ़िया है, बहुत अच्छा है। एक माननीय सदस्या कह रही हैं कि पहले से हैं तो उसके लिए धन्यवाद देता हूं। मेरा निवेदन यह है कि जिस प्रकार प्रशिक्षण के लिए, एक स्नातक जो हमारे अध्यापक हैं, वह प्रशिक्षित होने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हैं, लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उनके सामने समस्या क्या है कि हमारे विश्वविद्यालय ने न्यूनतम प्रतिशत चालीस प्रतिशत अंक निर्धारित कर रखे हैं। यदि इनके अन्दर किसी प्रकार का सुधार कर दें और दस वर्ष से लगातार जो अध्यापन का कार्य अध्यापक कर रहे हैं यदि उनको स्वतः ही प्रशिक्षित मान लिया जावे तो हमारे सामने आने वाली दिक्कत मिट सकती है। साथ ही इस प्रशिक्षण के मामले में भी अनुसूचित जाति और जन जाति के लोगों के लिए रिजर्वेशन कर दिया जावे तो मैं ऐसा समझता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि हमें पूर्ण रूप से अध्यापकों की जो कमियां हैं वह आसानी से उसे मिटा सकते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से अध्यापकों के जो स्थान रिक्त हैं, कई शिक्षा संस्थाओं के अन्दर अधिकारियों की जगह रिक्त हैं उन्हें पूरा कर दिया जावे। इसके साथ ही जो नगरपालिका और पंचायत समितियों की स्कूलों के ऊपर जो ध्यान नही दिया जा रहा है उनके ऊपर भी ध्यान देकर उचित अनुदान दिया जाय। साथ ही जिला बोर्ड के कई अध्यापक सरप्लस करके पंचायत समितियों में एडजस्ट करने के लिए भेज दिए जाते हैं उन पर विशेष रूप से ध्यान दिया जावे। मेरा निवेदन है कि शिक्षा सत्र के अन्दर इस ढग से सुधार किया जा सकता है।

दूसरा मेरा निवेदन है कि जैसे प्राइवेट या एडेड स्कूलें चल रही हैं उसके अन्दर जो जानता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो खुद उनमें पढ़ा हूं इसलिए मुझे मालूम है कि क्या होता है। तनख्वाह राज्य सरकार की ओर से दी जाती है। जैसे ढाई सौ रुपया दिया जाता है उदाहरण के तौर पर और उसमें सौ रुपया दिया जाता है और लिखवाया जाता है कि ढाई सौ रुपया। इसलिए मेरा सुझाव है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री महोदय को कि आप इस प्रकार की कमेटी बनायें और प्रत्येक एडेड और रिकोग्नाइज्ड जितनी

(श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा)

स्कूलें और पाठशालायें हैं उनका एक सर्वेक्षण करवाया जाय और उसके अन्दर जिस जगह इस प्रकार का अन्याय हो रहा है उन अध्यापकों के ऊपर, उनको ठीक ढंग से पूरा का पूरा वेतन दिलवाया जाय तो वास्तव में अध्यापकों को लाभ हो सकता है। यही मेरा निवेदन है। अब आज्ञा हो तो दो मिनट जेल के बारे में भी निवेदन कर दूं . .

श्री उपाध्यक्ष : आपके पांच मिनट को पन्द्रह मिनट समझूं।

श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा : जेल के ऊपर। यह जितने भी जेल और अपराधी हैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह स्वयं नहीं बन सकते, उनको हमारा समाज बनाता है और क्यों बनते हैं अपराधी कि जैसा मैंने शिक्षा स्तर के अन्दर निवेदन किया था कि व्यक्ति बेरोजगार होता है और जब व्यक्ति बेरोजगार होता है, अपने पेट की भूख को शांत करने के लिए उसे कुछ न कुछ साधन जुटाना पड़ता है। नौकरी नहीं मिलती, व्यापार नहीं मिलता, जमीन उनके पास नहीं खेती करने के लिए, इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, अंत में जाकर वह चोरी करता है, डाका डालता है, हत्या करता है। मजबूर होकर सारे के सारे अपराध करने पड़ते हैं। इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि इस प्रकार अपराधी लोगों को पूर्ण रूप से शिक्षित बनाया जाय। उन्हें खुले रूप में जेल का एक भवन बना कर इस प्रकार की संस्थायें बना कर उन्हें खुले मैदान में रखा जाय। उन्हें स्वतंत्रता पूर्ण रूप से दी जाय और धीरे 2 शिक्षित करके किसी प्रकार का रोजगार जुटायें तो धीरे धीरे जो उनके दिमाग से भ्रांति है, अपराध करने का जो तत्व उनके दिमाग और हृदय में एक स्थान कायम कर चुका है वह पूर्ण रूप से शांत हो सकता है। वहां पर खाने-पीने की व्यवस्था ठीक होनी चाहिये। हम उन्हें केवल अपराधी मान कर हमारे समाज का अंग नहीं मानते हैं। उसके अंग में अंग अलग कर देते हैं और जेली यह कर, अपराधी कह कर उसके विचारों का हनन करते हैं, इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार यदि उनके साथ सहानुभूति का व्यवहार किया जाय, अपराधी को अपराधी नहीं समझा जाय, उनकी व्यवस्था खाने-पीने की, पहनने-ओढ़ने की, शिक्षा की, घूमने फिरने की इधर उधर वार्तालाप करने की, विचार करने की, शिक्षा ग्रहण करने की, यदि इस प्रकार की व्यवस्था हम सही रूप से, सही ढंग से हमारे समाज का अंग मान कर, हमारे समाज की एक तरह से धरोहर मान कर उनके साथ यदि हम अच्छा व्यवहार करें तो धीरे धीरे इस प्रकार के अपराध स्वतः ही दूर हो सकते हैं। आपको एक उदाहरण देकर मैं एक बात रखता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि चीन के अन्दर एक इस प्रकार का राजा हुआ। धीरे धीरे उसने इस प्रकार की व्यवस्था करदी अपराधों के बारे में कि इस व्यवस्था करने के बाद अन्त में क्या हुआ कि कोर्ट्स बन्द हो गई, वकीलों की वकालत बन्द हो गई। क्योंकि उन्होंने अपराधियों को परिवार का अंग माना और परिवार का अंग मान कर सारों की सारी व्यवस्था कर देने से, अपराधी को अपराधी नहीं मानने से, उनके साथ अच्छा . .

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा : व्यवहार करने से ये सब झगड़े दुरुस्त हो सकते हैं और उनका सुधार हो सकता है। बस यही कह कर मैं अपना निवेदन समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री झाबरमल मूंडा (अनुपस्थित)

श्री दीनकर (अनुपस्थित)

श्री श्रीराम गोटेवाला।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने शिक्षा पर और कारागृह की मांगों पर कटौती प्रस्ताव पेश किये हैं। मैं सर्वप्रथम तो हमारे उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस प्रकार संस्कृत शिक्षा के बारे में कहा, यह सही है कि संस्कृत शिक्षा का ह्रास हो रहा है, मैं भी इस बारे में अनुरोध करना चाहूंगा। जहां तक मेरी जानकारी है, मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी को मुबारकबाद दूंगा कि सारे हिन्दुस्तान में, उत्तर भारत के अन्दर उन्होंने सबसे पहले राजस्थान के अन्दर महापुरा में संस्कृत शिक्षा का एस. टी. सी. सेंटर खोला। इसके लिए तो मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूं। मैं इस बात को महसूस करता हूं कि संस्कृत शिक्षा के प्रति अभिरुचि कम हो रही है, यह बात सही है। संस्कृत कालेजों के अन्दर छात्रों की संख्या बढ़े, वे अभिरुचि लें और अनुसंधान करें इस बारे में हमें कार्य करना पड़ेगा और मैं शिक्षा मंत्रीजी से अनुरोध करूंगा कि जहां उनके पास शिक्षा का महकमा है वहां उनके पास पुरातत्व का भी महकमा है। हमारे राजा, महाराजाओं के पास, हमारे 22 रजवाड़ों के पास बहुत सारी पांडुलिपियां पड़ी हुई हैं और उनके ऊपर शोध कार्य किया जा सकता है। मैं शिक्षा मंत्रीजी से आज के अवसर का लाभ उठाते हुए यह अनुरोध करूंगा कि वह इस प्रकार का प्रयत्न करें कि हमारे देश के सारे विद्यार्थी ही नहीं, विदेशों के भी जो संस्कृत में रुचि रखने वाले लोग हैं वह हमारे सारे कार्यक्रमों में रुचि लें उन्हें इस प्रकार की सुविधा दें और जगह जगह इस बारे में विज्ञापन करें ताकि हमारे इस ज्ञान का लाभ सारा विश्व उठा सके।

दूसरी बात अब मैं निवेदन करूंगा कि अभी माननीय सदस्य फरमा रहे थे कि इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन्स को एडेड स्कूल को जो ग्राण्ट मिलती है, उनके बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सौभाग्य से कहिये मैं वर्षों से इस बात की बराबर यहां मांग करता रहा हूं कि यहां पर कई स्कूल 63 से 64 से केटेगराईजेशन नहीं हुआ और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 63–64 में जो शिक्षण संस्थायें बहुत अच्छी रही हैं, ए श्रेणी की रही हैं किसी भी कारण से, प्रिंसीपल की वजह से, प्रधानाध्यापक की वजह से या किसी भी तरह से, उनका स्तर ऊंचा मान लिया और, उनको आज भी नब्बे प्रतिशत ग्राण्ट-इन-एड मिल रही है। अभी उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य उदयपुर के विद्या भवन के बारे में कह रहे थे, मुझे खुशी है, मैं शिक्षा मंत्रीजी को इस बात के लिये बधाई भी दूंगा कि उन्होंने इस केटेगराइजेशन कमेटी की नियुक्ति की और साथ ही साथ में यह भी निवेदन करूंगा कि केटेगराईजेशन कमेटी की रिपोर्ट वह शीघ्र से

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

शीघ्र सदन के पटल पर रखें और इसके अनुसार अब की बार वह दे पायेंगे या नहीं दे पायेंगे लेकिन यहां पर इतना जरूर निवेदन है कि इस केटेगराईजेशन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर यदि इस बार ग्रान्ट–इन–एड दें तो अधिक अच्छा है, अगर अब की बार नहीं दे पायें तो निश्चित रूप से सदन को इस बात के लिए आश्वस्त करेंगे कि अगले वर्ष जो ग्रान्ट–इन–एड होगी वह इस केटेगराइजेशन के आधार पर होगी ताकि जो अच्छी संस्थाएं हैं वे इस लाभ से वंचित न हों। उपाध्यक्ष महोदय मैं इस मत का हूं कि जितनी भी प्राइवेट शिक्षण संस्थाएं हैं, प्राइवेट कालेज हैं, जो निजी शिक्षण की दुकानें हैं, इन दुकानों के अलावा भी जो शिक्षा का कार्यक्रम चलाते हैं, वैसे तो शिक्षा मंत्री जी हिम्मत वाले हैं, उनके नाम के आगे राठौड़ लगता है और राठौड़ के नाम से राजस्थान का इतिहास प्रेरणा लेता रहा है, वैसे मैं यह कहने की अनधिकार चेष्टा कर रहा हूं, क्योंकि शिक्षा के बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं है, मैं बेपढ़ा लिखा हूं, और दुर्भाग्य से हमारे शिक्षा मंत्री जी भी कोई जाने माने शिक्षा शास्त्री नहीं हैं, तो भी मैं उनसे एक अनुरोध करूंगा कि आज उनको एक मौका मिला है, वे इस प्रकार के कदम उठावें–आज शिक्षा हम इसलिए देना चाहते हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य सुखद हो, उज्ज्वल हो परन्तु मैं यह देखता हूं कि मेरे पास पचासों बच्चे बी. ए., एम. ए., बी. एड., एम. बी., बी. एस. डाक्टर और इन्जीनियर आते हैं और वे नौकरी के लिए कहते हैं। इसका कारण क्या है ? हमारे संविधान में पांच सिद्धान्त तय किए हैं उनमें से एक शिक्षा है। यह हम अपना कर्त्तव्य मानकर चले हैं–सारे लोगों को शिक्षित करना हमारी एक जिम्मेदारी है। यह सौभाग्य की बात है कि शिक्षा मंत्री जी मेनीपुलेशन करने में दक्ष हैं। जहां पिछले साल शिक्षा के मद में 64 करोड़ का मद था इस वर्ष शिक्षा के मद में 74 करोड़ खर्च होने का अनुमान है। इस मेनीपुलेशन के लिए मैं उनको मुबारिकबाद देता हूं। जहां 1651–52 में शिक्षा के मद में केवल डेढ़ करोड़ रुपया खर्च होता था वहां अब 75–76 के वर्ष में 74 करोड़ 16 लाख रुपया खर्च होगा। इस सारे बजट की जानकारी हमको केवल चार पेज में दी गई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जो भी काम हो रहे हैं, जिस प्रकार के भी काम शिक्षा जगत में हो रहे हैं, उनके बारे में हम को विस्तृत जानकारी दी जाए। मैं समझता हूं, शिक्षा मंत्रीजी हिम्मत के साथ फैसला करेंगे और साथ ही साथ शिक्षा को लोगों के लिए रोजगार का साधन बनाएंगे। आज ही एम. बी., बी. एस. और इन्जीनियरिंग शिक्षा जोब ओरिएन्टेड शिक्षा नहीं हो सकती है। अस्सी, पिच्चासी हजार रुपया का खर्चा एक डाक्टर की शिक्षा पर व्यय होता है और वह शिक्षा प्राप्त कर रोजगार की तलाश में सड़कों पर मारा मारा फिरता है। उसके लिए आप स्टाइपेन्ड और दूसरी प्रकार की व्यवस्था करते हैं, इसके बजाए मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा–थोड़े दिनों पहले भारत सरकार के स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज के डाइरेक्टर महोदय का मैंने भाषण सुना था। उन्होंने अपने भाषण में एक महत्व की बात कही जहां तक मुझे जानकारी है हमारे देश का सर्व शिक्षा विभाग

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

तरफ से भारत सरकार के शिक्षा विभाग की तरफ से चल रहा है। यह सर्वे चल रहा है देश में एम्पलायमेन्ट पोटेन्शिलिटी के बारे में–किस प्रकार शिक्षा को ऐसी दिशा की ओर मोड़ा जा सके कि लोगों को, विद्यार्थियों को उस काम के बारे में शिक्षा दी जा सके। आज ऐसे कामों के बारे में शिक्षा देने की अधिक आवश्यकता है। आज देश को 80 खातियों की आवश्यकता है और हम तैयार कर रहें हैं इन्जीनियर्स। फिटर आप नहीं बना रहे हैं। आज के लड़के पढ़-लिख कर अपने कपड़ों को गन्दा देखना नहीं चाहते। वे हाथ से काम नहीं करना चाहते। यह मनःस्थिति आज के युवक की हो गई है। पंजाब ने इस दिशा में काफी तरक्की की है। वह ऐसे फोरमेना तैयार कर रहा है जो अंगूठा टेक हैं दस्तखत करना नहीं जानता फिर भी वह दो हजार रुपया प्रति माह कमा रहा है। इसलिए मैं यह निश्चित तौर से निवेदन करना चाहता हूं–मेरा थोड़ा सा इन्जीनियर्स से सम्बन्ध रहा है। आज आपको 400 रुपया माहवार पर इन्जीनियर मिल जाएंगे परन्तु फिटर एक हजार रुपये माहवार में नहीं मिलेगा। जिस राठौड़ी की मैं आपसे कल्पना करता हूं, शिक्षा में परिवर्तन की जो कामना हम करते हैं, उस कल्पना की ओर आप आज ही इस शिक्षा को मोड़ सकें, इस प्रकार की शिक्षा दिलाने की आप व्यवस्था करा सकें, शिक्षा से, पढ़ लिख कर आज के युवक बेरोजगार न हों, पढ़ लिख कर वह किसी प्रकार के धंधे में लग सकें, कोई कारोबार कर सकें, इसके लिए आपको जो भी कदम उठाना पड़े, आप उठायें। इसके लिए आपको कोई धन की कमी नहीं है, और कमी होगी तो उसको पूरा किया जाएगा। ऐसी संस्थाओं को आप शत प्रतिशत ग्रान्ट इन एड दें और इसका परीक्षण करें। भारत सरकार ने जो योजना बनायी है जिस प्रकार से पंजाब के अन्दर एक वातावरण बना है, वहां का एम. एस सी. का स्टूडेन्ट आज किस प्रकार रोजगार पर लगा हुआ है। यह प्रशंसा की बात है। मैं ऐसे एक युवक को जानता हूं जो जयपुर के अन्दर ही है और नरसरी का काम कर रहा है। इस काम को करने में इस लड़के को कोई हिचक नहीं है। अगर वह नौकरी करे तो एक हजार रुपया कमा सकता है। मैंने उससे पूछा यह काम क्यों कर रहे हो? नाले को हाथ से क्यों खोद रहे हो? नौकरी क्यों नहीं करते? उसका जवाब था, इस काम में जो आनन्द मिल रहा है वह नौकरी में नहीं मिल सकता। इस नरसरी के काम में मैं तीन हजार रुपया प्रति महीने कमा रहा हूं। तो ऐसे काम के लिए हमें प्रदेश में एक वातावरण पैदा करना होगा। आपका शिक्षा विभाग इसके लिए कैसे सक्षम होगा, किस तरह से इस प्रोग्राम को कार्य रूप में कार्यान्वित करेगा, यह आपके सोचने की बात है

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दूसरा यह निवेदन कर रहा था; कई माननीय सदस्यों ने और विशेष कर जयपुर से आते वाले माननीय सदस्य ने रवीन्द्र रंगमंच के बारे में कहा है। मैं इस सारी बात में नहीं जाना चाहूंगा लेकिन मेरा यह अनुरोध है कि रवीन्द्र रंगमंच के लिये आपने जिस प्रकार से मरम्मत के आदेश दिए हैं, उसके लिए तो मैं आपका आभारी हूं। आपने इसके लिए पचास हजार का प्रावधान रखा है। मैदिर-

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

बानी करके जो लड़के ऊपर बेरोजगार बैठे हुए हैं, उनके पेट पर लात मत मारिये। उनकी तनख्वाह चुकाने के भी आदेश दीजिये।

दूसरी एक बात पुरातत्व विभाग, म्युजियम के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। जैसा कि पूर्व में मैंने पांडुलिपियों के बारे में निवेदन किया है। हमारे रजवाड़ों के बारे में, रियासतों के पास, उनके कब्जे में कई प्रकार की पांडुलिपियां हैं, उनको सरकारी कब्जे में लिया जाय और उन पर शीघ्र कार्य करवाया जाये। यह अध्ययन के लिए भी उपलब्ध हों जयपुर का म्युजियम, जिसकी बिल्डिंग सारे हिन्दुस्तान में मशहूर है, जिसका नक्शा बहुत बढ़िया है, और जिसको पीछे की ओर एक्सटेन्ड करने की योजना थी, वह कब तक होगी किन्तु पीछे का जो बाग है वह तो करीब करीब नष्ट होता जा रहा है, इसलिए इसको कब तक डबल करवाएंगे, यह तो मैं नहीं जानता किन्तु इस सम्बन्ध में थोड़ा अनुरोध करूंगा कि इस प्रकार का संग्रहालय जयपुर में हो और इस के लिए आप कृपया समुचित व्यवस्था करें जिस प्रकार कि हैदराबाद का संग्रहालय सारे हिन्दुस्तान में मशहूर है। ऐसा संग्रहालय शिक्षा मंत्री महोदय आपके शिक्षा मंत्रित्व काल में हो, तो मैं आपको मुबारिकबाद दूंगा।

इस सदन के अन्दर राष्ट्रीयकृत पुस्तकों के बारे में कई बार चर्चा हो चुकी है। पहले सत्र के अन्दर यह चर्चा हुई थी कि विद्यार्थियों को समय पर पुस्तकें उपलब्ध नहीं होती। उत्तरप्रदेश में एक महीने तक स्कूल इसी कारण से बंद रहे। यह स्थिति हमारे प्रदेश की न रही। शिक्षा मंत्री महोदय ने इस सम्बन्ध में व्यक्तिगत तौर से दिलचस्पी लेकर सिवाय एक पुस्तक के करीब करीब सभी पुस्तकें उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर दी? मैं यह अनुरोध करूंगा कि वह एक पुस्तक भी आप उपलब्ध करा दें ताकि इसकी कमी न रहे।

एक बात और कहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय छोटी सी बात है। पब्लिक स्कूलों के बारे में बहुत ही विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं। एक प्रश्न इस सदन में आया था जिसका चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय ने उत्तर दिया था उनका उत्तर था कि शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स में योग्य छात्र नहीं हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इन पब्लिक स्कूलों में साधारण श्रेणी के बच्चे अगर नहीं पढ़ते हों तो उनको राज्य सरकार मान्यता नहीं दें। उन पर यह कम्पलशन लगा दिया जाए कि इतने प्रतिशत शिड्यूल्ड कास्ट, ट्राइब्स और निम्न क्लास के बच्चों को इन स्कूलों में पढ़ाना अनिवार्य होगा। यह कम्पलशन किया जाए। हम अपने दिमाग में जिस समाज की रचना की कल्पना करते हैं, जिस ढंग से समाज को बनाना चाहते हैं, उसमें इस दिशा से कार्य करना चाहिए। जो साधन सम्पन्न हैं वे अधिक साधन सम्पन्न होते जा रहे हैं। जिनके पास पहले से ही सुविधाएं हैं वे अधिक सुविधाएं प्राप्त करते जा रहे हैं और जिनके पास सुविधाएं नहीं हैं, जिनको सुविधा देने की हमारी जिम्मेदारी है, उनको हम वंचित करते जा रहे हैं। तो मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी आपसे यह अनुरोध करूंगा कि वहां पर इन सारी बातों के बारे में आप कम्पलशन लागू करेंगे।

श्री केदारनाथ : एम.एल.ए. और मंत्री अपने यहां पर बच्चे न भेजें। तो अमल हो जायगा।

श्री श्रीराम गोटेवाला : लेकिन दुर्भाग्य से आप जैसे विधायकों को यह परेशानी नहीं है। हम जैसों को परेशान होना पड़ता है। हम लोग ही इसकी कल्पना कर सकते हैं। वैसे प्रोफेसर साहब का सुझाव बहुत बढ़िया है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं एक ही बात निवेदन करूंगा कि सारा आपका खुद का विभाग सारा मजमून तो लिखता है अंग्रेजी में और नीचे नाटक आप करते हो हिन्दी में दस्तखतों का। तो मेहरबानी करके इस नाटक को बन्द कर दो। सारी ही हिन्दी की बात आप करें। राजस्थान जैसे प्रदेश में 28 वर्षों के बाद भी हिन्दी की बात नहीं कर सके। चिट्ठी नहीं लिख सकते हैं, हमारे अधिकारी पढ़ नहीं सकते और हिन्दी में काम नहीं कर सकते? मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जगह जगह सेक्रेटरियेट में और कई जगह बड़े बड़े पोस्टर आपने चिपका रखे हैं उनका कोई महत्व नहीं है। मैं अभी गुजरात गया था तो मैंने देखा है कि वहां के हाइएस्ट आफिसर केवल मात्र गुजराती में बात करते हैं। मैंने पूछा कि आप यू. पी. से आये हुए आदमी गुजराती में किस ढंग से बात कर सकते हैं तो उन्होंने कहा कि इन्होंने कम्पलसरी कर दिया है कि सारा पत्र-व्यवहार गुजराती में करना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री श्रीराम गोटेवाला : दो महीने में ही सारा काम सीख लिया। मैं अनुरोध करूंगा कि राजस्थान के सारे अधिकारी हिन्दी अच्छी तरह जानते हैं। आपके सारे मंत्री इस राजस्थान की धरती पर पैदा हुए हैं। उनके गीत जब जन्मे थे तो हिन्दी में ही गाये गये थे और आगे की बात मैं नहीं करता कि अंग्रेजी में रोयेंगे। सारे गीत हिन्दी में गाये गये तो सारा मजमून हिन्दी में लिखें ...

श्री गोपाल जोशी : गीत तो हमारे यहां मारवाड़ी में गाये जाते हैं और आपके यहां भी मारवाड़ी में ही गाये जाते हैं तो हिन्दी की जगह राजस्थानी और मारवाड़ी की बात करें।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं मेरी गलती को मानता हूं लेकिन कभी कभी हिन्दी में भी गीत गा लिये जाते हैं।

श्री रामकिशन : मारवाड़ी और राजस्थानी कोई भाषा नहीं है। मेहरबानी करके हिन्दी की बात करें।

श्री उपाध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करिये।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं सिर्फ एक बात निवेदन करूंगा। मैं शिक्षा मंत्री से अनुरोध करूंगा कि टेक्निकल शिक्षा हमारी तरक्की का आधार होता है। शिक्षा के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। उनकी उपलब्धियों की प्रशंसा करते हुए कि इतने हायर सैकण्डरी स्कूल खोल दिये हैं और इतने सारे कालेज चल रहे हैं, लेकिन टेक्निकल एज्यूकेशन के लिए जो मशीनें आई हुई है उन पर एक-एक इन्च धूल जमी

Page No 68

(68)

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

हुई है। हमारे सामने सारे उद्देश्य हैं और जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम संघर्ष करते हैं उसकी प्राप्ति में बाधा हो रही है तो उस सारे काम को टेक्निकल एज्यूकेशन को जैसा कि मैंने निवेदन किया कि किस काम के लिए कितने लोगों की आवश्यकता है, किस प्रकार की आवश्यकता के लिए किस प्रकार के लोगों की आवश्यकता है इसके बारे में जब तक नहीं सोचेंगे तब तक आपकी बात पूरी नहीं पड़ेगी।

मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि ला कालेज में हमारे यहां हड़ताल हो रही है। मैं इस बात के लिए माननीय शिक्षा मन्त्रीजी को धन्यवाद दूंगा कि राजस्थान इस वर्ष स्टूडेन्ट्स के आन्दोलनों के मामले में शान्त रहा है, शांत रहना गुनाह नहीं है। यह मान लें कि बगावत करें और झगड़ा-फसाद करें तभी सारी बात होना चाहिए तो वह ठीक चीज नहीं है। यहां पर ला कालेज के लड़कों की हड़ताल चल रही है। मैं अनुरोध करूंगा कि माननीय शिक्षा मन्त्रीजी उसमें दिलचस्पी लेकर जिस प्रकार भी हो सके इस झगड़े को निपटायें ताकि हम लोगों में जाकर यह बात कह सकें कि हमारी सरकार शान्ति की बात सुनती है और अपने कार्यक्रम के आधार पर सारी बातें करती है। यही बात कहते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकिशन !

श्री रामकिशन (भरतपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज जिस प्रकार का दवाव देश के सामने शिक्षा के सम्बन्ध में है, मैं समझता हूं कि राज्य सरकार उसके सम्बन्ध में गम्भीर नहीं है। अगर मन्त्रीजी खाली यह समझते हैं कि कुछ हायर सैकन्डरी स्कूल खोलकर, कुछ मिडिल स्कूल खोलकर हम शिक्षा का विस्तार कर रहे हैं वह केवल अक्षर ज्ञान कराने वाली शिक्षा का विस्तार हो रहा है। जिस प्रकार से राष्ट्र आज आन्दोलित है कि मौजूदा शिक्षा प्रणाली ऐसी है कि जो आदमी को बेकार बनाती है, जो आदमी को एक तरह से नाकारा बनाती है, उस शिक्षा-प्रणाली में परिवर्तन की आप क्या आवश्यकता अनुभव करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कोई शिक्षा शास्त्री नहीं हूं और मैं यह कहने की स्थिति में नहीं हूं कि उसके सम्बन्ध में क्या क्या सुझाव हो सकते हैं, लेकिन मैं सबसे एक निवेदन जरूर करना चाहता हूं कि कल दिल्ली में लाखों नौजवानों ने इसलिए प्रदर्शन किया था कि शिक्षा-नीति में परिवर्तन करो। आज सारा देश जिनमें कई शिक्षा-शास्त्री हैं इस बात को स्वीकार करते हैं कि इस नीति में परिवर्तन करें। मैं मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि आपने परिवर्तन की क्या पृष्ठभूमि तैयार की है? राजस्थान को किस ओर ले जाना चाहते हैं? कोई शिक्षा-शास्त्रियों की कमेटी बनाई है जो माननीय शिक्षा मंत्रीजी को शिक्षा में परिवर्तन के सुझाव देगी? उस कमेटी के टर्म्स क्या हैं यह मेरी जानकारी में नहीं है। अगर यही सुधार करना चाहते हैं कि हाई स्कूल इतने साल का है, इण्टर चले, बी. ए. चले, तो मैं समझता हूं कि आप लोग समय खराब कर रहे हैं। न तो उस कमेटी का उपयोग है और न शिक्षा में परिवर्तन का उपयोग है। आज स्थिति यह है, उपा-

(श्री रामकिशन)

घ्यक्ष महोदय, कि दुनिया के दूसरे देश शिक्षा के माध्यम से विज्ञान और टैक्नोलाजी के क्षेत्र में आकाश पर जा रहे हैं, वहां हमारे यहां की शिक्षा हमारे नौजवानों को बेरोजगार बना रही है। हम 25 साल में भी उस दिशा की ओर नहीं जा सके हैं। आज मन्त्रीजी अपने जवाब में कहेंगे कि कहां पर कौन सा कालेज खोला गया है कहां पर कौन सा सब्जेक्ट खोला गया है। यह चीज तो आप हमें प्राइवेट में समझा दें, लेकिन सबसे पहले सरकार यह बताये कि आज जिस प्रकार से राजस्थान के नौजवान में जो असन्तोष है, उनके अन्दर जो दूसरी तरह की भावना चल रही है, उनको दूर करने के लिए राज्य सरकार किस तरह से सोच रही है। मैं समझता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि इस सम्बन्ध में मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि हम लोगों के विचारों को आमंत्रित करें उस समय विस्तार से निवेदन करूंगा, लेकिन शिक्षा को जब तक रोजगार के साथ नहीं जोड़ेंगे तब तक हमारे लिए इस शिक्षा-प्रणाली का कोई उपयोग नहीं है सदन में इस प्रकार से शिक्षा पर बहस करना समय खराब करना है। इस सम्बन्ध में केवल इतना ही कहना था एक पृष्ठभूमि के रूप में। विस्तार पर जाना चाहे एक आदमी तो एक सब्जेक्ट पर ही जा सकता है।

एक दूसरा सवाल यह है कि माननीय मन्त्रीजी आपके पास में कई प्रकार की गतिविधियां हैं, जैसे संस्कृत शिक्षा है, म्यूजियम है, उसके बाद आपके पास खेल कूद है। मैं समझता हूं कि शिक्षा मंत्रीजी आप इससे सन्तुष्ट होंगे कि इस साल राजस्थान के शिक्षा विभाग में जितनी गड़बड़ियां हुई हैं उतनी कभी नहीं हुई हैं। राजस्थान में योग्य आदमी का अभाव हो गया है कि वह कमिश्नर, वही सेक्रेटरी और वही डाइरेक्टर आपने जो कदम उठाये हैं इनकी थोड़ी सी प्रशंसा किये देता हूं। आपने जो ऊपर की गड़बड़ थी उसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया। लेकिन उस परिवर्तन से काफी लाभ मिलने वाला नहीं है क्योंकि नीचे से लेकर ऊपर तक मंत्रीजी और स्टेट मिनिस्टर साहब तक इस तरह के मामले को जितनी गम्भीरता से लेना चाहिए उतनी गम्भीरता से नहीं ले पा रहे हैं। मैं कहूंगा कि शिक्षकों में बड़ा असन्तोष है। ट्रान्सफर्स की चर्चा हो गई है इसलिए उसको दोहराना नहीं चाहता हूं। अब के साल जिस तरह की मजाक बनी, जिस तरह के हालात बने वह मुझे अपने 15-20 साल के राजनैतिक जीवन में इस प्रकार के घपले देखने में नहीं आये। मैं समझता हूं कि मेरी दृष्टि में सारी जिम्मेदारी का विकेन्द्रीकरण करके सारी जिम्मेदारी इन्सपेक्टर से लेकर डाइरेक्टर और कमिश्नर को दे दें और मंत्री का काम शिक्षा की नीति में जो वैधानिक परिवर्तन की आवश्यकता आ पड़ी है, वह रहे। हो सकता है कि आपके दो-चार विधायक नाराज हो जायं जो कि ट्रान्सफर की लिस्ट देते हैं। लेकिन नाराज होकर जायेंगे कहां? आपके ही साथ रहेंगे। झक मार कर वहां पर ही रहेंगे। इनसे मत डरो। इन सालों में आप कोई क्रान्तिकारी परिवर्तन नहीं कर सके। इन मामलों में मंत्रीजी दबावों से मुक्त नहीं हो सके तो आगामी साल में आप आ नहीं सकते। अगर आ भी

(श्री रामकिशन)

गये तो उस वक्त हम लोगों का इतना दवाव होगा कि आप कुछ नहीं कर पाओगे। माननीय मंत्री महोदय इस बारे में आप सक्रिय रूप में क्या सोच रहे हैं उसकी जानकारी सदन को दें।

उपाध्यक्ष महोदय, उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य संस्कृत शिक्षा के सम्बन्ध में कुछ निवेदन कर रहे थे। संस्कृत के लिए मेरे दिल में बड़ा सम्मान है।

लेकिन यह एक तरह से ब्राह्मणों की सामन्ती भाषा है। ब्राह्मणों ने अपना साम्राज्य बनाने के लिए इसका उपयोग किया है। आप शिक्षण में इसको जो प्रोत्साहन दे रहे हैं, उसका जो नतीजा निकलेगा, वह देश में खासतौर से ब्राह्मण साम्राज्य स्थापित होगा।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : फिर तो माननीय सदस्य को फायदा होगा।

श्री रामकिशन : आप नहीं समझोगे। आप भी सवर्ण मुसलमान हैं।

संस्कृत अध्ययन की चीज कभी नहीं रही है। मैं जानबूझ कर यह शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। आपको अंग्रेजी का कुछ इस तरह से शौक है कि हरिजनों को आपने जमीन अलाट की है। मुख्य मंत्रीजी की चिट्ठी अंग्रेजी में मेरे पास गई। बच्चे ने बताया कि मुख्य मंत्री की है। अंग्रेजी में है। मैंने कहा रख दो। आप दस्तखत केवल हिन्दी में करते हैं। आखिर अंग्रेजी का मोह राजस्थान में आप क्यों फैला रहे हैं। जो अनुसूचित जाति के हैं या, जन जाति के हैं, उनके अन्दर आप अंग्रेजी इसलिए चलाते हैं ताकि आप ब्यूरोक्रेटिक बने रहें। आपको व्यवहारिक रूप से हिन्दी का प्रयोग करना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, दो बातों के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। वैसे मैं धन्यवाद देता नहीं हूं। एक तो आपने जो अल्प संख्यकों के 500 अध्यापकों के लिए घोषणा की है। वैसे मैं समझ रहा हूं कि आपका उद्देश्य यह नहीं है। आपने जिस दृष्टिकोण से किया है, वह मुझे मालूम है। आपने भाषा की दृष्टि से नहीं किया है। आपने यह वोट की दृष्टि से किया है। चुनाव की दृष्टि से यह किया है। आप इस नाम से भी यह करते हैं तो भी यह ठीक है। हिन्दी और उर्दू यह सभी एक मां की पुत्रियां हैं। जब तक उनका साथ साथ विकास नहीं होगा, हमारी भाषा में लोच नहीं आयेगा। अल्प संख्यकों की भाषा के लिए जो यह आपने किया है, इसके लिए मैं आपकी प्रशंसा करता हूं। दूसरा यह कि आप लड़कियों को भी उसी स्तर पर लाये हैं। मैं तो यह कहूंगा, शिक्षा विभाग एक विनाश करने वाला विभाग है। उसके पास कोई प्रोग्राम नहीं है। कोई प्रेरणा नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, आपके विभाग की समस्याएं बड़ी विलक्षण हैं। इतनी विलक्षण हैं कि आप उनमें सुधार नहीं ला सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने मुख्य मंत्रीजी को चिट्ठी लिखी। शायद आपको मिल गई होगी। आपने ट्रेनिंग के दो स्कूल खोले हैं। एक डीग में खोला है। एक एक लड़के से ××× फिर आपने मान्यता कब दी है। मान्यता दी जा रही है दिसम्बर में। वह लोगों को कहते फिर रहे हैं कि हम तो रुपया देकर आते

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्य विवरण से निकाली गई।

(श्री रामकिशन)

हैं। उपाध्यक्ष महोदय, ×××किसी ने दस्तखत नहीं जिला परिषद् का सेक्रेटरी जो कन्वीनर होता है। उसने भी दस्तखत नहीं किये हैं। वह कहते हैं कि हमने ××× वह वसूल करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, दिसम्बर में मान्यता क्यों दी है। ट्रेनिंग का समय निकल गया है तो कहें कि हम कर रहे हैं। उसमें व्यापक भ्रष्टाचार है। कई केन्द्रीय मंत्रियों की चिट्ठी आई है। उपाध्यक्ष महोदय, श्री उमाशंकर दीक्षित की पुत्रवधू की चिट्ठी पर मान्यता दी जा रही है। मैं केवल इसे संक्षेप में दे रहा हूं। डिटेल में जाऊंगा तो लम्बी बहस हो जायेगी। आज सारे राज्य में यह छाया है। यह मान्यता के बारे में और दूसरे मामलों के बारे में जो चर्चा है, उस चर्चा को दूर करने की मंत्री महोदय की जिम्मेदारी है। दूसरे जैसे जैसे मंहगाई बढ़ेगी, जो टीचर हैं वह मांगें करेंगे। अब कई यूनिवर्सिटी के शिक्षक हैं, उन्होंने परीक्षाओं का बहिष्कार किया है। सारी यूनिवर्सिटीज के शिक्षकों ने नोटिस दे दिया है। वह परीक्षाएं नहीं लेंगे। तो मेरा उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन यह है कि यू.जी.सी. ने जो फैसला लिया है। उसके अनुसार केन्द्रीय सरकार ने, बिहार सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको लागू कर दिया है। आपको 20% ग्राण्ट देनी है। आपको कठिनाई उठाकर भी इस कदम को उठाना चाहिए। टीचर्स के जो पे स्केल हैं, वह वही पुराने हैं, जोकि 10–15 साल पुराने थे। आप उनके लिए कोई कमेटी नहीं बनाते हैं। आप विचार करने का आश्वासन दे रहे हैं। वह विचार कब खत्म होगा, इसकी कोई जानकारी नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, आप ऐसे काम करते हैं जिससे कि लोगों के मन में शक पैदा होता है पिछले साल सेकेण्डरी के हैड मास्टरों के इण्टरव्यू लिये। डी. पी. सी. नहीं बैठी। 21–25 आदमी चुन भी लिये गये। लेकिन उनको कहीं नहीं लिया गया। पब्लिक सर्विस कमीशन ने चयन कर लिया है। लेकिन उनको नहीं लिया गया है। तो कोई शक नहीं करेगा। एडहाक बेसिस पर आप नहीं लेंगे क्योंकि दूसरों को हटायेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, चयन करने के बाद 6–6 महीने से लिस्ट को दबाये रखना और अगर कोई ऊपर का दबाव आ गया तो उसको निकाल दिया। अब इसको बदला जाये। जब आप सम्भालने के लिए आये हैं। आज सारे शिक्षा क्षेत्र में असन्तोष है। विद्यार्थियों में असन्तोष है। मंत्री और राज्य मंत्री को इस बारे में ध्यान देना चाहिए। आज बजट का बहुत बड़ा हिस्सा 73 करोड़ का शिक्षा के लिए प्रावधान है। आप ध्यान नहीं दे पाते हैं। यह राजस्थान की जनता का विश्वास है। आप निश्चित रूप से ध्यान देंगे। ऐसी आशा है। उपाध्यक्ष महोदय, प्राथमिक, माध्यमिक और विश्वविद्यालय की शिक्षा है। जब आप समझते हैं कि दुनिया के दूसरे देशों में शिक्षा के क्षेत्र में क्या प्रयोग हो रहे हैं। उनकी यहां आवश्यकता है। वह अपने यहां परिवर्तन कर रहे हैं। लेकिन आपका वही पुराना ढर्रा चल रहा है। एक बनवारी

×××अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्य विवरण से निकाली गई।

(श्री रामकिशन)
साल है, धौलपुर में। कहते हैं, स्कूल खोले जायेंगे तो जनता बेरोजगार हो जायेगी। मैं तो कहता हूं, शेरगढ़ में हायर सैकेण्डरी खोलना चाहिए। मेरी तरफ से यह प्रस्ताव है। यह हो जाये तो मजा आ जाये। वहां की जनता शिक्षित हो जायेगी। कांग्रेस पराजित हो जायेगी। आप घोषणा तो कुछ करते हैं। दिखाते कुछ हैं। करते कुछ हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में और विस्तार में नहीं जाऊंगा। जो कुछ मामले हैं, उन पर आप गम्भीरता से चिन्तन करें। जो प्राईवेट शिक्षा संस्थाओं की कई बार चर्चा सदन में हुई है मैं उनको दुहराऊंगा नहीं। लेकिन मैं चाहूंगा कि जो आप ग्राण्ट देते हैं तो आप उनसे बदले में क्या लेते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, सैण्ट एंजेला स्कूल का एक छोटा सा मामला है। वहां के दो कर्मचारियों को निकाल दिया। मुख्य मंत्रीजी ने स्टे दिया, हमारे शिक्षा मंत्रीजी की हालत तो यह हो गई है कि उनकी बात कोई मानने को तैयार नहीं है। आप हैं, आप अपनी जैसी स्थिति है, लेकिन सैंट एंजला के प्रबन्धक आपकी बात नहीं मानें तो आप मंत्री कैसे बने हुए हैं, यह मन में नहीं आता कि इसके बजाय तो इस्तीफा दे दें। आपके चाहे डाइरेक्टर हों, डाईरेक्टर माने नहीं आपकी, सचिव माने नहीं, प्रबन्धक मानें नहीं, और आपके घर में भी, शंका है, आपकी पत्नी मानती है या नहीं। मुझे शंका है, मैं पूछना चाहता हूं, प्राइवेट संस्थाओं में कमियों की, व्यवस्थाओं की बात करते हैं उसको आप कैसे दूर कर सकते हैं...

श्री उपाध्यक्ष: इस बारे में भी जवाब चाहेंगे क्या ?

श्री रामकिशन : मुझे अनुमान है, पत्नी भी इनकी नहीं मानती है। मैं कह रहा हूं, कितनी दयनीय स्थिति है।

श्री ओंकारलाल चौहान : माननीय सदस्य ने सवाल उठा दिया है, यह जानते हैं।

श्री रामकिशन : माननीय सुमित्राजी प्रोत्साहित कर रही हैं। आपके पति तो आपकी खूब मानते हैं, मैं ठीक कहता हूं।

तो इन तमाम शिक्षण संस्थाओं को चलाने का दायित्व लिया है यह किस आधार पर लिया है, किस हैसियत से लिया है ?

उपाध्यक्ष महोदय, यह ललित कला अकादमी है, साहित्य कला अकादमी है इनके सम्बन्ध में एक निवेदन करना चाहूंगा, मैं कल नेपाल के भूतपूर्व प्रधान मंत्री डी. पी. कोईराला...

एक माननीय सदस्य : कल !

श्री रामकिशन : उनके यहां किसी वजह से ठहरा। उनके यहां उस समय नेपाल के कुछ नौजवान आये हुये थे। हम नेपाल के सम्बन्ध में चर्चा कर रहे थे। मुझ से जब हिन्दुस्तान के सम्बन्ध में चर्चा हुई तो उनका विरोध प्रकट हुआ। मैंने पूछा कारण, तो उन्होंने कहा, हमारे देश में हिन्दुस्तान अनपॉपुलर होता जा रहा है। मैंने कहा, क्या बात है, नेपाल के विकास के लिए पर्याप्त मदद दी है, हमारा खून का रिश्ता है, सांस्कृतिक दृष्टि से हम एक हैं। उन्होंने कहा, हिन्दुस्तान ने हमारे देश पर सांस्कृतिक अग्रेशन कर दिया है। मैंने पूछा, क्या सांस्कृति अग्रेशन ? उन्होंने कहा, नेपाल में

(श्री रामकिशन)

जनता ने पर्दा रखना शुरू कर दिया है और दूसरे दहेज प्रथा शुरू हो गई है। इसलिए हमारा झुकाव चीन की तरफ ज्यादा है। हिन्दुस्तान का नेपाल पर सांस्कृतिक अग्रेशन चालू होगा, इस बात की नेपाल के नौजवानों के दिमाग में सम्भावना नहीं थी। लेकिन आज नेपाल के नौजवान सांस्कृतिक अग्रेशन से परेशान हैं। हमारे देश में कहीं भी चले जाइये, दिल्ली जाइये, बम्बई जाइये, कलकत्ता जाइये, मद्रास जाइये, और किसी कालेज में जाइये, कहीं हिन्दुस्तान दिखाई देता है, हिन्दुस्तान की सभ्यता, हिन्दुस्तान की संस्कृति, रहन सहन, खान-पान। मैं समझता हूं कि सम्पूर्ण रूप से शिक्षा विभाग से यह काम कराना चाहिए, सांस्कृतिक उत्थान का। आप जानते हैं कि चीन की शक्ति बढ़ी इसका क्या कारण है। वहां चीन ने जो सांस्कृतिक क्रांति की, उसके बाद उसका स्वरूप निखरा है। मैं चीन का प्रशंसक नहीं हूं। उसकी जिस प्रकार की कार्य प्रणाली है, दमन की और जो उनकी विदेश नीति है, उसका मैं प्रशंसक नहीं हूं। मैं प्रशंसक इस बात का हूं कि इस तरह से उन्होंने देश का निर्माण किया है। मैं पूछना चाहता हूं कि आप यह अकादमी लेकर बैठे हैं, इनका कार्य कलाप क्या है। अभी शास्त्री जी कह रहे थे, कत्थक कैसा होता है, आप बताइये। आपके लिए कत्थक और मणिपुरी में क्या फर्क है, आप क्या समझते हैं। और आपके लिए ही क्या, मेरे लिए भी यही बात है। आप सोचिये, ...

एक माननीय सदस्य : बराबर जानकारी है या ज्यादा है ?

श्री रामकिशन : न मणिपुरी का मतलब, न कत्थक का मतलब जानते हैं, मैं भी इस मामले में जानता नहीं हूं। मेरा अभिप्राय है, नेपाल के नौजवान आज इस बात से चिन्तित हैं कि नेपाल के अन्दर दहेज प्रथा शुरू हो गई है। वह इसलिए चिन्तित हैं कि वहां पर्दा प्रथा शुरू हो गई है। मैं पूछना चाहता हूं, हमारे देश की, हमारे राज्य की जो संस्कृति है, जितना हिन्दुस्तान विश्व में प्रतिष्ठित हुआ है, उस संस्कृति को, उस सभ्यता को नष्ट किया जा रहा है। और उसके बाद में सख्ती से किस बात पर कदम लिया जा रहा है। अकादमी के जो कार्य कलाप हैं, उस सम्बन्ध में न कह कर और डाइरेक्टर की चर्चा, क्यूरेटर की चर्चा और म्यूजियम की चर्चा न करके मैं पूछना चाहूंगा, आपने नया विवाद क्यों खड़ा कर दिया। आप चीजों को सम्भाल नहीं सकते हैं, तो आप बिगाड़ने की कोशिश भी मत करियेगा। आदमी राजस्थानी साहित्य के नाम से राजस्थानी भाषा का प्रचार कर रहे है, मैं सही कहना चाहता हूं, मैं राजस्थानी भाषा विरोधी नहीं हूं, लेकिन राजस्थानी भाषा है क्या ? एक डाइलेक्ट को आप भाषा बनाते हैं। यह आपकी नीति है क्या ? फिर ता बृज भाषा, मेवाड़ी, मारवाड़ी भाषा होगी, उदयपुरी होगी, जोधपुरी होगी, शेरगढ़ी होगी, जोधपुरी होगी...

श्री ओंकार लाल चौहान : हाड़ोती !

श्री रामकिशन : क्यों भाषा के विवाद को इस तरह खड़ा करते हैं। हमें जरूरत है, देश के एकाकरण की, देश में एकीकरण

(श्री रामकिशन)

की भावना करना चाह रहे हैं। लेकिन आप जान बूझ कर छोटे स्वार्थ के लिए, जो सवाल हल हो गया है, उसको उठा रहे हैं। राजस्थानी भाषा के ऊपर विश्वविद्यालय में बोलियों को लेकर शोध हो, उसमें अच्छाई आये, उसके साहित्य में वृद्धि हो—हम इसका स्वागत करते हैं। हर बोली है उसमें गुण होते हैं, उनके पीछे जीवन दर्शन होता है। डिंगल की कविताएं और मीरा के पद इस भाषा में आते हैं, उनको पढ़ कर आनन्द का अनुभव होता है, हिन्दुस्तान उनका आनन्द प्राप्त करता है। लेकिन आप इसको भाषा बनाने का प्रयत्न करेंगे तो नया विवाद खड़ा हो जायगा वह इस प्रकार का होगा जो बात हल कर ली है, जो बात गवर्नमेंट ने तय कर ली है उसको उठाने की कोशिश करेंगे। उसको दुबारा उठाने की कोशिश न करें। यह मैं चेतावनी के रूप में कहना चाहता हूं। यह स्थिति पैदा की तो राजस्थान के लिए नया सिरदर्द पैदा हो जायगा और विकास की सम्भावनायें कम होंगी। आपका प्रशासन जिस तरह से राज्य कर रहा है, आप राज्य चला रहे हैं, यह अजीब ढंग का है। उसमें यह मामला खड़ा कर दिया, जो कि मैं समझता हूं, जानबूझ कर खड़ा कर रहे हैं तो आर्थिक सवालों की तरफ से जनता का दिमाग हट कर सेन्टीमेंट्स की तरफ चला जायगा। मैं हमेशा से इसका विरोध करता रहा हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप कमेटी बठाते हैं, एक्सपर्ट कमेटी बैठाते हैं, आपने कोठारी कमेटी बैठायी। क्या उसकी रिकमन्डेशन्स को आप लागू कर रहे हैं? आपके पास में श्रीमाली कमेटी की रिपोर्ट पड़ी हुई है पिछले साल से, उसका क्या हुआ? क्या कमेटी से मामला सुलझ जायगा? आप कमेटी बनाते हैं, आयोग गठित करते हैं, उसकी रिपोर्ट को सही समझते हैं लेकिन जब तक आप उसको लागू नहीं करेंगे तब तक उसका मतलब क्या निकलेगा। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, इन सारी दिशाओं में सोचने के बाद इन सवालों पर विचार करें, जो राज्य के भविष्य के साथ जुड़े हुए हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान में बेरोजगारी है, लेकिन हमारी राज्य सरकार इस हालत में नहीं है, राज्य सरकार के पास ऐसी योजनायें नहीं हैं जिससे सब लोगों को रोजगार दे सकें। एक चीज आप देखेंगे, हमारे राजस्थान में नौजवान बेरोजगार हैं और राजस्थान में साक्षरता की कमी है। दोनों स्थिति को, समझ कर सरकार थोड़ा बहुत वजीफा बेरोजगार नौजवानों को साक्षरता के प्रसारण के लिए लगा सकती है। दुनिया के कई देशों में इस प्रकार के प्रयोग हुए हैं। हम नहीं कहते कि आप परमानेन्ट टीचर्स अपाइन्ट करिये। लेकिन साक्षरता के प्रसारण के लिए और निरक्षरता का निवारण करने के लिए ऐसे नौजवान, जो ट्रेंड बैठे हैं या अनट्रेंड बैठे हैं, उनको थोड़ा बहुत वजीफा देकर लगायें, उनको दो साल की गारन्टी दे दें और साक्षरता के प्रसार में उनका रिजल्ट अच्छा रहे तो उनको सरकारी नौकरी मिल जाय। तो आप तमाम गांवों में बहुत बड़ा काम साक्षरता का कर सकते हैं। लेकिन आपका विचार ऐसा नहीं है। आपने पढ़े-लिखे नौजवानों को वजीफा देना शुरू किया, इंजीनियर वालों के लिए, मेडिकल वालों के लिए वजीफा देना शुरू किया, और

(श्री रामकिशन)
बेरोजगार इंजीनियर और डाक्टरों को वजीफा दिया जा रहा है। यह ठीक है लेकिन आप जानते हैं कि इंजीनियर जिनके लड़के होते हैं, डाक्टर जिनके लड़के होते हैं, आज की समाज व्यवस्था है, उसमें 75 पर्सेन्ट वह लोग हैं, जो सम्पन्न हैं, उनकी हालत ऐसी है कि वह अपने लड़कों को डाक्टर और इन्जीनियर बना सकते हैं। 75 परसेंन्ट आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न लोगों के लड़के हैं, जिन्होंने पढ़ लिखकर डिग्री हासिल कर ली और वजीफा प्राप्त कर लिया है। लेकिन आर्ट साइड के लोग हैं, आर्ट साइड में लिट्रेचर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और दूसरे विषय में डिग्री हासिल किये हुए लोग हैं, मैं चाहता हूं कि उनके बारे में सोचने की कोशिश करें। अगर नहीं करेंगे तो इस तरह भेदभाव करेंगे। सारे बेरोजगार हैं, उनमें से कइयों को वजीफा दें, और कइयों को नहीं दें, किसी वर्ग को पकड़ लें और किसी को छोड़ दें–इससे वर्ग संघर्ष पैदा होता है। आज जो ला कालेज के छात्र मांग कर रहे हैं, वह अनुचित नहीं है। उनकी लाइब्रेरी के लिए, दूसरी तरह उनके प्रोत्साहन के लिए कोई न कोई व्यवस्था करनी चाहिए। इन समस्याओं के ऊपर आंख मूंद कर नहीं चल सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह पब्लिक स्कूल का मामला है, राजस्थान में यह नहीं सुलझ पा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आप पढ़ कर जवाब देना, खेतसिंह जी मैं निवेदन करूंगा, आप पढ़ समझ कर जवाब देना, क्या दुनिया के किसी देश में पब्लिक स्कूल चलते हैं? पब्लिक स्कूल से समाज की कौनसी गरिमा की प्रदर्शन करते हैं क्या इस से समाजवाद लायेंगे, समता का समाज बनायेंगे। आप ऐसे बच्चे जरूर पैदा कर रहे हैं इस देश में, जिनकी साधारण नागरिक से बहुत अधिक दूरी होगी। वह आपके इस जनकल्याणकारी राज्य में सहायक नहीं हो सकते, वह इसका विरोध करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, क्या एक झटके में आप पब्लिक स्कूल्स को बन्द नहीं कर सकते? जिन सरकारों ने, जिन देशों ने तरक्की की हैं, वहां राष्ट्रपति से लेकर मेहतर तक का लड़का साधारण स्कूल में पढ़ता है। इससे जनता में और स्कूल के बच्चों में समता का दर्शन, समता की मनोवृत्ति पैदा होती है। आप हरिजन और पिछड़े हुए वर्ग के कल्याण की बात करेंगे, लेकिन आप समाज का गठन जिस तरह कर रहे हैं, नेतृत्व के लिए जिन लोगों को तैयार कर रहे हैं उससे ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं, जिसके कारण जो समाज व्यवस्था के लिए कोशिश कर रहे हैं, वह समाज व्यवस्था कभी नहीं आयेगी, हमारे देश में कभी नहीं आयेगी। मैं निवेदन करूंगा कि पब्लिक स्कूल, प्राइवेट स्कूल की ग्रान्ट इन एड के बारे में मन्जूरी के नियम बनाये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, राजाशाही समाप्त हो गई, सामन्त सामाप्त हो गये, लेकिन खेतसिंह नये सामन्त हैं, नये सामन्त, वह इस मामले में अधिकारों को देना नहीं चाहते हैं। पहले जागीरदार ऐलान करते थे, हम प्रसन्न हो गये हैं इसलिए पांच रुपये का इनाम देते हैं। खेतसिंह नये सामन्त बने हैं, यह डेमोक्रेटिक सामन्त हैं, मैंने इनको चिट्ठी लिखी, आपके हाथ में ग्रान्ट देने का अधिकार है आपने पूर्वी क्षेत्र में कहां ग्रान्ट दी है। आप ताज्जुब करेंगे, मेरी चिट्ठी का जवाब नहीं दिया। या तो समझ में चिट्ठी आई नहीं या जवाब देने की जरूरत नहीं समझी, या मन्शा नहीं थी, या चिट्ठी

(श्री रामकिशन)

को पढ़ नहीं सकते। यह ग्रान्ट देने का तरीका, अधिकार अपने हाथ में रखा है, मैं पूछना चाहता हूं कि पूर्वी क्षेत्र में ग्रान्ट दी है। आपने किस स्कूल के लिए ग्रान्ट दी ? कभी जोधपुर में एलान कर आये, किसी विधायक से आपको स्वागत मिला, किसी ने भोजन कराया, दो एक हजार रुपये उसको। हम चाहते हैं कि इन सब चीजों के लिए कोशिश करें कि आपका, मन्त्रियों का आचरण ऐसा न हो कि आपको केवल शेरगढ़ से, या भरतपुर से या धौलपुर से सम्बन्ध है। आप सारी शिक्षण संस्थाओं के नेता हैं। आप अपने आचरण से औरों को प्रेरणा देंगे लेकिन आपकी स्थिति यह है कि 2–4 स्कूलों को पैसा देंगे, यह उचित काम है ? हमारे पत्रों का जवाब नहीं देना, क्या आपकी शालीनता है ? आप कहेंगे आपको पत्र नहीं मिला है। मैंने उसमें सुझाव दिये थे कि ऐसा मत करो। हम लोग आपके दरवाजे पर हर सुबह को खड़े हो जायं, वह स्थिति हमारी नहीं है। हम इसलिए आपके पास नहीं आना चाहते क्योंकि आप व्यस्त व्यक्ति हैं, क्योंकि आपके पास कई लोग ट्रांसफर वगैरह की सिफारिश लेकर पहुंच जाते हैं, तो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि कैसे आपसे बात करें। लेकिन कम से कम ऐसा नियम बनायें कि शिक्षा अधिकारियों पर भरोसा न करें। जैसे आपने शिक्षा आयुक्त को बदल दिया, बढ़िया किया। उसमें भी आप जैसा ही दोष था। कभी शिक्षा मन्त्री को फोन करें घर पर तो जवाब मिलेगा कि वह नहीं है कहां गये ? स्नानाघर या संध्या या पूजा। इन तीन जवाबों के अलावा और कोई जवाब नहीं। खेतसिंहजी, आप संध्या की बात कहलवाते हैं, आप एक श्लोक भी बोल सकते हैं ? इसका सीधा मतलब है कि आप अपने कर्मचारियों के मारफत झूठी सूचनायें देते हैं। ऐसे ही जब आपके आयुक्त सूद साहब को फोन करते थे तो जवाब मिलता था कि वह बाहर हैं या पूजा में हैं। तीसरा जवाब नहीं। मैंने सेंट एंजला स्कूल के बारे में संपर्क स्थापित करने की कोशिश की। मुख्य मंत्री अवेलेबुल हो गये, आप होते हुए भी न मिल सके। आप कह सकते थे कि सेंट एंजला वाले आपकी बात को नहीं मानते हैं तो आपकी मजबूरियों को मैं समझ सकता था लेकिन आपका जो व्यवहार होना चाहिए वह आदर्श होना चाहिए। आप 20–30 साल राज कर चुके हैं, आपने राज की सारी प्रणाली सीख ली है। लेकिन जो अच्छाइयां सीखनी चाहिए, उसके लिए आपने कोशिश नहीं की है। और बातों के लिए तो कभी मिलने और बैठने पर करेंगे लेकिन दो तीन चीजें ऐसी हम चाहते हैं जिनके बारे में अभी घोषणा करनी चाहिए। जो स्कूल्स और कालेजिज खोले हैं आपको अधिकार हैं, राज्य सरकार को अधिकार है लेकिन क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ रहा है, आप स्कूल खोलें तो हर जिला परिषद् से लिस्ट मंगायें उसके भीतर भी क्षेत्रीय असंतुलन न हो। मैं नहीं कहता कि मंत्री को अधिकार नहीं है। 4–5 जगह यदि आप विशेष रूप से इन्टरेस्टेड हैं तो खोलें लेकिन ऐसा मत करें जैसे पिछले साल आपने स्कूलों की घोषणा की। स्कूल खोल दिए ज्यादा, घोषणा की कम की। आपने लोगों से पैसा जमा करवा लिया और उनका पैसा वापस लौटा दिया तो यह सरकार का आचरण बहुत ही खराब है और इसको सरकार को बदलना चाहिए।

(श्री रामकिशन)

मैं शिक्षा मंत्री से नियुक्तियों के संबंध में और विशेष कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन शिक्षा विभाग ने जो मेरिट का सिलसिला शुरू किया है, इसमें सिफारिश का प्रभाव कम से कम हो गया है। यह अच्छी शुरूआत है लेकिन आप देखेंगे कि मेरिट के अन्दर जो तरह तरह के खेलकूद के सर्टीफिकेट्स और दूसरी एक्टिविटीज को भी शामिल कर दिया जिनको निकालना चाहिए। चाहे मेरा लड़का हो चाहे मुख्यमंत्री का, नम्बर्स के आधार पर लेना चाहिए। अगर सारे सर्टीफिकेट्स की छूट देते हैं तो घोटाला होता है। भरतपुर जिले में ऐसे 10-12 केसेज हैं जहां थर्ड डिविजन वाले लिए गये हैं और प्रथम श्रेणी वाले रह गये क्योंकि उन्होंने गलत सर्टीफिकेट्स पेश कर दिए। इसमें थोड़ी और कड़ाई बरतें।

एक बात और है जिससे आपका सीधा सम्पर्क नहीं है लेकिन रोजगार के मामले में कुछ मापदंड तय करना पड़ेगा कि रोजगार देते समय किसको प्राथमिकता देंगे? आप बेरोजगारी का उन्मूलन नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास इसके लिए कोई योजना नहीं है। हिन्दुस्तान ही ऐसा देश है जहां नदियों में पानी है फिर भी इंजीनियर बेरोजगार हैं। अमेरिका में बेरोजगारी के कारण हैं क्योंकि वहां विकास इस हद तक पहुंच चुका है कि जहां नहर, बिजली, सड़क इत्यादि की संभावना ही नहीं है। विकास का स्तर ऐसे बिंदु पर पहुंच चुका है लेकिन भारत में, राजस्थान में पढ़े लिखे इंजीनियर हैं, चाहे इससे शिक्षा विभाग का संबंध नहीं है लेकिन राज्य सरकार को सोचना चाहिए कि जब नदियों में पानी है, इंजीनियर बेरोजगार हैं तो कौनसी योजनायें बनायें जिनसे खेत को पानी मिले। हमारे बजट की हालत बुरी नहीं है, जितना पैसा आपके डिसपोजल पर है, 5 अरब रुपये खर्च करने जा रहे हैं इसके अलावा केन्द्रीय सरकार की योजना है तो सारे विभागों में कोआर्डिनेशन हो, समीकरण होने के बाद इस तरह की योजना चालू करें जिसमें राज्य का कल्याण हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं शिक्षा मंत्री से चाहूंगा कि जो कुछ कान्क्रीट काम करते हैं वह करें।

क्रीड़ा परिषद् आपने क्या बना रखी है? यह कोई आपकी और काक साहब की जागीर है? क्योंकि आप और काक साहब दोनों जोधपुर से संबंध रखने वाले हैं तब तो मुझे कुछ नहीं कहना है। जो इस परिषद् के आडिट रिपोर्ट्स आये हैं उन पर मैं चर्चा नहीं करता लेकिन वह पाइंट्स आपके नोटिस में आई हैं खेलकूद परिषद् का जिस तरह से विस्तार होना चाहिए, जिस तरह से उसे नौजवानों को तैयार करना चाहिए, वह कर पा रही है? आप देखेंगे कि क्रीड़ा परिषद् असफल रही है। इस प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने का सवाल है, केवल पैसे के रूप में ही नहीं। उपाध्यक्ष महोदय यहां से जिस तरह से कोटा की टीम, भरतपुर की टीमें थी, उस समय वातावरण था, यहां के लोग बढ़िया खिलाड़ी थे लेकिन आज हालत यह है कि शिक्षा में फिसल गए, सांस्कृतिक प्रवृत्तियों को लें चाहे खेलों के मामले में आप किसी राज्य का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। तो अब इन प्रवृत्तियों पर जोर देने की कोशिश करें। हमारी संस्कृति का पतन हो रहा है उसको रोकने के लिये क्या कोशिश कर रहे हैं?

Page No 78

(78)

श्री रामकिशन)

मैं स्कूलों व कालेजों में किसी प्रकार की ड्रेस या पहनावे की सिफारिश नहीं करता लेकिन कालेजों में, मैं जे. पी. को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो नौजवान गलत दिशा में जा रहे थे, वे क्रांति के रास्ते पर जा रहे हैं संघर्ष की राजनीति को अपनाया है। मैं राजस्थान विश्वविद्यालय में कामर्स फैकल्टी में बोल रहा था मैंने छात्रों की शक्लें देखीं, तो मुझे मालूम होता था कि यह राजस्थान नहीं है यह तो नारवे, स्वेडन, डेनमार्क है। उनका पहनावा, सिगरेट पीने का सिलसिला और मैं क्या कह सकता हूं। तो शिक्षा मंत्रीजी, आप शिक्षा मंत्री रहे या नहीं लेकिन अब सांस्कृतिक क्रांति के लिए इस देश को तैयार करें, जो आज देश में वातावरण बन रहा है वह इसमें सहायक बनेगा। अंत में इतना ही कहता हूं कि जो आपने कमेटी नियुक्त की है शिक्षा में परिवर्तन के लिए और प्रधान मंत्री भी कह रही हैं, इस सम्बन्ध में कई तरह के विचारों का आदान प्रदान हुआ है। विद्वानों को आपने उसमें रखा है और कहीं से भी विद्वान ला सकते हैं जो आज की हालत में बेरोजगारी इत्यादि के बारे में सुझाव दे सकें चाहे वे राजस्थान के बाहर के हों। लेकिन कमेटी का लम्बा मामला नहीं चलना चाहिये साल भर सिटिंग्स होती रहें, जल्दी से जल्दी अपनी रिपोर्ट दे, उससे राजस्थान के नौजवान के मन में जो निराशा है वह जायेगी। मैं मंत्रीजी से भी चाहूंगा कि वह अपने विभाग में सुधार लाने की कोशिश करें।

श्री उपाध्यक्ष (श्री ओंकार लाल से) : अगर आपकी इजाजत हो तो पहले नाहर साहब को बोलने दें? उनको भीलवाड़ा जाना है।

श्री ओंकार लाल चौहान : ठीक है।

श्री यशवंत सिंह नाहर : उपाध्यक्षजी, मैंने भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य का भाषण सुना। वह मंत्रीजी का स्नान घर में होने की बात कर रहे थे। लेकिन मैंने तो मंत्रीजी को स्नान घर की जगह बाथरूम में ही पाया। बाथरूम का मतलब वह टट्टी जाने की जगह है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 6 बजे से लेकर 10-11 बजे तक उनको छोड़ दिया जाए, तो अधिकांश लोग बाथरूम में बैठना ही पसंद करते हैं। विधान सभा या सेक्रेटरियट का कमरा अच्छा नहीं लगेगा उनको। मैं भीलवाड़ा किसी कारण गया था, मेरे बच्चे ने पूछ लिया कि आज मंत्री जी आ रहे हैं, ये लड़कियां क्यों खड़ी की हैं, कलश और आरती क्यों मंगा रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आया कि उसने यह सवाल क्यों किया? मैंने कहा कि यह तो राजस्थान की संस्कृति है। वह कहने लगा यह राजस्थान की संस्कृति कहां है यह तो सामन्त की संस्कृति है, चाहे आप इसको समाजवाद कहें। बच्चे ने कहा कि यह कौनसा जनतन्त्र है, यह तो सामन्ती प्रथा है यह तो समाजवाद नहीं हो सकता। तो मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे बच्चे किस दिशा मे जा रहे हैं, हम उनको किस ओर ले जा रहे हैं, लोकतान्त्रिक समाजवाद में या पूंजीवादी अमरीकी देशों की तरफ या सामन्ती प्रथाओं की तरफ या ब्रिटिश

(श्री यशवंतसिंह नाहर)

गवर्नमेन्ट की प्रथाओं की श्रेणी में या सामन्ती शासकों की उसी श्रेणी में, आखिर हम कहां ले जा रहे हैं, हमारी शिक्षा किस प्रकार की हो रही है। यह ठीक है राज के ठाठ बाट किसको अच्छे नहीं लगते परन्तु गलत प्रथाओं की तरफ तो बच्चों को नहीं ले जाना चाहिए। इसलिए मैं शिक्षा मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वह सामन्ती संस्कृति और आज की शिक्षा उसका सन्तुलन करके जवाब देवें। मैं तो इस नतीजे पर आया हूं कि आखिर इसको बन्द कराने की ओर क्या प्रयत्न होने चाहिए। मुझे यह नहीं लगता कि यह कोई समाजवाद का विकास हम इससे करने जा रहे हों। अब दूसरी बात, राजस्थान में, हिन्दुस्तान में किसी भी रियासत से अगर शिक्षा मन्त्रीजी आयेंगे तो यही बात कहेंगे कि शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए। इसमें किस प्रकार की कठिनाइयां आयेंगी, यह बातें संस्कृति का दावा करने वाले करते होंगे। पब्लिक स्कूल वाले कभी यह नहीं सोचते कि हमारी शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए, यह बात शिक्षा मन्त्रीजी को मालूम होना चाहिए। यह मेरी समझ में नहीं आता कि शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करने की बात पब्लिक स्कूल वाले तो नहीं करते जहां पर अमीरों के लड़के पढ़ने के लिये जाते हैं। अभी भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य भी कह रहे थे, पब्लिक स्कूलों में उच्चाधिकारियों के लड़के पढ़ते हैं जिनके हाथों में शासन सत्ता चल रही है उनके बच्चे पढ़ते हैं। दिल्ली का वेलिंग्टन कालेज है उसका 25 प्रति. कोटा आई. ए. एस. के लिये रिजर्व है। अब आप मुकाबला करिये पब्लिक स्कूल में पढ़ने वालों का और गांव के बच्चों का जहां पर एक ही कमरे में पांच पांच क्लासेज लगती हैं। क्या वह आर. ए. एस. और आई. ए. एस. पैदा कर सकेंगे। भूले भटके से कोई क्लर्क बन जायेंगे या ज्यादा से ज्यादा बी. ए. या एम. ए. होंगे। इसलिए मेरी मान्यता है कि जब तक बच्चों को, आपके कोर्स में तो कोई कमी नहीं है, मैं यह नहीं कहता कि आप उसको किसी धार्मिक स्कूल में और धर्म की शिक्षा के लिए भेजो, वह तो होना ही चाहिए, परन्तु मैं एक ही बात मानकर चलता हूं कि शिक्षा का उद्देश्य जीवन का कोई आधार होना चाहिए जिससे पढ़ने के बाद अपना जीवन यापन कर सके। आज जिधर देखो, कहीं सांई बाबा हो गया तो कहीं आचार्य रजनीश परमेश्वर हो गये।

एक माननीय सदस्य : उनका प्रमोशन हो गया।

श्री यशवंतसिंह नाहर : प्रमोशन नहीं, भगवान का लोकतन्त्रीकरण हो गया, उसका विकेन्द्रीकरण हो गया। इसलिए मेरा निवेदन है कि अगर हम चाहें तो आज गांव का एक एक स्कूल पब्लिक स्कूल बन सकता है लेकिन वह तभी हो सकता है जबकि हमारे बच्चों को अगर सही ढंग से पढ़ने का मौका मिले। बच्चे स्कूलों में पूछते हैं मास्टर साहब, यह क्या है, आबू पर्वत क्या होता है तो उनको शुरू से ही सही शिक्षा दी जानी चाहिए तभी हम आगे बढ़ सकेंगे और उनके जीवन में सुधार ला सकेंगे। हमारे भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था, वह तो जिला प्रमुख भी हैं, और

(श्री यशवंतसिंह नाहर)

मैंने लगभग पांच हजार बच्चों का इन्टरव्यू लिया है। कुछ बच्चों को छोड़कर उनको यह मालूम नहीं है कि गंगा कहां से निकलती है। कई लड़के उनमें बहुत पढ़े हुए होंगे, कोई मैट्रिक, कोई बी. ए. और कोई एम. ए. पास हो जाते हैं, मगर उनको छोटी छोटी बातों का भी पता नहीं है। यही हाल कालेजों के 99 प्रतिशत बालकों का है। एक बात और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज कल लड़कों में पीछे बाल बढ़ाने की बहुत आदत एक फैशन हो गई है।

एक माननीय सदस्य : उनको हिप्पी कहते हैं, हिप्पी मीन्स हैपी।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : आज हम इतने दकियानूसी विचारों के हो गये हैं कि हम आज से 25 सौ वर्षों पीछे समाज को ले जाना चाहते हैं। एक नया लोकतन्त्र का निर्माण कर रहे हैं, ये कोई नये ईसामसीह आ गये हैं। इन सबके पीछे इसका एक मूल कारण यह है कि हमारी शिक्षा पद्धति में सही शिक्षा का अभाव है, हम उनको सही शिक्षा नहीं देने जा रहे हैं। इसलिए हमको उनको इस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिये जिससे उनको जीवन में सुधार आवे, जिससे उनका भावी जीवन सुखी हो सके और उनके नैतिक मूल्यों का सुधार हो सके आज अगर हम यह दावा करें कि हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली विद्यार्थियों में नैतिकता का स्तर ऊंचा करती है तो मेरी मान्यता है कि यह गलत है। आज गांवों के जो प्राईमरी स्कूल हैं और शहरों में जो स्कूल हैं उनमें बड़ा भारी अन्तर है। एक बार मुझे एक टूर्नामेंट में जाने का अवसर मिला। भीलवाड़ा की टीम थी और एक गांव की लड़कों की टीम फुटबाल खेलने आई थी। उन दोनों का मुकाबला होना था। गांव वालों से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने तो फुटबाल देखी ही आज है। तो इस तरह की उनकी हालत है आज हमारे गांवों में। लड़कों को प्रारम्भ में हम जितना दे पायेंगे वही उनके भविष्य में काम आने वाला है। इसलिए आप आमूलचूल परिवर्तन की बात तो छोड़िये पहले प्रारम्भिक शिक्षा की बात कीजिये यह तो फिर देखेंगे। इन शब्दों के साथ उपाध्यक्ष महोदय, मैं क्षमा चाहता हूं, आपने मेरे निवेदन करने पर मुझे समय देकर मेरी प्रार्थना को स्वीकार किया।

श्री ओंकारलाल चौहान (डग) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में शिक्षा की मांगों पर बहस चल रही है उस पर मैंने भी कटौती प्रस्ताव दिये हैं उनके संबंध में भी कुछ निवेदन करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय आज सारे हमारे हिन्दुस्तान में सभी जगह यह चर्चा चल रही है कि शिक्षा की बुनियादी नीति क्या हो। शिक्षा में किसी प्रकार का परिवर्तन करने की आवश्यकता है क्या और अगर परिवर्तन करने की आवश्यकता है तो वह किस प्रकार का परिवर्तन किया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारा देश आजाद हुए 27 साल गुजर गये हैं लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि हम अभी तक यह तय नहीं कर पाये कि हमारी बुनियादी शिक्षा का आधार क्या होना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे सामने हमारी शिक्षा की नीति तय नहीं होने के कारण और शिक्षा के अन्दर दूषित प्रणाली की वजह से आज हमारा कोई वर्ग सन्तुष्ट नहीं है। आज हमारा युवा वर्ग

(श्री ओंकारलाल चौहान)

असन्तुष्ट हैं। और मैं तो यह कहूंगा कि इस शिक्षा प्रणाली से कोई सन्तुष्ट नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारी इस समस्या के लिये न केवल राज्य सरकारें ही बल्कि हमारी भारत सरकार भी इसके लिये चिन्तित है। वैसे तो उपाध्यक्ष महोदय, हमारी शिक्षा की नीति के लिये राधाकृष्ण कमीशन, सन्थानम कमीशन और कोठारी कमीशन बैठा था लेकिन आज भी 27 साल हमारे देश को आजाद होने के बाद कोई नेशनल कोन्सेन्सियस उभर कर नहीं आयी। इसमें हम यह भी तय नहीं कर पाये कि कौनसी पद्धति शिक्षा की अच्छी है। ऐसी कौनसी पद्धति उपयोगी हो सकती है कि जिससे कि हमारा देश आगे बढ़ सके और हमारे देश के बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। उपाध्यक्ष महोदय जिस प्रकार कृषि हमारी देश की रीढ़ की हड्डी है जिस पर हमारा जीवन यापन निर्भर है उसी तरह हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए देश का विकास करने के लिये हमारे देश के नौजवानों का भविष्य उज्जवल करने के लिये शिक्षा भी उसकी रीड की हड्डी है। लेकिन आज यह बड़े खेद का विषय है कि इतने समय गुजर जाने के बाद भी हम इस विषय पर अन्तिम निर्णय नहीं कर पाये हैं कि हमारी शिक्षा की पद्यति कौनसी हो। अभी एक दो दिन पहले शिक्षा मन्त्री जी ने एक प्रश्न के जवाब में कहा कि हम यह सोच रहे हैं कि थर्ड इयर कोर्स की बजाय मैट्रिक, फर्स्टईयर सेकिन्ड ईयर, थर्ड ईयर और बी. ए. की प्रणाली को रखें। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह सुनकर बहुत ही दुख हुआ कि हम कितने पिछड़े हुए हैं कि अभी भी 27 साल आजादी के गुजर जाने के बाद भी यही करने जा रहे हैं जो पहले प्रणाली मैट्रिक, फर्स्ट ईयर और बी. ए. तक जिस प्रकार पढ़ाई होती थी उसी प्रकार हो। आज हम हमारे देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं दूसरी तरफ उसी 27 साल पुरानी पद्धति को आप वापस ला रहे हैं। इन सालों में आप यह भी तय नहीं कर पाये कि आपकी शिक्षा की प्रणाली का आधार कौनसा सही है। कौनसी पद्धति से आपने अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित और उज्ज्वल समझते हैं। वह बच्चे जो आगे जाकर देश का निर्माण करेंगे, जो आगे जाकर देश की बागडोर सम्भालेंगे। जिनको हम अपने देश को आगे बढ़ाने के लिये भागीदार बनाना चाहते हैं जो देश के कर्णधार हैं जिनके हाथ में अपने देश का भविष्य उज्ज्वल होगा। आप उनके लिये शिक्षा की कोई निश्चित नीति निर्धारित नहीं कर पाये। अभी भी उपाध्यक्ष महोदय, हमारी राज्य सरकार ने शिक्षा की नीति के बारे में एक कमेटी बैठा रखी है जो इस सारी बातों पर विचार कर रही है। मैं मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस कमेटी को चाहिये कि वह सभी मुद्दों पर विचार करके इस सम्बन्ध में जल्दी से जल्दी निर्णय लें। यह पद्धति ऐसी होनी चाहिये कि जिससे कि हमारे यहां पर बेरोजगारी हटे और हमारे देश का विकास हो। उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो तीन सुझाव देना चाहूंगा। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जैसा कि पहले मैंने निवेदन किया कि शिक्षा हमारी रीढ़ की हड्डी है। इसलिये इसको हमें मजबूत करना चाहिये। पर उपाध्यक्ष महोदय, आज तक असलियत तो यह है कि हम इस बीमारी की जड़ को नहीं पकड़ पाये हैं।

(श्री ओंकारलाल चौहान)

उपाध्यक्ष महोदय, इस बीमारी की जड़ हमारे शहरों में नहीं है बल्कि यह जड़ हमारे ग्रामीण क्षेत्रों की प्राईमरी एजूकेशन के अन्दर जो टीचर्स हैं, वह है। जहां कि हमारे बच्चे अपने जीवन का पहला अध्याय शुरू करते हैं। आज आप इस बीमारी की जड़ को ढूंढ रहे हैं विश्वविद्यालयों में, कालेजों और हायर सेकेन्डरी स्कूलों में। आज आप हायर सेकेन्डरी स्कूलें बढ़ा रहे हैं कालेजेज बढ़ा रहे हैं कालेजों में सब्जेक्ट्स बढा रहे हैं उसके लिये तो आप धन्यवाद के पात्र हैं पर केवल कालेजेज खोलने से और स्कूलों के खोलने से लोगों को चाहे थोड़ा बहुत आप सन्तोष दिला सकते हैं। कुछ सबजेक्ट्स नहीं हों वहां पर सबजेक्ट्स बढ़ा कर थोड़ा सन्तोष दिला दें पर यह तो कोई उसका उपाय नहीं हुआ यह तो सिर्फ चेपा चेपी हुई। इससे हमारे देश का भविष्य उज्ज्वल नहीं हो सकता इससे हम आगे थोड़ी बढ़ पायेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब तक हमारा ग्रामीण स्तर में सुधार नहीं आयेगा जब तक हमारे ग्रामीण क्षेत्र की प्राईमरी स्कूलें और प्राइमरी स्कूलों के टीचर्स की हालत आप नहीं सुधारेंगे तब तक मैं समझता हूं कि आपके देश का भविष्य उज्ज्वल नहीं हो सकता। आज मैंने आपके प्रगति विवरण शिक्षा विभाग की रिपोर्ट देखी, उसमें आपने बताया कि इतने स्कूलों का नया निर्माण किया, इतनों को आप ग्रेड किया और इसमें कुछ ग्रेड्स आपने बताये इसमें 700 से 1200 के ग्रेड बताये और दूसरे ग्रेड्स बताये आपने इन सभी का ग्रेड तो सुधार दिया, लेकिन क्या कभी आपने अपने प्राईमरी स्कूल के ग्रेड के बारे में सोचा, क्या आपने उसकी समस्याओं के बारे में सोचा जो कि आपके द्वारा प्राईमरी एजूकेशन दिलाते हैं। कितनी डिसपेरिटी है आपके दूसरे ग्रेड्स के टीचर्स में और प्राईमरी स्कूल के टीचर में। ऐसी स्थिति में वह प्राईमरी स्कूल का टीचर क्या शिक्षा देगा आपके बच्चों को जो कि अपनी समस्याओं में ही उलझा रहता है जिसका आगे कोई भविष्य उज्ज्वल नहीं। इसलिये मैं शिक्षा मन्त्री को निवेदन करना चाहता हूं और एक संकेत देना चाहता हूं चेतावनी के रूप में अगर आपने इन लोगों की हालत नहीं सुधारी तो इसके परिणाम ठीक नहीं होंगे। आज उन लोगों में भयंकर आक्रोश है। उनका बेचारों का गुजारा तक नहीं होता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा और पुरजोर शब्दों में निवेदन करूंगा कि आप चाहे विश्वविद्यालय बन्द करदें, चाहे कालेजेज नहीं खोलें, नई हायर सैकेन्डरी स्कूलस खोलने की आवश्यकता नहीं है पर पहले उन प्राईमरी स्कूल के टीचर्स का जीवन स्तर ऊंचा करने के लिये विचार करें। अगर आप उनका स्तर ऊंचा करेंगे तो जरूर आपके बच्चों का भविष्य उज्ज्वल होगा। आप के बच्चे ज्यादा होशियार होंगे और देश को आगे बढ़ाने में सफल होंगे।

दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहूंगा उपाध्यक्ष महोदय, वह है पब्लिक स्कूल्स के बारे में जैसा कि अभी माननीय सदस्य श्री रामकिशनजी ने कहा आपने हिन्दुस्तान में पब्लिक स्कूल्स की वजह से इंगलिस्तान कर रहे हैं। यह बात बिलकुल सही है। आज आप हमारे यहां जो प्राईवेट स्कूल्स हैं उन्हें जो एड देते हैं वह पब्लिक स्कूल्स के मुकाबले बहुत कम देते हैं। आज

(श्री ओंकारलाल चौहान)

पब्लिक स्कूल्स में लाखों रुपये की एड आप देते हैं। यह डिसपेरिटी क्यों है? तब सवाल पैदा होता है इसलिये कि आज वहां पर आपके बच्चे और आई. ए. एस. और आई. पी. एस. आफिसर्स के बच्चे और प्रधान मन्त्री और राष्ट्रपति के बच्चे पढ़ते हैं इसलिये आप इन पब्लिक स्कूलों को प्राईवेट स्कूलों से कई गुना अधिक एड देते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आज जो बच्चा पब्लिक स्कूल से निकल कर आता है और जो प्राईवेट स्कूल्स से या ग्रामीण क्षेत्र की स्कूल्स से पढ़कर निकल कर आता है तो उसके मन में थोड़ी हीन भावना होती है, वह अपने आपको पब्लिक स्कूल के पढ़े हुए बच्चे से हीन समझता है। इसका कारण आपने डेसपेरिटी रखी है उन दोनों के बीच में इसलिये मेरा निवेदन यह है कि यह हीनता की भावना पैदा नहीं हो एक इन्टीग्रेशन होना चाहिए ताकि आने वाले वक्त में इन बच्चों के मनमें हीनता की भावना नहीं वरना इस तरह से आने वाले समय में हमारे प्रान्त में ही नहीं बल्कि पूरे हिन्दुस्तान में खतरा पैदा हो जायेगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि इन पब्लिक स्कूलों को बिलकुल बन्द किया जाना चाहिये इन्हें बिल्कुल प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिये आपको ऐसे नियम बनाने चाहिए कि इन पब्लिक स्कूलों को कोई भी एड नहीं दी जावेगी अगर इनको विना एड के स्कूलों को चलानी हो तो चलावें अन्यथा इनको बन्द करदी जावे। आज आपके सोफिया, सेन्ट जेवियर वगैरह जितनी भी मोटी मोटी स्कूल्स हैं उनको राज्य सरकार हर साल लाखों रुपयों की एड देती है अगर यह मदद हमारे ग्रामीण क्षेत्र में प्राईमरी स्कूल्स में दी जाय तो उचित होगा। अंग्रेजों ने ढाई सौ साल तक हमारे ऊपर राज्य किया उनकी एजूकेशन की निशानी को आप आज भी कायम रख रहे हैं जब कि हमें आजाद हुए 27 साल हो गये हैं। आज भी आप इनको वढावा देकर उन अंग्रेजों की शिक्षा पद्धति को वढावा दे रहे हैं उनके अंकुर पैदा कर रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि मन्त्री महोदय इस ओर ध्यान दें।

मैं उपाध्यक्ष महोदय यह निवेदन करना चाहूंगा कि मन्त्री महोदय को चाहिए इस बारे में शिक्षा पद्धति के बारे में शिक्षा शास्त्रियों से विचार विनिमय करके एक ऐसी पद्धति निकालें जिससे कि हमारे यहां पर सर्वांगीण विकास हो। इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ा मैं संस्कृत एजूकेशन के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं संस्कृत भाषा का हामी हूं। आज जो भी शिक्षा मन्त्री जी संस्कृत और उर्दू शिक्षा को हमारे यहां वृद्धि कर रहे हैं उसके लिये मैं उनका स्वागत करता हूं। मैं यह नहीं कहता कि किसी एक सब्जेक्ट को ही वढाया जाना चाहिये। लेकिन इसके बारे में यही निवेदन करना चाहूंगा कि जिसके पहले आप स्कूलों और कालेजों में जो नये सब्जेक्ट खोल रहे हैं उनको मत खोलो पर मेरा निवेदन यह है कि जो सब्जेक्ट्स आप खोलना चाहते हैं उसके लिये आप उनको जबरदस्ती बच्चों पर नहीं थोपें। उसके लिये आप लड़के लड़कियों की रुचि उन सब्जेक्ट्स में है या नहीं यह भी देखलें। नहीं तो अगर बच्चों की रुचि नहीं होगी तो क्या फायदा इसलिये इस बारे में भी राज्य सरकार ध्यान दे।

(श्री ओंकारलाल चौहान)

उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ा मैं मन्त्री महोदय का ध्यान एक दो बात की ओर दिलाना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, ट्रांसफर्स के बारे में कई बार सदन में आलोचना राज्य सरकार की हुई है। आज 8-3-75 का रोज है सत्र समाप्त हो रहा है पर आज भी सचिवालय में ट्रांसफर्स की लिस्टें बन रही हैं यह गलत है। मैं यह मानता हूं कि शिक्षा मन्त्रीजी के ऊपर दबाव है, लेकिन मेरा निवेदन यह है कि जब सत्र समाप्त हो रहा है तब यह ट्रांसफर्स करने की आवश्यता क्या है। इसके लिये मेरा निवेदन है कि इससे हमारे बच्चों का नुकसान हो सकता है इसका असर हमारे नेशन के ऊपर पड़ता है इसलिये हमें नेशन को बनाने के लिये ऐसी चीजों के लिये हमें हिम्मत से मुकबला करना पड़ेगा। कितना ही बड़ा आदमी हो, हमको इस बात को देखना पड़ेगा क्या अध्यापक को इस प्रकार से बार बार ट्रांसफर से दुख नहीं होता है, उसके परिवार के लोगों को दुख नहीं होता है। एक परिवार के अन्दर एक मेल टीचर है और दूसरा फीमेल टीचर है, एक को बाड़मेर, एक को कोटा, एक को अजमेर और दूसरे को दूसरे कोने के अन्दर। आपको देखना चाहिये जहां तक हो सके, आपको ऐसे पेयर्स को साथ रह सकने की व्यवस्था करनी चाहिये। आप में हिम्मत होनी चाहिये। प्रशासन के जो भी हित में हो वह आपको करना चाहिये। हम तो पब्लिक के चुने हुए नुमाइन्दे हैं. हम तो अपनी कांस्टिट्यूएन्सी की बात को रखना चाहेंगे लेकिन आपको तो प्रशासन चलाना है और आपको तो कड़ाई से ही काम लेना पड़ेगा। साथ ही जहां तक पावर्स का प्रश्न है आपको अपने विभाग में विश्वास करके चलना चाहिये।

मैं जान रहा हूं कि आप घंटी बजाने वाले हैं, लेकिन मैं एक दो मिनिट में ही समाप्त करने वाला हूं।

यह 74–75 की प्रगति रिपोर्ट मिली है। यह नाकाफी है। इस सम्बन्ध में सही ढंग से कोई चिन्तन होना चाहिये ताकि हम भी विशेष रूप से कोई अच्छे सुझाव आपके सामने रख सकें।

एक बात सामने आयी है राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल। पाठ्य पुस्तक मण्डल ने काफी अच्छा काम किया है। बड़ा सराहनीय कार्य। एक समय था जब पुस्तकें नहीं मिल पाती थीं। मण्डल ने बैठ कर कन्ट्रोल किया पुस्तकों का और समय पर पुस्तकें निकालीं। यह एक महान उपलब्धि है। इसके लिये मैं माननीय शिक्षा मन्त्रीजी को बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं। वेरी सेटिस्फेक्टरी वर्क। इसमें कहीं कमी नहीं है।

अब मैं तीन चार बातों का जिक्र करना चाहूंगा। महिला प्राइमरी एजुकेशन का कुछ भी बजट नहीं है। हमारे यहां पर 1 परसेन्ट महिला शिक्षित हैं और दूसरा 17 परसेन्ट। महिलाओं को भी शिक्षा के स्तर में आगे लाना चाहिये। इन्टरनेशनल वुमेन ईयर चल रहा है। इस में भी आपको इस ओर अधिक ध्यान देना चाहिये। महिला शिक्षा पर अधिक से अधिक रुचि लेनी चाहिये जिससे महिला ईयर में अधिक से अधिक उपलब्धि हो सके। कई माने में महिलायें पुरुषों से अच्छी हैं। ये

(श्री ओंकारलाल चौहान)
ही शिक्षित महिलायें समाज को उजागर करने में सक्षम होंगी।

क्रीड़ा परिषद् की बात आयी। शिविर वगैरा। मैं आलोचना का इसको विषय नहीं बनाना चाहता हूं जहां शिक्षा का स्तर गिर गया है, नैतिकता गिर गयी है, खेल का स्तर भी गिर गया है। हम भी खेले हैं। हॉकी में बराबर खेले हैं। कूदे हैं। आज तो पता ही नहीं कि क्या खेल चलते हैं। क्या गतिविधियां हैं। किस प्रकार से हिसाब किताब रखे जाते हैं। इस सम्बन्ध में मैं एक सुझाव दूंगा। क्रीड़ा परिषद् के लिये एक बोर्ड बनाया जाना चाहिये जो कि निष्पक्ष हो। जहां शिक्षा आवश्यक है वहां खेल भी आवश्यक है। साउन्ड बॉडी, साउन्ड माइन्ड एन्ड साउन्ड हैल्थ। यह आवश्यक है।

कहना तो मैं बहुत कुछ चाहता था। सन् 1969 से कोटा में वीमेन्स एजुकेशन के लिये बी. एड. कालेज था उसको बन्द कर दिया। कृपया इस मसले को लेकर अगले सत्र में इसको खोलने की कोशिश करें। कोटा क्षेत्र के असंतुलन की बात तो मैं नहीं करना चाहता लेकिन यह जरूर कहूंगा कि आप इसको पुनः चालू करके वहां की महिलाओं के साथ न्याय करेंगे और इस दृष्टिकोण से महिला शिक्षा को आप आगे बढ़ायेंगे। आपको उनकी ओर से धन्यवाद मिलेगा, उनकी ओर से आपको आशीर्वाद मिलेगा और उनकी इच्छायें इससे पूरी होंगी।

एक बात और कहना चाहूंगा कि कई जगह पर कई विषयां की क्लासेज नहीं हैं। कोटा है, बारां है। अन्त में यही कहूंगा कि आज जो शिक्षा की दशा है उसमें सुधार होना चाहिये। शिक्षा मंत्रीजी ने बजट में हिम्मत दी, सोचने का साहस दिया इन शब्दों के साथ उनको धन्यवाद दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बनवारीलाल !

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक प्रस्ताव भेजा है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलना चाहती हैं ?

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : मेरा गला बहुत खराब हो रहा है इसलिये सुमित्राजी मेरी ओर से बोल देंगी।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा प्रावधान नियमों में मैंने कहीं नहीं पढ़ा है कि स्वयं माननीय सदस्य न बोल सकें और प्रोक्सी के लिये दूसरों को खड़ा करें। ऐसा नियम बतला दें तो मैं इजाजत दे सकता हूँ।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : आप लेटर ऑफ अथोरिटी तो ले लें।

श्री उपाध्यक्ष : नियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि दूसरा कोई दूसरे के स्थान पर बोले।

श्री बनवारीलाल (धौलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज शिक्षा की मद है और मैंने भी कटौती प्रस्ताव इस पर दिये हैं। आज सब ही शिक्षा के ढांचे पर चिन्तित हैं और चाहते हैं कि इसमें परिवर्तन होना चाहिये। बहुत से साथियों ने मांग की है कि शिक्षा

(श्री बनवारीलाल)

के ढांचे में परिवर्तन होना चाहिये। किस प्रकार का परिवर्तन चाहते हैं? आमूलचूल परिवर्तन चाहते हैं। मैं समझ नहीं पाया कि क्या परिवर्तन होना चाहिये।

शिक्षा के सम्बन्ध में इतना सा निवेदन है कि आज शिक्षित लोगों में, पढ़े लिखे लोगों में बेकारी और बेरोजगारी फैल रही है। उसको किस प्रकार से दूर किया जाय इस सम्बन्ध में शिक्षा मंत्री महोदय को ध्यान देना चाहिये। आपको टेक्निकल एजुकेशन ज्यादा देना चाहिये। जो हमारे प्राइवेट सेक्टर में या दूसरे सैक्टर में कारखाने राजस्थान में विकसित हो रहे हैं उनमें टेक्निकल हैंड चाहिये वे नहीं मिल पाते हैं और बाहर से लोगों को उनमें काम करने के लिये बुलाना पड़ता है। इसलिये इस सम्बन्ध में आप व्यवस्था करें तो अच्छा है।

आपने संस्कृत के बारे में एस. टी. सी. का ट्रेनिंग सैन्टर खोला महापुरा में यह आपका बहुत ही सराहनीय कदम है। यह नदर्न इन्डिया में पहला ही है और एक बहुत अच्छा कदम है। वास्तव में आपने यह अच्छा कदम उठाया है।

आपने प्राइमरी शिक्षा को पंचायत समितियों के अधीन रखी है। उनको वापिस पंचायत समिति से हटा कर शिक्षा विभाग में ले लिया जाय क्योंकि विद्यार्थी और अध्यापक दोनों की ही बड़ी दयनीय अवस्था है। अध्यापक लोकल पोलिटिक्स में घुस जाते हैं बजाय लड़कों को पढ़ाने के। वह तो खुशामद में लग जाते हैं। न विद्यार्थी ही पढ़ पाते हैं। पंचायत समिति में फण्ड्स न होने से विद्यार्थियों को भी कोई सुविधा नहीं मिल पाती है। इसलिये इसको पंचायत समिति से हटा कर एजुकेशन डिपार्टमेन्ट में ले लें जिससे दोनों का ही फायदा हो।

प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स हैं, उनमें बहुत गड़बड़ घोटाला होता है। न पूरी तनख्वाह देते हैं अध्यापकों को और देते हैं तो कुछ देते हैं और लिखाते कुछ हैं उनके नाम पर। पूरी तनख्वाह पर दस्तखत करवाते हैं और देते कम हैं। इसलिये इनको नेश्नेलाइज्ड करें और इसमें दिक्कत आ रही है तो इस भ्रष्टाचार को बन्द करने के लिये ऐसा कोई कदम उठायें जिससे बैंक के द्वारा अध्यापक तनख्वाह उठा सकें। उनकी तनख्वाहें बैंकों द्वारा उठायें तो जो भ्रष्टाचार हो रहा है, वह कम होगा। इसके अलावा मैं निवेदन करना चाहता हूं जो एग्जामिनेशन है उनकी बार बार तारीखें बदल देते हैं। होता क्या है जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं वे बाद में होंगे। और बाद में होने पर उनके रिजल्ट्स देर से निकलेंगे और फिर एडमिशन में बड़ी दिक्कत आयेगी। यहां तो एग्जामिनेशन का कोई ढांचा नहीं बनाया है हाई स्कूल के कब होंगे, कालेज के कब होंगे, ला कालेज के कब होंगे। इस प्रकार जब एग्जामिनेशन में देरी करेंगे तो उनके रिजल्ट्स भी देर से ही निकलेंगे और एडमिशन में बडी भारी दिक्कत होगी अपने यहां तो दिक्कत न भी हो तो दूसरे प्रान्तों में यह दिक्कत अवश्य आ जाती है। इसलिये मेरा निवेदन है एग्जामिनेशन की जो डेट बढ़ाई है वह नहीं बढ़ाई जानी चाहिए।

इसके अलावा मैं स्वागत करता हूं माइन्योरिटी लेंग्वेजेज के 500 टीचर्स का

(श्री बनवारीलाल)

रखा है, यह बड़ा सराहनीय कदम है। अन्त में मैं निवेदन करना चाहता हूं इसके अलावा राष्ट्रीयकृत पुस्तकों के बारे में। सदन में कई बार चर्चा होती थी और समय पर किताबें नहीं मिलती थीं। मैं बधाई देना चाहता हूं आपके मण्डल ने काफी काम किया है। सारी किताबें सिर्फ एक किताब को छोड़ कर जुलाई में ही आपने सप्लाई कर दी है वास्तव में उत्तर प्रदेश में मेरे एक साथी हैं, एम.एल.ए. हैं उन्होंने स्वयं ने कहा है। आपके यहां किताबों की अच्छी व्यवस्था है। हमको किताबें समय पर नहीं मिलने के कारण स्कूलों को डेढ महीने तक बन्द रखने पड़े। इसके साथ जो पोलिसी बनी है उस पोलिसी को बुक सेलर्स फेल करना चाहते हैं इसलिये मेरा निवेदन है आप ज्यादा से ज्यादा डिपो खोलें और उनको ज्यादा से ज्यादा एक्टिव बनायें। बुक सेलर्स धन्धा करना चाहते हैं, कुंजी प्रणाली को भी खतम करें क्योंकि बच्चों की पढ़ाई में इससे नुकसान होता है।

अन्त में मैं निवेदन करना चाहता हूं म्यूजियम के बारे में। जैसा माननीय सदस्य श्री श्रीरामजी ने कहा राजस्थान में जितने राजा महाराजा हैं वे आपके अधीन आ चुके हैं। मेरा निवेदन है सारे राजस्थान में जहां बहुत अच्छी अच्छी चीजे हैं उनको वहां से हटाकर जयपुर राजधानी है, बड़े टूरिस्ट आते हैं उन सबको एकत्रित करके जयपुर म्यूजियम में लावें जिस प्रकार हैदराबाद के म्यूजियम को देखने जाते हैं उसी प्रकार जयपुर के म्यूजियम को भी लोग देखने आयें। अन्त में मैं निवेदन करना चाहता हूं धौलपुर के बारे में मेरी मांग है, किशनपोल से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है, आपको दिक्कत नहीं आयेगी। ला कालेज छोडने को तैयार हैं, मेरे यहां प्राबलम है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान तीनों प्रान्तों की बोर्डर पर है। वहां के छात्रों को शिक्षा लेने के लिये आगरा और मुरेना जाना पड़ता है। इस समय भी 80 छात्र धौलपुर के दूसरी जगहों पर पढ़ने जाते हैं। ला कालेज जो इस वर्ष खोल रहे हैं, उसमें धौलपुर को प्राथमिकता दें।

अन्त में राजस्थान प्रदेश ने जो स्काउटिंग में स्थान पाया है उसके लिये भी मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं और एन.सी.सी में जो महिला आई हैं उसके लिये भी मैं बधाई देना चाहता हूं। धौलपुर में जो सब्जेक्ट खोलें उसके बारे में भी गौर करें क्योंकि दूसरे प्रोविन्सेज से लगा हुआ है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ जब भी स्कूल खोलें धोलपुर का अवश्य ध्यान रखें, इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती शकुन्तला !

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव (आमेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने क्रम बिगाड़ दिया, तबीयत खराब है...

एक माननीय सदस्य : माननीय सदस्य अस्वस्थ हैं इसलिये आप...

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : इसके लिये मैं नहीं कहती हूं क्रम बिगाड़ दिया। हमारे समय में क्रम कभी नहीं बिगड़ा। अब माननीय उपाध्यक्ष महोदय आपके आदेशानुसार मैं अपने आज के कटौती

(सु श्री शकुन्तला श्रीवास्तव)

प्रस्ताव जो शिक्षा और जेल विभाग दोनों के मैंने दिये हैं। मैं कुछ कहना चाहती हूं और जैसी की इस समय मेरी हालत है मैं निवेदन करूंगी। मैं अपनी बात समाप्त करके स्वयं बैठ जाऊंगी, घंटी लगाने की जरूरत नहीं आयेगी। इसलिये जो मेरी बात है उसको पूरी हो जाने दें। मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय यह निवेदन करना चाहती हूं कि इस वर्ष जो बजट का प्रावधान रखा गया है शिक्षा और जेल में उसके लिये मैं वित्त मंत्रीजी को और शिक्षा मंत्रीजी को तथा राज्य सरकार को बधाई देना चाहती हूँ क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष है इसलिये इसमें मुझे जो एक कमी लगी है उस ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षिक करना चाहती हूं और मैं समझती हूं इसके ऊपर जरूर विचार किया जायगा।

जहां एक ओर हम यह कहते हैं कि हमारे देश की महिलायें या हमारे राज्य की महिलायें पिछड़ी हुई हैं–शिक्षा के क्षेत्र में वहां हमने उनके लिये अभी तक क्या किया है? उसके लिये मेरा नम्र निवेदन यह है कि हमने शहरों को छोड़कर देहात क्षेत्रों में क्या किया। यह आप सब जानते हैं। आज भी देहाती क्षेत्रों की सामाजिक व्यवस्था को पूरी तरह सुधार नहीं पाये हैं। आज भी को-एज्यूकेशन में लड़कियों को भेजने में माता पिता हिचकिचाते हैं। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करना चाहती हूं इस वर्ष को जब अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष माना गया है और शिक्षा के क्षेत्र में दूसरे क्षेत्र में महिलाओं को आगे ले जाना चाहते हैं तो यह बहुत जरूरी हो जाता है कि उनके लिये अलग से बजट प्रावधान भी किया जाना चाहिये जिससे लड़कियां शिक्षा पा सकें। उसके लिये मैं यह निवेदन करना चाहती हूं जैसा कि स्कूलों के लिये ग्रामीण क्षेत्र में खासकर शहरों को छोड़ दीजिये लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में मेरी विशेष रूप से मांग है सरकार अलग से इसके लिये जो अभी स्कूलों को बजट दिया गया है, शिक्षा विभाग को उसके अतिरिक्त और बजट महिला शिक्षा के नाम और दिया जाना चाहिये जिससे कि लड़कियों को पढ़ने के लिये प्रोत्साहन मिले और उनके प्रोत्साहन के लिये यह भी जरूरी है कि वहां स्कूलों के जो भवन हैं वह भी लड़कियों के लिए कम से कम भवन सरकार अपनी ओर से बनायें।

बड़े बड़े शहरों में युनिवर्सिटी सरकार अपने खर्चे से बनाती है लेकिन एक ग्रामीण क्षेत्र जो अपने को अन्न देता है और गरीब लोग बसते हैं। उनको कहते हैं तुम भवन बनावो तो यह कहां तक न्यायसंगत है इसलिये मेरा शिक्षा मंत्री जी से निवेदन है इस ओर ध्यान देकर योजना बनाई जाय जिससे अलग से बजट भी मिल सके और दूसरे महिलाओं के लिये कल्याणकारी प्रवृत्ति भी चालू हो सके।

इसी सन्दर्भ में जेल विभाग के बारे में चन्द शब्द कहना चाहती हूं। वह आये दिन हम यह सुनते हैं कि जेल विभाग में फलां जेल से अमुक कैदी भाग गया, फलां जेल से अमुक कैदी भाग गया और उसका दोषारोपण कर्मचारियों के ऊपर और अधिकारियों के ऊपर किया जाता है। यह मुझे बड़ा असंगत सा लगता है। मैं समझती हूं कि आप इस बात को देखें कि आखिर ऐसा होता क्यों है। जिस अनुपात में हमारे राज्य में अपराधी बढ़े हैं और जिस अनुपात में हमारे यहां पर बन्दी हैं उस अनुपात में क्या

(सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव)

हमने स्टाफ दे रखा है, क्या हमने वार्डर्स दे रखे हैं, क्या हमने अधिकारियों को वही सुविधायें दे रखी हैं जो कि दूसरे विभाग के कर्मचारियों को प्राप्त हैं ? उन बेचारों को इस बात की भी छूट नहीं है कि वह आन्दोलन तो कर सकें । दूसरे विभाग के लोग तो आन्दोलन करके अपनी तनख्वाहें भी बढ़वा सकते हैं, दूसरी सुविधायें भी प्राप्त कर सकते हैं । तो क्या सरकार ऐसा मानकर चलती है कि जेल विभाग के जो कर्मचारी और अधिकारी हैं इनके पीछे परिवार नहीं है या उनके लिए कोई जरूरी नहीं है कि इतनी हार्ड ड्यूटी लेने के बाद भी हम उनकी पे स्केल की तरफ ध्यान नहीं दें ? और तो और मैं आप सबको दावत देती हूं कि दूर मत जाइये । राजधानी की जेल में चलकर देखिये कि वहां के छोटे से कर्मचारी से लेकर उच्च अधिकारी तक किस तरह के मकानों में रह रहे हैं । क्या वह इन्सानों के रहने की जगह है ? जहां किसी जमाने में घुड़साल हुआ करती थी वहां उनके रहने की व्यवस्था है तो फिर हम यह उम्मीद कैसे कर सकते हैं, जो तबका हमारे ही समाज का अंग है और जिसके ऊपर हमारे समाज की रक्षा का दायित्व है उस तबके की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाये और केवल मात्र हमने बुराइयां ही लोगों में देखनी सीखी हैं और उनकी सुविधाओं की तरफ देखना नहीं सीखा है । इसके लिए मुझे माननीय सदस्यगण माफ करेंगे क्योंकि मैं स्पष्टवादी हूं और जो भी स्पष्ट देखती हूं वह कह देती हूं ।

दूसरे, मैंने जेल विभाग की रिपोर्ट पढ़ी है । उस रिपोर्ट में महिला बन्दियों के बारे में केवलमात्र फ्यूचर प्लान के लिए ओपिन एयर कैम्प की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है और उसके अलावा कुछ नहीं है और वह पता नहीं होगा या नहीं होगा । तो मेरी मांग है कि कम से कम इस महिला वर्ष में उन महिलाओं के लिए जो कि समाज का एक अंग बनने जा रही हैं उनके लिए जब वह रिलीज होती हैं तो उनके रिलीज होने के बाद उनको रिहेबीलीटेट करने के लिए, अपने पैरों पर खड़े होने योग्य बना सकें, इस प्रकार का प्रावधान करें और जो जेलों में काम करते हैं कर्मचारी लोग उनके वेतनमान भी बढ़ाये जाने चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मेरी 3 मुख्य मांगे हैं । एक तो यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा लड़कियों के स्कूल खोले जायं और उनके लिए सरकार भवन का प्रावधान करे तो मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि लड़कियां निश्चित रूप से पढ़ने के लिए आयेंगी और जो इस क्षेत्र में हमारा पिछड़ापन है वह भी दूर हो जायगा । नम्बर दो वार्डर्स की संख्या बढ़ाई जाये ताकि आये दिन जो कैदी भागते हैं वह समस्या हल हो जाये और कर्मचारियों के वेतनमान को सुधारा जाये और उनकी सुविधाओं की तरफ ध्यान दिया जाये । अधिकारियों को जो उनके अधिकार हैं उसके अनुरूप ही उनके वेतनमान रिवाइज किये जायें और उनके रहने की व्यवस्था है वह ठीक की जाये । जो 24 घण्टों की ड्यूटीज उनसे ली जाती उसमें कम से कम परिवर्तन उनको भी मिल सके और वह फील कर सकें कि वह समाज के अंग हैं और उनका दायित्व इतना बड़ा है–इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको

(सुश्री सकुन्तला श्रीवास्तव)
इस बात के लिए धन्यवाद देती हूं और मैं समझती हूं कि इस आशय के साथ अपने कटौती प्रस्तावों को पेश कर रही हूं कि सरकार इस ओर अवश्य ध्यान देगी। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भुवनेश चतुर्वेदी।

श्री भुवनेश चतुर्वेदी (कोटा) : उपाध्यक्षजी, शिक्षा विभाग की मांगों के सम्बन्ध में अन्त में हां तो करनी ही है लेकिन शिक्षा मन्त्रीजी को मैं बड़ा खुशकिस्मत मानता हूं कि उनको ऐसा विभाग मिला क्योंकि कई मन्त्रियों को तो ऐसा विभाग मिलता है जिसमें पत्थर तराशे जाते हैं लेकिन शिक्षा मंत्रीजी को तो आदमी तराशने का मौका मिलता है। मैं शिक्षा मन्त्रीजी से कहूंगा कि वह अपने भाग्य को सराहें। राजस्थान के लोग सराह सकें या नहीं यह दूसरी बात है। यह अभी देखना है लेकिन आप अपने भाग्य को सराहें।

मैं एक बात कहता हूं कि आप सपने देखने की आदत रखिये क्योंकि बिना स्वप्न के सृजन नहीं होता। अगर समाज का सृजन करना है तो स्वप्न देखने ही पड़ेंगे। स्वप्न कल या परसों में सच हो जायें वह सपना नहीं है। आपका समाज 10 साल में, 20 साल में या 50 साल में क्या बनेगा वह सपना आप देखिये। आप वह सपना मत देखिये कि सन 76 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और सन् 77 में असेम्बली के चुनाव होने वाले हैं. तो मेरा निवेदन यह है कि कम से कम एक पीढ़ी के लिए सपना देखिये क्योंकि यह शिक्षा का महकमा इतना महत्वपूर्ण है कि "मोहब्बत के लिये कुछ मखसूस होते हैं, यह वह नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता" इसलिए मैं उपाध्यक्ष महोदय, उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात को सुनेंगे।

श्रीमती मुमित्रासिंह : पाइन्ट आफ आर्डर, सर। कम से कम शिक्षा मन्त्रीजी या राज्य शिक्षा मन्त्री जा दोनों में से एक को तो यहां रहना चाहिए, नहीं तो हमारी बहस करना बेकार होगा।

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : शिक्षा के बाद अगर जेल ही भेजने का इरादा है तो इसको बन्द कर दिया जाये।

उपाध्यक्षजी, मैं सिर्फ 5 मिनट ही चाहता हूं, छठा मिनिट नहीं लूंगा। तो "सभी कुछ हो रहा है इस तरक्की के जमाने में, मगर यह क्या गजब है आदमी इन्सान नहीं होता" शिक्षा मन्त्रीजी नहीं हैं इसलिए मेरी बात का कोई असर नहीं होगा लेकिन जेल मन्त्रीजी यह भावना पहुंचा दें तो बड़ा अच्छा हो कि शिक्षा मन्त्रीजी अपने भाग्य को सराहें। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कालेज और यूनिवर्सिटी एजुकेशन के बारे में मैं बोलना नहीं चाहता क्योंकि जितने इन्टलेक्चुअल्स पैदा हो गये हैं उनसे ही काफी परेशानियां आ रही हैं मैं कई बार ऐसा समझता हूं कि यह सो काल्ड इन्टलैक्चुअल्स केरा तो नहीं है समाज के लिए, मुल्क के लिए। मुझे इस बात का दृढ़ विश्वास है कि अगर आपने प्राईमरी और सैकेण्डरी एजुकेशन को नहीं सुधारा तो यूनीवर्सिटी लेवल पर इतना बड़ा गैप हो जायेगा कि आप इस मुल्क को नहीं सम्भाल पायेंगे चाहे इस प्राईमरी और सैकेण्डरी एजुकेशन के लिए

(श्री भुवनेश चतुर्वेदी)

हमारे शिक्षा मन्त्रीजी या हमारा मंत्रीमण्डल यह समझता है कि बिना डाइरेक्टर के काम चल सकता है। चार-चार और छः-छः महीने पोस्ट खाली रहे तो यह बड़े दुःख की बात है। मैं आकांक्षा करता हूं कि प्राईमरी और सैकेण्डरी स्कूल के लिए विशेष ध्यान दें। कुछ वर्षों के लिए वह समझ भी लें कि हमारे यहां कोई कालेज या यूनीवर्सिटी का एक्सपेन्शन नहीं होगा क्योंकि मैं समझता हूँ कि यूनीवर्सिटी और कालेज एजुकेशन के एक्सपेन्शन का सवाल नहीं है बल्कि सवाल है उसके कन्सोलीडेशन का। सवाल तो है प्राईमरी और सैकेण्डरी स्कूल के एक्सपेन्शन का। मैं निवेदन करता हूँ कि आप एक व्हाइट पेपर निकालिये प्राईमरी और सैकेण्डरी शिक्षा के लिए और अपनी नीतियां निर्धारित कीजिए। आज जो राजस्थान का बालक पैदा होता है उसको आप 16 साल में क्या बनाना चाहते हैं। वही बात है, जेल मंत्री जी से ही नोट लिखवाना चाहते हैं तो हम समझ जायेंगे कि आपकी क्या शिक्षा नीति है। लेकिन में उम्मीद करता हूं कि आप इस बात पर ध्यान देंगे और प्राईमरी स्कूल्स और सैकेण्डी स्कूल्स पर आप विशेष महत्व देंगे।

दूसरा, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो आपकी अपनी (कैटेगराईजेशन आफ इन्स्टीट्यूशन्स) की बात थी और बड़े जोश के साथ यहां पर यह कहा गया था पिछले सदन में कि हम अगस्त, सितम्बर तक यह सिफारिश मान लेंगे और कार्यान्वित कर देंगे। गुस्ताखी माफ हो अगर मैं यह कहूं कि दिसम्बर जनवरी तक तो केटेगराईजेशन कमेटी के जो सदस्य हैं वह दौरा ही करते रहें और अगर मेरी सूचना गलत नहीं हो तो राज्य सरकार ने उस सिफारिश पर अभी तक गौर नहीं किया है। तो आप क्या चाहते हैं, आप हमको बहका देना चाहते हैं शिक्षा नीति के नाम पर या किसी कमेटी के नाम पर। मैं उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि आप जो भी आश्वासन दें, जैसा कई मित्रों ने कहा कि शिक्षा मंत्री जी बहुत बहादुर हैं आप राठोड़ी चला सकते हैं, शिक्षा मंत्रीजी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा बड़ा नाजुक और सोफिस्टीकेटेड परपज है। मैं यह निवेदन करता हूं कि जहां करप्शन मिटाने का सवाल हो, जहां खराब आदमियों को हटाने का सवाल हो वहां आप अपनी राठोड़ी चलाइये और बड़े जोर से चलाइये, लेकिन जहां तक शिक्षा नीति का सवाल है उसको आप देखिये। इसको आप एक अदना एल.डी.सी. और यू.डी.सी. पर मत छोड़िये, क्योंकि आपका असली काम यही है। हमने आपको मंत्री इसीलिए बनाया है कि आप शिक्षा की नीति का निर्धारण करें। कई बार हम भी आप पर प्रेशर लाते हैं लेकिन खुदा के वास्ते दिसम्बर, जनवरी, फरवरी में तबादले मत कीजिये। कोटा में मेरे पास एक प्रिंसिपल आए जो ट्यूटोरियल क्लासेज चलाते हैं इसलिए कि उनके बच्चे हायर सैकेण्डी में पोजीशन लायें। क्योंकि आपकी मार्च में पहले एग्जामिनेशन की डेट डिक्लेयर हुई थी। वे ट्यूटोरियल क्लासेज चलाते थे। आपका आदेश पहुंचा कि अमुक सीनियर टीचर का ट्रांसफर अमुक 2 जगह कर दिया जावे। मैं निवेदन करूंगा कि ट्रांसफर ही करना है आपको तो अप्रेल,

(श्री भुवनेश चतुर्वेदी)

मई, जून, जुलाई, अगस्त में कीजिये और दस्तूर के नाम पर 15 सितम्बर आपने समय भी निश्चित कर रखा है उसको निभाइये। उसमें हम कितना ही प्रेशर लायें आप हम पर राटोडी चलाइये। वहां हम आपसे अपेक्षा करेंगे कि आप कह दीजिए "माननीय सदस्य आपकी इच्छा है पर मैं तो मई, जून, जुलाई में ही आपकी दरख्वास्त पर फैसला करूंगा।" तो यह मैंने आपको बहुत मुद्दे की बात कही है। जो बडा फस्टेशन शिक्षकों में है उसको आप करटेल कर सकेंगे। विद्यार्थियों में कर सकेंगे। वैसे ही हमारे विद्यार्थी पढ़ाई नहीं करते। वैसे ही युवा आक्रोश का फैशन चल रहा है। विद्यार्थी सब कुछ करेंगे विद्या अध्ययन के अलावा। टीचर लोग सब कुछ करेंगे सिवाय पढ़ाने के। हमें यह देखना चाहिए कि जो कोई पढने पढ़ाने की बात करें उन लोगों को आपको विशेष प्रोत्साहित करते रहना चाहिये।

दूसरा, मैं आपसे यह कहता हूं कि आपका एक कोर्स चला था वोकेशनल एजूकेशन का। वोकेशनल एजूकेशन की बड़ी बहार चली। मैं बड़ी नम्रता से निवेदन करता हूं कि आपने समय की आवश्यकता को समझा। आप कैसे गांधीजी की बेसिक एजूकेशन को महत्व नहीं दे पाये और यह समझ लिया, आजादी के बाद मैं समझता हूं कि 51–52 में ही इसको समाप्त कर दिया। You did not give it even a decent burial वह बेसिक एजूकेशन क्या थी, it was Vocational education.

फिर उसके बाद एक बहार चली मल्टी-परपज हायर सैकेन्ड्री स्कूलों की, वह आपने बन्द कर दी। वोकेशनल स्कूल्स आपने बन्द कर दिये, कभी आपने इसके बारे में सोचा। आई. टी. आई. स्कूल खड़े किए, कितने आदमी एम्पलायड हो सके, कभी आपने सोचा। इसके बाद आपने पोलोटेक्निक स्कूल चलाये, उसमें पढ़े हुए कितने विद्यार्थी अनएम्पलायड हैं कभी आपने सोचा। तो यह आपने वोकेशनल एजूकेशन का नारा दिया और हम समझते हैं कि आप दुबारा उस नीति पर लौट कर आए और आपने स्कूलें खोलीं। मैं शिक्षा मंत्रीजी बड़ी नम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं, दिसम्बर जनवरी तक आपका स्टाफ वहां नहीं पहुंचा। कई स्कूलों में नहीं पहुंचा और अभी तक इस प्रकार की दृष्टि साफ नहीं है कि कौन इनके एग्जामिनेशन लेंगे और कौन एग्जामिनेशन देंगे। किस तरह के एग्जामिनेशन होंगे यह भी स्पष्ट नहीं। यह कन्फ्यूजन वोकेशनल एजूकेशन में है जिसको शिक्षा मंत्रीजी कृपा कर आप विचार करें और इसको सुदृढ कीजिए।

एक्सपान्शन आप न करें लेकिन कंसोलिडेशन आप जरूर करें। मैं कहता हूं कि प्राईमरी एजूकेशन में कितना वेस्टेज हो रहा है, आपने कभी इसका सर्वे किया। कभी आपने स्टेटिस्टिक्स उठा कर देखी कि प्राईमरी और सैकेन्ड्री स्कूल्स में कितना वेस्टेज है। क्या वजह है कि हम अन-इकोनोमिक स्कूल्स चलाते हैं, अन-इकोनोमिकल स्कूल्स को प्रोत्साहन देते हैं। हममें इनको बन्द करने की हिम्मत नहीं है। मैं निवेदन करता हूं और फिर आपसे अन्त में यही निवेदन करता हूं कि आपसे जिस मर्दानगी

(श्री भुवनेश चतुर्वेदी)
की उम्मीद है उसके आधार पर इन्हें खत्म करने की बात की जाय।

एक ट्रेनिंग स्कूल्स की बात करूंगा। एक बहार ऐसी चली कि सब एस. टी. सी. स्कूल बन्द कर दिए और एक मौका ऐसा आया कि तीन चार महीने में···

श्री रामकिशन : भुवनेशजी, मर्दानगी की हाऊस में क्या जरूरत पड़ गई। हम तो वैसे ही सब दबे हुए हैं।

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : ····आपने सब एस. टी. सी. स्कूल्स को चला दिया। आप अपने विभाग वालों को डांटिए की आपको सही बात क्यों नहीं बतलाते कि हमको ट्रेंड अध्यापकों की कितनी जरूरत है और कितने ट्रेंड अध्यापकों की हमें पंचवर्षीय योजना में जरूरत होगी। मैं आपको निश्चित रूप से कहता हूं कि इस जुलाई में आपको शिक्षित अध्यापक नहीं मिलेंगे। यह मैं आपको चुनौती के साथ कहता हूं कि आपको ये नहीं मिलेंगे। आप विभाग वालों से पूछिए कि क्यों ये आपको मिसगाइड करते हैं। यह गलत बात है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि बिल्कुल प्लाण्ड वे में सीरियसली विचार कर एक वाईट पेपर पब्लिश करिये प्राईमरी और सैकेण्ड्री एजूकेशन पर कि आप राजस्थान की इस पीढ़ी को क्या देने वाले हैं पन्द्रह बीस साल में जो हायर सैकण्ड्री तक बच्चे पहुंचेंगे।

दूसरा निवेदन यह है, पिछले वर्ष भी निवेदन किया था, सम्भव है उसको इतना महत्व नहीं मिला हो, आप इंस्पेक्टर्स बनाते हैं। मैं आपसे कहता हूं कि इंस्पेक्टर्स के बजाय उनको बनाइये जो (एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्पेक्टर्स) हों। जब तक एकेडेमिक इंस्पेक्टर्स नहीं बनेंगे तब तक आप कंसोलिडेशन नहीं कर सकेंगे। कुछ चौकीदारी नहीं कर सकते, कुछ आपका किसी प्रकार का अपना जो स्तर है शिक्षा का आप बढ़ा नहीं सकते उसको। आप पैनल इंस्पेक्शन की बात करते हैं। आप बता सकते हैं कि कितने स्कूलों का पैनल इंस्पेक्शन हुआ। आपकी School Complex आइडिया कितनी आगे बढ़ी। इतना ही पर्याप्त नहीं है कि लाइब्रेरी जितनी हैं वह हमारे यहां आ जाय, वहां के टीचर हमारे यहां आ जायं, वहां का फर्नीचर हमारे यहां आ जाय, इससे School Complex पूरा होने वाला नहीं है। कोठारी साहब ने एक इतनी बड़ी साईड लाईन तैयार की, खुदा के वास्ते, अगर खुदा पर भरोसा करते हैं तो उस पर पालन करें। अगर खुदा पर भरोसा नहीं करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव नीति के नाते भी आपका फर्ज है।

(समय-समाप्ति-सूचक–घण्टी)

केवल लिख देने से ही यह होने वाला नहीं है। मैं अब आपसे निवेदन कर देना चाहता हूं स्टुडेंट टरमोयल के बारे में। शिक्षा मंत्रीजी आप इस पर विचार कीजिए। मैं सन् 50–51 में मैं खुद कालेज में पढ़ता था, मैं भी स्टुडेंट यूनियन का पदाधिकारी हुआ करता था, उस समय प्रोफेसर कबीर ने सन् 50–51 में स्टुडेंट टरमोयल के बारे में पैम्फलेट निकाला और हमने उस पर विचार गोष्ठी की। और सन् 50–51 से बराबर उस पर बहस चल रही है, गोष्ठियां आयोजित कर रहे हैं, सन् 75 में भी इस

(श्री भुवनेश चतुर्वेदी)

नतीजे पर नहीं पहुंच सके कि स्टुडेंट टरमोयल क्या है और क्यों है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान भर में चाहे इस पर गम्भीरता से विचार होता हो या नहीं होता हो, आप यहां इसका कमीशन मुकर्रर करिये और यूनिवर्सिटी सिण्डीकेट में आप स्टुडेंट को रिप्रेजण्टेशन दें या न दें लेकिन स्टुडेंट टरमोयल की जांच करिये और उस हेतु बने कमीशन में आप स्टुडेंट को रखिये। आप पूछें कि उनकी आकांक्षायें क्या हैं, क्यों नाराज हैं वे। क्या करना चाहते हैं वे, आप उनसे बात करें। हमारी पीढी तो अब दस पन्द्रह वर्ष में खत्म हो जायेगी लेकिन उन्हें पचास साठ वर्ष और निकालना है और समाज को बनाना है। They are at that stage. Their stake is high. इसलिए यह विचार करना पड़ेगा।

डेमोक्रेसी में अगर अपनी कांस्टीट्यूएन्सी के बारे में जिक्र नहीं करूं और केवल फिलोसोफी की बातें करता हूं तो मेरे मतदाता मुझ से पूछेंगे कि आपने कांस्टीट्यूएन्सी की बात क्यों नहीं करी। तो मेरा निवेदन है कि आपने श्रीमाली कमीशन बैठाया कि अगली यूनिवर्सिटी कहां हो; अजमेर में हो कि कोटा में कि बीकानेर में हो। क्योंकि वह तो आपने अल्मारी में रख दी अंग्रेजी में कहते हैं शेल्व कर दिया। आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हमारे कालेज में कर दीजिए। दूसरा एक बड़ा Loffing हुआ है। मेरे मित्र नाराज न हों। मैं समाप्त करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि:

नाम वह कर कि जमाने में तेरा नाम रहे
काम वह कर कि पशेमन तुझे याद करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती निर्मलाकुमारी।

श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में इस वर्ष शिक्षा पर 74,04,14,000) का व्यय होगा। यह एक लोक कल्याणकारी राज्य का प्रतीक है। मान्यवर, शिक्षा जो है एक समाज का दर्पण है जिसमें किसी भी समाज का एक स्पष्ट प्रतिबिम्ब दिखाई देता है परन्तु हमारे प्रान्त में केवल हम 19 प्रतिशत का प्रतिबिम्ब ही देख पाते हैं। 81 प्रतिशत जनसंख्या जो है हमें इसके प्रकाशन में लाना है। यदि हम विश्व के मानचित्र पर दृष्टि डालें तो हमें पता चलेगा कि विश्व में 70 करोड़ व्यक्ति इस मानचित्र में अशिक्षित दिखाई देंगे। उसमें से 38 करोड़ 60 लाख सारे हिन्दुस्तान में और दो करोड़ की सेना जो है वह हमारे प्रान्त में विराजमान है। यदि इसी रफ्तार से हम चलते रहे, अशिक्षता इसी प्रकार से बनी रही तो मान्यवर मैं यह कहूंगा कि इस शताब्दी के अन्त तक भी हम निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो उद्देश्य है, उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। हमें अशिक्षा की जो समस्या है उसको युद्ध-स्तर पर निपटाना होगा। यद्यपि आपने प्रौढ़ शिक्षा और समाज शिक्षा के लिए कुछ धन-राशि रखी है। पांचवीं पंचवर्षीय योजना में आपने 45 लाख रुपये रखे हैं परन्तु मान्यवर, इसके हिसाब से लगभग दो करोड़ की अर्ध अशिक्षित जो जनता है उसके ऊपर पांच साल में यह 45 लाख रुपया व्यय होगा अर्थात् प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष पांच पैसा व्यय होगा। अब कल्पना कीजिये इससे समाज को क्या लाभ होगा? जब तक हम प्रौढ़ शिक्षा को प्राथमिकता नहीं देंगे तब तक इस शिक्षा

(श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत)

की जो समस्या है उसका निराकरण नहीं हो सकता। मान्यवर, मैं यह सुझाव देना चाहती हूं कि प्राथमिक शिक्षा से प्रौढ़ शिक्षा भिन्न होती है इसलिए हमें एक प्रौढ़ शिक्षा बोर्ड का गठन करना होगा—जिसके लिए पाठ्यक्रम के बारे में, इसके सब प्रकार के विद्यार्थियों के बारे में एक विशेष प्रकार से विश्लेषण करना होगा।

मैं दूसरी बात यह निवेदन करना चाहती हूं कि शिक्षा समाज की रीढ़ है अर्थात् जिस प्रकार के समाज का निर्माण हम करना चाहते हैं, उसी प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए। कहने का अभिप्राय यह है कि आवश्यकतानुसार परिवर्तन होना चाहिए। परन्तु बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारी शिक्षा प्रणाली बहुत अधिक परम्परागत है। परिवर्तन की बात हम सब कहते हैं, हर एक व्यक्ति कहता है कि उसमें आमूल चूल परिवर्तन होना चाहिए। जो शिक्षा शास्त्री हैं वे भी परिवर्तन की बात कहते हैं, जो अभिभावक हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो राजनेता हैं, इन सबके मुंह से यह बात सुनाई देती है। आखिर यह परिवर्तन क्यों नहीं हुआ? इसके पीछे क्या राज है? मान्यवर, मैं यह कहूंगी कि समाज में एक ऐसा प्रभावशाली वर्ग है जिसके लिए यह शिक्षा बड़ी फायदेमन्द साबित हो रही है और उसने एक ढांचा इस तरह का निर्मित कर रखा है और उसमें इस वर्ग का स्वार्थ तन्त्र ठीक से जमा हुआ है। यही कारण है कि हमारी शिक्षा के सम्बन्ध में जो रिपोर्ट चाहे वह राधाकृष्णमन् विश्वविद्यालय के द्वारा हो, चाहे वह रिपोर्ट मुदालिया शिक्षा आयोग की हो, इस प्रकार कोठारी कमीशन, श्रीमाली कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है, वे सारी की सारी रिपोर्ट्स पुस्तकालय की शोभा बढ़ा रही है अभी तक हम उसी पुरानी लब में चल रहे हैं जो उपनिवेशवादी शासन व्यवस्था में आरम्भ की गई वही पद्धति हम चला रहे हैं और उस व्यवस्था से हम अपने देश में एक आक्रोश, गरीबी, बेकारी ये सब समस्याएं देख रहे हैं परन्तु इसके हल की ओर हम नहीं बढ़ पा रहे हैं, मान्यवर, मैं यह कहना चाहती हूं कि इस शिक्षा को हमें प्लान करना होगा। शिक्षा का प्लान आप नहीं करेंगे तो यह समाजवाद की बात जो आप करते हैं, यह समाजवाद का जो नारा हम दे रहे हैं, वह बिलकुल ही निरर्थक होगा। यह जो प्लान करेंगे, उसमें यह सोचना होगा कि हम किस तरह से शिक्षा की व्यवस्था करें जिससे कि गरीबी और बेकारी का अन्त कर सकें। परन्तु यह ज्यामेट्रीकल जो यह बेकारी की जो सेना तैयार हो रही है, उसका मुकाबला करना हमारे लिए कठिन हो जाएगा। हम, शिक्षा के अन्दर, जब मांगें आती हैं, कई माननीय सदस्य अपने अपने सुझाव देते हैं। मैं भी पिछले तीन साल से सुझाव देती रही हूं। परन्तु शिक्षा में जो बुराइयां हैं उनकी बातें करने से क्या लाभ? अन्धकार को कोसने की बजाय मोमबत्ती जलाना ज्यादा उपयुक्त होगा। शिक्षा में हमें किस प्रकार का परिवर्तन लाना चाहिए? शिक्षा में परिवर्तन हम विदेशों की नकल करके नहीं ला सकते। पश्चिमी देशों में जिस प्रकार परिवर्तन हुआ है वह लागू करना हमारे लिए लाभदायक नहीं होगा। शिक्षा में हमारी जो मूल आवश्यकता है, जिसमें हमें शुरू से लेकर अन्त तक परिवर्तन करना होगा। यही नहीं, प्रारंभिक स्तर पर शिक्षा को हम बदलें, या

Page No 96

(९६)

(श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत)

जो माध्यमिक शिक्षा का ढांचा है, उस माध्यमिक स्तर को बदल लें और आगे वैसा ही चलने दें। तो इस प्रकार की व्यवस्था से काम नहीं चलेगा। हमें प्रारंभ से लेकर अन्त तक इस प्रणाली में परिवर्तन करना होगा। तो इस सम्बन्ध में थोड़े से क्रमिक सुझाव देना चाहती हूं।

प्राथमिक स्तर यदि आप देखें तो इसको दो भाग में बांटा जा सकता है। प्री प्राईमरी स्कूल-इसके पहले भाग की ओर अब तक ध्यान नहीं दिया गया है। यद्यपि कुछ समाज कल्याण विभाग की संस्थाओं द्वारा और कुछ प्राइवेट संस्थाओं द्वारा कहीं कहीं पर मान्टेसरी पद्धति से शिक्षा दी जा रही है परन्तु आप आम ग्रामीण बच्चे की तरफ भी देखें- उसे भी शिक्षा के प्रकाश के सामने लाना आवश्यक है। इसलिए यह सुझाव देना चाहती हूं कि हमें प्री प्राईमरी एजूकेशन को प्राथमिकता देनी होगी। और वहीं से बाल मनोवैज्ञानिक में ढले अध्यापक, अध्यापिका बच्चों को उपयुक्त ढांचे में ढाल सकेंगी क्योंकि बच्चा एक कच्चे घड़े के समान होता है जिसको जैसे चाहे वैसे सवारा जा सकता है। परन्तु अभी तक हमारे शिक्षा विभाग ने इस शिक्षा की उपेक्षा की है।

प्राथमिक शालाओं की बात कही गयी। इस वर्ष में एक भी प्राथमिक शाला खोलने का प्रावधान नहीं रखा गया है। मान्यवर अभी 81 प्रतिशत जनता अशिक्षित है। कई ऐसे दूरगामी स्थान है जहां पर कि स्कूल नहीं है तब हम इस उद्देश्य को कैसे पूरा करेंगे। प्राथमिक स्तर पर एक बात देखने को मिलती है-प्राथमिक स्तर पर शिक्षा को काम के साथ जोड़ना होगा। आज आम गांव का व्यक्ति यह बात कहता हुआ सुनाई देगा जब अमीर का 8 वर्ष का बच्चा स्कूल जाता है तो वह एक रुपया प्रतिदिन खर्च करता है और हमारा बच्चा एक रुपया कमाके लाता है। अर्थात् यह कह कर बच्चे को स्कूल नहीं भेजते हैं। वह यह कहेंगे कि बच्चा स्कूल चला जायगा तो खर्चा कैसे चलेगा? तो मान्यवर, इसको यदि आप काम के साथ जोड़ेगे, कुछ घन्टे पढ़ने के साथ साथ, कुछ घंटे काम के लिये भी रखने होंगे और हम ऐसे उद्योग सिखावें जिससे कि वह कार्य कर कुछ कमा सके।

दूसरा सुझाव मैं यह देना चाहती हूं कि जो नींव है वह प्राथमिक स्तर पर है वहां पर अध्यापकों का चयन अच्छे ढंग से होना चाहिए। परन्तु अच्छे व्यक्ति नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? इसका कारण आप जानतें हैं कि हमने उनको कोई विशेष प्रकार की सुविधा नहीं दे रखी है। शिक्षक एक राष्ट्र निर्माता है और उसका शिष्य, छात्र एक राष्ट्र है, जिसका निर्माण होना है। ऐसी स्थिति में हमें शिक्षकों को विशेष प्रकार की सुविधाएं देनी होंगी। मैं यह सुझाव दूंगी कि ग्रामीण शिक्षा के शिक्षक को सरल अलाउन्स दिया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में कुछ अध्यापक इस ओर आकृष्ट हो सकेंगे।

शिक्षा को आपने अशिक्षित सरपंचों के हाथों सौंप रखा है। और ये सरपंच और पंच जिनके हाथ में यह स्कूल है, ये आपके बच्चों के साथ किस प्रकार का खिलवाड़ कर रहे हैं, इसकी शायद आपको जानकारी नहीं है ...

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : जानकारी तो है।.....

श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत : कई बार सरपंच, शिक्षक महोदय आते ही नहीं हैं। बच्चों को यथा समय पढ़ाते नहीं हैं और ये शिक्षक महोदय छोटी सी दुकान लेकर बैठ जाते हैं और छोटा मोटा समान बेचते हैं। क्या आपने इस प्रकार से इसकी जांच की है ? मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में इस प्रकार की घटना होते हुए देखी है।

इसके साथ ही मैं एक बात और यह कहना चाहती थी कि आपकी इस शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है वह इतना ज्यादा है कि आपको इस परिमाणात्मक पर नहीं गुणात्मक तौर पर सुधारना चाहिए। एक छोटा सा बच्चा इतनी अधिक पुस्तकें स्कूल ले जाता है कि उनका भौतिक वजन तो वह उठा ही नहीं सकता तो उनका आत्मज्ञान कैसे करेगा ? इसके बारे में आपको सोचना होगा।

इसके साथ ही, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के जो बच्चे हैं और महिलाएं या बालिकाएं हैं उन्हें भी आपको विशेष प्रकार की कोई सहायता देनी होगी, और वह सहायता यह होगी कि उनको निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें दी जायं और इसके साथ–साथ स्कूल की जो ड्रेस है वह भी आपको फ्री देना चाहिए, क्योंकि बालिकाओं को शिक्षा के लिए इन्सेन्टिव देकर आकर्षित करना होगा।

मान्यवर, मैंने पहले भी यह बात कही थी कि एक अच्छे नागरिक के गुणों का विकास खेल के मैदान में ही होता है, परन्तु आपकी प्राथमिक स्तर की जो पाठशालाएं हैं वहां पर खेल का बजट शून्य के बराबर है। इस बजट को आपको बढ़ाना होगा। दूसरा मेरा सुझाव यह देना चाहती हूं कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को पुस्तकालय नहीं मिलता है। न उनको बाल साहित्य मिलता है, न पत्र-पत्रिकाएं मिलती हैं। आप एक चल पुस्तकालय क्यों नहीं रखते हैं ? वहां एक सामुदायिक स्तर पर चल–पुस्तकालय रखें अन्यथा वन्स ए वीक पाठशालाओं में जाकर वहां पर बाल–साहित्य वितरित करें। इसको आपको सोचना होगा।

मान्यवर, माध्यमिक शिक्षा जो है वह अन्धेरे में तीरन्दाज के समान है। वहां पर वह बच्चे जो हैं एक उद्देश्य हीन श्रम में लगे हुए हैं। उन्हें यह मालूम नहीं है कि हम क्यों हैं यहां और भविष्य में हम क्या करने जा रहे हैं ? आप इसमें कितने विद्यार्थियों का शिक्षण दे रहे हैं इसका कहीं विवरण नहीं है। कितने प्राथमिक शालाओं में बच्चे पढ़ रहे हैं और कितने माध्यमिक शालाओं में पढ़ रहे हैं यह कुछ नहीं है। आपका शिक्षा विभाग यह नहीं जानता है कि कितने बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। क्योंकि आपकी रिपोर्ट में कहीं वर्णन नहीं हैं।

आपने व्यवसायिक शिक्षा के बारे में बात कही है कि व्यवसायिक शिक्षा आरम्भ कर दी जायगी। परन्तु यह न हो कि जिस प्रकार से तकनीकी शिक्षा प्राप्त किये हुए युवक बेकार हैं उसी प्रकार से यह भी बेकार हो जायं। उसकी आपको इस प्रकार से स्थापना करनी होगी।

(श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत)

मेरा यह सुझाव है कि आप जो अन्य विषय हैं उनके साथ में एक स्पेशियेलाइज्ड सब्जेक्ट के तौर पर व्यवसायिक शिक्षा प्रारम्भ करें। सामान्य ज्ञान और भाषा ज्ञान के साथ साथ आप व्यवसायिक शिक्षा का विषय है, जैसे सिलाई, वढ़इगिरी, रेडियो मेकेनिक है और कई विषय हैं यह विषय माध्यमिक स्कूल के बच्चों को पढ़ायें। इसमें यह है कि आज जो हैं बच्चे जो माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करके नौकरी के लिए तलाश करते फिरते हैं तो आप उनमें एक ऐसी भावना उभारें कि वह स्वयं ही अपना मार्ग बनाने का साहस कर सकें और अपना एक विशेष प्रकार का रोजगार चला सकें।

मान्यवर, आज जो माध्यमिक पाठ्यक्रम है वह बहुत पुराने जमाने का है। उसमें क्या प्रकृति विज्ञान, क्या सामान्य विज्ञान, क्या वाणिज्य सभी पुराने विषय हैं। उनको बदलना होगा। विश्व की समस्याओं को आपको भारतीयता के रंग में रंगना होगा।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहती हूं कि माध्यमिक शिक्षा की जो आपकी परीक्षा-प्रणाली है वह बहुत ही डिफेक्टिव है। लड़के जो हैं वह स्वतः ही ज्ञान प्राप्त करके परीक्षा पास कर सकते हैं। आपने मार्केट में देखा होगा कि वन डेज सकसेस, सेवन डेज सकसेस मिलती हैं उनको विद्यार्थी लोग ले लेते हैं वर्षों तक कई अध्यापक भी इनसे पढते हैं। इस प्रकार से शिक्षा में यह जो चीज चल रही है वह शुरू से अन्त तक चलती रहेगी। इसमें दो काम करने होंगे, मान्यवर। एक तो सेमिस्टर सिस्टम भी माध्यमिक शिक्षा में करना होगा और आन्तरिक मूल्यांकन भी समय समय पर करना होगा। जो इस प्रकार की पुस्तकें मिलती हैं जिनको कुंजी कहते हैं उनको बिल्कुल बन्द करना चाहिए। बिना शिक्षा विभाग की अनुमति के किसी प्रकार का प्रकाशन मार्केट में न आये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

तो, मान्यवर, मैं जेल पर नहीं बोलूंगी। मेरा कटौती का प्रस्ताव दिया हुआ है। 5 मिनिट और दें। मैं शिक्षा पर ही बोलना चाहूंगी। मेरा उसका समय इसमें इन्क्लूड कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : समय हो गया है।

श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत : मान्यवर, मैं कहना चाहती थी कि इस प्रकार की कुंजियों को बन्द करना चाहिए।

एक और सुझाव माध्यमिक शिक्षा पर मैं देना चाहती हूं कि म्यूजियम कम्प्लेक्स, संग्रहालय संकुल वह आपको आरम्भ करना होगा। यद्यपि संग्रहालय संकुल के लिए आपके बजट में विशेष प्रकार का प्रावधान है, परन्तु वह इतना कम प्रावधान है कि; मान्यवर, आपका सारे का सारा संग्रहालय संकुल एक अलमारी में समा जाय, और उनमें जो चीजें रखी हुई हैं उन पर धूल चढ़ रही है। हर जिला स्तर पर संग्रहालय संकुल आपको डेवलप करना होगा जहां पर हर विद्यार्थी अपनी बनी हुई कृतियों को रख सके अपनी शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से। इससे विद्यार्थी विध्वन्सात्मक कार्यों से हटकर सृजनात्मक कार्यों में लगेगा। उनका आजकल सिनेमा ही एकमात्र मनोरंजन का साधन है, उसमें परिवर्तन आयेगा।

(श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत)

अनुशासनहीनता जो है वह माध्यमिक स्तर पर ही नहीं...

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज कन्क्लूड ।

श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत : महाविद्यालय स्तर पर भी दिखाई देगी। क्या कभी आपने इस विषय पर सोचा है ? सभी लोग कहते हैं कि विद्यार्थी अनुशासनहीन हैं । लेकिन जरा विश्लेषण इसका आप कीजिये । मेरी समझ में एक बात यह आती है सबसे बड़ा कारण यह है कि अध्यापकों का चुनाव ठीक प्रकार से नहीं होता है। योग्य अध्यापक वहां पर नहीं पहुँच पाते हैं । क्यों नहीं पहुँच पाते हैं, मान्यवर ? शैक्षणिक संस्थाओं में जो व्यक्ति काम करते हैं और वह व्यक्ति जो भौतिक खुराक देता है और उसके साथ-साथ सोसाइटी का जो क्रीम है उसकी तुलना प्रशासनिक सेवा या पुलिस सेवा से नहीं कर सकते हैं। उनके वेतनमान में अन्तर रखना होगा तभी जाकर इस ओर अच्छे व्यक्ति आ सकेंगे, सोसाइटी का क्रीम आ सकेगा ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहती थी कि आज जो है शिक्षकों और शिष्यों का जो सम्बन्ध है वह टेपरेकार्डर तथा भीड़ का हो गया है । इस प्रकार के जो संबंध हैं उनको मिटाने के लिए आपको ट्यूटोरियल कक्षाएं आरम्भ करना होगा, और साथ ही साथ अध्यापकों की संख्या में वृद्धि करनी होगी, वर्तमान जो संख्या है उसमें वृद्धि करना होगा ।

मान्यवर, अनुशासनहीनता का एक कारण यह भी है कि विद्यार्थी की जो आवश्यकता की चीजें हैं वे उसको नहीं मिल पाती हैं । गुजरात में जो हिंसात्मक आन्दोलन हुआ उसका रूट यही है और अन्य राज्यों में इस प्रकार के कारण हैं जिनकी वजह से आन्दोलन होते हैं। हमारे समाज का यह भावी कर्णधार है जो कि अपने निर्माणकाल में है उसको कम से कम रोटी की चिन्ता से मुक्त करें । कई प्रजातन्त्रीय देशों में विद्यार्थियों को इस प्रकार की सुविधाएं देते हैं । मैं पश्चिमी जर्मनी का उदाहरण देती हूं कि वहां पर जो ब्रेड 20 मार्क्स में मिलती है वह ब्रेड ढाई या तीन मार्क में विद्यार्थियों को मिलती है । तो हमको खाने पीने की चीज में कन्सेशन देना चाहिए कोआपरेटिव सोसाइटीज दूसरे अन्य माध्यम से, बच्चों को हौस्टल्स में जो चीजें मिलती हैं तो उनमें जरूर कन्सेशन करें ताकि हमारी भावी पीढ़ी को रोटी की चिन्ता न रहे । हौस्टल्स में मैंने कई बार अपने जीवन में यह बात देखी है ।

श्री उपाध्यक्ष : शुड आई एक्सरसाइज माई डिस्क्रीशन नाऊ ? बी वाचफुल आफ टाइम ।

श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत: मैं समाप्त कर रही हूं।

आज इस रिपोर्ट में यह बात कही गई है कि हमारे यहां 74741 विद्यार्थी वे हैं यह शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं । तो टोटल पोपुलेशन का 0.4 पर्सेन्ट इतना सा प्रतिशत प्रभावित प्रतीत होता है । उसी से आप डरते हैं ।

यह अपने जीवन के बीस बसन्त इस आशा से गुजार रहा है कि उस को काम

(श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत)

मिलेगा। परन्तु उसको काम नहीं मिल पाता है। तो उसमें आक्रोश पैदा होता है। उसे आज की शिक्षा ने भटका दिया है। केवल भटकाव और निराशा दी है। मान्यवर, यदि इसी प्रकार से शिक्षा देते रहे तो इसी प्रकार से युवकों में आक्रोश भी देते रहेंगे। आपने पोस्ट ग्रेजुएट कालेज खोलने की बात कही मेरे निर्वाचन क्षेत्र चित्तौडगढ़ में भी खोलने की बात है। तो मेरा निवेदन है कि उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश देना चाहिए, जो पढ़ना चाहते हैं। केवल अपना मनोरंजन करने के लिए या राजनीति का अखाड़ा बनाने के लिए नहीं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : वही आयेंगे।

श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत : विश्वविद्यालयों की जो शिक्षा है, उसके बारे में दूसरे देशों में बहुत अन्तर आ चुका है। आपको भी उसी प्रकार से परिवर्तन लाना होगा। आज आपके राजस्थान विश्वविद्यालय में, उन्होंने विद्यार्थियों के साथ में मजाक कर रखा है। यह पहले भी सदन में कहा गया है। भाषा हिन्दी, अंग्रेजी एक साइज में पास करना जरूरी नहीं, उसका जो पेपर है, वह तीसरे वर्ष में भी पास कर लें। कभी भी पास कर लें। लेकिन उसके नम्बर उसमें नहीं जोड़ते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि शिक्षा शास्त्रियों के दिमाग में थोड़ी सी बात नहीं आई कि लैंगवेज इज दी व्हीकल ऑफ कलचर है। उसको प्रधानता नहीं देंगे तो किस प्रकार से विद्यार्थी बढ़ सकता है। मैं अपने अनुभव से कह सकती हूं कि आज का ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट जो निकले हैं उनको न तो हिन्दी में सही लिखना आता है और न अंग्रेजी में ही सही लिखना आता है।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत : मैं निवेदन करती हूँ कि आपने शिक्षा के क्षेत्र में जो दुकानें खोल रखी हैं, जैसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लिए उनका एक निश्चित कोटा रखना चाहिए। वह पूरा करें, तभी उनको आगे ग्राण्ट दें। विश्वविद्यालयों में सेमेस्टर सिस्टम लागू करना चाहिए। मान्यवर, मैं यूथ केन्द्र के बारे में निवेदन करूंगी कि उनको केवल दफ्तरी कार्यालय ही नहीं बनाना है। बल्कि एक अभिभावक की तरह से उनको मार्ग प्रदर्शन करना है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, अभी दो मिनट में समाप्त कर रही हूं। सिर्फ दो मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : Now I think you should conclude.

श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत : मान्यवर, मैं यह कहना चाहती हूं कि ये केन्द्र दो खण्डों के रूप में होने चाहिये। एक तो युवा मंच और दूसरा युवा नव उद्यमी संगठन। मंच इसलिए आवश्यक है जिससे कि वह अपना आत्म प्रदर्शन कर सकें। उनके जो आत्म प्रदर्शन करने की प्रवृत्ति है, उनको वह प्रदर्शित कर सकें। दूसरे खण्ड में जो विद्यार्थी किसी विशेष दिशा में जाना चाहते हैं, जैसे कि वह किसी रोजगार में लगना चाहते हैं, तो उनको प्रोत्साहन

(श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत)

और सुविधा मिलनी चाहिये। और उनकी बनाई हुई चीजों को मार्केट की सुविधा दें।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया: उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री उपाध्यक्ष: श्री रतीराम। (अनुपस्थित)

आप बोलना चाहते हैं? (श्री इन्दलिया से)

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में शिक्षा के बारे में चर्चा हो रही है। बहुत से माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि हमें अगर शिक्षा का सुधार करना है, और शिक्षा को मजबूत करना है तो आप इस बात को ज्यादा दिन तक रोक नहीं सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा आप जिला परिषद्, पंचायत समितियों और जिला परिषद् को आप जब तक मिडिल स्कूल तक नहीं करेंगे तब तक निश्चित रूप से मेरी मान्यता है, आप सफल नहीं होंगे। आज शिक्षा में जो असफलता है, वह उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए ज्यादा है कि आपने जो हमारे नीचे के जन प्रतिनिधि हैं, पंच हैं, सरपंच हैं...

(3.19 म.प.)

(श्री फूलचन्द जैन, सभापति, पीठासीन)

मेम्बर हैं। आपने उनको साथ में नहीं लिया है। आपने डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं रखा है। इसलिए शिक्षा में धीरे धीरे आप फेल होते जा रहे हैं। मैं चाहूंगा सभापति महोदय, इसीलिए जो पावर है मिडिल स्कूलों की है वह पंचायत समितियों और जिला परिषदों को देना चाहिये ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का जल्दी विकास हो सके और ग्राम के जो विद्यार्थी है, वह वहां पर शिक्षा प्राप्त कर सके लेकिन मेरी समझ में नहीं आता है कि आपने इतने वर्षों तक क्यों रोक रखा है। अब समय आ गया है। वक्त रहते हुए आप इस ओर ध्यान नहीं देंगे तो मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि लोग इस बात को लेकर खड़े होंगे। आपको अधिकार देना होगा। मैं सभापति महोदय, लम्बा भाषण न देकर कुछ बीकानेर जिले के बारे में जो मेरा निर्वाचन क्षेत्र है मैं अपने कटौती प्रस्तावों के जरिये आपकी मारफत प्रस्तुत करना चाहूंगा। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक जसरासर गांव है। बीकानेर जिले में यह सबसे बड़ा गांव है। उसकी आबादी साढ़े 9 हजार है। वहां पर मिडिल स्कूल है, परन्तु उसको हायर सैकेण्डरी नहीं किया गया है। इसके लिए मुझे बड़ा खेद है। हायर सैकेण्डरी स्कूल के लायक वहां पर जनता ने भवन भी बना रखा है। पर ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार ने बहुत ढील बरती है। इसी तरह से मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक पांचू गांव है। उसकी आबादी भी जसरासर जितनी ही है। लेकिन हायर सैकेण्डरी स्कूल की तरफ ध्यान नहीं दिया गया है। एक ग्रामीण बच्चा बाहर जाकर शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता है बाहर जाकर पढ़ने की उसकी श्रद्धा नहीं है। आप जानते हैं कि शिक्षा में ज्यादा हिसाब चलता है। इस बात को भूल नहीं सकते हैं। जो हमारे गांवों के बच्चे हैं, वह आर्थिक संकट के कारण शहर की शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार से नागौर और

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

बीकानेर की सीमा पर बंधना पहाड़ी गांव है। वहां पर मकान बना हुआ पड़ा है। 12 लाख रुपये का मकान पब्लिक ने बनाया है। इसके बावजूद भी वहां पर स्कूल नहीं खोला गया है।

सभापति जी, इस तरह से करबा नोखा मण्डी एक बहुत अच्छा, सुन्दर ढंग का, सजावट-बसावट का शहर है। वहां पर गट्टानी गर्ल्स स्कूल का भवन पचास हजार का मकान जनता ने बना दिया। परन्तु खेद है कि लड़कियों के लिए वहां हायर सैकेण्डरी स्कूल की आज तक व्यवस्था नहीं की गई है। मैं चाहता हूं, आपकी मार्फत, राज्य सरकार इस वर्ष इस ओर ध्यान देकर गट्टानी गर्ल्स हायर सैकेण्डरी स्कूल खोल दे तो बहुत मेहरबानी होगी।

इसी तरह से, माननीय सभापति, नोखा में एक सेठ श्री मांगीलाल जी बागड़ी ने करीब पन्द्रह लाख रुपये की राशि लगा कर एक कालेज भवन का निर्माण किया है लेकिन इतना लम्बा अर्सा बीतने के बाद नोखा तहसील का सवाल है, डेढ़ लाख की जन संख्या होते हुए भी तीस मिडिल स्कूल और एक हायर सैकेण्ड्री स्कूल होने के बावजूद कालेज की व्यवस्था नहीं की गई है। मैं मानता हूं कि राज्य सरकार कहती है कि गवर्नमेण्ट की काश्तकारों के प्रति सहानुभूति है, लेकिन वह सहानुभूति नहीं है क्योंकि वहां व्यवस्था नहीं है शिक्षा की। मैं आपके मार्फत चाहूंगा कि गांव के लोगों के साथ इस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में उपेक्षा का व्यवहार न किया जाये, हम इसे ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें वहां कालेज बनाने को अपनी मांग को मनवाने के लिए कुछ करने को मजबूर होना पड़ेगा।

माननीय सभापति, बीकानेर जिला हैडक्वार्टर एक बहुत अच्छा शहर है, बहुत बड़ा शहर है और सीमावर्ती शहर है। इस नाते राज्य सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्र में शिक्षा के मामले में ध्यान नहीं दिया–यह बात दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं चाहूंगा वहां बीकानेर में यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। इस विधान सभा की याचिका समिति ने रिपोर्ट भी दी है कि वहां यूनिवर्सिटी होना बहुत जरूरी है, बहुत लाजिमी है। लेकिन खेद है, सीमा का जिला होने के नाते भी राज्य सरकार ने ध्यान नहीं दिया है। मैं लम्बी बहस में न जाकर दूसरे मेरे जो कटौती के प्रस्ताव हैं उनको आपके मार्फत प्रस्तुत करता हूं।

श्री सभापति : श्री सांवरमल मीर!

(अनुपस्थित)

श्री झाबरमल सूंडा!

(अनुपस्थित)

श्री भीमसेन!

(अनुपस्थित)

श्री अमृतलाल गहलोत

(अनुपस्थित)

श्री नारायण सिंह मसूदा!

श्री किशन मोटवानी : नम्बर से मौका दीजिये।

श्री नारायण सिंह (मसूदा) : सभापति महोदय, शिक्षा के विषय में चर्चा चल रही है।

श्री किशन मोटवानी : नम्बर से चलिये।

श्री नारायण सिंह : शिक्षा के विषय में बराबर चर्चा चलती रहती है। हमेशा यह कहा जाता है, शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन लाया जाय। जैसा निर्मलाजी ने कहा, हम परम्परागत शैली को पकड़े हुए हैं। मैं आपसे निवेदन करूं, चाहे मंत्री कुछ भी चाहे, मैं भी शिक्षा मंत्री रहा हूं, आचार्य जी ने मुझे संकेत कर दिया था, शिक्षा मंत्री बहुत थोड़े दिन रहते हैं, वह मैंने अनुभव किया, और अन्य भी रहे वे भी थोड़े थोड़े दिन रहे···

श्री ओंकारलाल चोहान : भविष्य-है क्या ?

श्री नारायण सिंह : मैंने कहा, मंत्री चाहें जो रहे, यदि इस प्रकार के शिक्षा शास्त्री होंगे, मैकाले पद्धति के अन्दर बिल्कुल प्रतिष्ठित हों, तो वह हमारी शिक्षा पद्धति को कहां तक अलग तरह की करेंगे या और करेंगे, क्या बुनियादी परिवर्तन करेंगे। वह तो मैकाले के आधार पर शिक्षा का ढांचा बनाना चाहते हैं। मैं निवेदन करूं, उस समय की भावनायें क्या थीं, जो मैकाले का कोटेशन है, वह मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं:—

"It is confessed that the language, Sanskrit, is barren of useful knowledge. We are to teach it because it is fruitful of monstrous superstitions. We are to teach false history, false astronomy, false medicine because we find them in company with a false religion. It is, I believe, no exaggeration to say that all the historical information which has been collected from all the books written in Sanskrit language is less valuable than what may be found in the most paltry abridgements used at preparatory Schools in England. A Single shelf of a good European library was worth the whole native literature of India and Arabia."

उसने आगे यह भी लिखा है:—

"We must at present do our best to form a class who may be interpreters between us and the millions whom we govern; a class of persons, Indians in blood and colour, but English in tastes, in opinions, in morals and in intellect."

जो आजादी के बाद, पच्चीस साल के बाद अंग्रेजी नहीं छोड़ सकते, हिन्दी के ऊपर नहीं आ सकते, आते शर्म आती है, यह इस का कारण है, ऐसे व्यक्ति जो पैदा हो गये, चाहे वह शिक्षा शास्त्री हों, चाहे और कोई हों वह सिवाय इंगलिश पद्धति के, उपनिवेशवादी पद्धति के कुछ सोच नहीं सकते। गांधीजी ने हमारे सामने लाकर रखा था, बेसिक स्कूल, उसको हमने ट्राइ नहीं किया। अभी किसी ने शिकायत की, मुझे याद है थोड़े दिन ट्राई करके सदा के लिये छोड़

(श्री नारायणसिंह मसूदा)

दिया। वोकेशनल स्कूल के अन्दर प्रेक्टिकल ट्रेनिंग होती थी, उसको छोड़ दिया। और प्राईमरी स्कूल का ढांचा आपने अपने ढंग का बना दिया। उसके बाद हम कहते कि वोकेशनलाइजेशन करेंगे और शिक्षा पद्धति को बदलेंगे, जिसमें पहले 11 साल और फिर 3 साल-11 साल की हायर सैकेण्डरी एजूकेशन रखी, तीनसाल की ऊपर की एजूकेशन रखी। अब करना चाहते हैं, दस साल तक एक रहेगी और दो साल की टेक्निकल, वोकेशनल एजूकेशनल मिल जायगी-इस प्रकार 12 साल की हो जायगी। असलियत में यह कन्फ्यूजन इसलिए है क्योंकि शिक्षा शास्त्रियों का मैकाले पद्धति का माइण्ड बना हुआ है, इसलिए मैकाले पद्धति है और उपनिवेश-वादी पद्धति तो है ही। उसके बाद सोशल पैटर्न की बात को कहते हुए भी नहीं समझ सकते। होता क्या है, इसमें एजूकेशनल क्वालिफिकेशन में दस नहीं, ग्यारह साल इतनी एजूकेशन का न्यूट्रिशन किया जाता है जिससे वह अपने पांवों पर खड़े हो सकें, और वोकेशन में जाते हैं तो प्रेक्टिकल ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। वैसे उसमें यह होना चाहिए कि 11 साल के पश्चात् स्वयं व्यक्ति एम्प्लायमेंट पा सके और उसके बाद जो डिग्री मिलती है वह मिलती रहे। इन चीजों पर सोचते नहीं और वोकेशनल सिस्टम करना चाहते हैं। सोचे तो सही, वोकेशनल सिस्टम, जैसा निर्मलाजी ने कहा, आदर्शहीन है। आपको श्रम और उद्योग-इसके अन्दर उनको ट्रेन्ड करना चाहिए। यह क्या करना चाहते हैं। कौन से वोकेशन के साथ आप लगायेंगे, कौनसी इन्डस्ट्री को आपने आज तक नेशनलाइज कर दिया है छोटी-छोटी या बड़ी बड़ी जिनके साथ आप इन स्कूलों को लगा कर प्रेक्टिकल ट्रेनिंग दे सकेंगे। इतना ही नहीं, पोलीटेक्निक चला रहे हैं, पोलीटेक्निक एक बहुत ही गजब का सिस्टम उद्घाटित किया। पोलीटेक्निक से मामूली, छोटे मोटे उद्योग में प्रवृत हो सकता है व्यक्ति और स्वाव-लम्बी हो सकता है। स्वचालित उद्योग चला सकता है। परन्तु पोलीटेक्निक स्कूल बन्द करने पड़े क्योंकि उसके बाद एम्प्लायमेंट नहीं मिलता था। हमने फोलो अप प्रोग्राम किया नहीं, जिससे वोकेशनल, पोलीटेक्निक शिक्षा के पश्चात् आगे बढ़े। आगे बढ़ाना है तो पोलीटेक्निक शिक्षा को बढ़ायें। यूनि-वर्सिटी को बढ़ा कर करेंगे क्या? एम. ए., बी.ए. पास करके करेंगे क्या? लेकिन आज यह चीज कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूं, इस शिक्षा पद्धति से आज शिक्षक और विद्यार्थी इतने असंतुष्ट हैं, और इतने कन्फ्यूजन में हैं कि अपने आपको चीर-फाड़ देना चाहते हैं। आज उच्छृंखलता है इसी कारण से, अनुशासनहीनता है, इसी कारण से यह बातें कर रहे हैं। वह चाहते हैं कि कोई मार्गदर्शन मिले जिससे उनके जीवन में संतोष हो सके, नामाकूल न हो जायं, इन्कांगुग्रस न हो जायं बड़ों के साथ इन सब बातों से चिन्ता होती है। मैं इसके बारे में आगे निवेदन करूंगा।

इसके पहले कुछ बातें यूनिवर्सिटी एजूकेशन, प्रोफेसर, रीडर और लेक्चरार के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। जब यूनिवर्सिटी बनी तो प्रोफेसर, रीडर की पोस्ट ओपन हुई और बाहर वालों को ले लिया। उसके बाद लेक्चरार की बात

(श्री नारायणसिंह मसूदा)

आयी। लेक्चरार की पोस्ट के लिए पहले एफीलियेटेड कालेज वालों को आप्शन दिया गया, यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं या कालेज में रहना चाहते हैं और फिर जो पोस्ट्स क्रीएट की गई आल इंडिया बेसिस पर उनके अन्दर काम्पटीशन रखा गया जिसका परिणाम यह हुआ कि लोकल टैलेंट को रेकग्नीशन नहीं मिला, बाहर के लोग आकर भर्ती हो गए। आज-एडहॉक पोस्ट्स भरी गई हैं और जो गत 7-8 सालों में लेक्चरार्स भर्ती हुए वे अधिकांश बाहर के ही हैं। इस प्रकार विश्वविद्यालय के लेक्चरार्स को प्रमोशन चांसिज नहीं हैं क्योंकि ऊपर की पोस्ट्स सब सिलेक्शन पोस्ट्स हैं उनमें ज्यादातर बाहर वालों को मौका दिया जाता है, इस कारण लेक्चरार, रीडर और प्रोफेसर का संघर्ष पैदा होता है। यह संघर्ष यूनिवर्सिटी एजूकेशन के अन्दर है। जो दुर्व्यवस्था, अनुशासनहीनता आई है, बेसिक कारण उसका यही है। जब पढ़ाने वाला ही कन्फ्यूज्ड है, असंतुष्ट है, उसके अन्दर खयाल ही नहीं तो पढ़ने वालों को क्या नागरिकता सिखाएगा, क्या अनुशासन सिखाएगा? जूनियर टीचर का जो प्रोमोशन होता है, वह काम्पटीशन से होता है और इसलिए उसे इस बात की फिक्र रहती है कि रिसर्च पेपर करे बजाय इसके कि वह अच्छी तरह से पठन पाठन का कार्य करे। उसका परिणाम यह होता है कि न हिंदी सीखी न अंग्रेजी सीखी। ऐसे लोग पढ़कर आगे बढ़ते हैं और जिस प्रकार की स्थिति पैदा करते हैं, वह हमारे सामने है। टीचिंग की तरफ उनका ध्यान नहीं रहता है। होना यह चाहिए कि जैसे 5-6 साल से यूनिवर्सिटी टीचर्स की मांग है, 10 साल की सर्विस वाले लेक्चरार को स्वतः ही रीडर बनाया जाए, वैसे ही 10 साल की सर्विस वाले रीडर को प्रोफेसर बनाया जाए। कुछ सिलेक्शन पोस्ट्स आप रख सकते हैं उसमें कोई एतराज नहीं।

राजस्थान विश्वविद्यालय एक कोलासल विश्वविद्यालय बन गया है जिसमें 140 एफिलिएटेड कालेजिज हैं और 1.25 लाख परीक्षार्थी होते हैं हर वर्ष, फिर कालेजों के 3500 टीचर्स और 600 यूनिवर्सिटी टीचर्स। रूटा की शिकायत है और मैंने अपने मंत्रित्व के समय में भी यह बात कही थी कि विश्वविद्यालय में बाहर के लोगों को प्रफरेंशल व्यवहार मिल जाता है और निर्णय लेने वाली बोडीज हैं सिंडीकेट, एकेडेमिक काउंसिल इन सब में रूटा का प्रतिनिधित्व नगण्य है और एकेडेमिक काउंसिल में कोई आवाज नहीं है। सारे डिसीजन्स डीन्स आफ फैकल्टीज, कन्वेनर्स आफ बोर्ड आफ स्टेडीज द्वारा होते हैं। इसलिए बरकत साहब से सलाह करके मैंने आवाज उठाई थी, उस समय ए.बी. लाल वाइस चांसलर जो मेरे स्वयं के गुरु रहे थे यूनिवर्सिटी में, से सलाह लेकर हमने इस बात को उठाया था कि एक एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। किसी ने पूछ लिया कि कहां होनी चाहिए, मैंने अजमेर का नाम नहीं लिया, परंतु उस बात को लेकर कुछ और गलत चीज जोड़ी गई, आखिर में हुआ क्या? यह हुआ कि बरकत साहब ने स्वयं ने कहा कि कमेटी बनाये तो श्रीमाली कमेटी बन गई केवल इसलिए कि सब पर ठंडा छींटा डाला जाए। अगर यू. पी. में 3-4 यूनिवर्सिटीज बन सकती हैं तो यहां पर यद्यपि मैं यूनिवर्सिटी

(श्री नारायणसिंह मसूदा)

एजूकेशन को बहुत ज्यादा बढ़ावा देने के फेवर में नहीं हूं, प्रैक्टीकल एजूकेशन को बढ़ावा देने के फेवर में हूं लेकिन कम्पेरेटिव हिसाब से कहना चाहता हूं कि अगर यूनिवर्सिटी खोलनी है तो बीकानेर, कोटा या अजमेर में खोलिए। अगर इसकी जरूरत नहीं है तो आप सीमित रहें, आप आटोनोमस कालेजिज को आगे बढ़ायें, जो छोटे छोटे कालेजिज हैं उनको आटोनोमस स्टेटस दें जिससे कि वे अपनी शिक्षा पद्धति को आगे बढ़ा सकें।

दूसरी बात, यू. जी. सी. ने यूनिवर्सिटी टीचर्स के लिए नई पे स्केल्स रिकमेंड कीं। बड़ा विवाद उठा कि अगर इनके वेतन-मानों में बढ़ोतरी की जाएगी तो राजस्थान के बजट में खलबली मच जाएगी और आर. ए. एस. वाले मांगने लगेंगे, छोटे टीचर्स मांगने लगेंगे। वास्तव में हमारा ये स्ट्रेक्चर अनसोशलिस्ट है इसलिए ये दिक्कतें पैदा होती हैं। मिनीमम पे स्केल हम रखें छोटे से छोटे कर्मचारी के लिए और मैक्सीमम पे स्केल रखें बड़े से बड़े कर्मचारी के लिए और फिर आगे बढ़ें। समाजवादी देशों में भी टैलेंट को, साइंटिस्ट्स को, पूरा वेतन दिया जाता है, पूरा इनाम दिया जाता है। मैं जिस समय रूस गया था और खास तौर से वहां एक प्रदेश की राजधानी है, मैं उस शहर का नाम भूल रहा हूं, उस समय मैं प्रोफेसर से मिला। उन्होंने सारी चीजें बताई कि उनके वेतन मान क्या हैं। इन सब को देखकर हमारे लिए शिकायत है, जो नये नागरिक बनाने वाले लोग हैं उनको अगर अच्छी पे स्केल्स देकर संतुष्ट रखें तो क्या हर्ज है? प्राइमरी टीचर्स को उसी प्रकार पे स्केल्स दें तो कोई हर्ज नहीं, थोड़ा सा भार पड़ेगा। आखिर हम नशाबंदी के लिए 80 करोड़ घाटा भुगतने के लिए तैयार हैं तो इस समाजवादी कदम के लिए 80 करोड़ खर्च करने के लिए क्यों नहीं तैयार हों। स्टाफ में कमी करें।

प्राइवेट कालेज और स्कूल टीचर्स को जहां तक सिक्योरिटी देने का सवाल है। उनके लिए पी. एफ. का प्रावधान करें जिस प्रकार से विश्वविद्यालय में है। उन्होंने 8-1/3 पर्सेंट रिकमेंड किया है आप 6-1/4 पर्सेंट दें लेकिन उनको यह सिक्योरिटी देनी चाहिए और दूसरे प्रकार की सिक्योरिटीज प्राइवेट कोलेजों को, प्राईवेट संस्थाओं को, वहां के टीचर्स को देनी हैं, वे देनी चाहिए। इस बारे में भी जब मैं मंत्री था तब प्रयत्न किया था, मैं समझता हूं आगे भी प्रयत्न चलते होंगे, लेकिन यह बहुत आवश्यक है।

रिटायरमेंट एज का जहां तक सवाल है, अगर यूनिवर्सिटीज में 62 साल में रिटायर किया जाता है तो कोई कारण नहीं कि दूसरी जगह कालेजों में 58 सालों में क्यों रिटायर किया जाता है। जितना वयोवृद्ध व्यक्ति होगा उतना ही उसकी शिक्षा के अन्दर खूबी रहेगी।

स्कालरशिप का सवाल आता है। 10-15 सालों से 50 से 75 रुपये ही प्रतिमाह चल रही है, इसमें भी 50 पर्सेंट राइज करने की आवश्यकता है। यूनिवर्सिटी स्कालर्स को जब स्कालरशिप दी जाती है तो कम से कम ऐसे स्कालर्स को भी, 50 रु. ही सही, देना जरूरी है। अब मैं एक मुद्दे की बात और कह कर अपना स्थान ग्रहण करूंगा। स्टुडेन्ट इन

(श्री नारायणसिंह मसूदा)

डिसिप्लीन की बात करता हूं । आखिर आज स्टूडेन्ट्स में इनडिसिप्लीन है क्यों । यह असन्तुलन इनमें आया क्यों । सबसे पहली बात तो यह है कि आज स्टूडेन्ट सोचता है कि वह कामन मेन की तरह सोसायटी में एडजस्ट हो सकेगा या नहीं, यह शक उसको खा जाता है । दूसरी बात है, एडम्स थ्योरी-एडम्स स्मिथ के फ्री कम्पीटीशन, लैसेज फेयर की सोसायटी में पनप सकेगा या नहीं । एवर इन्क्रीजिंग वान्ट की थ्योरी को हमने प्रेक्टिस में तो ले ली लेकिन from each according to ability, to each according to need. को कैसे समझें । यह जो थ्योरी आज मार्क्स की है उसको ऊपर ले जाने के लिए रास्ता दूसरा होता है जो एक वाद का विषय है । मैं उसमें नहीं जाना चाहता । जिसको हम चाहते भी नहीं हैं । आज हम सोशियलिस्टिक डेमोक्रेसी को तो चाहते हैं परन्तु गांधियन आइडल को नहीं चाहते । गांधीजी ने कहा था कि ever decreasing wants, कम से कम यह तो होना चाहिये कि समाज में किस प्रकार से रहना चाहिए, उनको स्वस्थ भोजन मिले, उनकी ड्रेसेज ठीक हों, और सब प्राथमिक चीजें ठीक हों, इस प्रकार की बातें भी सिखाई जानी चाहिये । आज टीचर्स भी ऐसे होने चाहिये जिनमें कम से कम इतनी लियाकत हो । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे मेरे क्षेत्र मसूदा में ही एस. टी. सी. का स्कूल चलाया जा रहा है । मेरे किले के अन्दर चल रहा है । उसमें जो तस्वीरें हैं उनको देखने के लिये जो टीचर्स हैं जिनको एस.टी.सी. में शिक्षा दी जा रही है जो भावी टीचर्स हैं वे कांच फोड़कर और डन्डों से तोड़कर अन्दर आते हैं । यह जो सिविक सेन्स है उनके अन्दर, इसके साथ में हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि इस प्रकार एस. टी. सी. में से निकले हुए जो प्राथमिक अध्यापक हैं, वे स्कूल में क्या गुणात्मक शिक्षा दे सकेंगे जिनकी खुद की हालत ऐसी है, उनमें इस प्रकार का सिविक सेन्स है । यह सब क्या है । केवल कोर्स सुनने से ही शिक्षा नहीं हो गई । मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे जमाने में जब हम पढ़ते थे, हाईजीन की एक पतली सी किताब हुआ करती थी उससे काम चल जाता था और आज नेचुरल साइन्स की एक बहुत भारी किताब रटते रटते थक जाते हैं । सारी हाईजीन तो उसके पढ़ने में ही खत्म हो जाती है । इसलिए मेरे ख्याल से शिक्षा शास्त्रियों को शारीरिक रूप से शिक्षित करायें, उनका एक एस. टी. सी. स्कूल हो और उसमें इसी प्रकार की उनको शिक्षा दी जाय कि किस प्रकार की शिक्षा की आज जरूरत है, उसकी जो जरूरत है वह शिक्षा दी जा सके । हमारे सेक्रेट्री साहब यहां मौजूद हैं वह सोच रहे होंगे परन्तु वह तो शिक्षा शास्त्री हैं नहीं । इसके अलावा आज हम देख रहे हैं कि सरकार का दखल यूनिवर्सिटीज एडमिनिस्ट्रेशन में और दूसरी आटोनोमस बोडीज में बहुत ज्यादा हो गया है । इतना ज्यादा दखल भी आवश्यक नहीं है । मुझे याद है कुछ एम. एल. ए. वहां विद्यार्थियों को लेकर अन्दर चले गये, उस पर काफी कमेन्ट्स आये थे, जब मैं शिक्षा मन्त्री था । परन्तु मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह हस्तक्षेप सीमित होना चाहिये । यह नहीं कि पुलिस डन्डा लेकर यूनिवर्सिटीज में घुस जाय और आटोनोमस टीचिंग मेथड जो अपनी एक अध्ययन और शिक्षण की एक शैली है उसको इससे बनाये रखने में,

(श्री नारायण सिंह मसूदा)

बाधा आयेगी। समय का संकोच है इसलिए मैं इतना ही निवेदन करके अपना स्थान ग्रहण करूंगा और आशा करता हूं कि कभी न कभी भूले-भटके शायद इस जगह पर बैठ कर हम सही प्रकार की शिक्षा का एक सोशियलिस्टिक पेटर्न बना सकेंगे और प्लान के अनुकूल इस प्रकार की शिक्षा बना सकेंगे।

श्री रामगोपाल : माननीय सभापति महोदय, आज शिक्षा और जेल की मांगों, जिन पर सदन के कई माननीय सदस्यों ने अपने सुझाव दिये, पर मैं भी अपने विचार रखता हूं। मेरे पूर्व वक्ता माननीय भूतपूर्व शिक्षा-मन्त्रीजी श्री मसूदा साहब ने जो जो सुझाव अभी दिये हैं मैं समझता हूं कि जब वे शिक्षा मन्त्री के पद पर थे अगर उनमें से कुछ सुझावों को क्रियान्वित करते तो निश्चित रूप से आज हमारी जो शिक्षा प्रणाली है जिसमें हम परिवर्तन लाना चाहते हैं, जिसमें हम सुधार लाना चाहते हैं और जब शिक्षा मन्त्री की हैसियत से कहते हैं, कि शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन करना है, हमको शिक्षा प्रणाली के अन्दर एक बदलाव देना है जिससे शिक्षा पद्धति में सुधार हो सकता है, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो शक्ति आज उनको यह कहने के लिये सदन में लगानी पड़ी वह नहीं लगानी पड़ती माननीय सभापति महोदय, शिक्षा प्रणाली के अन्दर, आज हम कितना ही कहें कि हमको शिक्षा प्रणाली में आमूल चूल परिवर्तन करना है, हमें शिक्षा प्रणाली में एक बदलाव लाना है, कितनी ही बातें इसके लिए कही जायं लेकिन मैं दावे के साथ यह कह सकता हूं और दोनों शिक्षा मन्त्री महोदय यहां मौजूद हैं, मसूदा साहब ने भी यह कहा है, यह दुर्भाग्य की बात है कि चाहे इसको कुछ भी समझें, शिक्षा विभाग किसी मन्त्री के पास बहुत ही कम समय के लिये रहता आया है। इसलिए, सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वे यदि अपने कार्यकाल के अन्दर शिक्षा प्रणाली में कोई सुधार ला सकें तो लोग उनको याद करेंगे। मैं यह कहना चाहूंगा, सभापति महोदय, कि शिक्षा हमारी ऐसी होनी चाहिए जो आदर्शों के मूल्यों से भरी हुई हो, शिक्षा ऐसी हो जो नैतिकता के मूल्यों से भरी हुई हो और शिक्षा ऐसी दी जाय जो चरित्र के मूल्यों से भरी हुई हो। शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए, माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं, जो स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती हो, वहां की स्थानीय समस्याओं को देखते हुए, राजस्थान के अन्दर वहां की समस्याओं के कारण, वहां के निवासियों को किस प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता है, यह सब बातें सरकार को सोचनी चाहिये और उसी के अनुसार पाठ्यक्रम लागू करना चाहिए। आज हम यह मानकर चलें कि यदि हमारी शिक्षा प्रणाली में यह कमियां होंगी तो निश्चित रूप से, बार बार यह मसला इस सदन में आता है, विद्यार्थियों में असन्तोष की भावना, आक्रोश की भावना और अनुशासनहीनता की भावना उत्पन्न होना स्वाभाविक है, वे तोड़-फोड़ और संघर्ष की ओर जायेंगे। माननीय सभापति महोदय, मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि हमारी शिक्षा प्रणाली में आज यह चीजें नहीं हैं, हमारी शिक्षा प्रणाली में आदर्श नहीं है, नैतिकता नहीं है वह चारित्रिक मूल्यों से भरी हुई नहीं है। इसलिए जब

(श्री रामगोपाल)

सत्र इस सदन का चलेगा यही समस्या हमारे सामने आयेगी। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि हमारी शिक्षा प्रणाली में यह सब चीजें नहीं होने की वजह से छात्रों को क्या करना पड़ता है, बार बार उन संस्थाओं में एडमीशन लेते हैं, बेरोजगार होने की वजह से उनमें असन्तोष फैलता है। उनके अन्दर नैतिकता और चारित्रिक मूल्यों की कमी होने की वजह से वे अनुशासनहीनता में उलझ जाते हैं, तोड़ फोड़ मचाते हैं और आन्दोलन का रास्ता अपनाते हैं। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं यदि हमारी शिक्षा प्रणाली आदर्शों, नैतिक मूल्यों और चारित्रिक मूल्यों से भरी हुई होगी तो निश्चित रूप से हमारे देश में एक अच्छा वातावरण पैदा होगा। इसलिए अगर विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता को खत्म करना है, बेरोजगारी की समस्या को हमको हल करना है तो निश्चित रूप से हमको स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रणाली को लागू करना होगा जिससे हम एक परिवर्तन की दिशा की ओर अग्रसर हो सकेंगे और विद्यार्थियों में असंतोष को दूर कर सकेंगे।

सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि अगर कोई सब्जेक्ट जरूरी हो तो जरूर खोला जाना चाहिये। जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता श्री श्रीराम गोटेवाला साहब ने यह कहा कि फारसी सब्जेक्ट खोला जाना चाहिये। क्योंकि इसके बगैर हम हमारे मध्यकालीन इतिहास का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। इसके लिये हमें विशेषज्ञ तैयार करने के लिये व्यवस्था करनी चाहिये। आज, सभापति महोदय, यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन ने बताया कि हमारे पास मध्यकालीन इतिहास जानने के लिये उनके शोध करने के लिये शोध कार्यकर्ताओं की कमी है। सभापति महोदय, मध्यकालीन इतिहास जानने के लिये फारसी शिक्षा की आवश्यकता है तो उसके लिये मेरा निवेदन है कि ऐसी महत्वपूर्ण अल्प संख्यक भाषा को बढ़ावा देना चाहिये, जो आज नहीं दिया जा रहा है। इसलिये मैं मन्त्री महोदय से यह मांग करूंगा कि हमारे यहां पर यूनिवर्सिटीज में और कालेजेज में फारसी सब्जेक्ट जरूर खोला जाना चाहिये जैसा कि श्री मसूदा साहब ने कहा कि उन्होंने अभी अजमेर में उद्घाटन किया है और आज फारसी की शिक्षा को महत्वपूर्ण मानते हुए हमें इस विषय को कालेजेज और यूनिवर्सिटी में खोलना चाहिये।

सभापति महोदय, अब मैं थोड़ा आपके माध्यम से मन्त्री महोदय का ध्यान कोटा डिविजन की तरफ ले जाना चाहता हूँ। सभापति महोदय, कोटा डिविजन में कोटा नगर बहुत ही महत्वपूर्ण नगर है। यह हाड़ौती का महत्वपूर्ण नगर है। इसके अलावा कोटा डिविजन कृषि के लिये, उद्योग धन्धों के लिये राजस्थान में बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभापति महोदय, कृषि के विकास की ज्यादा सम्भावनाओं को वहां पर देखते हुए वहां पर कृषि कालेज खोला जाना चाहिये। सभापति महोदय, वहां पर विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा है और उसमें भी ज्यादा लोग किसानों के परिवार के ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं अगर आप वहां पर कृषि कालेज की स्थापना करा दें तो वहां पर लोग कृषि शिक्षा को प्राप्त करके गांवों में जाकर खेती करेंगे और मैं समझता हूं कि

(श्री रामगोपाल)

इससे हमारे यहां का उत्पादन बढ़ेगा और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और हमारे यहां पर बेकारी हटेगी। इसलिये मेरा निवेदन है कि कोटा में कृषि कालेज खोला जाय।

सभापति महोदय मैं यह भी निवेदन करूंगा कि कोटा के अन्दर बिजनेस मैनेजमेन्ट की क्लासेज भी खोली जायें। सभापति महोदय, यह तो सर्व विदित है कि कोटा के अन्दर काफी उद्योग धन्धे है अगर आप वहां पर बिजनेस मैनेजमेण्ट का सब्जेक्ट खोल दें तो वहां पर लोग इस सब्जेक्ट को पढ़-लिख कर वहीं पर रोजगार प्राप्त कर सकेंगे इससे, सभापति महोदय, वहां के उद्योग-धन्धों में उन विद्यार्थियों को खपा सकेंगे।

सभापति महोदय, यह भी कहना चाहता हूं जैसा कि श्री मसूदा साहब ने कहा कि जगह जगह यूनिवर्सिटीज की मांग करना उचित नहीं है। और श्रीमाली कमेटी की रिपोर्ट में भी कहा गया है। मैं इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहता कि कहां पर यूनिवर्सिटी खोली जावे। लेकिन मैं इतना जरूर निवेदन करना चाहूंगा कि जहां पर बड़े-बड़े शहरों में कालेजेज की संख्यायें अधिक है और जो सेल्फ सफिशियेन्ट है उन कालेजेज को ओटोनोमस बोर्ड बना दिया जाना चाहिये। ताकि आज जो ज्यादा विद्यार्थियों की वजह से रिजल्ट देरी से निकलते हैं और लोगों के एडमिशन्स हो जाते हैं इससे विद्यार्थियों को दिक्कत होती है। इसलिये मेरा सुझाव है कि वहां बड़े बड़े शहरों में कालेजों की मात्रा अधिक है और विद्यार्थियों की सख्या अधिक है वहां पर उन कालेजों को ओटोनोमी दे दी जानी चाहिये। इसलिये मैं मांग करता हूं कि कोटा में जो कालेजेज हैं उन्हें ओटोनोमस बोडी बना दिया जाय।

सभापति महोदय, चूंकि कोटा में फैक्ट्रीज अधिक हैं इसलिये वहां पर अगर आप इन्जीनियरिंग कालेज खोल दें तो वहां लोगों को आप रोजगार दिला सकेंगे और मैं समझता हूं कि इससे बेरोजगारी मिटेगी और प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। इसलिये मैं शिक्षा मन्त्री से मांग करता हूं कि वहां पर इन्जीनियरिंग कालेज खोला जावे। सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान कोटा डिविजन में जो पत्थर की खानें हैं उनकी ओर दिलाना चाहूंगा। सभापति महोदय, कोटा के अन्दर पत्थर की बड़ी बड़ी खाने हैं वहां पर से पत्थर फॉरन तक जाता है कोटा स्टोन जो कि रामगन्ज मण्डी में निकलता है। आज बूंदी के अन्दर मारबल की खाने हैं। सभापति महोदय, आज पूरे कोटा डिविजन में पत्थर की खानों का अतुल भन्डार है। आज हमारे भूगर्भ में अतुल भन्डार है इस लिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस अतुल भू-गर्भ को बाहर निकाला जाय और कोटा में भू-गर्भ विषय को खोला जाना चाहिये जिससे कि वहां के लोग इस विषय को पढ़कर वहां पर रोजगार प्राप्त कर सकें। मेरी मांग है कि भू-गर्भ विषय कोटा में कालेज में खोला जाना चाहिये। इससे लोगों को तो काम मिलेगा ही पर इसके साथ साथ राज्य सरकार को भी इस अतुल भू-गर्भ से काफी लाभ होगा जिससे कि हम अपना विकास कर सकते हैं और अगर घाटा हो तो उसकी भी पूर्ति कर सकते हैं। सभापति महोदय, इसके अलावा मैं यह भी मांग करूंगा कि कोटा में एल-एल. बी. की

(श्री रामगोपाल)

क्लासेज तो हैं पर वहां एल-एल. एम. की क्लासेज नहीं होने की वजह से लोग इस विषय में आगे नहीं पढ़ पाते हैं इसलिये मैं मांग करूंगा कि कोटा कालेजेज में एल-एल. एम. का विषय खोला जावे। इसके साथ साथ, सभापति महोदय, शिक्षा मन्त्रीजी का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहूंगा कि कोटा कालेजेज में आज ज्योग्राफी, लेबर लॉ वगैहर के सब्जेक्ट्स नहीं हैं उन्हें भी खोला जाना चाहिये। आज, सभापति महोदय, लेबर लॉ की सिर्फ 30 सीटें ही हैं उन्हें बढ़ाया जाना चाहिये। इसके साथ साथ मैं यह भी मांग करता हूं कि वहां पर सोशियोलोजी, ज्योग्राफी, एल-एल. एम. की क्लासेज खोली जायें व लेबर लॉ की सीट्स बढ़ायी जायें।

सभापति महोदय, मैं शिक्षा मन्त्री का ध्यान कोटा कालेजेज छात्रावास की ओर भी दिलाना चाहूंगा। वहां पर छात्रावास में सिर्फ 110 विद्यार्थियों के लिये व्यवस्था है जब कि वहां पर सैंकड़ों लोग होस्टल में रहने से वन्चित रह जाते हैं। इस लिये मेरा निवेदन है कि वहां पर विद्यार्थियों की संख्या को देखते हुए छात्रावास और बनाये जाने चाहिये ताकि विद्यार्थियों को राहत मिले। आज गांवों से विद्यार्थी आते हैं उनको इसके लिए बहुत दिक्कत होती है इसलिए मैं यह मांग करता हूं कि कोटा में छात्रावास और बनाये जायें। कोटा कालेजेज में स्वीमिंग पूल को भी स्थापना की जानी चाहिये। इसके साथ साथ मैं यह भी मांग करूंगा कि वहां पर, सभापति महोदय, पोस्ट ग्रेजुएट में 300 छात्रायें हैं [illegible] तकलीफ उन्हें होती है। लड़कियों को कालेज जाने के लिए दूर दूर जाना पड़ता है। उनको दिक्कत न हो इसके लिए मांग करता हूं कि वहां पर सी. टी. बसेज चलाई जायें। वरना आप जानते हैं कि लड़कियों को कितनी तकलीफ आने जाने में होती है। इसमें मुझे कहने की आवश्यकता नहीं आप अपने अनुभव से ही समझ सकते हैं। अब थोड़ा मैं, सभापति महोदय, नारी जगत के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। वहां पर एक लड़कियों का स्कूल रामपुरा में है और वह बहुत दूर पड़ता है। लड़कियां गुमानपुरा से भी पढ़ने आती हैं। इसके लिए मैं मांग करूंगा कि गुमानपुरा में गर्ल्स कालेज खोला जावे। इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि अभी बजट में दस कालेजेज को पोस्ट ग्रेजुएट कालेज में क्रमोन्नत करने का प्रावधान है, पता नहीं कौनसी कालेजेज को क्रमोन्नत किया जायेगा। मैं मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्रों से विद्यार्थी आते हैं उनकी संख्या को देखते हुए वहां पर कालेजेज को पोस्ट ग्रेजुएट में क्रमोन्नत किया जाना चाहिये और उसके लिए भवन भी बनाये जाने चाहिये यह मैं मांग करता हूं। आज भवन नहीं होने की वजह से सारी अस्त व्यस्त हालत है इसलिए मन्त्री महोदय इस ओर ध्यान दें।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

सभापति महोदय, मैं खास तौर से एक तो छात्रावास की मांग करूंगा। दूसरे जो बून्दी, कोटा और झालावाड़ में कालेजेज हैं उनको पोस्ट ग्रेजुएट कालेजेज में क्रमोन्नत किया जाय इसके लिये मांग करूंगा।

(समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी)

(श्री रामगोपाल)

सभापति महोदय, आप जल्दी जल्दी घन्टी बजा रहे हैं मैं समाप्त कर ही रहा हूं। शाहबाद में जो हाई स्कूल की बिल्डिंग है वह ऐसी है कि उसके गिरने का भय है। तो मैं यह कहूंगा कि अगर शिक्षा मन्त्री महोदय उस स्कूल का जा कर मुआयना करें तो मैं समझता हूं कि उस स्कूल के गिरने के भय से दुवारा कभी वहां जाने की हिम्मत नहीं करेंगे। इसके अलावा साइन्स की क्लासेज खोल दीं पर वहां पर पूरे इक्विपमेन्ट नहीं हैं। वहां पर, सभापति महोदय, विद्यार्थियों के प्रेक्टिकल काम करने की कोई जगह साइन्स वाले छात्रों के लिए नहीं है। उसके लिए मेरा निवेदन है कि उनकी व्यवस्था की जानी चाहिए। यह मैं शिक्षा मन्त्री से मांग करना चाहूंगा। साइन्स टीचर नहीं है। भवन की अव्यवस्था होने से क्या होता है कि सुबह विद्यार्थी आते हैं, 12 बजे फिर दूसरी शिफ्ट चलती है और दूसरे विद्यार्थी आते हैं। इसलिये इस ओर पूरी व्यवस्था कराने की कृपा करें।

(समय–समाप्ति–सूचक–घंटी)

आगे बढ़िये। मिडिल स्कूल।

श्री सभापति : आपकी मांगें बढ़ती ही जा रही हैं।

श्री रामगोपाल : बहुत ही शोर्ट में कह रहा हूं। मिडिल स्कूलों को आप प्रमोट करें। भंवरगढ़ मेरी कान्सटीट्यूएन्सी में है, गडवाडा मेरी कान्सटीटयूएन्सी में है नाहरगढ यह भी मेरी कान्सटीट्यूएन्सी में है काफी अर्से से चले आ रहे है, यहां पर भवन की बुरी व्यवस्था है। यदि इनको आप क्रमोन्नत करेंगे तो निश्चित प से बड़ा उपकार होगा क्योंकि यह आदिवासी क्षेत्र है, वहां लोगों की आर्थिक स्थिति कमजोर है, बहुत दूर दूर तक विद्यार्थियों को जाना पड़ता है, जो कि गरीब आदमियों के लिए संभव नहीं हो पाता है। इसलिए तीनों ही मिडल स्कूलों को आप महरबानी करके प्रमोट कीजिए। गडवाडा, भंवरगढ़ और नाहरगढ़ ये तीनों ही मध्यप्रदेश की सीमा पर लगे हुए हैं।

मैं देख रहा हूं कि आप घंटी बजाने के लिए उत्सुक हैं। लेकिन मैं याद दिलाना चाहूंगा बुनियादी शिक्षा की ओर, जो कि ग्राम स्तर पर चलती है। यदि किसी भवन की नींव कमजोर होती है तो भवन बनने पर गिर जायगी। उसी प्रकार से यदि बुनियादी शिक्षा की नींव कमजोर रह गयी तो किसी प्रकार देश के भावी नागरिकों का जीवन सुदृढ़ और स्वस्थ नहीं रहेगा। हम बदल जावेंगे कई और आ जावेंगे लेकिन बुनियादी सुधार हमको लाना होगा। भवन की नींव सुदृढ़ है तो भवन बहुत वर्षों तक सुदृढ़ रहेगा। अस्तव्यस्त नहीं होगा।

जेल मंत्रीजी अभी नहीं हैं यहां पर लेकिन माननीय शिक्षा मंत्री जी से ही निवेदन करता हूं कि वे उनको सूचित कर देवें मेरी बात को। वे नोट कर लें। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ओपन एयर जेल होने चाहिए। कोटा के अन्दर भंवरखेड़ा में मांग है। ओपन एयर जेल के अन्दर रहने की सुविधा है झोपडियां, मकान बने हुए हैं। उनमें सुधार की बड़ी आवश्यकता है।

अटरू के अन्दर नयी मुन्सिफ मजिस्ट्रेटी बनी है। छबड़ा आपने देखा

(श्री रामगोपाल)

होगा। वहां से मुल्जिम आता है अटरू में। आने जाने का कितना सरकार को खर्चा होता है। जेल मंत्रीजी ने तीन चार महीने पहले इसको देखा है। इसका मकसद ही यह था कि इस योजना को देखना था योजना विचाराधीन है। इसलिये यहां निश्चित रूप से क्रियान्वित की जानी चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य। कृपया समाप्त करें। आपको बहुत समय दे दिया गया है।

श्री रामगोपाल : एक बात और है। जेल भवन इस ढंग के बने हुए हैं कि कोई भी देखेगा तो कहेगा कि यह कोई जेल भवन है। निश्चित रूप से इनमें सुधार होना चाहिये। कैदियों की शिक्षा में सुविधा हो, भोजन में भी सुधार हो, उनको लाइब्रेरी की भी सुविधा प्रदान की जाये। इसके साथ साथ उनको लघु उद्योगों की भी सुविधा हो ताकि एक अच्छा सुधार हो सकता है।

एक बात और निवेदन करना चाहूंगा इसी सम्बन्ध में। बेड़ियों में भी भ्रष्टाचार का बढ़ावा हो रहा है। बेड़ियां जिनको लगानी चाहिये उनको तो नहीं लगायी जाती और जिनको नहीं लगायी जानी चाहिये उनको लगायी जाती है।

तो मैंने शिक्षा पर, जेल पर अपने विचार रखे हैं। आपने समय दिया उसके लिये भी धन्यवाद। दोनों शिक्षा मंत्री महोदय यहां पर विराजमान हैं और मैंने जो सुझाव रखे हैं, गर्दन हिला रहे हैं, उनको स्वीकार करने की मेरी आशा पूरी हो जावेगी।

श्री सभापति : श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदय, मैंने शिक्षा और जेल दोनों विभागों पर कटौती के प्रस्ताव रखे हैं। मैं पहले शिक्षा पर आता हूं।

शिक्षा में सबसे पहले मैं प्राईमरी एजुकेशन पर प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। मैं यह देख रहा हूं कि गये वर्ष 74-75 के बजट में प्राईमरी एजुकेशन पर ध्यान नहीं दिया और इस वर्ष बजट भाषण पढ़ा तो उसमें भी मैंने पाया कि प्राईमरी एजुकेशन की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। यह लगातार दो वर्षों से हो रहा है। यह राज्य सरकार, शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री आज प्राईमरी एजुकेशन की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। सभापति महोदय, मैं शिक्षा मंत्री को बताना चाहता हूं कि प्राईमरी एजुकेशन की दृष्टि से हम सारे हिन्दुस्तान में सबसे पिछड़े हुए हैं और फिर भी आप प्राईमरी एजुकेशन की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसलिये आपको प्राईमरी एजुकेशन की तरफ ध्यान देना चाहिये। आज हमारे रेगिस्तानी क्षेत्र के जिले हैं वह बहुत अविकसित हैं। कई ऐसे गांव हैं जहां एक स्कूल खोल देने से काम नहीं चलता। 80 और 100 वर्ग मील में विलेजेज हैं, और उन विलेजेज में अगर आप एक प्राईमरी स्कूल खोलें तो दस मील बच्चों को जाना पड़ता है स्कूल पहुंचने के लिये। यह किसी भी तरीके से ठीक नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अगर शिक्षा की तरक्की चाहते हैं, अगर शिक्षा में उन्नति करना चाहते हैं तो आने

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)
वाले जो बच्चे हैं उनको शिक्षा का लाभ देने के लिये आपको प्राईमरी एजुकेशन की तरफ ध्यान देना होगा। अगर आने वाले बच्चे शिक्षा का लाभ न उठा सकें तो यह अनुचित होगा।

दूसरी बात जिस की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा वह है लड़कियों की शिक्षा। आपने इस ओर भी बहुत ही कम ध्यान दिया है। इस साल हम अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष मना रहे हैं, पर हम लड़कियों की शिक्षा की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं और हम जो जनता के प्रतिनिधि हैं, वह भी इस दिशा में जो कार्य करना चाहिये, वह नहीं कर रहे हैं। राज्य सरकार को समझना चाहिये कि प्राईमरी स्कूल भी लड़कियों के लिये अलग होने चाहिये। यह अभी तक फालो नहीं हुआ है। चाहिये यह कि लड़कियों के लिये प्राइमरी स्कूल भी सेपरेट होने चाहिये। इससे ज्यादा लड़कियां स्कूलों में प्रवेश लेंगी और लड़कियों की शिक्षा की उन्नति होगी।

श्रीमती निर्मला कुमारी : क्या आप परिवार से भी अलग कर सकते हैं?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : मैं प्राईमरी एज्यूकेशन के बाद में अपर प्राईमरी एज्यूकेशन के सुदृढ़ीकरण का कार्य है उसमें राजस्थान सरकार सफल हो रही है, वह सुदृढ़ करना चाहिये और सुदृढ़ीकरण करने के बाद में प्रश्न आता है 9 वीं, 10वीं और 11वी जो तीन क्लासेज हैं, सैकेन्डरी और हायर सैकेन्डरी की एज्यूकेशन कमिशनर ने यह राय दी है कि वोकेशनल एज्यूकेशन दी जाये। अब वोकेशनल एज्यूकेशन के बारे में मैंने प्रगति विवरण पढ़ा तो सिर्फ 6 उच्च माध्यमिक विद्यालय में पाठ्य क्रम चालू किया गया है।

यह सिर्फ जो 1260 सैकेन्डरी और हायर सेकेन्डरी स्कूल्स ने प्रोग्रेस की है वह सिर्फ 6 स्थानो में की है। आप व्यवसाय के आधार पर इन स्कूलों की प्रगति करना चाहते हैं तो यह प्रगति नहीं हुई। आज जो भी प्रगति करना चाहते हैं वह सैन्ट्रल गवर्नमेंट के जो फन्ड्स मिले उसमें प्राईमरी स्कूल का विस्तार करें, उसमें सैकेन्डरी स्कूलों का विस्तार करें, हायर सेकेन्डरी स्कूलों का विस्तार करें वोकेशनल एज्यूकेशन का विस्तार करें- राजस्थान गवर्नमेंट फन्ड्स क्या प्रोवाइड करती है, यह मैं जानना चाहता हूं। यह जो 6 वोकेशनल एज्यूकेशन स्थापित किये गये हैं इनमें क्या प्रगति की है? इनमें जो एज्यूकेशन पा चुके हैं उनको सर्विसेज मिली हैं क्या?

पहले मल्टी परपज हायर सैकेन्डरी स्कूल्स खोले थे उनसे पूरा परपज सर्व नहीं हो पाया कारपेन्टर, टेलरिंग आदि का। अगर कारपेन्टरिंग और टेलरिंग का पढ़ा लिखा विद्यार्थी जाये तो उसको तीन रुपये भी न मिलें तो इस व्यवस्था के लिये भी सोचना पड़ेगा कि काम करने वाले एक्सपर्ट होकर जायें और वे यूजफुल सिटिजन होकर अपना व्यवसाय चला सकें, व्यावसायिक एज्यूकेशन देंगे तो दो साल, तीन साल जिसमें उसकी रुचि हो उसको उसी प्रकार की ट्रेनिंग देनी होगी। व्यावसायिक एज्यूकेशन बढ़ाने का जो प्रस्ताव है वह सरकार का अपर्याप्त है। इसके लिये हम सन्तुष्ट नहीं हो सकते हैं। अब तीसरा पाइन्ट कहना चाहता हूं जब

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

तक शिक्षा में नैतिकता नहीं आयेगी तब तक कोई प्रगति नहीं हो सकती है। आज जो सदन में चर्चा उठ रही है शिक्षा के बारे में है उसमें क्या नैतिकता का प्रभाव रहता है जबकि हमारा कान्सटीट्यूशन बना है तो जो मूल भूत सिद्धान्त है, बुनियादी सिद्धान्त है उसकी क्या शिक्षा देते है? अगर सरल भाषा में शिक्षा दें तो बुनियादी सिद्धान्तों को मानकर उसमें दी जा सकती है। क्या हम जनतन्त्र की शिक्षा देते हैं? समाजवाद की शिक्षा देते हैं? और क्या छुआछूत की शिक्षा देते है? आज भी हमारा दृष्टिकोण जातीय आधार पर है। इस प्रकार का जो पाट्य-क्रम बनाना है तो इन नैतिक आधारों को मानकर अपने को एज्यूकेशन देना होगा। अगर यह नहीं देंगे तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा, रुकेगा नहीं।

अब मैं विश्वविद्यालय आयोग ने जो सिफारिशें की हैं कि युनिवर्सिटी टीचर्स के बारे में 80 पर्सेन्ट मदद दे रहे है। यू. पी. की गवर्नमेंट ने, बिहार की गवर्नमेंट ने निर्णय लिया है तो राजस्थान की गवर्नमेंट क्यों हिचकिचाती है। हम वेतन बढ़ा देंगे तो आर. ए. एस. अधिकारियों के भी बढ़ाने होंगे। मैं कहता हूं आर. ए. एस. अधिकारियों से टीचर्स योग्य होने चाहिये। प्राईमरी स्कूल के टीचर्स, सैकेण्डरी स्कूल के टीचर्स और हायर सकेण्डरी स्कूल के टीचर्स में सब जगह यह बात है जहां भी कहीं सर्विसेस नहीं मिले तो टीचर्स में जायं, यह दृष्टिकोण बहुत खराब दृष्टिकोण है। यह देश को आगे बढ़ाने का दृष्टिकोण नहीं है। टीचर्स के बारे में यह हो कि वे राष्ट्रीय चरित्र के हों, नेशनल केरेक्टर के हों और उसी प्रकार उनको वेतन देना होगा इसलिये योग्य से योग्य व्यक्तियों को लेंगे तो देश का असली विकास होगा।

आज अमेरिका और ब्रिटेन में प्रोफेसर्स और लेक्चरार्स का कितना सम्मान है। आज जो वहां के प्रोफेसर और लेक्चरार्स हैं वे एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर नहीं जाना चाहते हैं इसलिये अपने देश में भी यह अपनाना होगा। प्रोफेसरों को वेतनमान अधिक दें और उनकी बड़ी भारी रेसपैक्ट हो। यह कदम नहीं उठायेंगे तब तक कोई प्रगति नहीं कर सकते है और हमारा विकास नहीं हो सकता है।

अब मेरी जो मांग है बाड़मेर राजकीय कालेज के बारे में उसकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आपने हमारे राजकीय कालेज के प्रांगण में छात्रावास बढ़ाने की ओर एक लाख रुपया देने की घोषणा की और आज एक साल हो चुका है जब आप नये मन्त्री बने थे उस समय घोषणा की थी उस घोषणा को पूरा करना चाहिये। क्योंकि क्रियान्वित नहीं करते हैं तो विद्यार्थियों में रोष होता है और अभी रोष भी प्रकट किया था विद्यार्थियों ने चीफ मिनिस्टर साहब के सामने, रिप्रेजेन्टेशन किया तो मैं यह चाहता हूं शिक्षा मन्त्री जी जवाब दें तो जो डिक्लेरेशन किया है सदन में उसकी घोषणा करके क्रियान्वित करें।

केमिस्ट्री में जो प्रयोग शाला है उसमें आवश्यकता है एग्जास्ट फेन्स की। उसके

(श्री वृद्धि चन्द्र जैन) :

न होने से जहरीली गैस फैल जाती है विद्यार्थी और पढ़ाने वाले हैं उन पर बुरा असर पड़ता है, यह एक साधारण बात है। इस पर शीघ्र ध्यान दिया जाना चाहिये और यह जहां पर भी नहीं हो वहां पर व्यवस्था की जानी चाहिये। यह मांग मैंने बाड़मेर के राजकीय महाविद्यालय के बारे में रखी है।

बाड़मेर, जैसलमेर जो रेगिस्तानी इलाका है उनमें, हायर सैकेण्डरी स्कूल भवन की स्थिति बहुत ही खराब है। आप देखें जितने दरवाजे हैं सबके सब टूटे हुये हैं, कोई कांच खिड़कियों में लगे हुये नहीं है। 10–12 साल से वहां कोई रिपेयर नहीं हुई है। वहां कोई कन्ट्रीब्यूट नहीं होता है क्योंकि जनता गरीब है। जब कोई राशि फिक्स करें तो इन बिल्डिंगों के बारे में भी अधिक से अधिक प्रावधान करें।

अब मैं जेल की मांग पर संक्षेप में कहना चाहता हूं। मेरे यहां की बाड़मेर सब-जेल के बारे में कुछ कहना चाहता हूं और वह यह है कि मैं अभी दो महीने पहले से सब-जेल में गया था तो सब-जेल की बिल्डिंग जो 1968 में बनी थी उसकी कोई भी रिपेयर आज तक नहीं हुई। दूसरे पानी की व्यवस्था वहां माकूल नहीं है। वहां एक पार्ट टाइम डाक्टर होना चाहिए। वह व्यवस्था नहीं हैं तो यह व्यवस्थायें बहुत साधारण सी हैं और उन्हें ठीक की जानी चाहिए।

मैं आखिर में शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो मैंने मसले रखे हैं उनके ऊपर गौर करके उनका इम्पलीमेंटेशन करके हमारे डिस्ट्रिक्ट और राजस्थान की वह सेवा करें।

श्री सभापति : श्री नन्दलाल बैरवा !

(अनुपस्थित)

श्री गोपीलाल

(अनुपस्थित)

श्री लूणाराम।

श्री लूणाराम : सभापति महोदय, शिक्षा की मांगों पर आज जो विचार हो रहा है हमारी शिक्षा पद्धति जो है उसमें कई प्रकार की बुराइयों को देखकर चर्चा हो रही है। यह अकेली हमारी सरकार और शिक्षा मंत्री जी के बस की बात नहीं है कि वह इसका सुधार कर सके। इसमें हम सब का ही सहयोग आवश्यक है। मगर खासकर जो समस्याएं हमारे शासन द्वारा या शिक्षा मंत्री जी द्वारा हल की जानी हैं उनके बारे में मैं निवेदन करूंगा।

सबसे पहले प्राईमरी स्कूलों के बारे में कहूंगा कि इस साल हमारे बजट में नई प्राईमरी स्कूलों के खोलने के लिए कोई प्रावधान नहीं है और मेरा निवेदन यही है कि दो किलोमीटर से अधिक दूरी पर किसी भी गांव को प्राईमरी स्कूल मिला नहीं रहने देना चाहिए और जो इस तरह के गांव रह गये हैं उनमें कृपया इस वर्ष में स्कूलें खोलने की कृपा करें जिससे कि इस व्यवस्था से हमारा कोई गांव नहीं बच सके। दूसरे इसी सन्दर्भ में मेरा एक निवेदन और है और वह यह है कि प्राईमरी स्कूलों के अन्दर आज जो अध्यापक लगाये जाते हैं वह बिल्कुल ही नये लगाये जाते हैं और ज्योंहि वह सीनियर हो

(श्री लूणराम)

जाते हैं तो उनको मिडिल स्कूलों में भेज दिया जाता है। तो हम जब एक भावी पीढ़ी का निर्माण करना चाहते हैं और प्राईमरी क्लास तक के बच्चों में पूरा ज्ञान भरना चाहते हैं तो मेरी मांग है कि प्राईमरी स्कूलों में सीनियर अध्यापक रखे जायें ताकि वह अच्छी तरह से पढ़ा सकें। इसके अलावा प्राईमरी क्लास के बच्चों पर किताबों का इतना बोझा है कि जिसकी कोई आवश्यकता नहीं। हो सकता है हमारे शिक्षा विशेषज्ञों का ऐसा मानना हो लेकिन मेरा मानना है कि वह इसको कम करें। इसी प्रकार से आज स्कूलों के अन्दर बच्चों के मनोरंजन के लिये चरखी व फिसला बनाने की बहुत आवश्यकता है और इसका हमारे प्राईमरी स्कूलों में अभाव है। बल्कि है ही नहीं। तो यह अनिवार्य रूप में हर प्राईमरी स्कूल में लगवाने का मेरा निवेदन है। जिसमें बच्चों के खेलने की इच्छा भी स्कूल में पूरी हो सके।

दूसरे आज प्राईमरी स्कूलों की हालत यह है कि अध्यापकों की बहुत कमी है और आज ज्योंहि कोई प्राईमरी स्कूल से कोई स्कूल मिडिल स्कूल बनता है तो प्राईमरी स्कूल को तो खोलते समय एक अध्यापक से शुरू किया जाता है लेकिन ज्योंहि मिडिल स्कूल में कन्वर्ट हुआ कि शिक्षा विभाग से उन्हीं प्राईमरी स्कूलों में चार, चार अध्यापक पंचायत समिति की स्वीकृति के बिना जाते हैं। शिक्षा मंत्री जी जानते हैं क्योंकि वे प्रमुख रहे हैं इसलिए प्राईमरी स्कूलों के बारे में जानते हैं। इस प्रकार से आप प्राईमरी स्कूलों को ज्यादा पनपायेंगे तभी हमारी स्कूलों का आगे जाकर सुधार होगा। और मैं शिक्षा के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा कि खर्च में कुछ कमी करें कई ऐसी जगह है कि जहां बचत काफी की जा सकती है। आज हालत यह है कि फर्नीचर के लिए या तो जिला स्तर पर किसी एक को मुकर्रर करते हैं और इस कारण से सारे जिले में ट्रान्सपोर्ट का और ढुलाई का बहुत खर्चा होता है और मंहगा भी बहुत पड़ता है। आज, सभापति महोदय, प्राईमरी स्कूल और मिडिल स्कूलों का राज्य में इतना जाल बिछा हुआ है इसलिए मैं चाहूंगा कि शिक्षा मंत्री जी कोई ऐसी व्यवस्था कर दें कि एक कमेटी द्वारा हर तहसील स्तर पर ऐसी व्यवस्था करायें कि वहीं सामान उपलब्ध करा दिये जायं ताकि वह सस्ता पड़े और माल भी खराब नहीं आये।

इसी प्रकार से, सभापति महोदय, भवनों के बारे में अनुदान देने की बात है तो इस संबंध में मैं यह निवेदन करूंगा कि जो गांव है और जहां प्राईमरी और मिडिल स्कूल बनने की है वहां सरकार द्वारा अधिक से अधिक अनुदान के रूप में सहायता दी जाये और छात्रावासों को अनुदान दिया जाये। कालेजों के लिए धन शहरों में दिया जाना चाहिये लेकिन आज यह होता है कि चार-दीवारी बनाने के लिए पैसा दिया जाता है तो इस प्रकार के कामों के लिए पैसा नहीं दिया जाकर भवनों और छात्रावासों के लिए ही अनुदान दिया जाना चाहिए।

इसी प्रकार से आज जो दूसरी एड मान्यता प्राप्त शालाओं को दी जाती है मेरी यह मान्यता है कि इनके द्वारा भ्रष्टाचार होता है। जो इन स्कूलों के संचालक हैं वे हमारे सरकारी स्कूल हैं उनके अन्दर भी बड़ी गड़बड़ियां करवाते हैं। वह अपनी नेतागीरी जमाकर हमारे जो सरकारी स्कूल हैं उनको बदनाम करवाते हैं और दूसरी बात यह भी

(श्री लूणाराम)

है कि वह अनापशनाप पैसा ले रहे हैं। हमारा ही पैसा लेकर हमें ही आंखें दिखाते हैं और शिक्षा को बदनाम करते हैं। ऐड लेकर सरकार को लूटते हैं। कम देकर अधिक भुगतान दिखाकर मुख्याध्यापक को लूटते हैं और छात्रों के अभिभावकों से फीस लेकर उन्हें लूटते हैं। तो इस तरह से लूटने वाले इन लुटेरों की लूट बंद की जाय और आवश्यकता इस बात की है कि ऐसे स्कूलों को सरकार अपने अधिकार में ले।

इसी प्रकार से छात्रवृत्ति के बारे में कहूंगा। हरिजन छात्रों को तो जरूर छात्रवृत्ति दी जाती है लेकिन दूसरी ओर समाज के ऐसे बच्चे हैं जो कि शिक्षा को चालू नहीं रख सकते। तो इस बारे में व्यवस्था की जाये। इसी के साथ साथ एक और प्रश्न है कि, मैंने इस बारे में शिक्षा मंत्रीजी को एक चिट्ठी भी दी थी और उन्होंने आश्वासन भी दिया था लेकिन कुछ नहीं हुआ। अकाल के अन्दर बच्चों के अभिभावकों को मजदूरी के लिए अन्य जगह जाना पड़ता है इसलिए जो होनहार बच्चे होते हैं वह आंसू टपकाते हुए अपने अभिभावकों के साथ मजदूरी के लिए चले जाते हैं और मजबूरन उनको जाना पड़ता है और इस कारण से अकाल के दिनों में उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ता है। तो मैं चाहूंगा कि ऐसा देवीय संकट आये तो उस हालत में जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनकी पढ़ाई में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं पहुंचे। इस प्रकार की कोई व्यवस्था सरकार करे। इसी के साथ साथ मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा कि आज हमारे शिक्षा मंत्रीजी ने पहले एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि 70 पर्सेन्ट अनिवार्य शिक्षा, पांचवीं पंचवर्षीय योजना तक हम कर पायेंगे। ठीक है, सरकार के पास जिस प्रकार के साधन हों उसी में काम करना चाहिए लेकिन कम से कम 70 पर्सेन्ट के बजाय चाहे 40 पर्सेन्ट ही यह आंकड़ा क्यों न आ जाये लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम परिवार के एक बच्चे को अनिवार्य शिक्षा अवश्य दी जाये जिससे सारे राजस्थान का कोई भी परिवार इससे वंचित न रहे जिसको शिक्षा न मिले। कम से कम परिवार में एक बच्चे के लिए अनिवार्य शिक्षा कर दी जाये तो वह शिक्षा अधिक कारगर हो सकेगी न कि 60-70 पर्सन्ट का जो हम आंकड़ा लेकर चलना चाहते हैं वह आज प्रतिशत नहीं बन रहा है क्योंकि वह भूखे एवं पिछड़े वर्ग के छात्र हैं। उनके न पढने के कारण ही प्रतिशत की कमी है और कभी भी रहती रहेगी यदि ऐसा नहीं किया गया तो सभापति महोदय, इसी प्रकार से आज सेकेण्ड्री स्कूल के अन्दर हमारे शिक्षा मंत्रीजी ने बजट के अन्दर भी पचास स्कूलों के विषय में, जिनमें नहीं हैं, खोलने की घोषणा की है। मैं, माननीय सभापति महोदय, यह निवेदन करूंगा कि पिछले समय के अन्दर जो सेकेण्ड्री स्कूल खोले गये वह प्राय: कई गांवों में खोले गये और पहले गांवों के अन्दर हायर सेकेण्ड्री स्कूल कोई दस पर्सेन्ट सारे राजस्थान में खोले गये हों तो मैं नहीं कह सकता लेकिन बाकी जितने हायर सेकेण्ड्री स्कूल हैं वह सारे के सारे शहरों में खोले गये और 90 प्रतिशत स्कूल सेकेण्ड्री की गांवों में खोले गये हैं और उनके अन्दर कामर्स या साइन्स जैसे आकर्षक विषय खोले नहीं गए। नतीजा यह है कि साइंस वाले, कोमर्स वाले आगे निकल पायेंगे और वही आगे जाकर सिलसिला शिक्षा में चलेगा

(श्री लूणाराम)

तो हमारा जो पिछड़ापन था वही पिछड़ापन आगे भी रहेगा क्योंकि विषय यह नहीं है, तो मैं इस सम्बन्ध में सभापति महोदय, शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि चाहे जितने भी स्कूल हों, चाहे शहरों में हों या देहातों में, तमाम को इन विषयों से वंचित नहीं रखा जाय।

इसी प्रकार से एक बात और निवेदन करना चाहता हूं और वह यह है कि, सभापति महोदय, आज हमारे राजस्थान भर में सैनिकों के बनाने के लिए एक स्कूल चित्तौड़ के अन्दर है और वह स्कूल बड़ा भारी महगा पड़ता है। उस स्कूल के अन्दर अमीरों के बच्चे ही पढ़ सकते हैं या बड़े अफसरों के बच्चे पढ़ सकते हैं, बाकी आम आदमी के बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं जब कि एक सैनिक रिटायर्ड होने के बाद अपने दिल के अन्दर यह आशा संजोये रहता है कि मेरा बच्चा होनहार बने, अच्छा सैनिक बने, मेरा बच्चा सैनिक स्कूल में पढ़े लेकिन उसके अरमान पूरे नहीं होते। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि बिना किसी प्रकार के खर्चे के राजस्थान के अन्दर चूरू, झुंझुनूं, सीकर और नागौर ये चार ऐसे लगते हुए जिले हैं एक दूसरे से कि जहां से सैनिक जाते हैं। इन सैनिकों के जिलों के अन्दर चूरू ही बीच में पड़ता है, वहां पर एक सैनिक स्कूल की व्यवस्था करने का निवेदन है। जिसमें सैनिक के नहीं, पिछड़ी जाति के बच्चे भी भरती किये जायें।

इसी प्रकार से आज, सभापति महोदय, दूसरा मेरा यह निवेदन है कि अब मेरे क्षेत्र के मामले में इतना सा निवेदन करूंगा कि डूंगरगढ़ बहुत बड़ा कस्बा है। तीस मिडिल स्कूलें हैं और वहां पर 6 हायर सेकेण्ड्री स्कूलें हैं। इण्टर कालेज की इस वर्ष में व्यवस्था की जाये मैं शिक्षा मंत्रीजी से, सभापति महोदय, आपके जरिये निवेदन करता हूं कि जो मिडिल स्कूल सोनियासर, आऊसर और मोमासर में कन्या पाठशाला है बाकी को क्रमोन्नत किया जाये। मिडिल स्कूल के लिए अलग से मैं मंत्रीजी से मिल कर निवेदन कर दूंगा लेकिन यहां पर यही निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर हायर सेकेंड्री स्कूल भी खोलें।

सभापति महोदय, आज हमारे इसी प्रकार से कई ट्रेन्ड अध्यापक ऐसे हैं जिनको सर्विस नहीं मिलती है। उनका इण्टरव्यू ले लेते हैं, चूरू जिला शिक्षक अधिकारी ने 10 अक्टूबर, 74 को मोंटेसरी अध्यापकों के लिए इण्टरव्यू लिया जिनकी आज तक सर्विस नहीं लगी सर्विस नहीं मिलने का कारण यह है कि वहां इंस्पेक्ट्रेस के पास पहले बीकानेर में नियुक्ति के लिए भेजते हैं, वह कहती है कि मेल अध्यापक नहीं लूंगी। नतीजा यह होता है कि न वह इधर के रहते हैं और न उधर के रहते हैं और बीच में ही लटके हुए रहते हैं। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि फिर वह इण्टरव्यू किस परपज के लिए, किन स्कूलों के लिए लिया गया था। चाहे वह इंस्पेक्टर आफ स्कूल चूरू रखें या इंस्पेक्ट्रेस आफ बीकानेर रखें, उनको रखने की व्यवस्था होनी चाहिए।

इसी प्रकार से आज, सभापति महोदय,

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

(श्री लूणाराम)

पुरातत्व विभाग, अभिलेखागार तथा राजस्थान प्राच्य विद्यापीठ के बारे में भी निवेदन करूंगा कि आज हम जो काम करते हैं वह काम सराहनीय है। इस सम्बन्ध में इतना ही निवेदन है कि सम्पूर्ण राजस्थान के अन्दर गांव गांव और डोर डोर सर्वे करना चाहिए। इसमें चाहे एक वर्ष लगे, दो वर्ष लगें, पांच वर्ष लगें, हमें अनेक ऐसी चीजें उपलब्ध होंगी जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर पायेंगे और समय निकलने के बाद ऐसी चीजें खत्म हो जायेंगी, इसलिए उनका भी अधिक ख्याल किया जाना चाहिए।

इसी प्रकार से आज हमारी राजस्थान नाटक एकेडेमी और क्रीड़ा परिषद् का काम है, चाहे हम राजस्थान स्तर पर कुछ भी करें, जिला स्तर पर ऐसी संस्थायें नहीं खोलेंगे तब तक हमारा सारा काम बेकार है। इसलिए मैं चाहूंगा कि सरकार को इस तरफ ध्यान देकर जिला स्तर पर उनको स्थापित करके उनके प्रोग्राम से किसी भी मिडिल और सेकेंड्री स्कूल को अछूता नहीं रखा जाय।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

सभापति महोदय, अब मैं जेल की मांग के सम्बन्ध में दो मिनिट निवेदन करूंगा और वह यह है कि आज हम हर प्रकार की ट्रेनिंग बन्दी को जेल के अन्दर देते हैं। तो पहला मेरा सुझाव यह है कि कोई भी बन्दी हो उसको वही काम सिखलाया जावे कि उनको बन्दीपने से रिहा होने के बाद उसके निवास स्थान के नजदीक वह काम आसानी से मिल सके।

दूसरा मेरा इस सम्बन्ध में यह सुझाव है कि अगर बन्दी भूमिहीन है, वह अगर किसान और भूमिहीन की परिभाषा में आता है तो उसके लिए एक निश्चित सीमा तक उसके जिले के अन्दर भूमि रिजर्व रखी जाकर उसके रिहा होने पर अलाट की जावे।

तीसरा इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि जिस किसी कार्य के अन्दर उसकी इच्छा हो, जिस कार्य के अन्दर उसको ट्रेनिंग दी गई हो, उस कार्य को आगे चल कर करने के लिए जब वह रिहा हो तो ऋण और कुछ गाईड लाइन और ग्राण्ट इन एड के रूप में सहायता दी जाये जिससे वह औजार खरीद ले, अन्य सुविधा जुटा ले और वह अपने काम को शुरू रख कर अपराध करना छोड़ दे। इसके साथ-साथ मेरा निवेदन यह है कि जिले के अन्दर जो रहते हैं उनके लिए प्रौढ़ शिक्षा अनिवार्य कर दी जावे जिससे वह अक्षर ज्ञान होने से अपराध में फंसने से बच सकें।

इसी प्रकार से आज, सभापति महोदय, सब-कारागाह के बारे में निवेदन है कि उनमें भी और कारागाहों में जो सामान बनता है उस सामान का ढेर का ढेर पड़ा रहता है लेकिन हमारे बड़े 2 आफिसों के लिए और सरकारी विभागों के लिए अधिकारीगण अन्य फर्मों से खरीद लेते हैं। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि जब तक कारागाह से इस प्रकार की जानकारी हैड आफिस न ले कि कारागाह में सामान है या नहीं और अगर सामान है तो जब तक जेल से सामान मिले तब तक दूसरी जगह से नहीं खरीदे, वहीं से खरीदे जिससे उन लोगों को काम करने की मदद मिले। इसी प्रकार से सब-जेलों के सम्बन्ध में मेरा निवे-

(श्री सूणाराम)

दन है कि वहां पर इसकी व्यवस्था करें जिससे उनको भी काम मिले। दूसरा जब कोई अपराधी होता है जो कि जेल के अन्दर सजा पाने के लिए आता है, अदालत से बरी हो जाता है। उनको एक एक, डेढ डेढ साल तक जेल में पड़ा रहना पड़ता है ज्यूडिशियल लोक अप में। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि उनके लिए भी आप इसी तरह की व्यवस्था करें ताकि उनकी मनोवृत्ति बदले, उनकी आत्मा सुधरे। उन जेलों के अन्दर काम मिले और दूसरा वहां पर वाचनालय की व्यवस्था होनी चाहिए और एक कथा वाचन की व्यवस्था की जाये जिससे उनकी आत्मा का सुधार हो। क्योंकि जेल के अन्दर मुश्किल से तीस प्रतिशत अपराधी होते हैं और सत्तर प्रतिशत अपराधी ज्यूडिशियल लोक अप में या सब जेलों में रहते हैं और वहीं से कोर्ट लाये जाते हैं इसलिए इस प्रकार के सामान की व्यवस्था करेंगे तो अपराधवृत्ति करने वाले लोगों के दिमाग पर अच्छा असर पड़ेगा और उनमें सुधार होगा।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

इसी प्रकार से जो हमारे जेलों के सुधार की बात है उस सम्बन्ध में इतना ही निवेदन करना है। जेलों के सुधार के बारे में, माननीय सभापति महोदय, यही और निवेदन कर देना चाहता हूं कि जेल से रिहा होने के बाद में हर वह जेली वह बंदी, जो रिहा होकर गया, उसका कार्य कैसा रहा, उसका अच्छा चरित्र रहा है, जेलर के साथ उसका अच्छा बर्ताव रहा है, तो जिस जेलर ने, अधिकारियों ने सुशिक्षा दी, उसके चरित्र को जो बुरा चरित्र था उसको अच्छा चरित्र बनाया, उसके चरित्र का परिवर्तन किया, उसको काम सिखाया, उससे उसको एक शपथ-पत्र लेना चाहिए कि मैं इस वृत्ति को आगे चल कर नहीं करूंगा। इसकी व्यवस्था वहां पर रहनी चाहिए और आगे चल कर सरकारी खर्चे पर कम से कम तीन साल तक एक बार अवश्य वापस एक दिन के लिए उस अधिकारी के सामने, जिसने उसको रिहा किया था और जिसके अधीन उसने ज्ञान प्राप्त किया था, शपथ भी ली, जेल तक आने जाने का खर्च देकर बुलायें, जिससे अपराध करने की प्रवृत्ति नहीं रहे और यह सचेत रहे कि हमें एक साल में जाकर जेलर साहब को कहना है कि मेरा अनुभव यह रहा। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि इस पर गौर फरमायें। इन्हीं बातों के साथ में मैं आपने समय दिया उसके लिये धन्यवाद देता हूं।

श्री केशरीमल : सभापति महोदय,

श्री सभापति : यस।

श्री केशरीमल (ब्यावर) : माननीय सभापति महोदय, यह शिक्षा पद्धति के बारे में मेरा सुझाव है। अभी जो शिक्षा पद्धति अपने राजस्थान में, देश में जिस प्रकार से चल रही है वह सिर्फ ऐसे लोग पैदा कर रही है जो कहीं जाकर कार्य तक नहीं कर सकें या ज्यादा से ज्यादा नौकरी कर लें, इससे ज्यादा किसी काम की शिक्षा नहीं है। वास्तव में तो किसी काम के काबिल होकर भी नहीं निकलते हैं। आज की शिक्षा श्रम को नीचा दिखाने वाली शिक्षा है। शिक्षा प्राप्त कर वह श्रम को नीचा दिखाता है और

(श्री केशरीमल)

शिक्षित अपना अलग वर्ग बना लेता है सभापति महोदय, अगर हमारे देश में शिक्षा पद्धति इसी तरह चले बहुत बार यह बात कही जाती है कि इसमें सुधार होना चाहिए और यह शिक्षा पद्धति ठीक नहीं है लेकिन सत्ताईस सालों की आजादी के बाद, इस बीच में कितने ही विचार प्रकट हुए लेकिन कभी भी क्या सुधार करना है, कौन उनको रोकता है ? इसका मतलब यह है कि सरकार के कुछ लोग, कुछ राज नेता ऐसी बात कहते हैं लेकिन सुधार क्या करना है, यह उनके दिमाग में नहीं है। ऐसी कोई योजना नहीं है। अगर योजना है तो उस पर अमल नहीं करना चाहते हैं। सभापति महोदय, आज देश में नौजवान तबका जब पढ़ कर निकलता है तो वह सिर्फ बाबू बनने का प्रयास करता है। बाकी दूसरा काम करना पसन्द नहीं करता है। मैंने स्वयं ने दूसरे देशों में विशेष कर जर्मनी, पौलेंड, रशिया में यह देखा है कि वहां के विद्यार्थी कुछ और ही सोचते हैं। वे पढ़ने के साथ साथ काम भी करते हैं। दसवीं में पढ़ने वाला काम का ज्ञाता भी हो जाता है। जिस इलाके में वह पढ़ता है वहां की इन्डस्ट्री के साथ उसका जुड़ाव हो जाता है और उसके काम के बारे में उसकी जानकारी हो जाती है। पढ़ने के साथ वह काम का ज्ञाता हो जाता है और उनमें काम करने की बात सोचता है या दूसरा कोई काम करेगा। वह कुछ न कुछ ऐसा ज्ञान लेकर निकलता है कि वह शिक्षा के साथ-साथ उस काम का पूरा पूरा ज्ञाता हो जाता है। बारहवीं तक पढ़ने वाला अच्छा ज्ञाता हो जाता है या उसका मास्टर हो जाएगा। पढ़ने के साथ साथ एक दिन का प्रैक्टिकल भी उनको किसी कारखाने में ले जाकर कराया जाता है। और ऐसा करते करते वह इतना प्रवीण हो जाता है कि वह नौकरी करने की आवश्यकता नहीं समझता है। या तो वह कोई अच्छा बुक बाइन्डर होगा, अच्छा मेकेनिक हो सकता है। अच्छा टेलर हो सकता है, अच्छा डाक्टर बन सकता है, अच्छा पढ़ने वाला हो सकता है परन्तु हमारी शिक्षा में सिवाय कलम घिसू बनने के अलावा कुछ नहीं बनता है। जब हमारा नौजवान ग्यारहवीं पास कर के या बी. ए. की डिग्री लेकर निकलता है तो वह बेकार निकलता है। उसको यह पता नहीं कि वह किस तरफ जाए। यह हमारी शिक्षा पद्धति का बड़ा दोष है। इसमें सुधार करके उपयोगी काम में लगने के लिए लड़के तैयार नहीं होंगे तो देश का बहुत बड़ा नुकसान होगा और यह नुकसान हमारी यह राज्य सरकार कर रही है और आगे भी करेगी। जरूरत इस बात की है कि टैक्नीकल ज्ञान, टैक्नीकल शिक्षा, काम की बात सिखायी जाये, शिक्षा के साथ-साथ। हमारे देश में यह बहुत बड़ा काम है और देश के सारे के सारे बच्चे और बड़े से बड़े आदमी का इस शिक्षा के साथ ताल्लुक है। मैंने विदेशों के स्कूलों को देखा। वहां के बच्चे अच्छे खिलाड़ी और पहलवान निकलते हैं। उनका शरीर बलायमान होता है और वे स्वस्थ होते हैं। हमारे यहां बच्चों को खेल के लिए प्रोत्साहन नहीं मिलता है और न खेल के लिए किसी तरह की सुविधाएं ही दी जाती हैं और तो और हमारे स्कूलों में खेल के लिए मैदान भी नहीं हैं। मैंने विदेशों में यह देखा है, अगर स्कूल के लिए खेल का मैदान नहीं है तो आस पास के मकानों को तुड़वा दिया जाता है और ऊंची ऊंची मंजिलें, मकान बना

Page No 123

123

(श्री केशरीमल)

दिए जाते हैं, ताकि बच्चों को खेल के लिए मैदान उपलब्ध हो। इस प्रकार वहां पर मकानों को तोड़ कर मैदान निकाले जाते हैं और इसकी व्यवस्था की जाती है। परन्तु हमारी एप्रोच क्या इस दिशा में है? हमारी शिक्षा पद्धति का जो हाल बना है, वह अजीब है। शिक्षा पद्धति में परिवर्तन का एक लम्बे अर्से से माहौल चल रहा है। यह अंग्रेजी तरह से शिक्षा देने की पद्धति लम्बे अर्से से चल रही है। सभापति महोदय, यह हमारे देश के अन्दर एक ऐसा वर्ग तैयार करने जा रही है, यह देश को उस दिशा में ले जाना चाहती है, जिसकी भाषा दूसरी है, जिसके खाने का सम्बन्ध दूसरा है, बोलने का तरीका दूसरा है, जिसके कपड़े दूसरे हैं, जिसका व्यवहार दूसरा है, इसका कहीं कोई मेल नहीं है, यहां पर बच्चे दूसरे समाज के बन कर निकलते हैं, वे इसी मुल्क में ही रहते हैं लेकिन इस मुल्क के दूसरे बच्चों को हिकारत से देखते हैं, हिकारत के साथ उनसे बात करते हैं। यह शिक्षा पद्धति सिखा रही है। सभापति महोदय, इस तरह हमारे देश में दो तरह की व्यवस्था हमारी सरकार द्वारा चलायी जा रही है और इसको सरकार द्वारा चलाना मैं बुरा मानता हूं। यह एक ऐसे वर्ग को पैदा करने वाली व्यवस्था है, जो देश के लिए खतरनाक है। ऐसे वर्ग को तैयार करना, जो देश को दूसरी ओर ले जाएगा, जिसका चाल चलन, रंग ढंग हमारे देश के लिए मौजूं नहीं है, तो फिर क्या कारण है कि ये स्कूल चल रहे हैं। केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के सामने यह मसला बराबर उठा है कि इस प्रकार के स्कूलों को समाप्त करना चाहिए। एक जैसी शिक्षा होनी चाहिए। बड़े लोगों के बच्चे, पैसे वालों के बच्चे अलग से अपना एक वर्ग तैयार कर रहे हैं। इस व्यवस्था को चलते रहने देना, एक प्रकार से दो तरह के लोगों को तैयार करना होगा। इसलिए मैं मांग करता हूं कि यह व्यवस्था मिटायी जानी चाहिए। सभापति महोदय, एक ओर हमारे प्रदेश में, हमारे देश में ये शिक्षण संस्थाएं बेहद फैली हुई हैं ये संस्थाएं जो शिक्षा देती हैं, उनके साथ-साथ राजनैतिक कार्य भी करती हैं। राजनैतिक प्रचार करें, यह बात अलग है लेकिन साथ-साथ बड़ा व्यापार भी करती हैं। अगर कहीं किसी प्राइवेट स्कूल में डाक्टरी के लिए भर्ती करती है, बी. ए. की परीक्षा के लिए कालेज लेती है, या कोई ट्रेनिंग का कार्य करती हैं, तो, सभापति महोदय जो खर्चा होता है वह तो ये संस्थाएं वसूल करती हैं विद्यार्थियों से इसके अलावा भी बड़ा भारी चन्दा जबरदस्ती वसूल करती हैं। यह एक प्रकार से विद्यार्थियों की लूट है। वह सारा का सारा पैसा देना पड़ता है वरना भर्ती नहीं होती है। इन संस्थाओं को राज्य सरकार भरसक पैसा देती है, ग्रान्ट देती है, सहायता देती है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं सरकार से कि आप, चाहे 90 परसेंट सहायता दें, 50 परसेंट सहायता दें, और बच्चों को भी लूट लें, इस तरह हमारे पैसे से हम को ही लूटा जाये और दूसरी तरफ इन संस्थाओं में जो काम करने वाले अध्यापक हैं, उनको तनख्वाह देंगी 150 रुपये और दस्तखत करवाएंगी 450 रुपये पर। यह तो दोनों तरफ से लूट है। एक तरफ गवर्नमेंट से पैसा लें और वहां के शिक्षकों को लूटें, विद्यार्थियों को लूटें तो ऐसी शिक्षण संस्थाओं के बारे

[illegible]

(श्री केशरीमल)

में बराबर आवाजें उठायी जा रही हैं कि क्यों नहीं इनका राष्ट्रीयकरण किया जाए, सरकार क्यों नहीं इनको अपने हाथ में ले, जब पैसा हमारा लग रहा है, विद्यार्थियों का लग रहा है, हमारे लोग अध्यापक हैं, उनका पैसा काटा जा रहा है तब इन संस्थाओं को बरकरार रखने की क्या आवश्यकता है। राज्य सरकार को इसमें दखल करना चाहिए और इनको हाथ में लेना चाहिए परन्तु राज्य सरकार इनको हाथ में लेने का प्रयास नहीं कर रही है। इसका क्या कारण है? इन संस्थाओं के जरिए राजनीतिक विचारधारा फैलाई जा रही है जिससे बच्चे दूसरी ओर जा रहे हैं और देश में एक खतरनाक स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रही है।

सभापति महोदय, हमारे राजस्थान के अन्दर अध्यापकों के प्रति राज्य सरकार की नीति को लें। राज्य सरकार की अध्यापकों के प्रति नीति को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि अध्यापकों के साथ राज्य सरकार भेदभाव करती है, उनके ट्रान्सफर, तबादले होते हैं, उनके साथ ज्यादतियां की जाती हैं। तबादलों में उनके साथ ज्यादतियां हो रही हैं। उनके मसलों को हल नहीं किया जा रहा है, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है और कई प्रकार से उनका विक्टे-माईजेशन किया जा रहा है। मैं, सभापति महोदय, आपके जरिए मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा कि क्या इस तरह से इन अध्यापकों को दबाया जा सकता है। अंग्रेजों ने भी इस तरह से भारतियों को दबाने का प्रयास किया था, परन्तु उनके प्रयास भी सफल नहीं हुए और उनको भी भारत छोड़ना पड़ा। अगर राज्य सरकार की यह मंशा है कि हम अध्यापकों को दबाएंगे, उनका ट्रान्सफर करेंगे तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उनका गुस्सा बढ़ेगा, उनको राज्य सरकार के प्रति नफरत होगी और उसके बाद लड़ाई होगी। यह राज्य सरकार अध्यापकों की वाजिब मांगों को वाजिब बातों को नहीं सुनना चाहती है जो यह सरकार की सरासर ज्यादती है। सभापति महोदय, यह सरकार का लगातार रवैया चल रहा है। सभापति महोदय एक तरफ यह कहा जाता है कि अध्यापकों के ट्रान्सफर और सब तरह के मसलों के हल के लिए एक रीति नीति है, कोई कानूनी व्यवस्था है। मैंने भी सुना है दो साल से सुन रहा हूं, ऐसा कर रहे हैं। सभापति महोदय, कुछ नहीं किया जाता है। सरकारी अधिकारी अपनी मर्जी से कार्य-वाही कर रहे हैं और इस कानून के अन्तर्गत जो दो साल पहले ट्रान्सफर न करने का है उसके ऊपर पानी फेर रहे है। नियम धरे रह गये हैं। जिनका चाहा ट्रान्सफर किया है और जिनको न चाहा है उनका बीस बीस साल तक ट्रान्सफर नहीं किया। एक जंगल में पड़ा हुआ है तो इस बात को कोई नहीं देखता है। राज्य सरकार की यह मशीनरी, राज्य सरकार का यह विभाग अध्यापकों के साथ ज्यादती कर रहा है। सभापति महोदय, अध्यापकों के साथ यही ज्यादती नहीं हो रही है, अगर अध्यापक पंचायत समिति के अन्दर काम कर रहा है, तो तीन तीन महीने तक उसको तनख्वाह नहीं मिलती है। इसके लिए कोई उपाय नहीं है। पंचायत समितियां तीन-तीन महीने तक तनख्वाह नहीं दे पाती हैं। राज्य सरकार पंचायत समितियों को अध्यापकों के वेतन का जो पैसा देती है वह पंचा-यत समितियों की तरफ बकाया कर्जे के मद में जमा कर लेती है और इस तरह अध्यापकों

(श्री केशरीमल)

को भूखों मरने के लिए मजबूर कर दिया गया है। अकाल के समय उनको खाने को नहीं मिलता। उनके घर में अनाज नहीं है। माननीय सभापति महोदय, यह कौनसा रवैया है, कौनसा तरीका है, यह कौनसी नीति है ? यदि वही बाद में चार महीने बाद में, पैसे दिये जा सकते हैं किसी बजट हैड से तो वह क्यों नहीं दिये गये ? और तनख्वाहों का पैसा इसके पेटे क्यों रख दिया ?

एक गांव में वह अध्यापक है और कोई आने-जाने वाला नहीं। गांव के लोग उसके साथ में ज्यादती करें तो कोई सुनने वाला नहीं। वह बीमार हो गया और दवा लेने गया डाक्टर के पास। वैसे डाक्टर तो मिलता ही नहीं है गांव में, लेकिन किसी तरह से किसी डाक्टर की दवा ले ली, तो हमारे शहरों के रहने वाले जो बड़े बड़े अफसर हैं, और बड़े बड़े लोग हैं वह अपनी दवाओं का बिल चार दिन में पास करवाते हैं। इनके पी.ए. तैयार करने वाले हैं। वह पी. ए. इनके टी.ए. और दूसरे मेडिकल के बिल के फार्म दूसरे दिन ही तैयार करके रखेंगे। लेकिन उस अध्यापक जिसने कि दवा ली है उसको मेडिकल के पैसे साल भर तक नहीं मिलेंगे। माननीय सभापति महोदय, 200 रुपये कमाने वाला मास्टर है जिसके घर में खाने को नहीं है उसने दवाओं पर पैसा खर्च किया उसको साल भर तक पैसा नहीं मिले ? तो कौन उसके लिए जिम्मेदार है ? किसके घर में खाने जायेगा। क्यों नहीं पंचायत समिति को उसके लिए पैसा देती है। यह सरकार की जिम्मेदारी है वह क्यों नहीं देती है। आपने उसको पंचायत समिति में डाल दिया तो उसका क्या कसूर ? वह भी एक अध्यापक है वह भी एक राज्य-कर्मचारी है, राज्य का नौकर है, और राज्य की सेवा करने वाला है। चाहे वह यहां काम करता है चाहे वहां करता है, चाहे इस विभाग में काम करता हो चाहे उस विभाग में काम करता हो, तो सारी जिम्मेदारी सरकार की है, और सरकार वहां से पीछे हट जाती है और मेडिकल के बिल के पैसे उसको नहीं देना चाहती है। आज हजारों और लाखों रुपयों के इस प्रकार के बिल वहां पर पड़े हुए हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

मास्टरों के साथ ज्यादती हो रही है और शिक्षा का बिल्कुल अन्धेरा है। मैं आपके मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर कुछ सिन्ध से आये हुए अध्यापक और अध्यापिकाएं हैं, या अजमेर जिले के कुछ लोग हैं जो अजमेर जिले से पहले अजमेर राज्य के राजस्थान में मिलने से पहले के हैं, इन दोनों के मामले हैं वह कुछ इम्पार्टेन्ट मामले हैं। यह जो सिन्ध से आते थे चाहे वह अध्यापक हों, चाहे अध्यापिकाएं हों वह वहां की वर्नाक्यूलर परीक्षा का सर्टिफिकेट या उनके वहां जो परीक्षा होती थी उसका सर्टीफिकेट मिलता था या यहां पर जो प्राविन्शियल परीक्षाएं होती थीं उनका सर्टिफिकेट मिलता था, वह उनके पास है। वहां से यहां आने के बाद किसी ने शिक्षा हासिल नहीं की। नौकरी में लेने के बाद सरकार ने कहा कि ट्रेनिंग ले लो तो ट्रेनिंग ले ली। जो सर्विस कर रहे हैं और आज सर्विस करते करते उनको 20–20 साल हो गये हैं, लेकिन

(श्री केशरीमल)

आज तक सरकार यह तय नहीं कर पाई है कि यह जो सिन्ध से आने वाले अध्यापक और अध्यापिकाएं हैं इनकी शिक्षा मान्य है कि नहीं, जिसकी वजह से खास तौर से हमारे जिले के लोग इस बात से परेशान हैं। कहीं पर उनकी तनख्वाहें कट रही हैं। उनका स्थिरीकरण वगैरह इस प्रकार से कर रहे हैं कि जिनको 450 रुपये तनख्वाह मिल रही है उनकी तनख्वाह 250 कर दी इस महीने से। इतनी बड़ी चोट लगाई जाय तो वे सहन नहीं कर सकते हैं। 47 में आये और अब 77 आ रहा है तो 30 साल का अन्तर है। राज्य सरकार इस बारे में गंभीरता से सोचती नहीं है। वह जो अध्यापक यहां आ गये या अध्यापिकाएं आ गईं और उनकी शिक्षा की मान्यता तय हुई नहीं तो उनको ट्रेनिंग में क्यों लिया, सर्विस में क्यों लिया ? और लेने के बाद 30 साल बाद यह कहें कि उनकी शिक्षा मान्य नहीं है तो मजाक सा लगता है, ज्यादती सी लगती है।

मान्यवर, शिक्षा शालाओं के लिए पैसा नहीं मिले। गांवों में शिक्षा शाला के लिए पैसा नहीं मिले। बरसों से जिन इलाके में फेमीन चल रहा है वहां के गांवों के लोगों से कहते हैं कि चन्दा करके कमरे बनाओ। माननीय सभापति महोदय, जिसके घर में खाने को नहीं है वह चन्दा करके कमरे किस तरह से बनायेंगे ? सरकार कहती है कि भूख लगी है तो रोटी खाओ। वह कहते हैं कि रोटी नहीं मिलती है तो अंगूर खाओ, मक्खन खाओ। उसी तरह से उनसे कहती है शिक्षा लेना है तो कमरे बनाओ। पैसा नहीं है तो चोरी करके लाओ और लगाओ। बाकी सरकार के पास इन गांवों को देने के लिए खास तौर से फेमीन वाले इलाके में जहां कि इस तरह के लोग रहते हैं जिनके पास रोजगार नहीं है, खाने को नहीं है ? पैसा नहीं है वहां पर शाला बनाने के लिए क्यों व्यवस्था नहीं की जाती है। खास तौर से बजट में शिक्षा के बारे में राज्य सरकार ने अजमेर जिले को नजरअन्दाज किया है। राजस्थान में ही नहीं सारे देश के अन्दर एक अजमेर जिला ऐसा था जिसमें कि शिक्षा की पर्सेंटेज सबसे ऊंची थी, लोग ज्यादा पढ़े हुए थे। यही नहीं कि बच्चे पढ़ते थे लेकिन बच्चियां भी पढ़ती थीं। हम चाहते हैं कि बच्चियों के स्कूल बढ़ाये जायं....

श्री खेतसिंह : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि सदन का समय जब तक आज की डिमाण्ड्स पारित न हो जायं, तब तक के लिए बढ़ा दिया जाय।

श्री सभापति : क्या सदन की अनुमति है कि आज की डिमाण्ड्स पास होने तक सदन का समय बढ़ा दिया जाय।

(स्वीकृत)

सदन का समय मांगें पारित होने तक बढ़ाया गया।

श्री केसरी मल : तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह कुछ खामियां हैं तो कुछ अच्छी बातें भी हैं, कुछ शिक्षा को बढ़ाया भी है आपने। कुछ स्कूलों को क्रमोन्नत करने की बात की है। हम यह मानते हैं कि बच्चियों के लिए स्कूल ज्यादा खोले जायें। हमारे यहां ब्यावर में इतनी बच्चियां पढ़ती हैं कि आगे जाकर कालेज शिक्षा के लिए बड़ी मुश्किल पड़ती है। वर्तमान मंत्री जी से इल्तजा करता हूं और

(श्री केशरीमल)

पहले वाले शिक्षा मंत्री जी से भी इल्तिजा की थी कि जहां हजारों की तादाद में बच्चियां पढ़ती हैं वहां एक कालेज की आवश्यकता है, लेकिन कालेज खोलेंगे कहां ? कालेज वहां खोलेंगे जहां पर एक लाख या दो लाख रुपये देने वाला हो। हो सकता है कि किसी नगर में ऐसा सेठ न हो तो क्या वहां की रहने वाली बच्चियों को शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए। अगर जनता पैसा इकट्ठा नहीं कर सके तो क्या उन्हें शिक्षा न मिले ? यह नीति चन्दा लेने की बिल्कुल गलत नीति है। ऊंची शिक्षा देने के लिए वहां पर कालेज खोलेंगे और बच्चियों को शिक्षा देने का प्रयास करेंगे। हमारे इलाके में इसकी ज्यादा से ज्यादा मांग है। वहां पर प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल खोलना चाहिए और कालेज का खोलना आवश्यक है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : आपको पार्टी का पूरा समय लेना चाहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। आपकी पार्टी के और कोई सदस्य न बोलें।

श्री केशरीमल : मैं दो प्वाइंट्स ही कहना चाहता हूं। मैंने पहले भी निवेदन किया था और आपने (श्री गफ्फार) भी इशारा किया तो मुझे छोड़ना पड़ेगा।

मैं जेल के बारे में कुछ सुझाव देना चाहता हूं। जेल में जितने कैदी हैं उनकी शिक्षा होनी चाहिए। दूसरा वहां पर रेडियो, टेलीफोन वगैरह की व्यवस्था होनी चाहिए। शिक्षा के साथ जब यह चीजें होंगी और अच्छी लाइब्रेरी होगी तो वहां पढ़ेंगे तो वहां पर पढ़ाने की बात है तो ऐसे कैदी जो कि पढ़े हुए हैं तो उनसे कहें कि घण्टा दो घण्टा उन लोगों को पढ़ायें चाहे अखबार लेकर पढ़ायें, और सारे ऐसे लोगों के लिए कोई वाजिब रिम्युनिरेशन मिलना चाहिए। तीसरी बात वहां पर, सभापति महोदय, धन्धे का। कुछ न कुछ काम सिखाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। जो काम सीख जाते हैं और काम करते हैं तो उस काम की पूरी व्यवस्था उनको मिलनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ-साथ वह कम्बल जिन पर हम सोये थे, शायद अब बदल दिये हों, उनको बदल देना चाहिए। वह इतनी बदबू देते हैं कि उनको मुंह पर नहीं रख सकते हैं। वह कम्बल फटे हुए नहीं होने चाहिए। उनको बदलने की व्यवस्था होनी चाहिए। वहां पर बिस्तरे की व्यवस्था होनी चाहिये। उनके खाने-पीने की व्यवस्था ठीक नहीं है और सबसे बड़ी दुखदायी बात यह है कि जेलों की मरम्मत का काम बिल्कुल ही हाथ में नहीं लिया गया है। सारी जेलों में जा-जा कर घूम-घूम कर मैंने देखा है कि नीचे कचरा गिर रहा है। सफाई नहीं होती है तो उसकी व्यवस्था होनी चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

मैं अभी समाप्त करता हूं।

जेल के अन्दर ऐसे सिपाही हैं, जिनको 15, 16 साल हो गये हैं। दूसरे डिपार्टमेण्ट्स से यहां आये हैं। उनको वहां एडजस्ट किया गया है। लेकिन 15-15 साल से उनके मामलों को हल नहीं किया गया है। यह क्या अन्धेरगर्दी है। हमें कहना है, जेल के अन्दर जो फटी हुई वर्दियां हैं और फटे हुए कपड़े हैं, उनमें सुधार किया

(श्री केशरीमल)
जाये। जिन लोगों की पेंशन हो जाये उनको तुरन्त पेंशन दी जाये।

श्री सभापति : श्री भोपालसिंह।

श्री भोपालसिंह (जैसलमेर) : सभापति महोदय, जहां तक शिक्षा का प्रश्न है। पहले जहां 17 में 1 शिक्षित था, वहां आज 6 पाते हैं। प्राइमरी में 36% वहां अब 75-76% जाते हैं। इसके अनुसार हमारे राष्ट्र में शिक्षा की तरक्की हुई है। लेकिन इसके बारे में जहां तक उपयोगिता का प्रश्न है, शिक्षा के लक्ष्य दो प्रकार के होते हैं। एक तो व्यक्तिगत विकास के लिए। जिससे मानसिक, आध्यात्मिक और शारीरिक विकास हो सके। ताकि वह अपनी योग्यता के अनुसार समाज से लाभ उठा सके और दूसरा यह है कि वह इसके द्वारा सामाजिक विकास में अपना योगदान दे सकें। मैं इन दोनों बातों के अन्दर जो आज भारत के अन्दर ही नहीं, सभी देशों के अन्दर माना गया है। शिक्षा ही वह साधन है कि जिसके द्वारा विकास हो सकता है। चाहे वह आर्थिक, सामाजिक हो या आत्मिक हो। मैं आपकी आज्ञा से जो तीसरी योजना में शिक्षा के बारे में वक्तव्य है, वह उद्धृत करना चाहता हूं।

"तीव्रगति से आर्थिक विकास और टैक्नोलाजी के क्षेत्र में प्रगति तथा स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय और अवसर की समानता पर आधारित समाज के निर्माण में शिक्षा एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। देशवासियों के मान में एक ही राष्ट्र के नागरिक होने के भाव भरने, लोगों की शक्ति के रचनात्मक उपयोग तथा देश के प्राकृतिक और मानवीय साधनों के विकास की आधार शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम है।"

सभापति महोदय, जब शिक्षा का इतना बड़ा महत्व है तो सवाल यह उठता है कि क्यों वर्तमान शिक्षा ने हमारे उद्देश्यों की पूर्ति की है या नहीं। चाहे वित्तीय स्थिति हो, चाहे सामाजिक स्थिति हो। आर्थिक या राष्ट्रीय क्षेत्र जो चुनौतियां हैं, आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा कर सके हैं या नहीं। आज 27 साल के बाद शिक्षा की उपलब्धियों की जांच करें तो पता चलेगा कि वह उसी प्रकार से रूढ़िगत, परम्परागत व दिशाहीन हैं।

(5.04 सायं)

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता, सभापति, पीठासीन)

अगर इसकी गहराई के इतिहास में जायें तो पता चलेगा कि इस शिक्षा पद्धति का निर्माण इस उद्देश्य से नहीं किया गया था। जैसा कि कुछ पूर्ववर्ती माननीय सदस्यों ने कहा है। लार्ड मैकाले ने इसका निर्माण किया था। इंगलैण्ड में आक्सफोर्ड मोडल जो ऊंचे तबके के लड़कों के लिए मानसिक और बौद्धिक अनुभव प्रदान करती हो। मैट्रोपोलिटेन और कैम्पेरियल शक्ति की तत्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने पर उन्हीं का संशोधन करके मैकाले ने शिक्षा के आधार का निर्माण किया है जैसा कि माननीय नारायणसिंहजी ने कहा था, उसका उद्देश्य इस देश में ऐसे लोगों को तैयार करना था जो रूल्स और क्लर्स के बीच में इण्टरप्रेट हों। जो रंग और रूप में बिल्कुल, हिन्दुस्तानी हों लेकिन टेस्ट, ओपीनियन और मोरल्स में अंग्रेज हों। वह शिक्षा आज भारत की वर्तमान मांग को पूरी नहीं

(श्री भोपालसिंह)

कर सकी है। नेहरूजी ने आजादी से पहले और बाद में भी, हमेशा उन्होंने अपनी राय प्रकट की है। उन्होंने कहा है कि इस क्षेत्र के अन्दर सम्पूर्ण क्रान्ति व परिवर्तन होना चाहिए। इसके लिए मुदालियर कमेटी, राधाकृष्णन कमेटी और कोठारी कमीशन बैठा। शिक्षा आयोग एक शानदार प्रतिवेदन पेश किया है। उसके अन्दर कहा गया है। देश का आयन्दा भविष्य क्या होगा। यह हमारी शिक्षा में क्या परिवर्तन होगा। उस पर निर्भर करता है। यह 1966 में कहा गया है और आज 1974 आ गया है। आज भी हमने इस क्षेत्र में परिवर्तन नहीं किया है। भाषा आयोग ने भी यही कहा है। प्राइमरी एजूकेशन का नेशनलाइजेशन हो जाना चाहिए। प्राईमरी स्कूलों और सैकेण्डरी स्कूलों का वोकेशनलाइजेशन हो जाना चाहिये। आज हमारे सामने कुछ प्रश्न उभर कर सामने आते हैं। लड़के जो पढ़ते हैं। लड़के जो जानकारी आज प्राप्त करते हैं, वह सामान्य जीवन से बिल्कुल अलग और कटी हुई है। उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। अधिकांश में तो यह है कि जो पढ़ जाते हैं, वह काम में नहीं आता है। जो रटकर उपार्जन किया जाता है, वह उनके लिए निरर्थक है। तो इस प्रकार से बहुत बड़े मूल्यवान समय की छात्रों को बलि देनी पड़ती है आखिर वह अधकचरा ज्ञान लिये हुये फिरते हैं। उनको रोजगार नहीं मिलता है। तो उसमें खीझ उभर आती है। उसमें समाज और सरकार के प्रति विद्रोही भावनाएं पैदा होती है। वह बगावत करने की सोचता है। उसका परिणाम यह है कि उसके व्यवहार में अनुशासन हीनता है। उदासीनता है। शिक्षा के अध्ययन में उसकी कोई रुचि नहीं है। संसार के अन्दर उसकी अनरेस्ट स्थिति बनी हुई है। – There is a crisis in the education also.

आर्थिक क्षेत्र में आज ऐसी स्थिति है। इसी प्रकार से शिक्षा में क्राइसिस की सिचुएशन बनी हुई है। उसका नतीजा यह है कि आज गांवों के लोग शहरों में आते हैं और 18–18 साल पढ़ते रहते हैं। उनके जीवन में शहरीपन आ जाता है फिर उसके बाद गांवों में वापिस जाकर गांवों के जो कठोर और मेहनत के कार्य होते हैं, वह उनसे वहां पर किये नहीं जाते हैं। वह चाहते हैं कि साफ्ट जाव, ऐसा काम करें जिसमें पंखे के नीचे बैठकर फाइलों में काम करना पड़े। इस तरह जो श्रम की गरिमा है, उसको हेय समझने लगते हैं। इस तरह से गांव का आदमी है, जो हमारा बहुत बड़ा श्रमिक है, जो हमारे देश का उत्पादन करने वाला है, उसकी भी आदतें बिगाड़े। शिक्षा की बदौलत तो यह हमारे काम की नहीं रहती।

आज सरकार का रुख यह है, वह मानती है कि शिक्षा व्यवसायोन्मुखी होनी चाहिए, वोकेशनल ओरियंटेड होनी चाहिए, केरिअरिस्टिक होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए वह कहते हैं, हमारे पास साधन नहीं है और जो लक्ष्य है पांचवीं योजना का उसका केवल 20 पर्सेन्ट प्राप्त करेंगे, यह हमारे टार्जेट का अचीवमेंट है, यह बहुत कम है। अगले पांच साल के अन्दर इस कारण से लोग ऐसी शिक्षा पाने के लिए कोई तैयार नहीं होंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

एक निवेदन और करना चाहता हूं। हमारी आबादी 80 प्रतिशत गांवों में रहती

(श्री भोपाल सिंह)

है। 80 प्रतिशत जो गांवों में रहती है, उसके लिए राधाकृष्णन् आयोग ने कहा है, एजूकेशन का रूरलाईजेशन करना चाहिए। उनको वहीं रहने देना चाहिए। उनको वहां स्कूल देने चाहिए, ऐसे वोकेशनल कार्य देने चाहिए जिसमें दिलचस्पी ले सकें और इस कन्टेक्स्ट में एज्यूकेशन का शहरीकरण नहीं हो सके। रूरल इन्स्टीट्यूट का सवाल है, जहां तक राधाकृष्णन आयोग ने कहा है, राजस्थान में है, और जैसा माननीय सदस्य कह रहे थे, वह भी बन्द पड़ा हुआ है। यह खेद की बात है।

एक बात और मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं हमारी शिक्षण संस्थाओं के अन्दर वेकेशन होती है। पाश्चात्य देशों के अन्दर गर्मी के अन्दर खेती वगैरह का काम होता है और सर्दी में कुछ नहीं हो सकता है। हमारे यहां भी गर्मी के अन्दर वेकेशन होती है उसी आधार पर यह बिल्कुल गलत है। इससे लड़कों को कोई अवसर नहीं मिलता खेती से सम्बन्ध स्थापित करने का, उसमें काम करने का। अठारह साल तक गर्मी के वेकेशन में बैठे रहते हैं। इस कारण गांवों से सम्पर्क टूट जाता है। एक तरह से यह जरूरी है कि गर्मी में यह वेकेशन न होकर यह वेकेशन वर्षा ऋतु में होनी चाहिए ताकि अपने खेतों में काम कर सकें और मेहनत के प्रति प्यार बना रहे और उसके प्रति उनमें लगन रहे और हेय न समझे। इसके बारे में कई प्रयोग अमेरिका के अन्दर हुए सेवन्टीज के अन्दर यह बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्राइसिस है। वहां पर बहुत डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है। इस क्षेत्र के अन्दर बहुत बड़े एक्सपेरीमेंट हुए हैं। वह कहते हैं। आज की शिक्षा की पद्धति है उसमें "Education for what?" तब्दीली के लिए बहुत बड़े एक्सपेरीमेंट चल रहे हैं, उसमें चल रहा है आल द राउण्ड ऐसे स्कूल होने चाहिए, जिनमें चार ग्रुप हों एक क्लास में चार ग्रुप होने चाहिए, जिनमें से एक वेकेशन के लिए बाहर चला जाए और बाकी के तीन काम करते रहें। फिर दूसरा चला जाय और बाकी तीन काम करते रहें। इसमें इकानामी और प्लानिंग की आवश्यकता वह भी किया जा सकता है।

इसी प्रकार से एडमिशन लेते हैं कालेज में तो एडमिशन में किसी को कोई डिग्री की जरूरत नहीं होनी चाहिए। उनका कहना यह है कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो, उससे डिग्री कोई ताल्लुक नहीं रखती है। कैसे छात्र निकलते हैं, कैसे आदमियों का निर्माण करती है–इससे सम्बन्ध रखती हैं। उनका कहना है कि डिग्री की जरूरत नहीं है। जो पढ़ना चाहें, चाहे कभी आयें, कोई आयें, वह पढ़ सकते हैं। इस तब्दीली के अनुसार फ्री एडमिशन से जो एजूकेशन चल रही है– इसको भी आप देख लें।

फ्री एडमिशन यूनिवर्सिटी के अलावा जो तकनीकी विषय है उसको भी देखा जा सकता है।

श्री सभापति : कृपया समाप्त कीजिये।

श्री भोपालसिंह : एक मिनिट और चाहूंगा।

जो असन्तुलन बना हुआ है नारी शिक्षा के अन्दर और ग्राम शिक्षा के अन्दर-इसको

(श्री भोपाल सिंह)

करेक्ट करने की जरूरत है। इसके अलावा बैकवर्ड एरिया और विकसित एरिया, गांवों और शहरों में जो असंतुलन है उसको भी ठीक करने की जरूरत है।

दो शब्दों में जिले के बारे में कहना चाहूंगा। हमारे कालेज के अन्दर विज्ञान विषय के बारे में बहुत पहले मन्त्री महोदय ने आश्वासन दिया था, वायदा किया था कि खोल दिये जायेंगे। उनको अब खोलने की बात है।

एक कालेज है, उसकी इमारत का चार्ज लेने की बात है। पिछले बारह महीने से कोशिश कर रहे हैं लेकिन गवर्नमेंट उसका चार्ज नहीं ले रही है। उसका नामांकरण भी, जो दानकर्ता हैं, उनके नाम से करने की बात है। मैं शिक्षा मंत्री जी से चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में वह कदम उठायें।

धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री चेतराम।

(अनुपस्थित)

श्री उम्मेदीलाल।

(अनुपस्थित)

श्री चिम्मनसिंह भाटी।

(अनुपस्थित)

श्री विजयसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री नानालाल।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : हमारा नाम गायब है।

श्री नानालाल (राजसमन्द) : सभापति महोदय, शिक्षा की मांग पर जो चर्चा चल रही है····

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मेरा नाम गायब है और रतीरामजी का भी।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपका नाम बोल दिया गया है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : बोल दिया तो हम डिफाल्टर तो नहीं हो जायेंगे।

श्री सभापति : आपका नाम आया था।

श्री रतीराम : मैंने उस वक्त कहा था, थोड़ी देर बाद बोलूंगा।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : पांच सात मिनट इन्हें बोल लेने दीजिये। पांच सात मिनट मैं बोलूंगा।

श्री नानालाल : शिक्षा की मांग पर विचार चल रहा है। इस पर मैं भी अपने विचार रखना चाहता हूं। आज राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार शिक्षा के लिए वाकई बहुत अच्छे कदम उठा रही है किन्तु सरकार को चलाने वाले जो पहिये हैं, उनका रुख दूसरी तरफ है, सरकार के सिद्धान्त को बदलने में उनका बहुत बड़ा सहयोग है क्योंकि सरकार तो चाहती है लेकिन पहिये, या मशीनरी जो उसे चलाने वाले हैं, उनकी मन्शा दूसरी है। सरकार चाहती है कि प्राथमिक शिक्षा में सुधार हो, जितने गांवों में स्कूल हैं, वहां की शिक्षा अच्छी हो। किन्तु यह बात कौन सोचता है। वही सोच सकता है जो गांव में रहता है, वही अधिकारी सोच सकता है जो गांव का है। किन्तु यहां तो शायद, मेरे खयाल में, कोई अधि-

(श्री नानालाल)

कारी नजर नहीं आता है जो गांव से आया हो और यह बात जिसे ज्ञात हो कि गांवों की क्या दशा है और इस प्रकार इस दशा को सुधारना है। माननीय सभापति महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री, जो शायद ग्रामीण क्षेत्र की तरफ जाते ही होंगे, उन्होंने देखा होगा, आज जो प्राथमिक शालायें खुलती हैं, उनकी क्या दशा है, लड़के कहां बैठते हैं और अध्यापक हैं वे कहां बैठते हैं। आज उनकी तुलना शहर के किसी प्राथमिक स्कूल से कर लिजिये, उनमें जमीन और आसमान का अन्तर नजर आयेगा। गांव का लड़का अगर आपके शहर के किसी प्राथमिक स्कूल में चला जाय तो स्कूल के अन्दर से बाहर नहीं निकल पायेगा, वह चकरा जायेगा, यह क्या है, मुझे कहां ले आये। मेहरबानी करके यह देखिये, प्राथमिक स्कूल जहां तीन सौ लड़के पढ़ते हैं और दस, बारह, पन्द्रह अध्यापक हैं, कोई प्रावधान चपरासी का नहीं है। जो बजट बनाते हैं, जो पैसा दे रहे हैं, शिक्षा के लिए उसमें प्राथमिक शालाओं को पंचायत समिति को सौंप दिया है, उनके पास बजट नहीं हैं, अगर सब घाटे में नहीं हैं तो एक नया पैसा न मकान के लिए दे सकती हैं। न फर्नीचर के लिये दे सकती है। तो मेहरबानी करके इन अध्यापकों के वेतन के साथ साथ, क्योंकि वेतन की राशि आप देते हैं, आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का प्रावधान कर दें। कम से कम एक प्राईमरी स्कूल में एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का होना अनिवार्य ही होना चाहिये। किन्तु आप देखिये, कोई स्कूल नहीं है जहां चतुर्थ श्रेणी का कोई भी कर्मचारी हो, आज जो शिक्षा विभाग के अन्तर्गत प्राथमिक शाला चल रही हैं, उनमें चार चार चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, लेकिन जिनमें बारह अध्यापक हैं, जहां तीन सौ लड़के पढ़ रहे हैं, जो पंचायत समिति के अन्तर्गत चल रहे हैं, उनमें एक भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नहीं है, वहां पानी पिलाने वाला नहीं है, वहां पर झाड़ू लगाने वाला कोई नहीं है। मैं कहता हूं कि सरकार तो चाहती है लेकिन मशीनरी नहीं चाहती है तो वह कैसे चला सकती है। इसलिए, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं, आप कम से कम दिमाग लगाइयेगा। उनके भरोसे मत रहियेगा। मशीनरी के भरोसे रह कर गांवों के प्रति भेदभाव बरतेंगे तो माननीय सभापति महोदय, आज आप देखिये, 80 प्रतिशत जनता गांवों में है, उनका यह हक है कि उनको भी समाज शिक्षा मिले। किन्तु, माननीय सभापति महोदय, उनकी उपेक्षा, अभी तक बरती जा रही है। आज गांवों में माध्यमिक स्कूल खोल दिये गये हैं किन्तु वहां कोई मकान की व्यवस्था नहीं है। गांवों में जो लोग रहते हैं, पहले तो वह गरीब हैं, उनके पास पैसा नहीं है, फिर उनको कहा जाय कि जब तक मकान नहीं बनाओगे तब तक हम आपके यहां स्कूल नहीं खोलेंगे। वही मुश्किल से जैसे तैसे मकान बना कर सौंपते हैं किन्तु वापिस रिपेअरिंग के लिए एक पैसा सरकार की तरफ से नहीं मिलता है, चाहे वह गिर जाय मकान। इधर आलीशान भवन जिनमें स्कूल है, महाविद्यालय है, जिनमें लेट्रिन जितनी जगह की व्यवस्था है, और जितना पैसा उसमें लगा है, उतना पैसा आप माध्यमिकशाला की पूरी बिल्डिंग पर नहीं लगा सकते। आप इसमें सुधार कीजिये और गांव और शहर का भेद मिटाइये।

(श्री नाथालाल)

कुछ माननीय सदस्यों के जो आक्षेप थे कि माननीय मंत्री महोदय सिर्फ स्थानान्तरण का काम करते हैं। एक बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ, जिन लोगों का स्थानान्तरण मंत्री महोदय करना चाहें उनका छः छः महीने स्थानान्तरण नहीं होता है। किन्तु कोई अधिकारी चाहता है तो दिन अस्त होने के पहले स्थानान्तरण कर सकता है। इसलिए इस ओर मेहरबानी करके ध्यान रखना चाहिए निर्माण कार्यों के लिए भी बजट में प्रावधान रखा गया तो वह सिर्फ कालेजों के लिए है। वह गांवों में भी होना चाहिये। मैं मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वह उत्तर के समय कुछ ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों के निर्माण हेतु कुछ अपने बजट में संशोधन करायें।

सभापतिजी, शिक्षा क्षेत्र में सरकार की गांवों के प्रति उपेक्षा बढ़ती जा रही है, उस बारे में मैं कई बार निवेदन कर चुका हूं। मैं अपने क्षेत्र के बारे में भी निवेदन करना चाहता हूं मेरे स्कूल में माध्यमिक स्कूल तो हैं किन्तु राजसमंद एक बड़ा सब-डिवीजन हैं वहां कालेज खुलवाने के लिए प्रयत्न किया गया, कहा गया कि नहीं खुल सकता है। इसलिए इस ओर भी थोड़ा विचार किया।

अन्त में सभापतिजी, मुझे निवेदन करना है कि आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद, मैं अधिक समय न लेते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : श्री रामलाल वाड़ी।

श्री रामलाल (वाड़ी) : सभापतिजी, आज शिक्षा के बारे में चर्चा हो रही उसके लिए मेरे कुछ सुझाव हैं। शिक्षा के क्षेत्र में वाकई सुधार हुआ है, इसके लिए तो मैं मंत्रीजी का स्वागत करता हूं साथ में विद्या के बारे में थोड़ी सी कठिनाइयां हैं इनका भी मंत्री महोदय ध्यान रखें व कठिनाइयों को दूर करने के लिए ऐसे कदम उठाएं कि जो विद्या ग्रहण करने के बाद घर पर आकर बैठते हैं, वे चक्कर लगाते रहते हैं नौकरी के सम्बन्ध में। जयपुर में और मंत्री महोदय के पास में और खास तौर से जो लोकल विधायक है उनको भी परेशान करते हैं। उनके बारे में ऐसी योजना सोची जाय उद्योग धंधा या कृषि कालेज खोला जाय जिनमें उनके लिए ऐसी शिक्षा दी जाय जो काम में लग सकें। बिजनेस है, कई काम ऐसे हैं जैसे पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया था कि हमारे यहां पाली इलाके में काफी संख्या में उद्योग चल सकते हैं तो ऐसे उद्योग खोले जायं कि विद्यार्थी नौकरी के लिए चक्कर नहीं काटें। जितने विद्यार्थी विद्या ले रहे हैं उन सबको नौकरी मिलना, असम्भव है।

जिस क्षेत्र से मैं आया हूं वहां दो तहसीलें हैं एक वाड़ी और बसेरी। दोनों जगह हायर सैकेन्डरी स्कूल्स हैं। पंचायत समितियों में तीन स्कूल्स और हैं। उनको देखते हुए 5–7 हायर सेकेन्ड्री स्कूल्स हैं। तो वाड़ी में कालेज होना जरूरी है। इतने लड़के जो अपने यहां से पढ़कर निकलते हैं तो या तो धौलपुर कालेज शिक्षा के लिए जाते हैं, उनको वहां अगर जगह नहीं मिलती है तो मध्यप्रदेश में जाते हैं या यू.पी. में जाते हैं। तो उनकी कठिनाइयों को देखते हुए वाड़ी में कालेज होना चाहिए। वाड़ी के हायर सेकेन्डरी स्कूल में कोई ऐसा विषय नहीं है

Page No 134

(134)

(श्री रामलाल)

जो लड़कों को उद्योग में लगा सके, वहां कामर्स विषय पढ़ाया जाए, अर्थ शास्त्र पढ़ाया जाए। तो ऐसी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए जिससे जो लड़के परेशान होते हैं वे परेशान न हों। मेरे क्षेत्र में शिड्यूल्ड कास्ट व शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग ज्यादा हैं तो जो पैसे वाले हैं वे तो अपने लड़के को जयपुर या मध्य प्रदेश में या यू. पी. में भेज देते हैं लेकिन गरीब लोगों के बच्चे कालेज शिक्षा से बंचित रह जाते हैं। वह पिछड़ा इलाका है, पिछड़ी जाति के हैं।

काफी मात्रा में हमारे यहां जो लड़के घूमते हैं उनके लिए इन्जीनियरिंग कालेज खोला जाए, ताकि भरतपुर में ही वे इंजीनियरिंग कोर्स कर सकें। इससे वहां लड़कों के लिए काफी मात्रा में सुविधा मिलेगी। कृषि कालेज भी खोलें। जो उद्योग धन्धे वाले हैं वे इन्जीनियरिंग में जा सकें।

जेलों के बारे में थोड़ा सा और निवेदन करूंगा। हमारे यहां धौलपुर में जेल है। उनके लिए मन्त्रीजी सोचें कि सभी जगह बन्दी हैं उन्हें अच्छा ज्ञान प्राप्त करायें ताकि उनका जीवन सुधर सके। मेरे बाड़ी क्षेत्र में मुंसिफ मजिस्ट्रेट का कोर्ट खुल गया है। अब धौलपुर से कैदियों को लाना ले जाना पड़ता है सुबह से शाम तक उनका सारा दिन चला जाता है। इसलिए उनकी कठिनाइयों को देखते हुए बाड़ी में एक जेल बनाना चाहिए ताकि वहां बन्दी रह सकें। लाने ले जाने में कैदी भाग भी सकता है तो कर्मचारियों के लिए मुसीबत होगी, रास्ते में काफी जंगल हैं। इन कठिनाइयों को देखते हुए मन्त्री महोदय सोचकर जेल का निर्माण कार्य करायें।

श्री सभापति : श्री गोपाल जोशी।

श्री गोपाल जोशी (बीकानेर) : सभापति महोदय, मांग संख्या 24 मुख्य शीर्षक 277 शिक्षा के सम्बन्ध में मेरा कटौती प्रस्ताव है। वैसे तो इस मुख्य शीर्षक के अन्तर्गत शिक्षा, श्रम, रोजगार इत्यादि इन सभी पर बोलना चाहूं तो इतना समय लेने की आप इजाजत नहीं देंगे। इसलिए थोड़े में ही मैं अपने विचार रखना चाहता हूं।

सभापति महोदय, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना है, नोलेज-ज्ञान, किसके लिए प्राप्त करना है, जीवन के लिये और जीवन क्या है, जैसे किसी ने कहा है कि Knowledge, power and love make a life. यह सब बातें हमारी शिक्षा दे सके, ऐसी शिक्षा हो, फिर शिक्षा ऐसी हो कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब शिक्षा लेकर विद्यार्थी कालेज से निकले उसमें एक कान्फीडेन्स हो जीवन के लिये कि वह जहां कहीं भी जायगा, जिस जगह पर, जिस क्षेत्र में उसी कान्फीडेन्स के साथ जायगा जैसे कि मिल्टन ने कहा है कि–इसलिए शिक्षा का उद्देश्य यह भी होना चाहिए कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद शिक्षार्थी में एक तरह का कान्फीडेन्स पैदा हो। हम एक डेमोक्रेटिक कन्ट्री के नागरिक हैं और इस डेमोक्रेसी को आगे जीवित रखना है तो मेरी प्रार्थना है कि डेमोक्रेसी की शिक्षा भी इस शिक्षा प्रणाली में उसका समावेश इस तरह से कर दिया जाय कि जब तक लड़का पढ़ कर कालेज से निकले इस डेमोक्रेसी के बारे में पूरी तरह

(श्री गोपाल जोशी)

से असोसिएशन प्राप्त कर सके, इसमें उसकी शिक्षा सहायक हो, अन्यथा किसी ने कहा है–They are just a burdon on Society. और वैसे शिक्षा अधिकारियों ने, कई शिक्षा शास्त्रियों ने और कई कमीशन्स ने अपनी रिपोर्ट दी हैं, बड़ी बड़ी रिपोर्टें दी हैं परन्तु वे इस रूप में विचार नहीं कर सके फिर भी यदि उन रिपोर्टों पर जो सलाह दी गई है और जो विचार उन्होंने रखें हैं उनको भी अगर क्रियान्वित किया गया होता तो वह भी एक बहुत बड़ी बात होती है, मैं समझता हूँ कि अगर उन सुझावों को अमल में लाने की कोशिश करते तो भी हम अपने उद्देश्य को कुछ हद तक पूरा

(5.32 सायं)

(श्री फूलचन्द जैन, सभापति, पीठासीन)

कर सकने में सफल होते। आज आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षा एक्स्टेन्सिव और इन्टेन्सिव दोनों ही प्रकार की होनी चाहिए, क्वालिटेटिव और क्वान्टीटेटिव दोनों ही प्रकार की होनी चाहिए। अभी जैसा कि माननीय सदस्य रामकिशनजी ने कहा कि ज्यादा शिक्षा फैलेगी तो कांग्रेस दल हार जायगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की उनकी धमकियों से डरने की कोई बात नहीं है। शिक्षा से कांग्रेस हार जाय तो भले ही हार जाय परन्तु शिक्षा कम नहीं हो सकती यह रामकिशनजी को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। बल्कि मेरा तो यह निश्चित मत है कि ज्यादा शिक्षा फैलाने से कांग्रेस हारेगी नहीं, जीतेगी ही। क्योंकि विद्यार्थियों में जो आज असन्तोष है, जो स्टुडेन्ट अनरेस्ट हम देख रहे हैं वह उनके सड़कों पर भटकने से पैदा हुआ है। उनमें असन्तोष विरोधियों के बहकाने से पैदा हुआ है। कालेज में पढ़ने वाले लड़कों का, स्कूल में पढ़ने वाले लड़कों का और उन लोगों का ऐसा मानस कभी नहीं होता कि वे हड़ताल करें, आन्दोलन करें, तोड़फोड़ करें और मुर्दाबाद के नारे लगाये। यह सिर्फ उन लोगों के भुलावे में आकर ये अबोध लड़के आन्दोलन की और अनरेस्ट की बात करते हैं। इसलिए हमारा लक्ष्य कम से कम हर गांव में एक स्कूल खोलने का लक्ष्य होना चाहिए। सभापति महोदय, जैसा कि कहा गया है कि हमारे देश में– थर्ड लार्जेस्ट पूल आफ साइन्टिस्ट है। हमारे देश में बड़े-बड़े साइन्टिस्ट हैं जिन्होंने दुनिया में नाम कमाया है परन्तु खेद की बात है कि हमारे देश में उनको एब्जार्व करने का कोई जरिया नहीं है। यह तो अच्छा तो है कि हमारी विदेश नीति के कारण ईरान और ईराक में हमारे कई साइन्टिस्ट काम कर रहे हैं और भी कई देशों में हैं जहां पर यह आदान-प्रदान हुआ है। हमारे शिक्षा मंत्रीजी मृदुभाषी हैं, बड़ी मीठी बातें करते हैं और आश्वासन भी देते हैं और मैं समझता हूं कि वे काम भी अच्छा करते हैं लेकिन मैं उनका ध्यान थोड़ा उनके विभाग की तरफ भी आकर्षित करना चाहूँगा। विभाग में कई जगह ठीक ढंग से वर्क नहीं चल रहा है। क्योंकि मैं बीकानेर से आता हूं, मैंने कई जिला अधिकारियों से मिलने की कोशिश की कई कामों के लिये, चूंकि समय कम है इसलिए मैं अधिक तो नहीं कह सकता, परन्तु यह निवेदन करना चाहता हूं कि पब्लिक रिप्रेजेन्टेटिव के साथ जिस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए, उनके साथ जिस प्रकार का रुख

(श्री गोपाल जोशी)

अपनाना चहिए मुझे यह कहना पड़ता है कि उस प्रकार का नहीं अपनाया जाता। इसी प्रकार से और भी कई समस्याएं हैं जिनकी ओर मैं शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहूंगा। जिस प्रकार से हमारे शिक्षा मंत्रीजी मृदुभाषी हैं और उनकी वाणी में मिठास है उसी प्रकार का मिठास अधिकारियों और दूसरे लोगों में भी हो तो उपयुक्त होगा। अपनी तरफ कटौती प्रस्ताव....

श्री रामगोपाल : आपके बीकानेर के रसगुल्लों की तरह मीठा होना चाहिए।

श्री गोपाल जोशी : सभापति महोदय, सन् 72 में मैंने याचिका समिति को एक याचिका प्रस्तुत की थी और उसने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि वहां पर ऐसा वातावरण है, ऐसी परिस्थितियां हैं कि एक विश्वविद्यालय खोला जा सकता है। बीकानेर मण्डल में विद्यार्थियों की संख्या लगभग 29 लाख 7 हजार 12 सौ की है और इस क्षेत्र में नहरों की बहुतायत होने के कारण और रेतीले धोरे के कारण कई प्रकार के रिसर्च की बहुत सी सुविधायें उपलब्ध है, इनका स्कोप है। पूरी भूमिका एक विश्वविद्यालय के लिये तैयार की गई है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अभी जो विश्वविद्यालय है उसका क्षेत्र बहुत विस्तृत होने से उसका डिसेन्ट्रेलाइजेशन करना बहुत जरूरी है। वह बहुत फैल गया है जिससे उसके परिणाम भी ठीक नहीं निकलते हैं। इसके अलावा कुछ आटोनोमस कालेज भी बनाये जाने चाहिएं उनकी रूप रेखा कैसी हो यह तय करना चाहिए। मैं चाहूंगा कि बीकानेर का डूंगर कालेज और चूरू जिले के और गंगानगर जिले के तथा इधर उधर के कुछ कालेजों को लेकर एक विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए और उन कालेजों को अधिक सहायता दी जाय तो राजस्थान यूनिवर्सिटी का कार्य बहुत हल्का हो जायगा। इसके साथ-साथ मैं चाहूंगा कि डूंगर कालेज में सोशियोलाजी और ज्योग्राफी की फैकल्टीज भी खोली जाय जिसकी वहां पर नितान्त आवश्यकता है और जिसके लिये कई बार निवेदन भी किया जा चुका है। बीकानेर में हमारे एक एम. एम. स्कूल है उस स्कूल में कामर्स की कक्षाएं खोले जाने के लिये भी कोशिश की जा रही है, इसलिए वहां पर वह मेहरबानी करके कर दी जावे। सभापति महोदय, मैं एक बात विशेष तौर से निवेदन करना चाहूंगा, जैसा कि अभी रिपोर्ट में बताया गया है माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षा के बारे में क्या वर्क हो रहा है इसका इसमें कहीं भी लेखा जोखा नहीं है। ऐसा लगता है आपके आंकड़ों से कि 44780 लड़के राजकीय महाविद्यालयों में पढ़ते हैं और 22921 छात्र स्वयंसेवी संस्थाओं में पढ़ते हैं। इन संस्थाओं में सरकार का खर्चा भी कम होता है, इनके नियम भी बने हुए होते हैं और रिजल्ट भी इन संस्थाओं के बेहतर रहते हैं, क्वालिटेटिव और क्वान्टिटेटिव दोनों ही रूप में, तो समझ में नहीं आता कि क्यों नहीं इन संस्थाओं को प्रोत्साहन दिया जाता है। यह जरूर है कि इन पर नियन्त्रण पेमेन्ट करने के तरीकों पर रखा जाय।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

सभापति महोदय, एक दो बात और कहकर अभी समाप्त करता हूं। खास तौर से बीकानेर...

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : बीकानेर में तो रसगुल्लों के अलावा और कोई बात है ही नहीं।

श्री गोपाल जोशी : सभापति महोदय, अब मैं थोड़ा बीकानेर में स्पोर्ट कौन्सिल खोलने के बारे में निवेदन करना चाहूंगा।

एक माननीय सदस्य : अजी आप तो रसगुल्लों की बात करो।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अजी आपकी बातों में ही मिठास है।

श्री गोपाल जोशी : आपकी बहुत मेहरबानी है। तो सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि बीकानेर में स्पोर्ट कौन्सिल खोली जाये। सभापति महोदय इसके लिये मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि बीकानेर की स्पोर्ट के बारे में शुरू से ही परम्परा अच्छी रही है और आज भी वहां पर स्पोर्ट्स बहुत ही अच्छी तरह पनप रहे हैं। मैं इसका उदाहरण दूं कि हमारे बीकानेर की आर.ए.सी. का खिलाड़ी मगनसिंह हमारी इन्डिया की फुटबाल की टीम के कैप्टेन हैं और आपको निवेदन करना चाहूंगा कि उन्हें भारत सरकार ने अर्जुन पुरस्कार दिया है। इसी तरह हमारे बीकानेर के महाराजा जो थे श्री करणी सिंह जी ने राईफल सूटिंग के अन्दर अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में काफी अच्छी ख्याति प्राप्त की है उन्हें भी भारत सरकार ने अर्जुन पुरस्कार दिया है। इसके अलावा साईक्लिग के बारे में भी यह निवेदन कर दूं कि हमारे यहां पर जो लड़के हैं उन्होंने अच्छा नाम किया है तथा इसके साथ में यह भी अर्ज करना चाहूंगा कि हमारे बीकानेर वालों ने पांच बार साईक्लिग में नेशनल चैम्पीयनशिप जीती है। इसके अलावा हमारे यहां पर जो 42 स्वर्ण पदक बांटे गये थे उनमें से 34 स्वर्णपदक हमारे बीकानेर के स्पोर्ट्स मैनों को मिले हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि अगर आप हमारे यहां के स्पोर्ट्समैन को प्रोत्साहन दें तो मैं समझता हूं कि हमारे यहां के स्पोर्ट्समेन न केवल राज्य स्तर और भारतीय स्तर पर बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने प्रान्त का नाम उज्जल कर सकते हैं। आप को इन्हें प्रोत्साहन देने से अच्छे से अच्छे नतीजे मिल सकते हैं।

(5.32 सायं)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय को यह निवेदन करना चाहूंगा कि बीकानेर में स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स को देखते हुए वहां पर स्पोर्ट्स कौन्सिल खोलने का प्रावधान करें ऐसी मेरी मांग है। इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय को यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आपने पिछले साल हमारे बीकानेर से गर्ल्स फिजीकल ट्रेनिंग सैन्टर को बीकानेर से हटा कर जोधपुर स्थानान्तरित कर दिया है उससे हमारे यहां के लोगों के मन में थोड़ी ठेस पहुंचायी है। यह तो ठीक है कि आपने वहां एक छोटी चीज को लेजा कर बड़ी चीज खोल दी है। एक ज्यादा खर्च की योजना को वहां रखा है और छोटे खर्च की योजना जो गर्ल्स फिजीकल इन्स्टीट्यूट की थी उसे ही हटाया है। यह आप कह सकते हैं लेकिन मेरा निवेदन है कि यह आपकी जो वर्षों से चली आ रही थी अगर वहां पर रहती तो कोई दिक्कत की बात तो थी नहीं। इसलिये

(श्री गोपाल जोशी)

मेरा निवेदन है कि उसको वापिस बीकानेर लावें तो ठीक रहेगा। इसके साथ साथ मैं यह भी मांग करूंगा कि आप बीकानेर में स्पोर्ट्स कौन्सिल का दफ्तर खोलें उपाध्यक्ष महोदय, हमारे बीकानेर का जो स्टेडियम है वह स्पोर्ट्स के लिए काफी डीसेंट है। लोगों में स्पोर्ट्स की काफी तमन्ना है अगर आप वहां के लोगों को प्रोत्साहन दें तो इसके नतीजे काफी अच्छे राज्य स्तर पर ही नहीं बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छे परिणाम निकल सकते हैं।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, अब थोड़ा मैं जेल विभाग के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा। इसके लिए मेरा निवेदन यह है कि बीकानेर की जेल बहुत अच्छी है और अभी तो आपने बीकानेर की जेल को 'ए' श्रेणी में रखा है लेकिन मेरा निवेदन यह है कि बीकानेर जेल को आप · · ·

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : आपको पसन्द है क्या आपने देखी है।

श्री गोपाल जोशी : मैंने देखी है। वह बहुत अच्छी जेल है उसको सेन्ट्रल जेल बना दिया जाय। अगर आप उसे सेन्ट्रल जेल बना दें तो वह एक अच्छी जेल साबित हो सकती है। वहां की जेल में उपाध्यक्ष महोदय कारपेट्स बहुत अच्छी बनती हैं अगर आप वहां पर टैक्निकल ट्रेन्ड, लोगों को ट्रेनिंग देने के लिये रख दें तो वहां यह उद्योग बहुत ही अच्छी तरह पनप सकता है इससे लोगों को फायदा होगा।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

बस मुझे इतना ही निवेदन करना है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जगमोहनसिंह।

श्री जगमोहनसिंह (छबड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले कई वर्षों में हमारे प्रान्त में ही नहीं बल्कि हमारे राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा प्रणाली को बदलने के लिए और उसमें आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए मांग बड़ी जोरों से चल रही है। आज जो भी अनएम्पलॉयमेंट है और स्टूडेन्ट अनरेस्ट है उसका कारण लोग मौजूदा शिक्षा प्रणाली को ही बताते हैं। मान्यवर, लेकिन मेरा मत है कि सारा का सारा कारण आज जो शिक्षा प्रणाली चल रही है उसी की वजह से यह हो रहा है वह बात नहीं है आज हमारे समाज के अन्दर जो वातावरण है वह अकेला उसका कारण नहीं है। मान्यवर आजादी के बाद जहां हमारे देश में पहले 70 से लेकर 75 प्रतिशत बिना पढ़े लिखे थे वहां आज हमारे देश में एजूकेशन का एक्सपान्शन तो हुआ ही है। हमारी एजूकेशन की जो एक्सपान्शन की पॉलिसी थी वह बहुत अच्छी थी जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता श्री गोपाल जोशी ने कहा था कि डेमोक्रेसी में democracy without education is hypocrasy,

तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज जो एजूकेशन का एक्सटेन्शन किया वह बहुत अच्छा काम किया। इसके साथ आपने मान्यवर हमारे यहां टैक्निकल शिक्षा भी बढ़ायी। काफी टेक्निकल कालेजेज आपने देश में बढ़ाये। जहां पर सन् 52–33 में हमारे राजस्थान में सिर्फ एक मेडीकल कालेज जयपुर में था और एक जोधपुर में इन्जीनियरिंग कालेज था वहां पर आज कई मेडिकल कालेज और इन्जी-

Page No 139

139

(श्री जगमोहन सिंह)

निर्यारिंग कालेज खुले है। मान्यवर स्थिति यह है कि आज एक तरफ तो सैंकड़ों की तादाद में डाक्टर्स और इन्जीनियर्स जो कि जॉब ओरियेन्टेड है बेकार घूम रहे हैं उन्हें कोई जॉब नहीं हैं वहां आज गांवों में मान्यवर अस्पतालों में डाक्टर्स नहीं हैं स्कूलों में टीचर्स नहीं हैं जगहें खाली पड़ी हैं। इसका कारण यह है कि लोग आज गांवों में जाना नहीं चाहते हैं। इसलिये आपने लोगों को जॉब ओरियेन्टेड तो कर लिया लेकिन क्या आपने जॉब की समस्या का हल कर दिया। मैं कहता हूं कि सिर्फ जॉब ओरियेन्टेड करने से ही यह समस्या हल नहीं हो सकेगी ऐसा मेरा मत है। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें हमें आमूल-चूल परिवर्तन करना होगा। मान्यवर, स्थिति यह है कि सारी की सारी शिक्षा प्रणाली का जो विकास हुआ है वह शहरों में हुआ है। आज शहरीकरण हुआ है। आज सारे के सारे बड़े मेडिकल कालेजेज, इन्जीनियरिंग कालेजेज, पोलीटेक्निक वगैरहा जो हैं वह सभी सुविधायें आपने शहरों में रखी हैं। आज बड़े बड़े विश्वविद्यायल शहरों में हैं, कालेजेज शहरों में हैं। इसलिये गांवों के लोग पढने के लिये शहरों में आते हैं और यहां पर वर्षों तक शहरों में रहते हैं विद्या अध्ययन करते हैं तो वह लोग जो ओरियेण्टेड होने के बाद भी शहरों से जाकर गांवों में बसना वह लोग नहीं चाहते वह गावों में जाना पसन्द ही नहीं करते।

दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं मान्यवर वह यह है कि आज जॉब ओरियेन्टेड कोई भी युवक हो वह नौकरी करना चाहेगा। लेकिन वह नौकरी भी शहरों में ही रह कर करना चाहेगा। आज नौकरी का जो आकर्षण है वह आकर्षण का कारण है आपकी ब्यूरोक्रेसी आज मान्यवर, जब लोग ब्यूरोक्रेसी के लोगों के ठाठबाट देखते हैं तो वह लोग भी उनकी ओर आकर्षित होते हैं। आज हमारा जो युवा वर्ग है, वह भी नौकरी इसीलिये करना चाहता है, वह चाहता है कि वह भी ऐसी नौकरी करे कि जिससे कि उनके भी वैसे ठाठबाठ हो। तो ब्यूरोक्रेसी का भी बहुत बड़ा भारी इम्पेक्ट हमारे युवा वर्ग पर पड़ा है।

इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर युवा वर्ग पर पाश्चात्य सभ्यता का भी काफी असर पड़ा है। आज हमारी भारतीय संस्कृति का जितना ह्रास इस पाश्चात्य सभ्यता की वजह से हुआ है उतना दूसरी बातों से नहीं हुआ। आज हमारे यहां स्टूडेन्ट का थिंकिंग बदल गया है वह पाश्चात्य हो गया है वह लोग सारी की सारी सुविधायें वहीं प्राप्त करना चाहते हैं जो पाश्चात्य देशों में है लेकिन आज हमारे यहां की स्थिति ऐसी नहीं हम उनको वह सुविधायें नहीं दे सकते हैं जो कि विदेशों में मिलती हैं। इसका भी काफी बड़ा इम्पेक्ट हमारे यहां पर पड़ा है। Then there is political participation by political parties in the institutions तो इस तरह एक ही फेक्टर नहीं होकर कई फेक्टर हैं जिससे कि आज यह स्थिति पैदा हमारे देश में हुई है। इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आपको शहरों के बजाय जो ओरियेन्टेड ट्रेनिंग सेन्टर गांवों में खोलने चाहिये। आपको चाहिये कि आप गांवों में, उद्योग-धन्धे खोलें। लोकल उद्योग आज हमारे

Page No 140

(१४०)

(श्री जगमोहनसिंह)

यहां नहीं हैं उनको खोलना चाहिये। ताकि ऐसा वातावरण बने कि लोग गांवों में जाना पसन्द करें। आज हमें पुरानी मान्यताओं को बदलने की आवश्यकता है। अगर आप पुरानी मान्यताओं को तोड़ेंगे तो ही जाकर शिक्षा की दिशा में ठीक तरह से विकास हो सकता है।

दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहूंगा वह यह है कि उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे देश में 80 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं। लेकिन गांवों में स्कूल या कालेज खोलने की बात जब राज्य सरकार के पास की जाती है तो राज्य सरकार पहले यह कहती है कि आधा आप ग्रामीण क्षेत्र के लोग पैसा लगावें। आप श्रमदान करें। लेकिन जहां पर शहरों में आप लाखों रुपये लगाकर स्कूलों के भवन, कालेजों के भवन बनाते हैं और स्कूलें या कालेज खोलते हैं तो क्या आप शहरी लोगों से श्रम दान की बात करते हैं? क्या आप उन्हें कहते हैं कि मकान बनाकर दो या कमरे बना कर दो। यह राज्य सरकार का कितना बड़ा डिसक्रिमिनेशन है आपका शहर के लोगों में और ग्रामीण क्षेत्र की जनता के बीच में आप कितना डिफरेन्स रखते हैं। एक व्यक्ति जब गांव से शहर में आता है और यहां पर जब बड़े-बड़े आलीशान स्कूलों और कालेजों के भवन देखते हैं तो उन्हें महसूस होता है कि शहरों में तो कालेजों के भवन राज्य सरकार के अनुदान से बनते है और गांवों में अगर स्कूल और कालेज खोलना हो तो गांव वालों को श्रम दान करना पड़ता है चन्दा देना पड़ता है।

एक बड़ा डिसक्रिमिनेटरी है। फण्ड्स आप अलॉट करते हैं फोर सिटी एजुकेशनल इन्स्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स और रूरल इन्स्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स इनमें आप कोई फर्क मत कीजिये जैसा कि आप करते हैं आज। कन्स्ट्रक्शन की दृष्टि से और सब दृष्टि से। आपने जो गांवों के लिये श्रम दान की बात रखी है उसको भी आप समाप्त कर दीजियेगा।

मैंने कुछ क्वेश्चन्स भी दिये थे, शिक्षा क्षेत्र के बारे में। मैं पुनः अर्ज करना चाहूँगा। छबड़ा में पूरी तहसील में एक हायर सैकण्डरी स्कूल है। माननीय मंत्रीजी मानते हैं और उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि हम इस कमी को दूर करने की कोशिश करेंगे। इन्टरमिडियेट का हायर सैकेन्डरी वाला करें, जो कुछ भी आप करना चाहते हैं, इन्टरमिडियेट को वापिस रिवाइव करना चाहते हैं और जैसा भी आप करना चाहते हैं, करके, मेरे क्षेत्र में सैकेन्डरी स्कूल हैं उनको रेज किया जाय और दूसरी इन्स्टीट्यूशन्स और खोली जायं।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

दूसरा मेरा निवेदन है कि एक लाख की आबादी पर भी कन्याओं की उच्च शिक्षा का प्रबंध नहीं है। नये स्कूल आप क्रमोन्नत कर रहे हैं तो कृपा करके कन्या माध्यमिक विद्यालय को भी क्रमोन्नत कीजिये जिससे बच्चियों को थोड़ी उच्च शिक्षा प्राप्त हो सके।

छबड़ा में कृषि कालेज खोलने के लिये बात चल रही है। सब तरह के साधन वहां पर उपलब्ध हैं। मंत्री महोदय से इसके

(श्री जगमोहन सिंह)

लिये निवेदन करूंगा कि वे इसको ही पूरा करेंगे।

दो मिनिट में जेल के सम्बन्ध में भी निवेदन करना चाहता था। आजादी के बाद डेटेरेन्ट पनिशमेन्ट को बदल कर साधारण पनिशमेन्ट कर दिया गया सुधार की दृष्टि से और भी कई सुधार किये गये हैं। मान्यवर, बहुत अच्छी बात है, इस तरह के विचार अच्छे हैं। लेकिन जो कन्डीशन्स हैं देश की उन पर हम को गौर करना चाहिये। टाइप ऑफ क्रिमिनल जैसा है उसको उसी प्रकार से डील करना चाहिये। एक हीडियस क्राइम करके जाता है उसको भी वह ही सुविधा प्रदान करेंगे जो कि सिम्पल क्राइम करके जाता है रिफोर्मेटरी वाली बात की दृष्टि से और इस तरह से क्रिमिनल एक ही प्रकार के बन जावेंगे। दोनों बराबर के क्रिमिनल बराबर की सुविधा का उपभोग करेंगे। मान लीजिये कि कोई व्यक्ति किसी कारणवश मर्डर कर लेता है, कुछ लोग हैबिचुअल ऑफेन्डर्स हैं समाज के अन्दर जिनको डेटेरेन्ट पनिशमेंट की बात हो सकती है, उनके द्वारा आये दिन हत्यायें और डकैतियों का वातावरण पैदा किया जाता है, ऐसे लोगों को भी यदि जेलों में अधिक से अधिक सुविधायें दी जावेंगी तो उससे समाज पर एडवर्स इफेक्ट पड़ने वाला है। ऐसे लोगों को तो सख्ती से डील किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष: श्री फूलचन्द जैन।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री जी यहां हैं नहीं, अभी मैं कोई भाषण देना नहीं चाहता किन्तु कुछ बेसिक मुद्दे यहां सदन में उठाये गये हैं और कुछ मेरे विचार से आवश्यक समझता हूं, मैं चाहता हूं, माननीय शिक्षा मंत्री जी जब जवाब दें तो स्पेसिफिकली कुछ बातों के बारे में सारी स्थिति को स्पष्ट करेंगे।

एक तो यह पूछना चाहता हूं माननीय शिक्षा मंत्रीजी से कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली के बारे में सदन में चर्चा की गयी और आम तौर पर चर्चा होती है, आप कृपया बतायेंगे कि इसमें परिवर्तन की आवश्यकता महसूस करते हैं? हम महसूस करें या न करें आप क्या महसूस करते हैं? यदि आप यह महसूस करते हैं तो उसके लिए किस प्रकार से कदम उठाने का दृष्टिकोण रखते हैं और इस सम्बन्ध में यह भी जानना चाहता हूं कि इसके लिये समय समय पर कमेटियों का गठन किया गया, कमीशन वगैरा बनाये गये, उनसे अब तक जो भी सुझाव प्राप्त हुए हैं, उन पर आपने अब तक क्या क्या कदम उठाये हैं, और इसके साथ साथ आपने एक शिक्षा शास्त्रियों की कमेटी का गठन किया उसके टर्म्स ऑफ रेफरेन्स क्या हैं? यह मैं चाहता हूं कि आप हमारे सामने स्पष्ट करें।

इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मुझे पता नहीं किन शिक्षा शास्त्रियों की और किन बेसिक सवालों के ऊपर रिपोर्ट आने के लिये उस कमेटी का गठन किया गया, परन्तु मैं आपसे यह जरूर जानना चाहता हूं कि क्या यह आप आवश्यक नहीं समझते हैं कि शिक्षा शास्त्रियों के द्वारा जो अब तक शिक्षा में परिवर्तन के बाबत, जो भी सुझाव आये हैं, या समय समय पर जो भी उनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है उसके पश्चात्

Page No 142

(142)

(श्री फूलचन्द जैन)

आजादी के बाद में आज 26-27 वर्ष के बाद में भी हम यह चर्चा कर रहे हैं कि हमारी शिक्षा प्रणाली में क्या परिवर्तन हो और इसको कैसे ठीक बनाया जाय इस दृष्टि से आप यह आवश्यक नहीं समझते हैं कि शिक्षा शास्त्रियों के साथ साथ में जो सुधारवादी हैं अच्छी विचारधारा के, अच्छे बौद्धिक लोग हैं, जो एक रियलिस्टिक एप्रोच रखते हों, जिनका सम्बन्ध हमारी ग्रामीण जनता से हो, जिनका एप्रोच हमारे साधारण लोगों से हो, उनकी आवश्यकताओं और आकांक्षाओं से हो, देश की पुरानी संस्कृति को ध्यान में रखते हुए, थोड़ी देर के लिये आप भूल जाइये कि आप शिक्षा मंत्री हैं, आप स्वयं भी क्या महसूस करते हैं, ऐसे व्यक्ति आ सकते हैं जो अपने रियलिस्टिक सजेशन्स दे सकें, उनको इसमें लाना उपयुक्त समझते हैं ?

मेरी ऐसी मान्यता है कि शिक्षाशास्त्रियों का एक निश्चित एप्रोच बना हुआ है और घूम फिर कर यदि आप उन्हीं से सुझाव लेंगे तो आपको कोई नवीनता उसमें नहीं प्राप्त हो सकेगी, जिसकी कल्पना करके सोसाइटी में शिक्षा के माध्यम से परिवर्तन लाना चाहते हैं।

मेरा इसके पीछे यह भी मानना है कि जहां शिक्षा ज्ञान के लिये बहुत आवश्यक है वहां पर कन्ट्री के सोशियल, इकोनोमिक और पोलिटिकल रिफोर्म्स के लिये भी, मैं यह मानता हूं कि उसका बहुत बड़ा महत्व है। आखिर हम कन्ट्री को कैसे बनाना चाहते हैं। केवल ज्ञान ही देना चाहते हैं ? या कन्ट्री का फ्यूचर फ्रोम आल पोइन्ट आफ व्यू से कैसा बनाना चाहते हैं उसी पर हमारी शिक्षा आधारित होनी चाहिये और शुरू से ही किस तरह से बच्चे को, बालक को ट्रेन्ड करते हुए जायें ? इस आधार पर सोच सकें तो, मैं समझता हूं, सही दृष्टि से एक एप्रोच होगा शिक्षा के बारे में।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जो कुछ भी आप सोचते हों, आपको पहले यह तय करना होगा कि आप शिक्षा में परिवर्तन के मोटे तौर पर क्या आधार तय करते हैं उसके ऊपर फिर तय होगा कि शिक्षा मंत्री जी को इस आधार पर तय करने के लिये किन व्यक्तियों के जिम्मे डिटेल्स सौंपनी चाहिये।

मेरा यह भी मानना है, उपाध्यक्ष जी, यहां पर यह बात कही गयी है, मैं इसको रिपीट नहीं करना चाहता। पर मैं यह जरूर मानता हूं कि और कन्सीडरेशन्स के अलावा हमारी सोसायटी की वैल्यूज कायम रहे और आज का हमारा जो नौ जवान है वह शिक्षा प्राप्त करके रोजगार में तुरन्त लगाया जा सके इसको सबसे अधिक प्राथमिकता देकर सोचना होगा। इस दृष्टि से मैं एक बात और कहना चाहता हूं और आज ऐसी बात नहीं है कि हमारे पुराने ट्रेडीशन्स क्या हैं उनको आधार बनाकर चलें। आज साइन्स और टेक्नोलोजी के बढ़ते हुये युग में मैं यह भी कह सकता हूं एम्पलायमेंट ओरियन्टेड करके कोई यूथ जिन्होंने इस प्रकार की शिक्षा पद्धति को अपनाया उसको आप ठीक प्रकार समझ करके और उसमें पूरी हिम्मत करके कोई ड्रास्टिक चैन्ज लाना चाहते हैं तब तो ठीक है जिसे आप भी महसूस करते हैं, मैं भी महसूस करता हूं और सब प्रकार के लोग महसूस करते हैं, वह परिवर्तन लाया,

(श्री फूलचन्द जैन)

जा सकता है और न पूरा परिवर्तन किया, न किसी काम का परिवर्तन किया और जैसा अभी है वैसा का वैसा रखा तो मेरा मानना है उससे परिवर्तन सम्भव नहीं होगा।

दूसरे क्या आप यह आवश्यक नहीं समझते हैं अध्यापकों का जो स्तर है वह नहीं ऊंचा उठायेंगे तो जिन अध्यापकों से शिक्षा दिलाना चाहते हैं वे क्या आपको उस ढंग की शिक्षा दे सकते हैं? उसके बाद में मैं यह कहना चाहता हूं सबसे पहले क्या यह आप आवश्यक नहीं समझते है जो अब तक प्राइमरी, सेकेण्डरी और अपर सेकेण्डरी को डवलप किया है उनको एक प्रकार ठीक ढंग से कन्सोलिडेटेड करके जो कमियां हैं, जो खामियां हैं उनको ठीक करके शिक्षा प्रसार करते चले जायें। अगर शिक्षा को ठीक ढंग से नहीं बनाया जाय तो क्या आप समझते हैं यह ठीक है और इसके साथ साथ आज की वर्तमान परिस्थितियों में अपर एज्यूकेशन से अन एम्पलायमेंट की प्राबलम आई है परन्तु उसके साथ साथ फालो–अप प्रोग्राम बनाये और जो प्राईमरी एज्यूकेशन दे रहे हैं वहीं से सुधार का लेवल नहीं बनाया तो अपर लेवल पर जाकर सुधार कर सके यह मुश्किल होगा।

मैं यह कहना चाहता हूं प्राईमरी और मिडिल स्कूलों तक फिर भी लड़कों में इतना इनडिसिप्लिन नहीं होता है, इतनी बुराई नहीं होती है जितनी अपर लेवल पर जाकर बुराई डवलप होती है। उनका थारोली इन्वेस्टीगेशन करके एक दफा मुकम्मिल इलाज करना होगा और यह नहीं करेंगे तो एक दूसरे का रिफ्लेक्शन पड़े बिना नहीं रहेगा।

इसके साथ यूथ और स्टूडेन्ट्स के बारे में वैसे समय नहीं है, बीच में लिया है परन्तु मैं इतना कहना चाहता हूं चाहे आप यह कहें इनडिसिप्लिन आ गया है, किसको दोष दें और किसको दोष नहीं दें परं मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं उनके वेलफेयर के लिये, उनके शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास के लिये जो हेबिट्स डवलप हो रही हैं उसका मनोवैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करके वेलफेयर एक्टीविटीज कर के कन्सोलिडेटेड क्या राइट ढंग से उनको चेनेलाईज किया है, क्योंकि यूथ बोर्ड के बारे में आप भी घोषणा करते हैं, मुख्य मंत्रीजी भी घोषणा करते हैं, आप भी अभी यह कर देंगे क्योंकि यूथ बोर्ड बनाना मेटेरियल है? यूथ बोर्ड बनाने की आवश्यकता क्या आप महसूस करते हैं तो क्या यूथ बोर्ड के गठन में पूरी तरह से इतना सक्षम बनाने के लिये तैयार हैं, क्या आप आज के यूथ और स्टूडेन्ट्स के प्राबलम को फाम आल पाइन्ट आॅफ व्यू से दिशा दे सके और संचालित कर सकें।

ये बातें मैं आपको मोटे तौर से कहना चाहता हूं और इसके साथ अन्त में एक बात यह निवेदन करना चाहता हूं एज्यूकेशन का महत्व हमारी डेमोक्रेसी में बहुत ज्यादा है और मैं सोचता हूं सोसियल और इकोनोमिक रिवोल्यूशन की बात करता है उसमें आज हमारे एज्यूकेशन के माध्यम में क्या आप यह आवश्यक नहीं समझते हैं, हमारी जो डेमोक्रेसी है और सोसलिजम का बेसिक कन्सेप्सन है, जो वेल्यूज है उसका समावेश इसमें हो न कि और कोई अन्य चीजों का समावेश हो। चाहे जैसी पाठ्यक्रम बना दिया और दे दिया आखिर पुस्तकों के माध्यम से क्या परपज सर्व करना चाहते हैं।

Page No 144

(१४४)

(श्री फूलचन्द जैन)
इसके पीछे विलियर कन्सेप्शान नहीं होगा तो फिर भी मैं समझता हूँ चाहे कितना ही परिवर्तन कर दें, आपका परिवर्तन अधूरा रहेगा। इन सब चीजों के बारे में हम चाहते हैं और जिन माननीय सदस्यों ने अपनी अपनी प्राबलम्स रखी हैं उसके साथ आज आप कृपा करके इस एज्यूकेशन के बारे में जो फील करते हैं और अन्त में आप उसको करने के लिये समक्ष हैं या नहीं। अभी भूतपूर्व शिक्षा मंत्री बोल गये और वे भी बोल गये यह होना चाहिये और वह होना चाहिये तो जैसा वे अपने कार्यकाल में क्या कर गये तो मेरा मतलब है आपको इन्टरनल क्या प्राबलम्स है, आपकी केपेसिटी क्या है, आपका जूरिसडिक्सन कितना है उसके साथ साथ आपकी ताकत कितनी है ताकि यह हाऊस जो आपकी फीलिंग है उससे अवगत हो सके। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय मुझे भी आपको टाइम देना होगा।

श्री उपाध्यक्ष : मुझे निवेदन यह करना है जो चेनल है उनमें कई दिक्कतें हैं। इसलिये टाइम नहीं मिल सकता है।

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, बद्रीप्रसाद जी तो अब 60 साल के हो गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : यह मुझे पता नहीं था जन्म-पत्री तो आपके पास है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि मुझे बोले बहुत दिन हो गये शायद वर्षों हो गये··

श्री उपाध्यक्ष : मैने तो कल भी आपका नाम पुकारा था।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता :····मैं शिक्षा के बारे में आज जो विचार चल रहा है उसमें मेरा निवेदन है···

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : बद्रीप्रसादजी कल आप कहां गायब थे आपका कल····(अश्रव्य) था। आप कहां तशरीफ ले गये थे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आप तशरीफ रखिये। तो सबसे पहले उपाध्यक्ष महोदय मैं यह कहूंगा शिक्षा में आमूल-चूल परिवर्तन की जो बात कही जा रही है, मैं समझता हूं उससे कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। अभी माननीय जैन साहब ने जो प्रश्न किया यह मैं जबसे विधान सभा खुली है 52 से तब से लगातार जो विचार आज व्यक्त किये गये हैं उनको सुनता आ रहा हूं और अभी शिक्षा मंत्रीजी का जो जवाब है, वह मैं बता देता हूं कि उन्होंने एक कमेटी बना दी है। आज प्रथम प्रधान मंत्री पं. नेहरू से लेकर गांव के स्कूल का मास्टर सब यही कहते हैं शिक्षा में परिवर्तन होना चाहिये लेकिन कैसे किया जाय, किस प्रकार का किया जाय कहां किया जाय यह कोई नहीं कहता लेकिन उसका एक मात्र उपाय यह है कि महज शिक्षा में परिवर्तन से काम चलने वाला नहीं है। हमारे समाज में परिवर्तन होगा तब काम चलेगा वरना मैं सदन के सामने यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि समाज में कैसे परिवर्तन किया जाय ताकि

(श्री बद्री प्रसाद गुप्ता)

एक नए समाज का निर्माण कर सके लेकिन अभी उस बात के लिये समय नहीं है लेकिन मैं यह जरूर निवेदन करना चाहता हूं बिना शिक्षा में परिवर्तन किये देश के लिये जो लक्ष्य मुकर्रर कर रखे हैं कि लोकतन्त्री समाजवाद हो तो लोकतन्त्र की जगह हम समाजवाद लायें और समाज में छोटे मोटे का भेद मिटा दें। जो हम धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाना चाहते हैं, यह लक्ष्य और इसकी पूर्ति में जब तक हम समाज में मूलभूत परिवर्तन नहीं होगा, नहीं हो सकेगा। एक बात मैं यह भी कहना चाहता हूं इसके लिये हम यह उम्मीद करें कि आपके जो शिक्षा शास्त्री हैं वे इसमें परिवर्तन कर सकें, यह बात नहीं हो सकती है। कोई महात्मा गांधी जैसा व्यक्ति या ऐसे लोग जो समाज की नब्ज पहचान गये हैं इसलिए मैं अधिक न कहकर एक नयी बात कहना चाहता हूं जिसका जिक्र अभी तक नहीं हुआ और जिसके ऊपर मैंने कट-मोटशन दिया है कि हमारे यहां पर यौगिक क्रियाओं का अभ्यास और उनका अध्ययन होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं नम्रता से निवेदन करूंगा कि मैं अपने अनुभव और इस विषय में अध्ययन की वजह से कहूंगा कि हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए यह यौगिक क्रिया का अध्ययन आवश्यक है। मेरी इस बात को चाहे सदन के माननीय सदस्य दकियानूसी मानें और जब कि आज वैज्ञानिक युग में बहुत सी नयी नयी चीजें हमारे सामने आ रही हैं और ऐसे समय में यदि मैं योग की बात कहूं तो बड़ी अटपटी सी मालूम होगी लेकिन मैं यह इसलिए कहना चाहता हूं कि हमारे यहां पर एक यौगिक रिसर्च सेन्टर खुला हुआ है भारत सरकार की ओर से हमारी राजस्थान यूनीवर्सिटी के सामने और जब मैं यहां चिकित्सा मंत्री था तो मैंने वह सेन्टर काफी प्रयत्नों के बाद कायम कराया था और इसके लिए भारत सरकार से 40 हजार रुपये साल के भी प्राप्त होते हैं। इस संबंध में मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां भारत में योग के बारे में कोई खास एक्टीविटीज नहीं हैं लेकिन यूरोपियन कन्ट्रीज में जो हमारे यहां के स्वामी हैं उनकी बड़ी भारी प्रतिष्ठा है और उन्हें कई बार बुलाया जाता है और वहां के लोग इसका बड़ा फायदा उठाते हैं। यहां भी जब कभी इस विषय पर मैं और लोगों से मिलता हूं तो वह कहते हैं कि आपने अपने कार्यकाल में यह काम बहुत अच्छा किया है। इसमें बहुत ज्यादा खर्च करने की बात भी नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि हमारे स्कूलों में यह यौगिक-शिक्षा कम्पलसरी कर देनी चाहिए। इसके लिए हमारे शिक्षा मंत्रीजी यह कहेंगे कि हमारे सामने फाइनेन्सेज की दिक्कत है। मैं ऐसा मानता हूं कि इसमें बहुत ज्यादा खर्चा नहीं होगा क्योंकि हमारे यहां पर फिजिकल इन्सट्रक्टर्स ऑलरेडी मौजूद हैं। उनको आप दो महीने का रीओरियन्टेशन कोर्स दिला दें और अब वैसे भी गर्मियों की छुट्टियां होने जा रही हैं। इसलिए इस पीरियड में उनको ट्रेनिंग दिलाने के बाद वह योग की शिक्षा प्राप्त करने में ज्यादा समय नहीं लेंगे। इस विषय पर हमारे यहां कई पुस्तकें भी हैं और फिर यह प्रेक्टिकल भी है, बहुत खर्चा भी नहीं जो होगा। उससे मैं समझता हूं कि हमारे समाज को और हमारे विद्यार्थियों जो ट्रेनिंग पायेंगे सबको बहुत बड़ा फायदा होगा।

(श्री बद्री प्रसाद गुप्ता)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, योग के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा और सिर्फ एक मिसाल दूंगा कि हमारे यहां पर एक कलकत्ता हाईकोर्ट के जज थे। वह अंग्रेज थे। वह यहां पर आये तो उन्होंने योग की शिक्षा ली। उन्होंने संस्कृत भाषा पढ़ी और योगों का अभ्यास किया उन्होंने यहां पर गुरु बनाया और कुण्डल योग नाम की पुस्तक भी लिखी और यह पुस्तक हमारी असेम्बली की लाइब्रेरी में है। जब मैं इस पुस्तक को पढ़ता हूं तो समझ में नहीं आता कि क्या लिखा है। इसके अलावा मैं समझता हूं कि और भी अमेरिकन्स हैं और दूसरी कन्ट्रीज के लोग हैं जिन्होंने हिन्दुस्तान में आकर योग की प्रेक्टिस की है और एक बात निवेदन करूं कि जितने भी एशियन कन्ट्रीज हैं जो कि विकास की पराकाष्ठा पर पहुंच चुके हैं और उनके पास धन की कोई कमी नहीं है उनमें आप देखेंगे कि तीन मुख्य बीमारियां चल रही हैं। या तो उनको टी. डी. होगी या फिर हार्ट डिजीज होगी या फिर उनको मेन्टल पीस नहीं होगी। इन सब चीजों का इलाज कहीं पर है तो सिर्फ यौगिक क्रिया में है, यौगिक एक्सरसाइज से है और उसको मैं साइन्टिफिक एक्सरसाइज कहता हूं। इस पर बहुत सी पुस्तकें भी हैं और हिन्दुस्तान में मिसाल के लिए कहूं कि यूरोप और दूसरी जगह यह यौगिक क्रियायें अब ज्यादा हैं। हिन्दुस्तान के लिए यह बहुत पुरानी चीज है और इसके बारे में ज्यादा भाषण देने की आवश्यकता नहीं है। समाधि तक की बात योग में आती है जिसका बहुत बड़ा महत्व था।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां एक अंग्रेज आये थे और उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी 'हरमन इन हिमालयाज'। इस पुस्तक में उन्होंने हवाला दिया है कि एक महात्मा सर्दी के दिनों में हिमालय पर्वत पर जहां साल भर ही बरफ पड़ती है और कैलाश पर्वत में आप सोचिये कितनी सर्दी होती है वहां पर वह महात्मा एक महीने तक तपस्या में रहे। उस स्थान पर जहां साल में 10 महीने बरफ पड़ती है और जहां एक मिनट इन्सान खड़ा नहीं हो सकता लेकिन वहां एक महीने तक संन्यासी तपस्या करते रहे। मैंने पता लगाया कि क्या बात है और इस महीने में जब कि परिन्दा भी पर नहीं मार सकता वहां पर इन्सान जिन्दा रहे तो यह कैसे हुआ। तो मालूम हुआ कि यह कोई जादू की बात नहीं है, यह योग की बात है। हिन्दुस्तान के योगी अपनी क्रियाओं के जरिये अपने शरीर में अग्नि प्रज्वलित कर लेते हैं और फिर मेल्टिग स्नो के ऊपर बैठकर योगिक अभ्यास करते हैं। यह उस पुस्तक में है जो कि हमारी असेम्बली लाइब्रेरी में है। अब इस बात का दुनियां सम्मान करने लगी है और दुनियां इस रास्ते पर आ रही है। इसलिए हमारे यहां पर और खास तौर से हमारे जो टेबल पर काम करने वाले हैं, कुर्सियों पर बैठने वाले हैं उनसे मैं नम्रता से निवेदन करूंगा कि जिनको गैस ट्रबल हो, हार्ट ट्रबल हो–मैं मेडिकल डिपार्टमेंट का मिनिस्टर रहा हूं कई सालों तक और मैंने जो छानबीन की है उससे मालूम हुआ है कि अगर इन बीमारियों को दूर भगाना चाहते हैं तो आपको योगिक अभ्यास करने चाहिए।

(श्री बद्री प्रसाद गुप्ता)

यहां इस आश्रम के जो गुरु हैं उनके गुरु दिल्ली में हैं और वह पंडित जवाहरलाल नेहरू को यौगिक क्रियायें सिखाते थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू नियमित रूप से एक्सरसाइज करते थे और आपने पढ़ा होगा कि वह कई तरह के आसन करना जानते थे और इसीलिए उनकी तन्दुरुस्ती इतनी अच्छी थी। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इसमें खर्चा बहुत कम है। मध्यप्रदेश में इस प्रकार का किया गया था लेकिन उन्होंने लम्बा चौड़ा खर्चा बांध लिया और इस कारण से उनको यह बन्द करना पड़ा। मैं कहूंगा हमारे शिक्षा मंत्री जी से कि यह बहुत प्रेक्टिकल है। एक और बात निवेदन कर दूं कि आध्यात्मिक शिक्षा के बारे में हमारे दिमाग में कुछ गलतफहमियां रही हैं। यह सही है कि हम धर्म निरपेक्ष राज्य बनाना चाहते हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपने विद्यार्थियों को हमारे जो बहुत से रिलीजन्स हैं उनकी शिक्षा भी सही ढंग से नहीं दें और हम सभी धर्मों की बेसिक कन्सेप्ट भी नहीं बता सकें। अगर हम बेसिक कन्सेप्ट को सही तरीके से बतायेंगे तो भी एक दूसरे में विश्वास बढ़ेगा और आज रात दिन घटनायें होती हैं वह घटनायें भी कम हो जायेंगी। मैं समझता हूं कि यह बात बहुत आसानी से की जा सकती है और हमारा जो लक्ष्य है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य हो उसमें दिक्कत भी नहीं आयेगी इसलिए इसके अध्ययन की व्यवस्था हमारे स्कूलों में होनी चाहिए।

एक मिनट का समय और दें, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। दुनिया में 300 धर्म और 15 हजार लड़ाइयां हो चुकी हैं। मनुष्य का सही धर्म क्या है? मनुष्य का सही धर्म मनुष्य बनाना है और 15 हजार लड़ाइयां हो चुकी हैं। जिसमें पिछली जो लड़ाई हुई उसमें पांच करोड़ आदमी मारे गए, उसके बाद जो लड़ाई हुई उसमें साढ़े तीन करोड़ आदमी मारे गए और आज तो जो पचास हजार उद्जनबम और हाईड्रोजन बम बना लिए हैं जिससे यह सारी पृथ्वी ही नहीं बल्कि इस तरह की सात पृथ्वियां बन जायें उनको भी नष्ट किया जा सकता है। पृथ्वी को एक बार नष्ट कर दिया और उसके बाद फिर पृथ्वी बनाई और उसको नष्ट कर दिया और इस तरह से सात बार पृथ्वी बना कर नष्ट की जा सकती है इन पचास हजार बमों से।....

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : यह साइन्स की बात किसने बताई आपको।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आपको इसका ज्ञान नहीं है, आपका ज्ञान रहा हो तो बताइये।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज!

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : मैं क्षमा चाहता हूं साहब।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं निवेदन करता हूं कि इतनी घृणा, इतनी नफरत, इतना क्रोध, इतना आक्रोश आज दुनियां में फैला हुआ है। कोई यह नहीं सोचता कि मुझे आत्म शक्ति की जरूरत है। हमारे यहां पर भी इसी बात पर ट्रेनिंग देते हैं विद्यार्थियों को कि इस प्रकार की शस्त्रों की शक्ति बढ़ाने से और अपनी शक्ति बढ़ाने से ही

(श्री बद्री प्रसाद गुप्ता)

सारी बातें हो सकती हैं, सारी समस्यायें हल हो सकती हैं। इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि यह मैंने कुछ बातें आपके सामने रखी हैं। आपने मुझे समय दिया उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं और शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि जो कुछ विचार मैंने रखे हैं आप उन पर विचार करेंगे।

मुझे एक विभाग से भी शिकायत थी वह अभी मैं नहीं कहूंगा। नये कमिश्नर साहब आ गए हैं उनके सामने रखूंगा। मैंने अपने जिले के बारे में भी कुछ नहीं कहा है। हमारे जिले में, अलवर जिले में भी काफी समस्यायें हैं। अलवर में जो कॉलेज है वह सबसे बडा कॉलेज है और उसमें 3700 लड़के हैं। वहां पर बड़ी कमियां हैं। मैंने पहले भी निवेदन किया था और इस तरह की किसी लोकल समस्याओं का मैंने यहां पर उल्लेख नहीं किया है, मैं अलग से शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करूंगा इस आशा के साथ कि वे उन पर ध्यान देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भगराज चौधरी।

श्री रतिराम यादव : उपाध्यक्ष महोदय मेरा भी नाम था।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने आपको मौका दिया था लेकिन आप उपस्थित नहीं थे। अब मेहरबानी करके बिराजिये।

श्री गोकुलचन्द : अलवर जिले के सब को मौका दे दिया और मुझे छोड दिया एक मौका मुझे भी दे दें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भगराज चौधरी।

श्री भगराज चौधरी (रानीवाडा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पूर्व वक्ता श्री बद्री प्रसादजी गुप्ता जो अलवर से आते हैं, मेरे खयाल से योग क्रिया के बारे में और उसके ज्ञान के बारे में इसलिए प्रभावित हुए हैं कि वह शायद सन्यास आश्रम से वानप्रस्थ आश्रम की ओर जाने की सोच रहे हैं।

(व्यवधान अश्रव्य)

सोरी, वानप्रस्थ आश्रम से प्रस्थान कर सन्यासाश्रम की ओर जाने का विचार कर रहे हैं। आज हम लोग विज्ञान के युग से गुजर रहे हैं। पहले हजार–हजार, दो दो हजार साल पहले यौगिक क्रियाओं से मनुष्य के जीवन में किस प्रकार अन्तर आता था, मनुष्यों को फायदा पहुंचता था यह सारी गये गुजरे जमाने की बातें हैं। आज एक तरफ विज्ञान ने इतनी बातें पैदा कर दी हैं कि हम लोग...

श्री फूलचन्द जैन : ये व्यक्तिगत बात कह रहे हैं, हम यौगिक क्रियाओं से सहमत हैं।

श्री भगराज चौधरी : हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि किस प्रकार से हमारे मानव समाज की जो समस्यायें हैं उसमें विज्ञान का पुट देकर और हम देश को आगे ले जावें। और भौतिक उन्नति के साथ-साथ बौद्धिक उन्नति और मानसिक उन्नति वैज्ञानिक दृष्टि से किस प्रकार करा पायेंगे हमारे समाज का यह बहुत बड़ा सवाल है। खैर, इन्होंने एक बात कही, मैं निवेदन करूंगा कि आज पिछले कुछ वर्षों से बराबर यह बात आ रही है कि हमें शिक्षा प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन करना चाहिए।...

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह आपने बिना जानकारी के कह दिया, आपकी इस बारे में कोई स्टडी नहीं है।

श्री फूलचन्द जैन : हम लोग सहमत हैं आपसे।

श्री भगराज चौधरी : मैं भी आपके विचारों से सहमत हूं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आपने यह कैसे इसे गये गुजरे जमाने की बात कह दी, यह तो वैज्ञानिक बात है।

श्री भगराज चौधरी : I don't want to enter into this controversy.

जहां तक हमारी शिक्षा प्रणाली का सवाल है, बहुत कुछ कहा जा रहा है, इसके परिवर्तन के बारे में। मगर जहां तक शिक्षा शास्त्रियों का सवाल है, इण्टेलेक्चुअल्स का सवाल है, राजनेताओं का सवाल है, जन प्रतिनिधियों का सवाल है और साथ ही साथ शिक्षा शास्त्रियों का सवाल है वह सब मिल कर यह बात सोचें लेकिन अभी तक उनके दिमाग में इस बात पर परिपक्वता नहीं बन पायी कि किस प्रकार का परिवर्तन वे चाहते हैं। जैसा कि माननीय सदस्य ने पहले ठीक ही कहा है कि हम कैसा परिवर्तन चाहते हैं। समाज को क्या देना चाहते हैं वह हमारे शिक्षा शास्त्रियों के दिमाग में कोई चीज नहीं बैठ पाती। आखिर में इसलिए जो सोच पाया हूं वह यह है कि देश के अन्दर जो मौजूदा हालात है उन समस्याओं को सुलझाने के लिए और समाज को सुखी और समृद्धशाली बनाने के लिए, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, आजादी के दृष्टिकोण से, भौतिक दृष्टिकोण से और सब तरीके से विश्व के अन्दर सारी जो बातें हैं उनको देख कर हमें देश में आगे बढ़ना है, हमारी शिक्षा प्रणाली को ढालना है। यह बात अवश्य है कि हमारे देश की आबादी अभी जो है वह साठ करोड़ है और आबादी बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। आज पच्चीस तीस प्रतिशत आबादी जो कि सारे विश्व की है वह शिक्षा प्राप्त करके कोई नौकरी चाहती है। लेकिन छोटे-मोटे रोजगार मिल जाने से ही इस समस्या का हल नहीं होने वाला है। आज हमारे बहुत से विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करके, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों से विद्याध्ययन करने के बाद बाहर आते हैं तो मैं समझता हूं कि सारे के सारे विद्यार्थियों को कोई धन्धा नहीं मिल पाता है। तो धन्धा नहीं मिलने की जहां तक बात है उसका जरूर सवाल है, यह सारी समस्यायें हैं कि युनिवर्सिटी की हमारी शिक्षा किस प्रकार की होनी जरूरी है। विद्याध्ययन करने के बाद कोई भी विद्यार्थी चाहे वह माध्यमिक तक की शिक्षा हो चाहे वह कॉलेज तक की शिक्षा प्राप्त करे उसके बाद में उसको कहीं न कहीं अपना रोजगार मिल जाना चाहिए। अब रोजगार कैसा हो यह भी एक प्रश्न है : जहां तक मैं समझ पाया हूं रोजगार के लिए हम यह वैज्ञानिक युग को देखते हुए इस प्रकार का अपनी शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन करें, कोर्सेज कायम करें कि जिससे ज्यादा से ज्यादा विज्ञान का उपयोग विद्यार्थी विद्याध्ययन करने के बाद अपने जीवन में कर सके। उसके लिए कुछ टैक्निकल क्वालिफिकेशन हों, कुछ टेक्निकल कोर्सेज हों, वह सेकेंड्री स्टेज पर भी चालू कर सकते हैं, उसको बाद में यूनिवर्सिटि स्टेज पर भी कर सकते हैं।

(श्री भगराज चौधरी)

मगर सारी एजूकेशन सिस्टम के अन्दर या शिक्षा प्रणाली के अन्दर या शिक्षा के कोर्सेज के अन्दर परिवर्तन करने के बाद, वोकेशनल एजूकेशन का प्रवन्ध करने के बाद, या जोब ओरियेन्टेड एजूकेशन करने के बाद भी आखिर में मैं यह समझता हूं कि समाज के विभिन्न अंगों को सोचना पड़ेगा एक बार, शिक्षा शास्त्रियों को सोचना पड़ेगा कि आखिर में शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है। शिक्षा का मूल उद्देश्य होता है हमारा मानसिक, हमारा बौद्धिक विकास। इसके सिवाय कोई विकास नहीं होता। पहले के जमाने में जब शिक्षा ग्रहण किया करते थे तो कोई इस दृष्टिकोण से नहीं कि शिक्षा ग्रहण करने के बाद राज्य सरकार नौकरी देगी। यह बात जरूर है कि नौकरी भी मिलती थी लेकिन आखिर में इसकी भी कुछ सीमा होती है। जब करोड़ों विद्यार्थी हर साल में हमारे कॉलेजों से निकलते हैं तो आखिरकार करोड़ों विद्यार्थियों को कौन 2 से व्यवसाय में खपा सकते हैं। जब सरकार के पास में भी व्यवस्था नहीं है तो निश्चत तौर से जवाब यह है कि हम शिक्षा प्राप्त करके बाहर आवें तो खुद ही अपना रोजगार लगावें, खुद अपना जोब क्रियेट करें। वह जोब व्यापार हो सकता है, खुद का कारोबार हो सकता है, खेतीबाड़ी में लग जाइये। अपने जो पुराने खुद के धन्धे हैं, पेरण्टल धन्धे जिन्हें कहते हैं, उनमें लग जायें। कुल मिला कर हमें इस प्रकार के हालात पैदा नहीं करने चाहिए, इस प्रकार का वातावरण नहीं बनाना चाहिए कि बहुत कुछ शिक्षा प्रणाली ही गलत है। सरकार विद्यार्थियों को गलत रास्ते पर ले जा रही है, कोई खास दिशा नहीं दे रही है, मैं समझता हूं कि यह बात ठीक नहीं है। दूसरे देश जो भारत के अलावा हैं वहां पर क्या हो रहा है? वहां पर भी कोई हमसे ज्यदा शिक्षा प्रणाली में फर्क नहीं है, कोर्सेज में बड़ा फर्क नहीं है। यह हो सकता है कि कहीं पर सेमेस्टर प्रणाली हो, विद्यार्थियों की सफलता के बारे में जांच करने का कोई तरीका दूसरा हो। मगर जहां तक शिक्षा का सवाल है, मानसिक विकास करने का, बौद्धिक विकास करने का और अच्छे नागरिक पैदा करने का और स्वच्छ समाज के अन्दर एक सामाजिक व्यक्ति विद्याध्ययन के बाद बनाने का, सारे देशों का मापदण्ड यही है। यह जब हमारा मापदण्ड है, तो शिक्षा प्रणाली में परिवंतन करने की जरूरत नहीं है। यह जरूर है कि सैकेंड्री स्कूल हायर सैकेण्ड्री स्कूल स्टेज पर इस प्रकार के कोर्सेज शुरू करने चाहिए जिनका ताल्लुक केवल कागजी ज्ञान तक ही सीमित नहीं हो बल्कि हमारे व्यवहार में आने वाला हो, जोब ओरियेंटेड हो जिससे कि हाई स्कूल और हायर सैकेंड्री स्कूल तक दस बारह साल तक विद्याध्ययन के बाद जब वह बाहर आये तो छोटे मोटे कारोबार में लग सके, यह मापदण्ड अवश्य होना चाहिए ताकि सरकार पर भार न बने। कुछ लोगों ने कहा कि हमारी शिक्षा प्रणाली जोब ओरियेंटेड नहीं है, लोगों को काम पर नहीं लगा सकती, मैं इससे इन्कार नहीं करता, जरूरी होनी चाहिए। शिक्षा जोब ओरियेंटेड हो सकती है, इसको व्यवसायोन्मुखी बनाना चाहिए। मगर इतना करने के बाद भी हमारी शिक्षा प्रणाली की हालत पर या शिक्षा प्रणाली पर जो अलग 2 विचार कर रहे हैं, जो विद्यार्थियों में असंतोष है वह असंतोष मिटने वाला नहीं है।

(श्री भगराज चौधरी)

विद्यार्थियों में असंतोष का कारण शिक्षा नहीं है इसका सम्बन्ध तो बहुत कुछ हमारे समाज के एक जनरल एटमास्फियर से है, वातावरण से है। आज हमारे समाज का वातावरण दूषित होता जा रहा है। बहुत बड़ी राजनीतिक पार्टियां दखल कर रही हैं। दुर्भाग्य से हमारे देश में पांच साल ऐसी पोलिटिकल पार्टियां हैं। हर पोलिटिकल पार्टी अपने पोलिटिकल एन्ड को मीट आउट करने के लिए अपरिपक्व दिमाग के लोगों को उकसाती हैं। और इसके लिए वे विद्यार्थियों को आगे लाने का प्रयास करती हैं। विद्यार्थियों को कहा जाता है, फीस ज्यादा है, फलां की जरूरत है, रोडवेज की सुविधा विद्यार्थियों को नहीं मिल पा रही है। इन बातों को लेकर विद्यार्थी समाज में ऐसा वातावरण पैदा कर रहे हैं, जो अव्यवस्था और अशांति को बढ़ावा दे रही है। इन सब बातों के लिए मैं सरकार को जिम्मेदार नहीं मानता हूं। हम लोगों की एवं समाज की यह जिम्मेदारी है। शिक्षा शास्त्री, टीचर्स एवं अभिभावकों पर इसकी जिम्मेदारी है और कुछ हद तक यह जिम्मेदारी विद्यार्थियों की भी है। इसका इलाज यह है कि हम देश में एक अच्छा वातावरण पैदा करें। टीचर्स में डिसीप्लीन पैदा कर, विद्यार्थियों में डिसीप्लीन पैदा करें। देश को सही दिशा में ढालने के लिए, देश की तरक्की करने के लिए अपने कर्तव्यों को निभावें। पिछले दो सालों से हम क्या देख रहे हैं? गुजरात में आन्दोलन चला क्यों हुआ? कुछ पोलिटिकल पार्टीज ने अपने पोलिटिकल एन्ड को मीट आउट करने के लिए स्टूडेन्ट को उकसाया। शायद उन्होंने सोचा कि सरकार हमारी बात को नहीं माने उन्होंने विद्यार्थियों को आगे किया और उन्होंने विद्यार्थियों को आगे करके मांगे रखवायीं, भ्रष्टाचार दूर हो, अनाज सस्ती दर से मिलना चाहिए, फलानी बात होनी चाहिए। यह सरकार भ्रष्ट है। नये चुनाव होने चाहिये। कहने का मतलब यह है कि ऐसी मांगें पेश की जिनका कि विद्यार्थियों से ताल्लुक नहीं था। शिक्षा प्राप्ति का मूलभूत उद्देश्य अध्ययन करना है। हमने भी शिक्षा प्राप्त की है। पोस्ट ग्रेजुएट मैंने भी किया है। गांव में रहा हूं। शहर जाकर अध्ययन किया है। कॉलेज में पढ़ा हूं। होस्टल में रहा हूं। वापिस गांव गया हूं और आज प्रैक्टिस कर रहा हूं। मैंने इस सारे वातावरण को देखा है और देखते-देखते 40 साल हो गये।

श्री उपाध्यक्ष : आपकी चुनौती को स्वीकार कर लिया है?

एक माननीय सदस्य : हम आपकी विद्वत्ता को मानते हैं। हमें आपकी विद्वत्ता के बारे में कोई सन्देह नहीं है।

श्री भगराज चौधरी : मैं कोई शिक्षा शास्त्री नहीं हूं। मैं यह कहना चाहता हूं माननीय सदस्य जो इस सदन में बैठे हैं वे भी कोई शिक्षा शास्त्री नहीं है। जो दूसरे पोलिटिकल लीडर्स है, समाज के नेता हैं, वे भी कोई शिक्षा शास्त्री नहीं हैं। वे भी कहते हैं हमारी शिक्षा प्रणाली समय से मेल नहीं खाती है। हमारे जो गिने चुने शिक्षा शास्त्री हैं उन्होंने भी इसके बारे में सोचा है और वे भी चाहते हैं कि हमें शिक्षा को काम के साथ-साथ जोड़ना चाहिए। तो इसके बारे में कोई कमीशन हो शिक्षा शास्त्रियों का, उस कमीशन में कुछ हमारे आदमी हों। तो इसके बारे में सुधार और परिवर्तन की मांग ठीक हो सकती है। आप

(श्री भगराज चौधरी)

क्या ठीक समझते हैं। खेतसिंह जी इस बारे में क्या कह पाएंगे, वे कोई शिक्षा शास्त्री नहीं हैं। वे भी यह भावना व्यक्त करेंगे कि शिक्षा प्रणाली ऐसी हो जिससे युवकों को काम मिल पावे। एक बात जरूर समझ में आती है कि हमारी शिक्षा व्यवसायोन्मुख हो, समय की जरूरत के अनुसार हो, और इसकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। रहा सवाल स्टूडेन्ट्स अनरेस्ट का, मैं यह नहीं समझ पाता कि केवल सरकार पर दोष मढ़ देने से क्या यह अनरेस्ट ठीक होगा? इस स्टूडेन्ट अनरेस्ट को दूर करने के लिए हमें टीचर्स को डिसीप्लीन्ड करना होगा। आज से पन्द्रह साल पहले कभी जब सरकार स्कूल कॉलेज की फीस बढ़ा देती थी तो कॉलेज के बच्चे हड़ताल किया करते थे। परन्तु यह देख कर ताज्जुब होता है कि आज प्रोफेसर भी हड़ताल कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी टीचर की हड़ताल चल रही है। टीचर अपनी मांगों के लिए हड़ताल कर रहे हैं। क्या वे देश के नागरिक नहीं हैं। वे सभ्य हैं। उनको तनख्वाह मिल रही है। उनको तो कम से कम बच्चों जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। वे ऐसा क्यों कर रहे हैं, यह हमारा दोष है हमारे समाज का। वे शान्ति का वातावरण छोड़ कर एक दूषित वातावरण पैदा कर रहे हैं। उनकी मांगों पर सरकार को विचार करना चाहिए। जो भी मांग पेश करते है उन पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए और उनकी मांगे बिना हड़ताल के हल होनी चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं क्षेत्र की समस्याओं के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। समय लेने के लिए माफी चाहता हूं। वित्त मंत्री महोदय आगामी वर्ष 125 प्राथमिक शालाओं को माध्यमिक शालाओं में क्रमोन्नत कर रहे हैं। इसका मैं स्वागत करता हूं। पिछले दो तीन सालों से·····

श्री उपाध्यक्ष : आप सीधे फरमा दीजिए।

श्री भगराज चौधरी : उच्च माध्यमिक स्कूल नहीं खुले हैं। इससे यह हुआ है कि शिक्षा प्रणाली के अन्दर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा के अन्दर कुछ इम्बेलेन्स हो गया है। मिडिल स्कूल खुल गये तो हायर सैकेन्डरी स्कूल नहीं खुले। हायर सैकेन्डरी के लिए मैं दो साल से मांग कर रहा हूं। देर आयद दुरुस्तआयद सरकार ने इस बात को अब माना है और सरकार अब 125 स्कूल खोलने जा रही है। जालोर जिले के अन्दर ऐसे पंचायत समिति के क्षेत्र हैं जहां कि 30/40 मील की परिधि के अन्दर कोई संकेन्डरी स्कूल नहीं है। इसके मुकाबले में शहरी क्षेत्रों में अनेक स्कूल हैं····

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : मैंने पहले ही आपसे निवेदन किया है इन-डाइरेक्टली न कह कर सीधे ही कह दें।

श्री भगराज चौधरी : इस बार आपने हायर सैकेण्डरी स्कूल खोलने का प्रस्ताव किया है--तो हमारे जिले में भी एक-दो स्कूल खुलने चाहिएं। मैं खेत सिंहजी से एक निवेदन करना चाहता हूं। आप मिडिल स्कूल, हायर सैकेण्डरी स्कूल जो भी किसी जिले में खोलें उसके लिए एक कमेटी जिला

(श्री भगराज चौधरी)

स्तर पर बना दें जिसमें जिले के प्रतिनिधि हों और वह कमेटी जिले के अन्दर स्कूल खोलने का निर्णय करे। डाइरेक्टली, सेक्रेटेरियेट लेविल पर स्कूल किस किस जिले में खोले जाएं यह निर्णय आप न करें। आप जिलों को स्कूल आवंटित कर दें ...

श्री उपाध्यक्ष : आप शीघ्र समाप्त करें।

श्री भगराज चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रायः यह देखा गया है और यह महसूस किया गया है कि यह निर्णय ऊपर ऊपर हो जाता है। इसलिए मेरा शिक्षा मंत्री जी से विशेष तौर पर निवेदन है कि जिला स्तर पर कमेटी का गठन कर दें और जिलों को स्कूल आवंटित कर दें। कहां कहां स्कूल खोले जायं, यह निर्णय जिला स्तर पर गठित कमेटी जिले की प्राथमिकता को देख करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री किशन मोटवानी।

श्री किशन मोटवानी (अजमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रायः यह देखा गया है और यह महसूस किया गया है कि जो रीजन्स किसी परटीकूलर स्फीअर में, किसी परटीकूलर क्षेत्र में अपनी प्रगति के पथ पर है, उनमें अवरोध कर दिया जाता है। उदाहरण स्वरूप अजमेर शिक्षा के क्षेत्र में अपने आप में प्रगति के पथ पर था, उस प्रगति को अवरोध कर दिया गया है। जबकि वहां पर दो चीजें खुलना अति आवश्यक थीं वहां की परिस्थितियों के अनुसार–एक तो यूनिवर्सिटी का खुलना और दूसरा गवर्नमेन्ट गर्ल्स कालेज का खुलना आवश्यक था। इन दोनों कमियों के कारण यह मान्यता दिमाग में आती है जो रीजन्स जिस स्फीअर में प्रगति के पथ पर है उनको रोक दिया गया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि श्रीमाली कमेटी की रिपोर्ट आ गई है, उसको आप शेल्व न करें और जो भी उसकी रिकमण्डेशन है उनकी क्रियान्विति करने का आप प्रोग्राम बनावें। मैं कुछ चन्द बातें और निवेदन करना चाहूंगा। जो एडेड स्कूल हैं, उनके प्रति हमारा क्या रवैया है, उसके लिए कुछ नहीं कहूंगा परन्तु इन स्कूलों में जो अध्यापक हैं, उनकी सुख सुविधा के बारे में निवेदन अवश्य ही करना चाहूंगा।

आपने अपने रूल्स में यह मान रखा है कि गवर्नमेन्ट टीचर्स और एडेड स्कूल के टीचर्स को एक समान स्तर पर माना जायगा। उसकी ग्रेड सामान्य मानी जायगी, उसकी सर्विस कन्डीशन्स–सस्पेन्शन की, प्रमोशन की–वह सामान्य मानी जायगी, तो आज हम क्या यह मानते हैं कि हमने एडेड स्कूल के टीचर्स को उस स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया है–जैसा कि House rent नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं देते हैं, Medical सर्विस की वही फैसिलिटी नहीं देते हैं, उनकी पेन्शन, उनको ग्रेचुएटी इत्र एलाऊ नहीं करते हैं। तो इन पहलुओं पर इसका अध्ययन और अवलोकन और मूल्यांकन अत्यन्त आवश्यक है और जो आज एडेड टीचर्स के मन में भ्रान्ति है, असन्तुलन दिमाग में पैदा कर रखा है तो उसके दिमाग में सन्तुलन पैदा करना आवश्यक है जैसे कि सरकम्स्टान्सेज चल रहे हैं उनमें। इस प्रदेश के वातावरण में उनका रोल रहेगा। अगर वह संतुलित रहेंगे तो संतुलित तरीके से वातावरण बनाने में हमारे सहयोगी

(श्री किशन मोटवानी)

होंगे। एडेड स्कूल का समानीकरण हो उस पर मंत्री महोदय ध्यान देंगे।

दूसरा प्राब्लम मेरे साथी केशरीमल ने उठाया है। मैं समझता हूं कि इतने 25 साल की सर्विस के बाद आज Refugee teachers वर्ग सर्विस कन्डीशन्स में डिफरेन्स ला देंगे, जो हमने सिक्योरिटी उनकी बातें मानकर 71 में दीं और 71 से उनका स्थिरीकरण कर दिया ग्रेड्स का, और जब ग्रेड का फिक्सेशन हो गया उसके बाद पुनः उनको रिवाइज कर रहे हैं महज एक छोटी सी गलती के कारण कि वह मान्यता न स्वीकृति Primary leaving examination के सर्टिफिकेट के साथ है या नहीं जिसको आप मान चुके हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि एक्सटेन्शन के केसेज और रिएम्प्लायमेन्ट के केसेज हैं। उनको माननीय मंत्री महोदय देखेंगे। और जो 15–15 महीनों से कुछ टीचर्स को तनख्वाहें नहीं मिली है तो आप इस समय में अन्दाज लगा सकते हैं कि वह टीचर्स किस तरह से अपना जीवन-निर्वाह कर रहे होंगे। डिटेल्स में लेटर में डाईरेक्टर को, कमिश्नर महोदय को और मंत्री महोदय को लिख चुका हूं, और कई बार इस पर डिस्कशन भी हो चुका है। टीचर्स के खाते खुलवाये हैं कि किस तरह से इस प्राब्लम को साल्व किया जाय, परन्तु कहीं न कहीं गड़बड़ हो जाती है और मामला दब जाता है। तो नये कमिश्नर साहब आये हैं वह मैं समझता हूं कि रिफ्यूजी टीचर्स के एक्सटेन्शन और रिएम्प्लायमेण्ट के केसेज की जो फाइलें हैं उनको देखेंगे और उनसे पहले वाले कमिश्नर महोदय ने निर्णय दिये हैं उसके बाद में उनको क्रियान्वयन कराने की कोशिश करेंगे। तो मैं समझता हूं कि यह प्राब्लम जिसमें छोटी छोटी बातें खड़ी हो जाती हैं वह साल्व हो जायगा।

एक बहुत बड़ा प्राब्लम हमारे अजमेर में खड़ा हुआ है सावित्री गर्ल्स कालेज का। वहां की मैनेजिंग कमेटियों का झगड़ा हमने एक एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर रखा है। जब मैनेजमेंट का कार्यकाल था तो आडिटर्स ने शैडयूल्ड फीस के अतिरिक्त जो फीस ली जाती है वह गलत है और उसके लिये जाने पर आब्जेक्शन किया है। आज समझ में नहीं आता है कि जब गवर्नमेंट का कन्ट्रोल है और एडमिनिस्ट्रेटर बैठा हुआ है तो वही गलती एडमिनिस्ट्रेटर क्यों दोहरा रहा है और उन बच्चियों से करीब 35-40 हजार रुपया इस नाम से लिया जा चुका है। जब मैनेजमेंट था तब लिया गया था तो आब्जेक्शन किया गया। मैं रूल्स के बारे में निवेदन करूंगा और जो आपका शेड्यूल आफ फीस है उसमें साफ लिखा है—

"Rates of additional fees to be charged in the different schools and institutions in Rajasthan:—

Other fees will be charged in Government institutions.

अदर फीस जो चार्ज की जा रही है जिसको आडिटर्स ने आब्जेक्ट किया तो अब हमारे कार्य काल में ही वह गलती कर रहे हैं तो मैं मानता हूं कि इसके नजरिये को देख कर आज हम खुद उसमें ईन्वाल्वड हो रहे हैं जिसको हम गलती मानते हैं। तो यह

(श्री किशन मोटवानी)

अनएप्रूव्ड फीस बच्चियों से न लें इसकी व्यवस्था की जाय ।

इसके बाद मैं धन्यवाद देता हूं मंत्री महोदय को कि माइनोरिटी लैंग्वेज के विकास के पहलुओं पर एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया। दो साल तक अप्रिय स्थिति रही। दो साल से एस. टी. सी. स्कूल से जो टीचर्स निकलें उनके एम्प्लायमेंट का कोई प्रावधान नहीं रखा है। अब 500 टीचर्स का प्रावधान रखा है तो दूसरे और तीसरे साल में जो निकलेंगे सब एम्प्लाय हो जायेंगे। उनको एम्पलायमेंट प्लस लैंग्वेज विकास के बारे में कोशिश एक सराहनीय कदम है।

इसके बाद कोटा का प्राब्लम है वहां पर गवर्नमेंट कालेज में सिन्धी सब्जेक्ट के लिए फुल-फ्लेज्ड लेक्चरार नहीं है। अभी टेम्पोरेरी बेसिस पर किसी रेलवे आफिस के आदमी को बुलाकर पढ़ाते हैं किसी को रीएम्प्लाय करके, रीएम्प्लाय नहीं तो पार्ट टाइम देकर बुलाते हैं तो उसकी व्यवस्था करना आवश्यक है। आपने माइनोरिटीज लैंग्वेज S.T.C. के जो पढ़ने वाले हैं उनका स्टाइपेंड बन्द कर दिया, उनकी स्थिति दयनीय है। वहां पर गरीब जनता के बच्चे स्टिपेंड्स से पढ़ते हैं। उनकी हालत इतनी खराब है कि फीस के लिए उनके पास पैसा नहीं है तो लड़के आपस में मिल मिलाकर Contribute करते हैं।

आज यहां पर बात करते हैं और शिक्षा पद्धति में परिवर्तन की बात चलती आई है और उसमें मेरी अब मान्यता है कि आज जो सोचते हैं और आज ही नहीं करते हैं तो आज की परिस्थितियां क्या हैं और कल परिस्थितियां क्या होंगी इनका मूल्यांकन नहीं है। आज भी सुझाव आये हैं और परिवर्तन की बात आई है। ठोस सुझाव नहीं है परन्तु जो भी हैं तो जो टर्म्स आफ रेफरेन्स आये और इसके लिए कोई पर्टीक्यूलर कमेटी बनाई जाय तो टर्म्स आफ रेफरेन्स और टाइम बाउण्ड प्रोग्राम आवश्यक है, क्योंकि जब तक वह सुझाव देंगे तब तक परिस्थितियां चेन्ज नहीं हो जाती हैं। 52 में, 56 में और 60 में किया तो उन परिस्थितियों में आज अन्तर है। आज जो हम अध्ययन करवायें वह टाइम बाउण्ड होना चाहिए कि इतने समय में दे देंगे और इतने समय में कार्यान्वयन किया जायगा।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

साथ में, मैं एज्यूकेशनस्टि नहीं हूं, शिक्षा-शास्त्री नहीं हूं, परन्तु मैं इतना सा निवेदन करूंगा कि जब एज्यूकेशन का बिस्तार हो तो उसका plan से समन्वयन होना चाहिए, इतना उसमें कोआर्डिनेशन होना चाहिए कि शिक्षा लेकर कोई निकले तो उसको एम्प्लायमेंट मिल जाय। वह एम्प्लायमेंट ओरियेन्टेड हो। एक प्लान्ड फीचर में एज्यूकेशन की प्रोग्रेस होनी चाहिए। उस तरह से एज्यूकेशन प्रोग्रेस नहीं होती है तो इससे असन्तोष पैदा हो सकता है। आज स्टूडेंट को अपने फ्यूचर का कुछ नहीं मालूम है। कल उसके फ्यूचर की सिक्योरिटी है कि नहीं; एम्प्लायमेंट पोटेन्शियेलिटी उसमें होना चाहिए।

(श्री किशन मोटवानी)

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

मैं निवेदन करूंगा कि जो पहले बोलते हैं उनको ज्यादा समय दिया जाता है और जो आखिर में बोलते हैं उनके समय में आप कटौती करेंगे। मैं निवेदन करूंगा कि दो मिनिट मुझे दे दें मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा।

एक तो टाइम बाउण्ड प्रोग्राम हो और एम्प्लायमेंट पोटेन्शियल का कोआर्डिनेशन हो।' आज क्षेत्री ताम्बा अंक से तो उसमें मेट्रालाजी के अध्ययन कर प्रावधान हो और जो लोग छोटे काम वाले लोकती-सुशिक्षित हैं तो उनको एम्प्लायमेंट मिल सकता है। इस किस्म की एज्यूकेशन प्रोग्रेस में कोआर्डिनेशन अत्यन्त आवश्यक है।

दो मिनिट और निवेदन करूंगा कि एक तो key Production मतलब यह है कि cheap जियो वाले किताबों ऐसे बच्चे पैदा हो जाते हैं जिनमें संस्कार नहीं होता है। वह प्रोडक्शन key Production जो बाजार में अनरिकग्नाइज्ड इन्स्टीटयूशन्स हैं उनके माध्यम से आज हजारों की संख्या में निकलते हैं। जहां आपका कोई नियन्त्रण नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है जहां उनके पास टीचर्स पढ़ाने वाले वह शिक्षित नहीं हैं, उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जो स्टूडेन्ट्स निकलेंगे वह डिसिप्लिन्ड होंगे ? key प्रोडक्शन व यह इन्स्टीट्यूशन्स हैं उन पर आप कोई न कोई नियन्त्रण लागू करें। key प्रोडक्शन को बन्द करें और इन इन्स्टीट्यूशन्स पर नियन्त्रण लागू करें। उसके बाद आप अपने उद्देश्य को प्राप्त कर पायेंगे।

दूसरा टीचर्स के दिमाग में आपको संतुलन पैदा करना पड़ेगा। उनकी सर्विस कन्डीशन्स हैं, उनके प्रोमोशन्स की कन्डीशन्स हैं, उनके जो ग्रेड्स हैं, उनके लिए आपको वक्त का तकाजा देखते हुए उनके साथ मिल कर चलना पड़ेगा।

एक और निवेदन है.....

श्री उपाध्यक्ष : आपके दो मिनिट हो गये।

श्री किशन मोटवानी : युनिवर्सिटीज को आटोनॉमस बनाने का उनकी लायेबिलिटी का दायित्व का एक छोटा सा उदाहरण दूं। अजमेर में इस बार स्ट्राइक हुई उसके कारणों का आप अध्ययन कीजिये। उसमें स्टूडेन्ट्स का क्या दोष था ? आप उसका अध्ययन कीजिए। उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का क्या दोष था उसका अध्ययन कीजिए। आपने सितम्बर में रिजल्ट निकाला और October में एडमिशन दिया। सेप्टेम्बर के बाद 5 महिने में वे क्या पढ़ेंगे ? जिसमें दो महीनें छुट्टियां रही हैं। तीन महीने बाद ही बोर्ड एक्जामिनेशन लेना चाहे जब कि 50 पर्सेन्ट कोर्स भी नहीं कराया हो।

तो फिर बच्चे कहां जायेंगे। आप यह मानकर चलिये कि बच्चे स्ट्राइक पर जायेंगे। आप इस पर सोचें। आप जो व्यवस्था बिठाने जा रहे है, वह अकार्डिंग टू रूल है। अगर आप उनके बारे में सोचते। तो मैं मानूंगा, मैंने जो सुझाव दिये हैं, उन पर ध्यान दिया जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोकुलचन्द।

श्री गोकुलचन्द जाटव (कठूमर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कटौती प्रस्ताव, सरकारी आदेशों की अनुपालना समय पर न किये जाने सम्बन्धी विभागीय लापरवाही पर चर्चा के लिए है। उपाध्यक्ष महोदय, यह कितना आश्चर्य जनक और खेदजनक विषय है कि सरकार के इस विषय पर बोला जाये। विषय आपको मालूम है।

श्री उपाध्यक्ष : संक्षिप्त में बोलें।

श्री गोकुलचन्द जाटव : मैं दो मिनट ही लूंगा। मैं धन्यवाद के प्रस्ताव पर नहीं बोला, बजट भाषण पर भी नहीं बोला। बजट भाषण पर नहीं बोला। इसी समय बोल रहा हूं, थोड़ा सा ही समय लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि पिछले 18 साल से हमने जिस परेशानी को नहीं भोगा है, वह पिछले 3 साल से काफी परेशानी में हैं। मैं इस बारे में निवेदन करूंगा कि वो केस मेरे सामने आये 3 साल से उनमें उलझ रहा हूं। आज तो जो लेटर मैंने लिखे हैं, उनकी प्रतियां मैंने दे दी हैं। शायद वह काम पूरा हो सके। एक अपने अलवर में अध्यापिका श्रीमती प्रेमकान्ता शर्मा हैं। उनका ट्रान्सफर आबू में हुआ। 61 से वह वहां प्रधानाध्यापिका पद पर रहीं। जो अपने ग्रीष्मावकाश के वेतन के लिए लिखा पढ़ी करती रहीं। अब तो 9 साल लिखा पढ़ी को हो गये हैं। 9 साल के बाद उनके हस्बेण्ड से मेरी चर्चा हुई। पत्र देखकर आश्चर्य होता है। उन्होंने साफ लिखा है – 1972 में लिखा है:—

"उपरोक्त विषय में लेख है कि अध्यापिका का वेतन देय है अतः आपसे अनुरोध है कि वेतन बिल बनाकर इस निदेशालय को भेजें जिससे इस कालातीत मामले को नियमित किया जा सके।" यह लिखा है, शिक्षा उपनिदेशिका (महिला), जोधपुर।

इसके बाद 1972 में लिखा है, उपनिदेशक (महिला) शिक्षा विभाग जोधपुर ने उसमें लिखा है कि उनकी "प्रथम नियुक्ति तिथि दि. 3-1-61 को हुई थी। अध्यापिका ने सत्र 60-61 के ग्रीष्मावकाश में मुख्यालय छोड़ने की अनुमति चाही थी। लेकिन आपने उनको तार द्वारा सूचित किया था कि शाला का भवन के चार्ज सम्बन्धी कार्य हेतु वह शाला में ही ग्रीष्मावकाश में कार्य करें।" फिर उन्होंने लिखा—

"उक्त अध्यापिका की ग्रीष्मावकाश सत्र 1960-61 का वेतन देय है। अतः इनका वेतन बिल बनाकर शीघ्र ही सहायक लेखाधिकारी, शिक्षा विभाग, जोधपुर की मारफत निदेशालय बीकानेर को प्रेषित करें।" फिर उन्होंने आगे लिखा है—"ताकि इस कालातीत मामले को नियमित किया जा सके।"

इसके बाद भी जब कुछ नहीं हुआ तो मैंने मन्त्री महोदय को लिखा। इस पर भी जब कुछ नहीं हुआ तो मैंने सोचा कि विधान सभा में अपने अधिकारों का प्रयोग करूं। प्रश्न का उत्तर मिला लेकिन उससे मुझे सन्तोष नहीं हुआ। आज सारा अमला यहां पर है। सारे मामले को निबटाया जायेगा। वाजिब है तो हां कर दें। आपके कानून से मेल नहीं खाता है तो कह दें। लेकिन आप इस बात को भूल से जाते हैं। हम लोग चुनकर आते हैं। आप सर्विस के लोग हैं।

(श्री गोकुलचन्द जाटव)

आप सर्विस में नियुक्त हो गये हैं। पेंशन लेकर हटेंगे। हम विधान सभा में हैं। 5 साल के बाद हो सकता है, हार भी जाते हैं। तो यहां से हट जायेंगे।

दूसरा मामला है, जब स्वर्गीय बरकत उल्ला खां मुख्यमंत्री थे। तब 1972 में उनको पत्र लिखा था। दो हरिजन अध्यापक थे। एक अलवर का और एक भरतपुर का। उनको 8 साल हो गये थे। उस समय बृजेन्द्रसिंह, अभाव अभियोगों को देखते थे। हम उनसे बराबर मिलते रहे। उन्होंने कहा कि हमें पत्र मिल रहे हैं। लेकिन इसमें बैन लगी हुई है। हम इसमें संशोधन ला रहे हैं। इस प्रकार का प्रपोजल भेज रहे हैं। इन दो अध्यापकों के साथ में औरों का भी भला हो जाय। हमने कहा यह तो बहुत अच्छी दृष्टि है। कहने का मतलब है कि वह मुख्य मन्त्री भी नहीं रहे। शिक्षा मन्त्री भी वह नहीं रहे। 1 अगस्त, 74 को शिक्षा आयुक्त ने यह आदेश दे दिये कि जैसलमेर से उनका ट्रांसफर 1-2-74 से होम डिस्ट्रिक्ट को कर दिया गया। मैंने लिखा कि अभी भी नहीं हो रहा है। मुझे सन्तोष है कि आयुक्त महोदय को दे दिया गया है। इस पर उन्होंने फिर लिखा है कि इम्प्लीमेण्ट किया जाये। उसके बाद एक का ट्रांसफर हो गया भरतपुर में 8 साल के बाद वह अपने घर में पहुंच गया है। दूसरे के बारे में लिखा तो मुझे लिखा गया कि कार्यालय में आदेश की मूल प्रति नहीं मिल रही है। इसलिए कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर मैंने कहा क्या करें। अब उन्होंने मूल प्रति भेज दी है। इसकी जिम्मेदारी गवर्नमेण्ट अथोरिटी पर है। शिक्षा आयुक्त का आदेश भेजा जाये तो यह किसकी जिम्मेदारी है। आप जानते हैं, बैन लगी हुई थी इस बीच में ही अलवर और जोधपुर से कई अध्यापकों के ट्रांसफर हुये हैं। वह बात नहीं है। फिर क्या कारण है। इस विषय में यह आज से नहीं, कई वर्षों से यह वातावरण बना हुआ है। सरकार के आदेश समय पर पालन नहीं होते हैं। ढील होती है। सतर्कता आयोग भी काम कर रहा है। मैं बहुत ही दुख भरी आवाज में कहना चाहता हूं। समाज और प्रशासन मर्यादाओं में बंधा हुआ है। जिस दिन वह भंग हो गया उस दिन सब कुछ भंग हो जायेगा जिस दिन वह हुआ उस सारे काम क्या से क्या होने लगेंगे। धर्म कुछ नहीं रहेगा। समाज कुछ नहीं रहेगा। इसलिए मैं चन्द शब्द में कह रहा हूं। मन्त्री महोदय को यह कहता हूं चालक महोदय को कहता हूं। आप को यह देखना है कि कौन क्या कह रहा है। मैं कह रहा हूं या कोई कह रहा है। कोई ऐसा आदमी है या वैसा आदमी है। पर आपका यह रुख, कि चलता है, चलने दो।

उपाध्यक्ष महोदय, अगर बात वाजिब है....

श्री फूलचन्द जैन : आपको जब सीनियर मानते हैं तो फिर ऐसा क्यों करते हैं ?

श्री गोकुलचंद जाटव : इस राज्य में रहता हूं लेकिन चलती हमारी कहां है ? किस ने माना है सीनियोरिटी को ? सीधी भर्ती हो जाती है।

एक माननीय सदस्य : आज आपके दर्द को जान गए।

श्री श्रीराम गोटेवाला : दर्द की दवा हो गई।

श्री गोकुलचंद जाटव : इस दर्द के रोगी काफी हैं, आप भी हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आपके दर्द को सुनने के लिए सरकार हैं।

श्री गोकुलचंद जाटव : हर आदमी तो वहां नही बैठता। श्री गोटेवाला साहब आपको मेरे विचारों से संतोष हुआ है। हर व्यक्ति तो वहा नहीं बैठ सकता। वहा तो बैठने वाले हो बैठेंगे।

श्री श्रीराम गोटेवाला : कई बार मौका चूक गए हैं, इसलिए मुझे परेशानी है।

श्री गोकुलचंद जाटव : अपनी सलाह से सरकार बनती है, अपने संतोष के लिए काफी है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : दो एग्जाम्पलस आपने कोट किए हैं।

श्री गोकुलचंद जाटव : मैंने कुछ बातें कहीं हैं। एक मामला और है, उपाध्यक्षजी आपकी कान्सटीट्यूएंसी का है। एक मांगीलाल पालीवाल, हैड मास्टर हाई स्कूल का सीनियर टीचर बनाया गया था। पहले सेकेन्ड ग्रेड में थे बाद में सीनियर टीचर बना। तो उनका यह कहना है कि उसे 20 अगस्त 1969 से सितम्बर 1970 तक वापस सेकेन्ड ग्रेड मान रहे हैं, वह अपना प्रार्थना-पत्र कन्फरमेशन के आदेश की कापी शिक्षा आयुक्त के कार्यालय में 21 फरवरी को दे आए हैं, प्रतापराय एल. डी. सी. को दे आए हैं क्योंकि शिक्षा आयुक्त आफिस में नहीं थे। वाजिब नहीं है तो ना कह दीजिए, हर्ज क्या है लेकिन लटकाए मत रखो किसी को।

अन्त में मैं उपाध्यक्षजी आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : उपाध्यक्षजी, शिक्षा नीति के बारे में बहुत से सदस्यों ने कहा है। मैं सिर्फ कटौती प्रस्ताव, जो स्पेसीफिक मैटर्स पर पेश किए गए हैं, उन पर थोड़ी सी बात कहना उचित समझता हूं। यह एक नियम है कि जहां पर प्राथमिक शाला में 40 विद्यार्थी हैं वहां एक शिक्षक देना चाहिए और दूसरी ओर जहां प्राथमिक शाला से माध्यमिक शाला में जब कोई स्कूल क्रमोन्नत होता है तो कुछ परसंटेज शिक्षकों की कटौती की जाती हैं। इसके लिए लड़कों की संख्या के अनुपात में तो मास्टर देने में निदेशालय समय लगाता है और ज्यों ही स्कूल क्रमोन्नत हो जाता है तो उतनी परसेंटेज शिक्षकों की कटौती फौरन हो जाती है। उदाहरण के लिए पंचायत समिति सांचोर में 29 अध्यापकों की एकदम कटौती आ गई, वहां से कलक्टर पंचायत समिति और जिला परिषद से लिखा पढ़ी होती रही। विभाग के हिसाब से लड़कों की संख्या को देखते हुए 32 शिक्षक और चाहिए। वह तो दिए नहीं लेकिन 29 शिक्षकों की कटौती कर दी। तो मैं चाहूंगा कि जितनी लड़कों की संख्या है उसके हिसाब से शिक्षकों की और जो कटौती कर दी है, तो एजस्टमेंट के आदेश हो जाय तो हम आपके आभारी होंगे। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि 29

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

प्राथमिक शालाओं को एकदम बंद करना पड़ा और अभी भी बंद हैं। कटौती करनी थी तो लिख दिया गया कि तुमको तनख्वाहें अपने घर से देनी पड़ेंगी। फिर मैंने शिक्षा मन्त्री को लिखा, उन्होंने शायद आदेश जारी किए। तो एक तरफ आप प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य करने जा रहे हैं और दूसरी तरफ प्राथमिक शालायें बंद पड़ी हैं। रूरल एरियाज में जो आपने यह मापदंड रखा है कि 40 लड़कों के पीछे एक शिक्षक, वह भी समान रूप से नहीं बैठती। कुछ एरियाज इतनी लंबी हैं जिनमें जन संख्या के हिसाब से अगर यह 40 लड़कों का मापदंड हार्ड एण्ड फास्ट रूल के रूप में लागू किया जाए तो 15-20 मील में कोई स्कूल ही नहीं मिलेगा। तो आपको कुछ रिलैक्सेशन करनी पड़ेगी। कुछ एरियाज में जहां पर 10 मील में एक स्कूल है वहां इस रूल की वजह से शालायें बंद हो जाती हैं तो फिर यह प्राथमिक शिक्षा कम्पलसरी कैसे चलेगी? तो यदि आप बिल्कुल नियम से चलेंगे तो आपका जो उद्देश्य है--प्राथमिक शिक्षा का प्रसार--उसकी पूर्ति नहीं होगी।

एक तो ग्रामीणों के लड़के बहुत दूर से आते हैं, दूसरी बात शिक्षक वहां बिल्कुल नहीं रहते, पीने के लिए खारा पानी, रहने के लिए मकान नहीं। ऐसी हालत में शिक्षा विभाग पैसा भी नहीं दे पाता, गरीब जनता है, मकान भी नहीं बना पाती। ऐसे हार्ड एरियाज में कुछ स्पेशल एलाउन्स शिक्षकों को दिया जाए ताकि शिक्षक वहां रह सकें। जहां प्राथमिक शालायें, सेकेन्ड्री व हायर सेकेन्ड्री स्कूल्स ऐसी हार्ड एरियाज में हैं तो जैसे डाक्टरों के लिए रूरल नियम है कि रूरल एरियाज में तीन साल तक नहीं रहेंगे तो उनका प्रोमोशन नहीं होगा, तो ट्रांसफर्स और पोस्टिंग्स के बारे में राज्य सरकार को कड़े नियम बनाने की आवश्यकता है क्योंकि कुछ शिक्षक, जिनकी सिफारिशें बहुत ज्यादा होती जैसे अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, जिनकी सिफारिशें आती हैं वे अच्छी जगह रहते हैं, कुछ शिक्षक सजा के तौर पर हमेशा ऐसी जगह रहते हैं जो मजबूर होकर मेडीकल लीव लेकर बैठ जाते हैं, परिणामस्वरूप लड़के पढ़ाई से महरूम रह जाते हैं। पहले अलवर भरतपुर में शिक्षा ज्यादा है। हमारे जैसलमेर, बाड़मेर और जालौर में पहले सर्विस देते हैं फिर वापस अपनी जगह चले जाते हैं। सेकेन्ड्री, हायर सेकेन्ड्री और एस.टी.सी. ट्रेनिंग सेंटर्स में भी ऐसी एरियाज के लड़कों को प्रायोरिटी आधार पर एडमिशन्स देने चाहिए। होता क्या है कि जहां शिक्षा ज्यादा है, वहां के लड़के तो रेमोट कार्नर्स के ट्रेनिंग सेंटर में भरे जाते हैं और सेकेन्ड्री और हायर सेकेन्ड्री ट्रेनिंग सेंटर्स में आप हार्ड एरियाज के लड़कों को एडमिशन नहीं देते। नतीजा यह होता है कि जालोर, बाड़मेर और जैसलमेर शिक्षा के क्षेत्र में पीछे रहेंगे। इसलिए ट्रेनिंग सेंटर्स में ऐसी एरियाज के लड़कों को प्राथमिकता के आधार पर एस.टी.सी. में भर्ती करना चाहिए। अभी भी हमारे यहां मास्टरों की कमी है। दूसरी जगहों से ट्रांसफर होकर आते हैं। तो हार्ड एरियाज के लोगों को प्राथमिकता के आधार पर एस.टी.सी. की ट्रेनिंग दें ताकि स्कूलों में काम तो हो सके।

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

दूसरी बात रूरल एरियाज में हायर सेकेन्ड्री स्कूलों के सार्वजनिक हॉस्टिल हैं जैसे सांचोर में है, वहां कमेटी बनाकर रजिस्ट्रेशन करवा कर काम चला रहे हैं लड़कों के खर्चे से तो सरकार उनको कोई एड नहीं देती। डाहिरेंड अकाउंट्स वगैरह आ जाते हैं पर सेट जाते हैं ऐसे रेमोट कार्नर्स का होस्टल की खर्चा खुद लड़के चलाते हैं तो कुछ न कुछ एड का आधार आपको चेंज करना पड़ेगा। रेमोट एरियाज में कुछ न कुछ ग्रांट-इन-एड मिलनी चाहिए। आप वहां कोई ग्रांट-इन-एड नहीं देते।

यह साल महिला वर्ष कहलाता है। जो एडेड गर्ल्स स्कूल्स चलते हैं जैसे मरुधर बालिका विद्यापीठ उनमें ग्रान्ट-इन-एड भी नहीं बढ़ाते हैं। जब शिक्षा मंत्री जाते हैं, घोषणा करके आ जाते हैं। और मिशनरी स्पिरिट्स स्कूल चलाते हैं, उसमें स्टाफ भारतीय संस्कृति के अनुसार रख कर चलाते हैं, उसमें ग्रान्ट-इन-एड बढ़ायें तो क्या समस्या आती है।

इस रूप में जो शिक्षा ग्रामीण स्तर पर, मामूली स्तर पर है—इसकी हालत दयनीय है। ऐसी हालत है कि गांवों में बिल्डिंग नहीं है। गांव वाले चन्दा करके स्कूल चलाते हैं, उसके बाद आप रिकग्नाइज करते हैं, फिर टीचर्स की कटौती हो जाती है। वैसे इस क्षेत्र में काफी प्रगति की है। अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के लिए घोषणा की थी कि दो तीन मील के रेडियस में प्राथमिक स्कूल खोलेंगे। लेकिन भौगोलिक स्थिति को देखते हुए शिक्षा के प्रसार की ओर ध्यान देना चाहिए ताकि जो बैकवर्ड एरिया है वह पीछे न रह जाय। इसके लिए रूल्स को सरल करके, असुविधा को हटा कर व्यवस्था करें ताकि यह क्षेत्र हमेशा के लिए पीछे न रह जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सुरेशचन्द्र।

श्री सुरेशचन्द्र (कोटपुतली) : उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा पद्धति के बारे में काफी कुछ कहा जा सकता है। लेकिन मैं समझता हूं कि शिक्षा पद्धति के परिवर्तन के बारे में नीति निर्धारण के बारे में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी मुझे कम समय दिया है, तो मैं समझता हूं कि मेरे कटौती प्रस्ताव के साथ में मुझे अपने भाषण में भी कटौती करनी पड़ेगी। लेकिन आज शिक्षा पद्धति ऐसी पद्धति है जिससे न छात्र संतुष्ट है, न समाज सन्तुष्ट है, न विद्वान संतुष्ट है, न विभाग के अधिकारी संतुष्ट हैं और मैं जानता हूं कि मन्त्री महोदय भी संतुष्ट नहीं हैं। मैंने उनका भाषण सुना था, वैसे हार्ट अटेक और शिक्षा का क्या मुकाबला, लेकिन शिक्षा मंत्री को हो गया इसलिए हार्ट हटेक हो गया। इसलिए इस पद्धति में परिवर्तन आये—यह समझ में कम आता है। अभी थोड़ी देर पूर्व भूतपूर्व मंत्री का भाषण सुना और जो शिक्षा मंत्री रह चुके हैं उनसे चर्चा की है तो वह अपने पर तरस खाते हैं और तरस उन बेचारों पर आता है कि वह अपने कार्यकाल में कुछ नहीं कर पाये। शायद वह अधिकारियों के चंगुल में फंस गये, या न जाने कैसे उन्हें मौन रहना पड़ा। बड़े जोश से शिक्षा मंत्री बनते हैं और बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन जब निकलते हैं तो बेबस से निकलते हैं। इसलिए इसमें बदलाव सम्भव नहीं है....

श्री खेतसिंह : बेचारे शब्द का मेरे लिए प्रयोग किया ?

श्री सुरेशचन्द्र : यह सदन आपकी राठौड़ी का कमाल मानता है, आपके लिए बेचारा कैसे बोलूंगा। मेरा निवेदन है कि शिक्षा पद्धति नहीं बदलती, शिक्षा मंत्री बदलते हैं–यह परम्परा है।

पिछले समय सरकार ने घोषणा की थी कि आज छात्र वृद्धि अभियान चलायें। माननीय सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्रों का दौरा किया और छात्र वृद्धि का अभियान सम्पन्न किया। छात्रों की संख्या काफी बढ़ गई। लेकिन आप शिक्षा विभाग की शिथिलता देखिये, सत्र समाप्त होने को आया, लेकिन अध्यापक आज तक नहीं भेज सके। आज भी वह स्कूल खाली पड़े हैं, चाहे गर्ल्स स्कूल हो, चाहे बोइज स्कूल हैं–आज उनमें अध्यापक नहीं हैं। यह विडम्बना है। एक तरफ बेरोजगारी है, लोग आपके दरवाजे खटखटा रहे हैं कि हमें नौकरी दीजिये, दूसरी ओर स्कूल खोले हैं शिक्षा मंत्री ने कई शिक्षण संस्थाओं की संख्या बढ़ाई है, उसके लिए तो मैं बधाई देना चाहता हूँ, लेकिन जब तक आप इनको सुधारने की बात नहीं कर पायेंगे तब तक आपका अभियान सफल नहीं होगा। प्राथमिक शाला जहां जारी कर दी है, उनकी ओर आपको ध्यान देना चाहिए कि उनकी हालत क्या है। आज वहां न अध्यापक है, न भवन है, न खेल का सामान है। चार्ट और श्याम पट्ट तक भी स्कूल में नहीं है। यह हालत चल रही है। मैं कहना चाहूँगा, इन हालात में शिक्षा विभाग प्राथमिक शाला को चलाना चाहता है तो यह चलाने वाली बात नहीं है, केवल आंकड़ों की खाना पूर्ति कर रहे हैं कि इतने स्कूल खोल दिये हैं, इतने विषय बढ़ा दिये हैं इतने अपग्रेड कर दिये हैं। यह ठीक है, कुछ हद तक आपको यह करना आवश्यक है, लेकिन क्वालिटी को इम्प्रूव करने की ओर भी आपको ध्यान देना चाहिए। आज जो समस्यायें है वह माननीय सदस्यों ने बता दी हैं, उसमें अगर इस शिक्षा पद्धति में परिवर्तन नहीं करेंगे और गम्भीर रूप से विचार नहीं करेंगे तो यह स्थिति अधिक समय तक नहीं चलने वाली है।

पंचायत समिति के स्तर पर शिक्षा की हालत में आपको निवेदन करना चाहूंगा। मेरा निवेदन है कि पंचायत समिति को शिक्षा सम्भला रखी है, शिक्षण संस्थाओं शिक्षा विभाग ने पंचायत समिति को सम्भला दिया है लेकिन फिर भी राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, जब शिक्षण शालाओं को पंचायत समिति को सम्भालते हैं तो आप सारा सामान देते हैं, वेतन का आवंटन करते हैं। फिर बाद में आप जिम्मेदारी से बरी हो जाते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि आप पंचायत समिति के पास में फण्ड नहीं होते हैं, वह इस स्थिति में नहीं है कि प्राथमिक शाला चला सकें। जहां तक अध्यापकों का सवाल है, मैने निवेदन किया कि हायर सैकेण्ड्री स्कूल, सैकेण्ड्री स्कूल में आप बारह पन्द्रह, सोलह अध्यापक देते हैं लेकिन प्राथमिक शाला में एक अध्यापक देते हैं, चालीस विद्यार्थियों पर एक अध्यापक। वही सारे विद्यार्थियों को पढ़ायेगा। वह भी कहीं कहीं पर है नहीं। आप प्राथमिक शाला को चलाना चाहते हैं, फिर यह समझ में नहीं आता कि प्राइमरी स्कूल में एक अध्यापक क्यों देते हैं? किसी प्रकार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हायर सैकेण्ड्री में चार चार देते हैं लेकिन वहां

(श्री सुरेश चन्द्र)

एक भी नहीं देते हैं। आप इस पर विचार करते हैं या नहीं कि यह स्थिति क्यों चल रही है। इस पर मैं अधिक न कहते हुए निवेदन करूंगा कि जो समस्यायें हैं उन पर आप गम्भीरता से विचार कीजिये।

मैं अपने क्षेत्र की बात कहना उचित समझता हूं। मेरे क्षेत्र में एक डिग्री कालेज है। बहुत बड़ी छात्र संख्या है। राजस्थान में पहले नम्बर कालेज है। जनता ने कालेज भवन बना कर दिया है। जन सहयोग दिया है और उसमें बहुत अच्छा पुस्तकालय है। मैंने इसके सम्बन्ध में प्रश्न पूछा था और पिछले तीन साल से बराबर पूछता आया हूं। हर बार शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि हम अब करेंगे, अब करेंगे। इस तरह की परम्परा है कि...

श्री रामकिशन : अब कर देंगे।

श्री सुरेशचन्द्र : छात्र संख्या आदि के आधार पर अपग्रेड करते हैं, लेकिन अभी तक अपग्रेड नहीं किया है। और ऐसा स केत नहीं है कि इस बार कुछ करने जा रहे हैं। यह वहां की वाजिब मांग और न्याय के अनुसार इस बात का तकाजा है कि वहां पर डिग्री क्लासेज चालू करनी चाहिए। आपके पास शिक्षा विभाग के साथ साथ विधि एवं न्याय विभाग है। वास्तव में आपका यह कर्त्तव्य है कि आप न्याय दें। यहां की वाजिब मांग है इसलिए आप उनके साथ न्याय कीजिये और वहां डिग्री क्लासेज जारी कीजिये।

एक सैकेण्डरी स्कूल खोलने के लिए और आप्शनल विषय जो खोलने चाहिए, उसके बारे में कोई आधार तय होना चाहिए। ऐसा नहीं हो, जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं, जोधपुर डिवीजन में आपने काफी काम कर दिया है, मेरा निवेदन है कि मैं नहीं जानता, कहां तक सही है कहां तक गलत, लेकिन जयपुर डिवीजन में जो इस मामले में असमानता है, उस असमानता को आप दूर कीजिए। सड़कों के बारे में, सिंचाई के बारे में और दूसरी चीजों के बारे में जो असमानता चल रही है उसके सम्बन्ध में मंत्री महोदय से बात करेंगे। लेकिन आप समानता का बरताव करें और जो वाजिब मांग है उसको पूरा करें।

स्पोर्ट्स कौंसिल कहां काम करती है, इसका पता नहीं चलता है। मैंने इसकी एक्टि-विटीज देखी नहीं है। मैं अपने इलाके के लिए कहता हूं, मेरे इलाके के एक स्पोर्ट्स-मैन श्री रामसिंह ने राष्ट्रपति से अर्जुन अवार्ड प्राप्त किया है और सात कन्ट्रीज में रिप्रेजेंट किया है। लेकिन स्पोर्ट्स कौंसिल ने एक नया पैसा भी इस सब-डिवीजन पर खर्च नहीं किया है, वहां पर क्या एक्टि-विटीज हैं इसका इसे पता नहीं, प्रतिभाशाली स्पोर्ट्समैन कहां कहां पहुंच गये हैं यह भी पता नहीं। यह तो माउण्ट आबू में कैम्प लगाती है, यह सुनते हैं कि वहां अच्छा खाना पीना किया जाता है। लेकिन स्पोर्ट्स कौंसिल गांवों में कहां काम करती है। खाली यह जयपुर तक सीमित हो तो दूसरी बात है। कम से कम इसकी एक्टिविटीज को गांवों में पहुंचाया जाय और शहरों में ही नहीं रहे। क्योंकि स्पोर्ट्स कौंसिल है, तो जयपुर में, कालेज खुलेगा तो गोठेवाला के क्षेत्र में...

एक माननीय सदस्य : यूनिवर्सिटी भी।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : स्पोर्ट्स कौंसिल जयपुर में है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : 25 साल में एक नहीं खुला है। सही आंकड़े दो।

श्री गोपाल जोशी : मांग करने से गये क्या?

श्री सुरेशचन्द्र : विश्वविद्यालय जोधपुर में हो जायगा, जयपुर में हो जायगा . . .

श्री श्रीराम गोटेवाला : कोटपूतली में खुलवायें विश्व विद्यालय।

श्री सुरेशचन्द्र : कोटपूतली में न खोलें। केवल डिग्री क्लासेज खोल दें। आप शहरों में खोलते हैं तो भवन बनाते हैं, लेकिन गांव वाले भवन देते हैं, पैसा देते हैं, जन सहयोग देते हैं, उसके बावजूद भी नहीं खोलना चाहते हैं। यह आपका असमानता का आधार है, इसको जल्दी समाप्त कर दें।

एक बात और कहना चाहूंगा, इस बात का ख्याल रखें, 1972 से अब तक आप तीसरे शिक्षा मंत्री हैं। दो शिक्षा मंत्री ने कहा था कि डिग्री क्लासेज चालू करेंगे लेकिन उन्होंने नहीं की। नहीं की तो वह नहीं रहे। आप इस बात का ध्यान रखिए।

श्री मोहरसिंह : माननीय सदस्य ने भाषण में फर्माया कि जोधपुर में पोस्ट-ग्रेजुएट क्लासेज खोल दीं—यह निराधार बात है। आपके पहले शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने नहीं खोलीं। उनके पीछे थे, उन्होंने खोलीं। भवन के लिए पैसा देकर मुख्य मंत्री को कहा था।

श्री सुरेशचन्द्र : जन सहयोग देने से करते हैं तो हम भी देने को तैयार है।

श्री मोहरसिंह : उस वक्त आप शिक्षा मंत्री नहीं थे। उस वक्त वित्त मंत्री थे।

श्री सुरेशचन्द्र : उसमें वित्त की बात नहीं है।

श्री प्रतापसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा की डिमाण्ड के विषय में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि शिक्षा शास्त्रियों ने जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है उसमें दो लाख छात्रों के प्रवेश देने की बात कही गई है किन्तु छात्रों के नामांकन की जो बात कही गई है, अब तक कितनी संख्या में नामांकन हो गए हैं और इसी प्रकार से 3670 नये पद सृजन की बात कही गई है और कितने व्यक्तियों को पद सृजन से लाभ मिल सका है और कितना फायदा मिलने जा रहा है ऐसी कोई सूचना अब तक नहीं मिली है। मेरा निवेदन करना है कि गत वर्ष यूनिवर्सल एजूकेशन का प्रोग्राम चलाया गया था उसमें कितने परसेण्टेज में उपलब्धि हुई है इसका कोई ज्ञान नहीं होता और ऐसी हालत में यह कहना कि शिक्षा में प्रगति हुई है अथवा जो कार्य अब तक हाथ में लिए गये हैं उसमें हमको कितनी सफलता मिली है इसके लिए कोई बात तथ्यों के आधार पर कुछ भी नहीं निवेदन किया जा सकता तो इसका मुख्य कारण यही रहा है कि जितनी भी प्राइमरी स्कूलें गत वर्ष खोली गई थीं, उन सबका सीधा सम्बन्ध पंचायत समितियों से रहता है, और पंचायत समितियों के साथ

(श्री प्रताप सिंह)

में हमेशा शिक्षा विभाग का सौतेला व्यवहार रहा है, उसको हम सराहनीय नहीं कह सकते और यही कारण है कि हमारे प्रोग्राम विफल होते जा रहे हैं। आज पंचायत समितियों में जो भी अध्यापक लिये जाते हैं, मैं निश्चित तौर से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर अच्छे और योग्य अध्यापकों को नियुक्त नहीं किया जाता और जो गये गुजरे अध्यापक होते हैं उनको पंचायत समितियों में भेज दिया जाता है। और उनका जब वे गांवों में जाते हैं, तो गांव के लोगों में भी उनके प्रति कोई श्रद्धा नहीं होती है और न वे कोई सहयोग की भावना रखते हैं। उनको वहां पर पूरी तरह से सुविधाएं भी नहीं मिलती हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि जहां पर बुनियादी शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा का जो ग्रामीणों से सीधा ताल्लुक है वहां पर शिक्षा विभाग में बड़ा भेदभाव हो रहा है, जब कि अनेक माननीय सदस्यों ने निवेदन किया कि हमारी बुनियादी शिक्षा को सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए, मैं भी उनकी इस बात को पूरी तरह से समर्थन देता हूं और यह निवेदन करूंगा कि इस ओर विभाग को बहुत ही सक्रिय होकर और सावधानी से इसके लिए कोई कारगर कदम उठाकर इस फर्क को दूर करना चाहिए। इसके अलावा इस सन्दर्भ में यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी डिसीजन लिये जायं वह उचित समय पर लिए जायं और उनकी क्रियान्विति के लिए समय पर ही कार्यवाही की जाय तो अधिक उपयुक्त होगा।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि गत दो वर्षों से किशनगढ़ कन्या शाला के लिये एक टैम्पो की व्यवस्था की गई थी किन्तु केवल एक उसके चालक के अभाव में काफी अरसे से उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है और उसके लिये बार-बार निवेदन करने के बाद भी आंख मींचकर बैठे हुए हैं। इस बात को मैंने मन्त्री महोदय को और सूद साहब तक उसके आदेश भी पहुंचा दिये कि यह क्या बात है और ऐसा अब तक क्यों नहीं हो रहा है। मैं, मन्त्री महोदय से इसकी जानकारी जब वे अपना उत्तर देंगे तो इसका भी उत्तर देने की कृपा करेंगे।

जहां तक संस्कृत शिक्षा का प्रश्न है इसके लिए जो आपका बजट प्रस्तुत किया गया है उसमें काफी अच्छा प्रावधान इसके लिये रखा गया है। परन्तु इस के लिए भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में संस्कृत का एक अच्छा विद्यालय है उसको भी इस कार्य में जोड़ दिया जाय तो मैं समझता हूं काफी अच्छी संस्कृत की सेवा हो सकेगी और विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सकेगा। इसी प्रकार से किशनगढ़ के छात्रों की मांग है कि किशनगढ़ में पोस्ट-ग्रेजुएट कालेज होना चाहिये उसको पूरा किया जाना चाहिए, क्योंकि, वह एक वाजिब मांग है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री रतीराम यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही सूक्ष्म शब्दों में, चूंकि समय बहुत कम है, कुछ बातें आपके सामने रखने का प्रयत्न करूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक शिक्षा के विकास का प्रश्न है, मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान तो शिक्षा की दृष्टि से एक पिछड़ा हुआ प्रदेश है उसके लिए इतनी सी मांग रखना और इतने से धन का प्रावधान रखना बहुत ही अपर्याप्त

(श्री रतीराम यादव)

है इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि और अधिक धन इसके लिए रखा जाता तो अच्छा होता। लेकिन इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि अगर राजस्थान के पिछड़ेपन को हमको दूर करना है, हमको वास्तव में तरक्की शिक्षा के क्षेत्र में करनी है और एक नये समाज का निर्माण करना है तो हमको एक नया शिक्षा कानून बनाना पड़ेगा जो उन सारी कमजोरियों को दूर कर सके और शिक्षा में आमूल-चूल परिवर्तन ला सके। वर्तमान में जो हमारा शिक्षा का कानून है, उपाध्यक्ष महोदय, वह बहुत पुराना कानून है और उसके अन्दर निश्चित रूप से सुधार होना जरूरी है। हम गत वर्ष से सुनते आ रहे हैं कि नेपालसिंह तंवर ने एक नया शिक्षा बिल तैयार भी किया है, उसको सबमिट भी किया है और हमारे सामने आने वाला है, यह भी सुनने में आ गया कि सदन में पिछले सदन में आ रहा है, फिर यह आया कि बजट सेशन में आयेगा लेकिन मैं नहीं समझ सका कि आखिर उस बिल का क्या हो रहा है। उसके बारे में कोई डिसीजन भी लिया गया है अथवा नहीं लिया गया है, इसलिए मैं, माननीय शिक्षा मन्त्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि नये शिक्षा कानून को शीघ्र ही स्थापित किया जाये और राजस्थान में शिक्षा में परिवर्तन लाने के लिये इस ओर शीघ्र ही ध्यान दिया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी बात यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक कोई नया शिक्षा कानून बन कर तैयार हो और नया सुधार किया जाये, शिक्षा में कोई क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिये कदम उठाये जायें, तब तक फौरी तौर से कुछ समस्याओं का हल किया जाना चाहिये और शिक्षा के क्षेत्र में जो शिक्षा के मुख्य रूप से अंग हैं, जो छात्र हमारे राष्ट्र का निर्माण करते हैं और विद्यार्थी जो शिक्षा प्राप्त करने के बाद आगे आकर हमारे राष्ट्र का नया निर्माण करना चाहते हैं उनकी भी कई समस्याएं हैं, उनकी तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिये। और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम न्यूनतम समस्याओं को तो फौरी तौर पर ही सही, दूर करने की कोशिश की जानी चाहिये। शिक्षकों की भी कई समस्याएं हैं, सेन्ट्रल स्कूल के टीचर्स हैं और हमारे राज्य के अध्यापक हैं, उनके वेतनमानों में भारी अन्तर है जिससे भी हमारे शिक्षकों में भारी असन्तोष की भावना है, इस पर विचार किया जाना चाहिये। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि जो छोटे-छोटे स्कूल स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे हैं या म्यूनिसिपैलिटीज के द्वारा चलाये जा रहे हैं या हमारी पंचायत समितियां चलाती हैं उनके टीचर्स के साथ और राजकीय स्कूलों में जो टीचर्स काम करते हैं दोनों में बड़ा भेदभाव रखा जाता है, उन टीचर्स को मेडीकल एड नहीं मिलती है, वे उस पैसे को रिइम्बर्स नहीं करा सकते हैं। इसी तरह से पेन्शन और ग्रेच्युटी का भी जो लाभ मिलता है वह उनको नहीं मिल पाता है इसलिये उनमें असन्तोष बढ़ता जा रहा है और यही कारण है कि पंचायत समितियों के जो शिक्षक हैं, उनका स्तर दिन-पर-दिन गिरता जा रहा है। इसी तरह से सीनियर टीचर्स की ग्रेड की समस्याएं हैं, उनकी भी मांगे हैं। कालेजों के

(श्री रतीराम यादव)

जो प्राध्यापक हैं उनकी भी कई समस्याएं हैं, उनके प्रति भी हमारे शिक्षा विभाग का व्यवहार काफी गलत रहा है। मिसाल के तौर पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि श्री ईयर्स डिग्री कालेज के फर्स्ट ईयर में हिन्दी और अंग्रेजी दोनों ही विषय अनिवार्य रूप से पढ़ाये जाते हैं और यूनिवर्सिटीज के जो नियम हैं उनके अनुसार 6 घंटे पर पेपर, हिन्दी और अंग्रेजी विषयों को वीकली मिलने चाहिएं लेकिन शिक्षा विभाग क्या कर रहा है हिन्दी वालों को तीन घंटे और अंग्रेजी पढ़ाने के लिये 6 घंटे दिये जाते हैं और स्थिति में अगर हम यह कहें कि हमने अपना उद्देश्य हिन्दी की तरक्की करने के लिये बना रखा है, हम हिन्दी में ही सारा काम करना चाहते हैं लेकिन वास्तव में हो रहा यह है कि हिन्दी के लिये यूनिवर्सिटीज के निर्देशन के बावजूद भी केवल तीन घंटे दिये जाते हैं और अंग्रेजी के लिये 6 घंटे दिये जा रहे हैं।

दूसरी बात जो मैं अब यहां पर निवेदन करना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, वह है हमारे यहां पर क्लासेज के बारे में। हमारे यहां पर एम. ए. की तीन क्लासेज तो हैं अंग्रेजी की और सात क्लासेज हैं हिन्दी की। लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य होगा उपाध्यक्ष महोदय कि टीचर्स की संख्या अंग्रेजी की ज्यादा है और हिन्दी में जब कि लड़कों की संख्या ज्यादा है लेकिन प्राध्यापकों की संख्या हिन्दी में कम है। इससे लड़कों की पढ़ाई नहीं हो पाती है इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि वह इस बारे में व्यवस्था करे।

अब उपाध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा मन्त्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि वह हमारे पूरे राजस्थान प्रान्त में सभी को साक्षर बनायें। और इस के लिये एक कानून ऐसा बनायें कि जिससे हमारे ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में जो बच्चे 6 से लेकर 11 साल के हों उनके लिये प्राईमरी एजूकेशन को कम्पलसरी बना दिया जावे। आप उनके लिये प्राईमरी एजूकेशन को अनिवार्य शिक्षा बना दीजिये। ताकि हमारे यहां पर कोई भी व्यक्ति बिना पढ़ा लिखा नहीं रहे।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं थोड़ा हमारे प्रदेश में जो निजी शिक्षण संस्थायें हैं उनके बारे में कुछ निवेदन करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर जो निजी शिक्षण संस्थायें हैं उनमें काम करने वाले शिक्षकों की हालत बहुत ही खराब है। वैसे तो निजी शिक्षण संस्थाओं के अध्यापकों के लिये पिछले सत्र में एक भी प्रश्न पूछा गया था तो उसके उत्तर में मन्त्री महोदय ने अपने भाषण के दौरान यह कहा कि आइन्दा से निजी शिक्षण संस्थाओं में काम करने वाले अध्यापकों को तनख्वाहें चैक द्वारा दिलाई जायेंगी। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह मेरा तजुर्बा है कि आपने तो चैक की व्यवस्था करादी लेकिन उसमें भी अभी तक घोटाले बाजी बन्द नहीं हुई है और बेचारे उन अध्यापकों को तनख्वाहें चैक के बदले कम दी जाती हैं। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि प्राईवेट शिक्षण संस्थाओं में आज भी टीचर्स को तनख्वाहें कम दी जाती हैं। इसके लिये मैं यह सुझाव देना चाहता हूं

(श्री रतीराम यादव)

कि अगर आप वास्तव में उन निजी शिक्षण संस्थाओं के अध्यापकों की हालत सुधारना चाहते हैं या उनकी जिन्दगी सुधार करना ही चाहते हैं आप वास्तव में यह चाहते हैं कि उन प्राईवेट शिक्षण संस्थाओं से अच्छे बच्चे पढ़ लिख कर निकलें तो आप को वहां पर काम करने वाले अध्यापकों की जिन्दगी सुधारनी पड़ेगी। मेरा निवेदन यह है कि यह जो प्राईवेट शिक्षण संस्थायें राजस्थान में हैं उनका राष्ट्रीयकरण कर लिया जाय। उपाध्यक्ष महोदय यह शिक्षण संस्थायें ज्यादा नहीं है करीब 1200 के करीब होंगी कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं है अगर आप इन्हें अपने हाथ में ले लें तो उन अध्यापकों का भला हो सकता है अगर आप की वित्तीय हालत ठीक नहीं है। और आप बड़े पैमाने पर इनको एक साथ हाथ में नहीं ले सकते हैं तो इसके लिये आपको मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि आप पहले साल 50 साल स्कूलों को हाथ में ले लीजिये या एक साथ सौ साल स्कूलों को चुन लीजिये फिर उसके अगले साल और इसी प्रकार पचास या सौ स्कूलों को हाथ में ले लें तो इस तरह थोड़े असें में यह सभी प्राइवेट शिक्षण संस्थायें आपके हाथ में आ जायेंगी आपको कोई नुकसान भी नहीं होने वाला है। और वहां पर जो काम करने वाले अध्यापक हैं, उनकी जिन्दगी भी सुधर जायेगी। वैसे भी आप हर साल स्कूलें नयी खोलते ही हैं उनके बदले में उन्हें रखलें। यों भी तो आप उन स्कूलों को कुछ न कुछ एड देते फिर ही उनको आप अगर हाथ में ले लें तो आपको क्या तकलीफ हो सकती है। मैं आपको पड़ोस के प्रान्त की मिसाल दे देता हूं दिल्ली में ऐसा किया गया है। आप भी उसी तरह करलें।

(समय समाप्ति-सूचक-घण्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं जल्दी जल्दी समाप्त कर रहा हूं। दूसरी बात जो मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि आप प्राईवेट इन्स्टीट्यूशन्स को एड तो देते ही हैं उसको आप इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स के पास जमा करावें और जो प्राईवेट इन्स्टीट्यूशन्स अपने बच्चों से फीस लेते हैं उन्हें आप आदेश दीजिये कि तुम्हें यह अध्यापकों की तनख्वाहों के लिए इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स के पास जमा करानी होगी ताकि उन प्राईवेट शिक्षण संस्थाओं के जो अध्यापक हैं उनको वहीं से तनख्वाह मिले। अगर मेनेजमेन्ट वहां पर पैसे जमा करा देते हैं तो उन शिक्षण संस्थाओं के अध्यापकों को तनख्वाहें बराबर मिलती रहेंगी और कोई उन अध्यापकों को दिक्कत नहीं होगी। यह सिस्टम आप अगर लागू कर देंगे तो उनको राहत मिलेगी। और जो आज घोटाले बाजी वहां पर हो रही है वह समाप्त हो जायेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह मैं एक और बात शिक्षा मन्त्री के नोटिस में लाना चाहता हूं कि आज जो हमारे शिक्षकों का शिक्षक संगठन है राजस्थान शिक्षक संघ है उसके प्रति हमारे मन्त्री जी का व्यवहार ठीक नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उपाध्यक्ष महोदय मन्त्री महोदय का रवैया उपेक्षापूर्ण है। आज जब शिक्षक संघ के रिप्रजेन्टेटिव्ज अपनी कठिनाइयों को लेकर मन्त्री महोदय के पास लेकर जाते हैं तो मन्त्री महोदय उनसे ठीक तरह से

(श्री रतीराम यादव)

बात-चीत नहीं करते हैं और उनसे मिलते तक नहीं। इसलिये मेरा निवेदन है कि मन्त्री महोदय को चाहिए कि उनके रुख में परिवर्तन करें। उपाध्यक्ष महोदय अभी शिक्षक संघ ने शिक्षा मन्त्री को मांग-पत्र दिया है और आपने अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं की।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मन्त्री को चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर उनकी मांगों का सही हल जल्दी से जल्दी नहीं किया तो उपाध्यक्ष महोदय जल्दी ही राजस्थान के शिक्षक आन्दोलन करने वाले हैं। उपाध्यक्ष महोदय परीक्षायें आने वाली हैं और आपने उनकी मांगों पर कोई सहानुभूति पूर्ण कदम नहीं उठाये तो शिक्षक आन्दोलन करेंगे क्या मन्त्री महोदय के पास इस भयंकर स्थिति का सामना करने के लिये कोई रास्ता है? और अगर नहीं है तो आप उनकी वाजिब बातों को क्यों नहीं मान रहे हैं?

(समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी)

बस एक बात और कह कर समाप्त कर रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वह अध्यापकों की मांगों के लिये अपने नौकरशाही के भरोसे नहीं रहे। आप अपने अध्यापकों को नौकरशाही के भरोसे और दया पर उन्हें नहीं छोड़ें। अगर आप उनको इस नौकरशाही के भरोसे छोड़ेंगे तो आपका अध्यापक वर्ग बरबाद हो जायेगा। मैं आपको अपने नौकरशाही की एक दो मिसाल अलवर जिले की देना चाहूंगा आपके शिक्षक समाज को अपनी नौकरशाही के भरोसे छोड़ने के कारण हमारे अलवर जिले में एक अध्यापक श्री भीमसेन तंवर को डेढ़ साल तक बिना किसी कसूर के सस्पेन्ड रहना पड़ा। उपाध्यक्ष महोदय उसका कोई कसूर नहीं था। उसने नीचे से लेकर ऊपर तक आपके इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल के खिलाफ में डाईरेक्टर, एजूकेशन सैक्रेट्री और चीफ सैक्रेट्री तक पुकार की। जब वहां पर कोई सुनवाई नहीं हुई तो उसने मन्त्री महोदय और मुख्य मन्त्री महोदय तक पुकार की। उपाध्यक्ष महोदय मैंने भी उस क्षेत्र का विधायक होने के नाते मुख्य सचिव को पत्र लिखा लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अन्त में मैंने मन्त्री महोदय को पत्र लिखा उनसे मिला और इसके लिये जो कार्यवाही हुई है उसके पोथीना मेरे पास अभी भी मौजूद हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक-लम्बी-घन्टी)

बस समाप्त कर ही रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है आप देखिए तो सही कि न चीफ सैक्रेट्री साहब ने सुना और मन्त्री महोदय तक पुकार की मुख्य मन्त्री महोदय तक पुकार की गयी और अन्त में उस व्यक्ति के खिलाफ कोई चार्ज नहीं होने के कारण उस व्यक्ति को डेढ़ साल बाद सात जनवरी को उसे रिइन्स्टेट किया गया। उपाध्यक्ष महोदय उसका कोई कसूर नहीं था और आपकी नौकरशाही ने उसको सस्पेन्ड कर दिया। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आपने बिना कसूर एक अध्यापक को सस्पेन्ड डेढ़ साल तक रखा तो क्या आपने उस व्यक्ति को जिसने उस बेकसूर व्यक्ति को सस्पेन्ड किया उसके खिलाफ में

(श्री रतीराम यादव)
कोई एक्शन लिया ? और अगर नहीं लिया तो क्यों नहीं लिया ?

(समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ एकाध मिनट बस। उपाध्यक्ष महोदय, भोमसिंह कोर्ट में गया। इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल घीसालाल को तलब किया गया वह कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ उस इन्सपेक्टर को आपने अब प्रोमोशन देकर जयपुर में बुला लिया है। यह है आपका न्याय। आपने उस व्यक्ति को जिसने बेकसूर व्यक्ति को सस्पेन्ड किया उसको जयपुर में प्रमोशन दे दिया। उपाध्यक्ष महोदय, उस घीसालाल के कोर्ट में तलब होने पर नहीं जाने के कारण कोर्ट ने कुर्की निकाल दी जिससे कि अलवर इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स का फर्नीचर, टाइप राइटर, मेज कुर्सी सभी नीलाम कर दिया गया। क्या आप ऐसी राज्य सरकार की बेइज्जती बरदाश्त कर सकते हैं ? इतनी बड़ी राज्य सरकार की तौहीन शायद पहले इस नौकरशाही ने कभी नहीं की होगी।

इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय आज इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स का वहां पर ऐसा रवैया है कि अगर शिक्षक संघ वाले लोग अपनी कठिनाइयों को लेकर उनके पास जाते हैं तो उनकी वहां पिटाई की जाती है अगर उसकी शिकायत की जाती है तो उसके खिलाफ में एक्शन आप लेते नहीं हैं यह कितने शर्म की बात है कि बेचारे शिक्षक संघ वाले अपनी कठिनाइयों को लेकर जाते हैं वहां उनके साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार किया जाता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप इन बेचारों को आपकी नौकरशाही से बचाइये। इनकी रक्षा कीजिये। अगर आप इस तरह की कार्यवाही करते हैं तो मुझे खुशी होगी। मुझे खुशी होगी अगर आप अपनी राठौड़ी की शक्ति का प्रदर्शन इस नौकरशाही के विरुद्ध अंकुश लगाने के लिये काम में लें। अगर आप अपनी राठौड़ी की शक्ति का प्रदर्शन इस नौकरशाही के खिलाफ में लेंगे तो अध्यापक वर्ग आपका हमेशा ऋणी रहेगा। राजस्थान का शिक्षक संघ आपका शुक्र गुजार रहेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : आपको काफी समय हो गया है अब समाप्त करें।

श्री रतीराम यादव : उपाध्यक्ष महोदय, बस एक बात कह कर समाप्त कर रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय मैं अपने क्षेत्र की एक बात रखना चाहता हूं। हमारे राजस्थान के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री श्री बरकतुल्लाखां ने यहां सदन में एक आश्वासन दिया था कि एक प्रश्न के जवाब में कि हमारे क्षेत्र में कृषि कालेज खोली जायेगी लेकिन वह कृषि कॉलेज आज तक वहां पर नहीं खुला है। अगर आप स्वर्गीय मुख्य मन्त्री की आत्मा को शान्ति प्रदान करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उनकी आत्मा को सन्तोष मिले तो आप वहां पर कृषि कालेज खोलने की उनकी बात को पूरा करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री माणकचन्द सोगाना।

श्री माणकचन्द सोगानी (अजमेर पूर्व): उपाध्यक्ष महोदय, आज काफी चर्चा हो चुकी है, मैं केवल कोई बात रिपीट नहीं करते हुए एक दो मेरे सुझाव हैं उन्हें आपके

(श्री माणकचन्द सोगानी)
समक्ष निवेदन कर देता हूं। एक सुझाव तो मेरा यह है कि साल भर में जो इम्तिहान होता है, जो छात्र फेल हो जाते हैं उसमें ऐसा देखा गया है कि आज जो अच्छे से अच्छा छात्र है बीमारी की वजह से पिछले दिनों में पढ़ाई नहीं कर सका और वह फेल हो गया, उसको साल भर तक दुबारा इन्तजार करने में खराब करना पड़ता है। मेरा यह सुझाव है कि इस पर गौर करें और जिस तरह छः महीने के अन्दर और दूसरे इम्तिहान होते हैं, इसी तरह से हो सकें तो उसमें काम हो सकता है।

दूसरा मेरा सुझाव यह है कि स्पोर्टस् कौंसिल के लिए एक विधायक महोदय ने भी ध्यान आकर्षित किया था। आज के दिन में जबकि अपने एजूकेशन डिपार्टमेंट के मार्फत स्पोर्ट्स की मदद मिलती है तो यह जहां कहीं भी होते हैं, एक उदाहरण के रूप में पेश कर रहा हूं कि अगर क्रिकेट का मैच शुरू हुआ तो हजारों बच्चे बूढ़े तमाम रेडियो के सामने अपना सब काम को छोड़ कर सुनेंगे। तो ऐसी जगहों पर अपना इतना ऊंचा स्तर करना चाहिए कि जो लोग खेल में चतुर हैं उनको बाकायदा प्रोफेशनल टाईप टर्न करके उनको मदद दी जाय ताकि यह चीज ख्याति प्राप्त कर सके और पूरे देश के लिए ख्याति हो, यह दूसरा सुझाव है।

आगे एक बात और मैंने देखी कि जो हम एम. एल. एज. को भुगतनी पड़ती है और जब कभी ट्रांसफर होते हैं इसके अन्दर एक दफा चाहे जितना टाइम लगे लगा दें और जहां पर कोई पति हैं और कहीं पर पत्नि हैं, रोजमर्रा की दिक्कत है...

एक माननीय सदस्य : कहीं पर दूसरी पत्नी है। दो पत्नियां हैं।

श्री माणकचन्द सोगानी : ऐसा तो अब कोई कानून ही नहीं है कि दो पत्नी रख सकें। तो मेरा यह कहना था कि इस तरह अपना रोज का काम निकल आया है कि शिक्षा मंत्रीजी से मिलें और इस वेदना पर जाकर ज्ञापन दें। कम से कम इस चीज को ध्यान में रखें कि यह जो एम. एल. एज. का काम निकल आया है वह भी सरल हो जाएगा और आपके पास भी आने वालों की संख्या कम हो जाएगी। इसलिए इसमें जितना टाइम लगे इस काम को खत्म करके सरकार को समाधान कर देना चाहिए।...

श्री श्रीराम गोटेवाला : इस वेदना का तो ध्यान ही रखें साहब।

श्री माणकचन्द सोगानी : एक और बात है, हमारे अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कहा था, मैं थोड़े में दोहरा रहा हूं। सवाल यह है कि अटेंडेंस के मामले में विद्यार्थी बड़े उत्तेजित थे। वह कहने लगे कि हमारे अटेंडेंस के प्रश्न को आप थोड़ी शिथिलता से लेवें। क्या यह उचित है कि अटेंडेंस के मामले में बिल्कुल ही छूट दी जावे और जो प्रोफेसर अच्छा पढ़ाते हैं उनकी क्लास में अपने आप ही अधिक विद्यार्थी पहुंचेंगे। इतना जरूर होना चाहिए कि जो प्रोफेसर अच्छा पढ़ाते हैं उनके जो वेतनमान बने हुए हैं उनको कुछ बोनस इस बात का मिले कि उनकी कक्षा में ज्यादा विद्यार्थी मौजूद हैं। इसके ऊपर आप ध्यान दें।

इसके बाद कुछ चीजें आपने जो प्रगति विवरण में बताई, वह बड़ी सुन्दर हैं। एक

(श्री माणकचन्द सोगानी)

तो आपने संस्कृत के बारे में बताई कि संस्कृति के अन्दर बहुत उन्नति हो रही है तो यह आपकी बड़ी प्रशंसा की बात है। मैं आपकी सूचना के लिए और सराहना के लिए पढ़ देता हूं :

"इस वर्ष राजकीय संस्कृत कालेज, अजमेर को शास्त्री स्तर की मान्यता विश्वविद्यालय द्वारा दे दी गई है"

यह बहुत खुशी की बात है। आगे इसमें हैं :

'राजस्थान एन. सी. सी. विभाग की एक प्रशंसनीय उपलब्धि इस वर्ष यह रही है कि लड़कियों का वायु सेना की ग्लाईडिंग एवं वायु सेना के अन्य विषयों पर प्रशिक्षण हेतु एक स्क्वाड्रन वनस्थली में आरम्भ किया गया जिसका उद्घाटन एयर चीफ मार्शल ने किया"

सो यह राजस्थान की सुन्दर बात है इनको तारीफ करनी पड़ेगी। विद्या से चरित्र निर्माण होना चाहिए मगर आज तो बिल्कुल उल्टा हो रहा है। आज की शिक्षा से चरित्र निर्माण नहीं होता। होता क्या है कि घर के अन्दर बच्चा ज्योंही छः साल का हुआ, पांच साल का हुआ और उसको स्कूल में भेजकर माता पिता यह समझ लेते हैं कि जिम्मेदारी पूरी हो गई। उसके बाद फिर पूरी जिम्मेदारी स्कूलों पर आकर पड़ जाती है और वह माता पिता अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते, उनकी देख-रेख नहीं कर पाते और बच्चों को स्कूल भेज देते हैं। तो वहां पर बच्चों के साथ क्या होता है यह यहां पर बैठे हुए सभी माता पिता अपने आप सोच लें, मैंने जिक्र कर दिया है। और आखिर में कालेज की स्टेज पर एक चीज आती है जो बताना चाहता हूं कि हैल्दी माईण्ड इन हैल्दी बोडी। यह हमारे तमाम कालेज स्टेज पर पूर्ण रूप से विकसित होकर आती है। यह जो कालेजों में पढ़ने वाले लोग हैं उनको इस तरफ ध्यान देना चाहिए। उनके लिए यह ध्यान जरूरी है कि आज विद्या के जरिये हम नहीं तो अमेरिका वाले ही सही, हम भी कभी चांद पर पहुंच सकते हैं जैसे वे पहुंच गए। हमारे यहां पर भी पोकरण में एटम विस्फोट किया गया है। इसलिए जो अंग्रेजों की, अमेरिका की पाश्चात्य देशों की जो कुछ भी अच्छी चीज हैं उनका अनुकरण करना चाहिए और वह आमूल-चूल परिवर्तन में नहीं निकल जाय।

श्री उपाध्यक्ष : आप तो पुरातन चीजों के प्रेमी हैं।

श्री माणकचन्द सोगानी : आपका बहुत 2 धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शिक्षा मंत्रीजी।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : उपाध्यक्ष महोदय, पांच मिनिट के लिए सुझाव के रूप में अर्ज करना चाहता हूं ...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शिक्षा मंत्रीजी।

श्री खेतसिंह (शिक्षा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सभी सदस्यों का बहुत ही आभारी हूं। आज कुल मिलाकर 32 माननीय सदस्यों ने आज की इस मांग पर अपने विचार व्यक्त किए और शिक्षा

(श्री खेत सिंह)

पद्धति के बारे में तथा अपने क्षेत्रों की समस्याओं के बारे में यहां पर अपने 2 विचार प्रकट किए हैं। मैं खास तौर से उन माननीय सदस्यों का और भी आभारी हूं कि जिन्होंने यह सुझाव भी दिया कि आप शिक्षा के अन्दर किसी प्रकार का कुछ परिवर्तन करें कि जिससे आज के समय के अनुसार हम शिक्षा के अन्दर कुछ परिवर्तन ला सकें। खास तौर से मैं दो एक विधायकों के बारे में जो आपने इस विषय में बात कही है, पहले मुद्दे पर बात कर लेता हूं। खास तौर से सुजानगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने और भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह प्रश्न उठाया था कि आप हमें यह बतलाने का प्रयत्न कीजिए कि आपके दिमाग में क्या योजना है और आप किस प्रकार से शिक्षा पद्धति को बदलना चाहते हैं? मैं आपसे उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी मान्यता यह है कि जैसा आप चाहते हैं कि मैकाले पद्धति बहुत त्रुटिपूर्ण है और उसको हटा देना चाहिए और नया सिस्टम इवोल्व करना चाहिए, इसके फेवर में मैं नहीं हूं। मेरी ऐसी मान्यता है कि जिस सिस्टम से आप सब पढ़े हैं, आज विधान सभा के सदस्य बने हैं, इस सिस्टम से एक से एक आला वैज्ञानिक हुए हैं। इस पढ़ाई के पढ़ने के बाद ही अच्छे से अच्छे एथलेटिक्स, अच्छे से अच्छे फिलोसोफर्स, लायर्स हुए हैं, अच्छे व्यावसायिक हुए हैं और अच्छे साहित्यकार हुए हैं और हर देश के अन्दर इसी सिस्टम से आज भारत के अन्दर भी जो कुछ हुआ है वह मेरे पूर्व वक्ता महोदय ने कहा कि हमारे यहां पर भी वैज्ञानिक हुए हैं जो दुनियां के अच्छे से अच्छे वैज्ञानिकों का मुकाबला कर सकते हैं। एटमबम बना लिया और सब कुछ हुआ है। इसलिए मैं माननीय सदस्यों की इस बात को मानता हूं कि हमें समय के अनुसार कुछ चेंजेज अवश्य लाने चाहिए लेकिन यह कहना कि यह पद्धति बिलकुल ही गलत है या जो माननीय सदस्य यह कहते हैं कि इस शिक्षा पद्धति में आमूल-चूल परिवर्तन की तुरन्त आवश्यकता है, मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैं आपसे, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमने इस बात को बहुत सोचा और अभी पिछले महीने के अन्दर ही हमारे भारत सरकार के केन्द्रीय शिक्षा मंत्री जी ने समस्त भारतवर्ष के शिक्षा मंत्रियों की बैठक बुलाई थी जिसमें भारत के शिक्षा मंत्री सम्मिलित हुए और हमने इस विषय पर बहुत विस्तार से दो रोज तक विचार विमर्श किया। मैं इस बात को मानता हूं कि आज सभी एक बात को मानने वाले हैं कि हमें जरूर कुछ न कुछ परिवर्तन लाना चाहिए, लेकिन परिवर्तन क्या हो, किस प्रकार का हो, उसमें कितना व्यय करना होगा, यह सारी बातें जब हम सोचते हैं तो हमें अभी तक जैसा कि भरतपुर से जाने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि बीमारी तो मालूम हो गई लेकिन इलाज करने में समय लगेगा। हकीकत यह है कि हम यह जरूर चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा शिक्षा को व्यवसायोन्मुखी करें। हम जरूर चाहते हैं कि आज जिस प्रकार से हजारों की तादाद के अन्दर हमारे मैट्रिक स्टूडेंट्स निकलते हैं और चूंकि उनका भविष्य न होने के कारण वह लड़के कालेजों में जाते हैं, वहां पर इस प्रकार से पढ़ते रहते हैं और उसके बाद भी उन्हें कोई भविष्य नहीं दीखने के कारण आज अनु-

(श्री खेत सिंह)

शासनहीनता, उनके दिल के अन्दर एक उपद्रव की भावनाएं जो बढ़ती हैं, वह सारी बातें हैं। लेकिन हमने इन सारी समस्याओं को समझते हुए यह तय किया कि हम पूरे भारत के अन्दर एक सा सिस्टम इवोल्व्ड करें। जैसा एक प्रश्न के उत्तर में मैंने निवेदन किया था कि हम यह चाहते हैं कि 10 प्लस 2 प्लस 3 जो भारत के शिक्षा मंत्रियों ने इस बात को माना है, हम भी मानने जा रहे हैं। इसके तहत हमने यह तय किया है कि दसवीं तक सभी को साक्षर ज्ञान अवश्य हो जाय और अन्य विषयों का भी ज्ञान दें। क्योंकि वह दसवीं पास कर ले उसके बाद में जो अच्छे छात्र हैं, पढ़ाई में होशियार हैं, आगे जाकर विज्ञान के अन्दर, कोमर्स के अन्दर, आर्ट्स के अन्दर बहुत ही होशियार छात्र हैं उनके लिए हम यह सोचते हैं कि उनको आगे पढ़ाई करना चाहिए लेकिन जो माध्यमिक स्तर पर सैकिंड डिविजनर हैं, थर्ड डिविजनर हैं उनको व्यवसायोन्मुखी शिक्षा में जाना चाहिए और कोई न कोई ट्रेड पकड़ लें, उसके अन्दर निपुण हो जायं तो निश्चित रूप से यह साक्षर ज्ञान हो जाय और दूसरा ज्ञान हो जाय तो वह अपने व्यवसाय को अच्छी तरह से चला सकता है। उसके लिए हम प्रयत्नशील हैं और हम चाहते हैं कि दो वर्ष के अन्दर हम ऐसे कोर्सेज शुरू करें और ऐसे कोर्सेज बढ़ायें। पिछले वर्ष भी इस ओर प्रयत्न किया गया और हमने वोकेशनल एजूकेशन शुरू किया है...

हमारे यहां आज दर्जियों की बहुत कमी है। आज आप देखेंगे और कोई भी कपड़ा सिलायेंगे तो आज उसकी रेट बहुत हाई हैं इसलिए हमने सोचा कि एक ड्रेस डिजाइनिंग और टेलरिंग का कोर्स शुरू करें और वह हमने बीकानेर में शुरू किया है। इसके अलावा आज हमारा काफी विद्युतीकरण हुआ है और होता ही जा रहा है। गांवों में जगह जगह बिजली दी जा रही है और आज काश्तकार बिजली से लाभ उठाते हुए अपनी फसलों में पानी दे रहे हैं। लेकिन आज आम शिकायत यह है कि उनकी बिजली की मोटरें जल जाती हैं। हमने इसलिए सोचा कि एक इलेक्ट्रिक मोटर वाइंडिंग का कोर्स भी शुरू करें और ऐसे लड़कों को गांवों में भेजें और वह गांवों में ही दुकानें लगायें और काश्तकारों की मोटरें खराब होने पर तुरन्त ही उसकी वाइन्डिंग वहीं कर दें और उससे काश्तकारों को भी नुकसान नहीं होगा, उनका काम भी वहीं पर हो जायेगा और वह अपनी फसलों को भी समय पर पानी पिला सकेंगे और उधर लड़कों को भी रोजगार मिल जायेगा। इसके अलावा हमने सोचा है कि स्कूटर और थ्री व्हीलर्स का काम भी बहुत बढ़ता जा रहा है और हम इस ओर सोच रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा ऐसे वोकेशनल कोर्सेज हों जिनकी मार्फत हम ऐसे विद्यार्थियों को डिफरेन्ट कोर्सेज में डाल दें जैसे कि हमने अजमेर में एक कोर्स रेडियो एण्ड ट्रांजिस्टर्स की रिपेयर्स का शुरू किया है। इसकी बहुत मांग है। इसी प्रकार से और नये नये कोर्सेज के लिए सोच रहे हैं। किस जिले में क्या रा मेटेरियल होगा, किस जिले में कौन सा कोर्स खोलने से जल्दी से जल्दी लड़कों को जाब भी मिल जायेगा और लोगों की नीड्स को भी पूरा कर लेंगे—इसके लिए सर्वे करना शुरू कर दिया है और हम उस सर्वे के

(श्री खेत सिंह)

आधार पर आने वाले वर्षों में और नये नये कोर्सेज शुरू करेंगे जिससे हम सोचते है हम व्यावसायिक शिक्षा को आगे से आगे बढ़ायेंगे तो निश्चित रूप से हमारे वह छात्र जो कि यूनीवर्सिटीज की शिक्षा में सफल नहीं हो सकते उनको हम डाई-वरशन देना चाहते हैं जिससे सही माने में वह समाज के लिए उपयोगी हो जायें और एक प्रकार से समाज की धरोहर बन जायें और जो आज समाज के ऊपर और अपने ही अभिभावकों पर बोझा बने हुए हैं वह बोझा न होकर धरोहर हो जायें, इस और हमारा प्रयास है।

मैं यहां यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि सुजानगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि आपने जो कमेटी बनाई है उसका क्या प्रयोजन है। आपने यह भी पूछा कि उस कमेटी की टर्म्स एण्ड कन्डीशन क्या हैं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी उस कमेटी की एक ही मन्शा है और वह यह है कि हम वोकेशनलाइजेशन्स किस प्रकार से ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं, किस प्रकार से यहां की जनता की मांग को पूरा कर सकते है और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने उस कमेटी के सामने चार, पांच टर्म्स रखी हैं जो कि मैं पढ़ कर सुना देता हूं। इस कमेटी के चेयरमैन श्री मन्नारायणजी हैं और मेम्बर श्री कोठारीजी हैं और भी मेम्बर हम इसके अन्दर को-आप्ट कर सकते हैं और हम तो चाहेंगे कि सदन के माननीय सदस्यों में से जो भी इच्छुक हों हम आपको भी आमन्त्रित करते हैं कि आप भी अपने सुझाव दें। आपके पास यदि समय नहीं है तो आप लिखित में अपने सुझाव भेज सकते हैं तो भी हम आपके सुझावों पर विचार करेंगे और कुल मिलाकर चाहते है कि आपकी और फीलिंग यह है कि राजस्थान के अन्दर यह प्रवृत्ति है कि राजस्थान का भविष्य अन्धकार में होने के कारण उनको आगे क्या जाब मिल सकते हैं उस ओर आप भी सुझाव देंगे तो इस कमेटी को हमने यह कहा है कि शिक्षा को व्यवसायोन्मुखी किस प्रकार से किया जाये, परीक्षा पद्धति में किस प्रकार के सुधार लाये जायें, शारीरिक शिक्षा को किस प्रकार से महत्वपूर्ण बनाया जाये? इस तरह की बातें हमने उस कमेटी को कहीं हैं। उस कमेटी की दो तीन मीटिंग भी हो चुकी हैं। जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि आप इस प्रकार की कमेटीज बनाते रहते है और यह सही भी है कि भूत में ऐसी कमेटियां बनी हैं लेकिन उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि हम चाहते हैं कि कमेटी की जो रिपोर्ट आये और हमने कमेटी को साफ कहा कि हमारे फाइनेन्सेस बहुत लिमिटेड हैं और उनको ध्यान में रखते हुए ही हम चाहेंगे कि कमेटी अपनी रिपोर्ट दे। हम ऐसा नहीं चाहते कि कमेटी की रिपोर्ट आ जाये और उसमें करोड़ों रुपयों का इनवाल्वमेंट हो और उनको हम पूरा न कर सकें। तो ऐसी रिपोर्ट जो भी आई है वह इसी तरह से कोल्ड स्टोरेज में जाती रही हैं। इसलिए हम जल्दी से जल्दी उनको क्रियान्वित कर सकें इसलिए हमने 3 महीने का समय दिया है और हम सोचते हैं कि रिपोर्ट के आने के बाद कुछ इस ओर प्रयास प्रारम्भ करेंगे। हम यह कभी नहीं कहते कि हम सारा स्विच-ओवर एक ही दफा में कर देंगे और सारा सिस्टम बदल देंगे। ऐसा करने

(श्री खेत सिंह)

में करोड़ों रुपयों का इनवाल्वमेंट है और आज इतना खर्च करने के लिए हमारी माली हालत ठीक नहीं है। इसलिए हम स्टेजेज में ही आगे बढ़ सकते हैं। इस वर्ष में हमने 6 कोर्सेस शुरू किये हैं और आगे आने वाले वर्ष में और भी शुरू करेंगे और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा पायेंगे।

श्री रघुनाथ विश्नोई : इसमें यौगिक क्रिया को और जोड़ लें।

श्री खेतसिंह : बानसूर से आने वाले माननीय सदस्य ने यौगिक क्रिया के ऊपर बहुत जोर दिया और इसको मैंने भी बहुत गम्भीरता से लिया है। हमने इस साल एक लाख रुपया का प्रावीजन रखा है और हम चाहेंगे कि स्कूलों के अन्दर यौगिक एक्सरसाइज भी सिखाई जायें। इससे लाभ भी होता है और इस ओर भी हमारा प्रयास है।

मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता था कि माननीय सदस्यों ने यह कहा कि शिक्षा के अन्दर जितनी प्रगति होनी चाहिए उतनी नहीं हुई है। इसके बारे में मुझे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारा राजस्थान किन परिस्थितियों में बना और क्या हमारी भूमिका थी और क्या हमारी भौगोलिक परिस्थितियां थीं ? यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है। ऐसे कई रजवाड़े थे जिनमें पहले एक एक स्कूल थी। जैसलमेर से आने वाले मित्र कह रहे थे, वह चले गये हैं, वहां पर मर्जर के समय एक ही स्कूल था और आज हजारों हो गए। इसी तरह से छोटी-छोटी स्टेट्स में स्कूल बहुत कम थे, कुछ स्टेट्स में तो थे लेकिन कईयों में नहीं थे। उस समय के यदि आप आंकड़े देखें तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बहुत बड़ा अन्तर है उस समय में और आज की स्कूलों की प्रगति में। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जिस समय राजस्थान बना उसके तीन साल के बाद 1950-51 के आंकड़े इकट्ठे किये हैं। उस समय प्राथमिक शालाओं की संख्या 4336 थी और आज वह संख्या 19,390 है। उसी प्रकार से उच्च प्राथमिक शाला पहले 732 थीं और आज वह 4837 हो गयी हैं। उस समय माध्यमिक स्कूल 175 थे और आज 1348 हैं। इसमें हमारा नम्बर कम है। हम मानते हैं कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों की संख्या जितनी बढ़नी चाहिए थी वह नहीं बढ़ी। अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि प्राथमिक शालायें और भी ज्यादा खोलनी चाहिये, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि डेजर्ट और हिली एरियाज के अन्दर जहां डिस्टेन्सेज बहुत ज्यादा हैं वहां कमी रही होगी लेकिन आज हम इस परिस्थिति में पहुंच गये हैं कि 500 की आबादी पर एक प्राथमिक शाला निश्चित रूप से हो··

श्री रघुनाथ विश्नोई : अभी बहुत सी जगह नहीं है।

श्री खेत सिंह : आप तो डेजर्ट में आते हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : 500 की आबादी के कई गांवों में नहीं है।

श्री खेत सिंह : अगर आप ऐसा उदाहरण देंगे तो हम निश्चित रूप से कार्यवाही करेंगे। मैं यह प्रयत्न करूंगा कि 500

(श्री खेतसिंह)

की आबादी पर हर जगह स्कूल हो जाने चाहिए। साथ ही मैं यह भी कहता हूं कि हमारा यह भी प्रयास रहा है कि हर 4 प्राथमिक शाला के ऊपर एक उच्च प्राथमिक शाला होनी चाहिए और 4 उच्च प्राथमिक शाला पर एक मिडिल स्कूल होनी चाहिए और 4 मिडिल स्कूल पर एक माध्यमिक शाला होनी चाहिए और 4 माध्यमिक शाला के ऊपर एक उच्च माध्यमिक शाला होनी चाहिए। पिछले वर्ष में जो 2 हजार स्कूल खोले हैं और फिर 2॥ हजार खोले हैं तो रेशो देखें तो चार पर एक प्राईमरी स्कूल खोला गया है। तो यह हमारे सोचने का तरीका है लेकिन इसमें समय लग सकता है क्योंकि हमारे पास वित्तीय साधन नहीं हैं।

इस बजट के अन्दर 125 स्कूलों को क्रमोन्नत करेंगे जिससे हमारा बजट 10 करोड़ का और बढ़ गया है तो आप सोचिये कि अगर हम सारे के सारे अनुमान एक साथ लगायें तो मैं समझता हूं कि राजस्थान का आधा बजट केवल शिक्षा विभाग के ऊपर करना पड़े। इसी प्रकार से माननीय सदस्यों ने कहा कि भवन बनाने के लिए पैसा नहीं देते और कहा कि शहरों में कालेज बिल्डिंग के लिए तो पैसा दे देते हैं। मैं तो कहता हूं कि शहरों में कोई दानदाता आता है तो हम पैसा उससे सहर्ष स्वीकार करते हैं और उस पर उसका नाम भी लिखाते हैं। यह इसलिए करते हैं कि बिल्डिंग बनाने के लिए हमारे पास पैसा बहुत कम है हम नहीं दे सकते हैं। आज 74 करोड़ का बजट होते हुये भी हमारी स्थिति यह है कि टीचर्स की तनख्वायें नहीं बढा सकते हैं। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि बिल्डिंगों के लिये, लायब्रेरी के इक्विपमेंट के लिये, उनके फर्नीचर के लिये जितना पैसा चाहते हैं उतना नहीं दे सकते हैं। स्कूल बिल्डिंग जितना सम्भव हो सके गांव वालों को बनाना चाहिये। लायब्रेरी के अन्दर हम जरूर पैसा देना पसन्द करेंगे क्योंकि बिना लायब्रेरी के स्कूल किस काम का है. उसके बाद फर्नीचर के लिये प्रायरटीज हम रखते हैं लेकिन बिल्डिंग के लिये हम चाहते हैं आपका ही सहयोग मिले तभी सफल हो सकते हैं वरना शिक्षा विभाग के लिये बहुत मुश्किल होगा।

कुछ माननीय सदस्यों ने महिला शिक्षा पर बहुत जोर दिया और बहुत पिछड़ा हुआ बताया, मैं इससे सहमत हूं और उसका मुख्य कारण यह रहा कि राजस्थान रियासतों से बना और पर्दा सिस्टम रहा है और कुछ ऐसी कम्यूनिटीज हैं जो आगे पढ़ाना नहीं चाहती है। कुछ कारण और हैं लेकिन 50-51 से 73-74 को कम्पेयर करें तो स्पष्ट है हमने प्रगति की है। पहले प्राथमिक स्कूल बच्चियों की 452 थी आज 910 है तथा उच्च माध्यमिक 109 थी और अब 604 हैं, पहले माध्यमिक शालायें 110 थीं अब 646 हैं उच्च माध्यमिक शाला थीं एक और अब है 61–प्रगति हुई है। और उसी प्रकार स्तर में भी वृद्धि हुई है और कुछ माननीय सदस्यों ने कहा सहूलियतें दीजिये हमने यह तय कर रखा है कक्षा एक से 8 तक बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा दी जायगी। उसी प्रकार हमने यह कह दिया है 10 हजार से जिनकी वार्षिक आय कम है उन लड़कियों की फीस नहीं

(श्री खेतसिंह)

ली जायगी। हम उनको निःशुल्क पढ़ायेंगे यह इसलिये रखा है जिससे ज्यादा से ज्यादा बालिकाओं को प्रोत्साहन मिल सके, हमने यह भी ध्यान रखा है, उनके शरीर की दृष्टि से आम तौर से बालिकायें घर पर एक्सरसाइज नहीं कर सकती हैं तो उनके लिये ट्रेनर कोचेज तैयार किये हैं उनका शरीर सुडौल हो, हृष्ट-पुष्ट हो उस तरफ भी ध्यान दिया है।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं यहां पर यह बात कही गई कि तबादले बहुत होते हैं। मैं इस बारे में निवेदन करना चाहता हूं और गत सत्र में भी निवेदन किया था हमने पालिसी बनाई है और उस पालिसी के तहत ही चलना चाहते हैं और 15 सितम्बर के बाद नहीं चाहते हैं ट्रान्सफर हो। कुछ चीजों में हमने किये हैं और जैसे मान लीजिये हार्ट पेशेन्ट है, कैन्सर है या किसी भयंकर बीमारी से पीड़ित है या फिर जहां पति-पत्नी का मामला हो या म्यूचुअल ट्रान्सफर्स हो इनको छोड़कर 15 सितम्बर के बाद ट्रान्सफार्म नहीं होने चाहिये लेकिन मजबूरी आप जानते हैं। पोलिटिकल प्रेसर इतने पड़ जाते हैं और माननीय सदस्यों के और टीचर्स के इतने प्रेसर पड़ते हैं कि कुछ मामलों में मानना ही पड़ता है। इसको मैं किसी तरह छिपाना नहीं चाहता हूं। इसमें आप भी सहयोग देवें तो निश्चित रूप से इस पालिसी को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं और चाहते हैं 15 सितम्बर के बाद ट्रान्सफर नहीं होने चाहिये, यह मेरी पूर्ण मान्यता है लेकिन इतना होते हुये जो परिस्थितियां बताई हैं मैं निवेदन कर चुका हूं।

आपने अभी कहा, तिजारा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा शिक्षक संघ से बेरुख हैं, आप उनकी सुनते नहीं हैं मैं कहता हूं मैं पहला व्यक्ति हूं। 17 जिलों में मैं गया हूं और उनके शिक्षक संघों से मिला हूं और उनको मैंने एड्रेस भी किया है। उनकी प्राबलम्स को मैंने सुना है और वहीं पर मेरी पूरी कोशिश रही है और जितनी बातें हैं उन पर विचार करके जो निर्णय लिये जा सकते थे, उन पर निर्णय लिया है और राज्य स्तर पर विचार किया है। एक माननीय सदस्य ने कहा सिरोही में आपके प्राईवेट सेक्रेटरी को पीटा गया, यह गलत न्यूज आई है। मैं स्वयं वहां पर था उन्होंने मुझ से कहा बिशन सिंह जी को आप जयपुर में लगा दीजिये। उन्होंने यह भी कहा कि हम चाहते हैं एक्जीक्यूटिव की बाडी है उसको जयपुर में लगा दीजिये और हम चाहते हैं एक्जीक्यूटिव वहां रहे। मैंने उनसे कहा यह कहीं पर लिखा हुआ नहीं है और ऐसा कोई कानून नहीं है...

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूं कि ट्रेड यूनियन की बाडी होती है उनके कर्मचारियों को ट्रान्सफर नहीं किया जा सकता है।

श्री खेतसिंह : मैं समझ गया, चूंकि आपकी पार्टी से एफीलियेटेड होगी। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं जब आप बोले थे तब मैं बिलकुल नहीं बोला।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : आपको गलत फहमी है, मैं बोला ही नहीं हूं।

श्री खेतसिंह : आपका नम्बर नहीं आया तो वह नाराजगी आप मेरे पर निकाल

(श्री खेत सिंह)

रहे हैं। शिक्षक संघ कोई ट्रेड यूनियन नहीं है और अब फिर जो हमने किया है उसकी एक्जीक्यूटिव बदल गई है, मि. विलियम है उनका पोस्टिंग जयपुर में है लेकिन मैंने कहा इस शर्त को हम मानने को तैयार नहीं है। इससे वे उग्र हुए और उग्रता में ही उन्होंने बताया कि पाली में ट्रान्सफर के लिये पैसे लिए हैं और मैंने कहा आप प्रूफ देंगे तो जिसने ऐसा किया है उसको सस्पेन्ड करेंगे। उन्होंने बताया हम अभी सबूत देते हैं और मैंने कहा जो ऐसा करता है उसके जूते मारो, यह बात मैंने भाषण में भी कही है। उसके बाद कोई प्रदर्शन नहीं हुआ। भाषण का टाइम्स आफ इंडिया में कोई लेटर आ गया उसकी एक फिजा बनाकर यह बात यहां कह दी गई है। आप जिम्मेदार सदस्य हैं आपके पास फुल प्रूफ न हो तब तक इस प्रकार की बात कहना उचित नहीं है और न माननीय सदस्यों के लिये यह शोभा की बात है। वे माननीय सदस्य चले गये, ज्यादा इसलिये कहने की अभी आवश्यकता नहीं समझता हूं कि उनके पास कोई सबूत नहीं है इसलिये मैं यह बात यहीं समाप्त करता हूं।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं स्पोर्ट्स कौन्सिल के बारे में कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे। मैं निवेदन करना चाहता हूं बिलकुल जैसा आपने कहा इतना डार्क नहीं है। मैं मानता हूं कुछ कमियां हो सकती हैं स्पोर्ट्स कौन्सिल में और हम भी चाहते हैं इसका दायित्व रूरल में ज्यादा बढ़े और ग्रामीण खिलाड़ी हैं, उनको आगे लायें, यूनिवर्सिटी के लड़कों को आगे लायें। स्पोर्ट्स कौन्सिल का डिपार्टमेंट स्वयं खेल कूद करवाता है हमने इस बात को इसीलिये माना है कि विभाग अच्छे अच्छे कोचेज तैयार करें और आज इंडिया के मशहूर कोचेज में से है। आज दौड़ का भी हमने किया है जिस प्रकार आज के हवाई जहाज को देखेंगे उनकी नोकें इतनी तेज होती हैं कि हवा को चीरती हुई चली जाय तो उसी प्रकार 100 मीटर दौड़ाने का, ऊंचा कूदने का, हाई जम्प वगैरह इसमें हुआ करते हैं उन्होंने इस प्रकार के कोचेज बहुत बढ़िया तैयार किये हैं। उन्होंने अभी यह भी बताया था आबू में एक शिविर हो क्योंकि आबू में आकर्षण भी रहेगा और गर्मियों में लोग आना भी चाहेंगे और जो नेशनल स्कीम है उनको यहां भेजिये—इस बात को हमने मंजूर किया है महज इसलिये किया था कि आबू के पीछे अट्रेक्शन रहेगा, वे चले जावेंगे, वहां पर और गर्मियों की छुट्टियां भी रहती हैं। अच्छा कोचिंग मिल रहा है तो हमको लाभ उठाना चाहिये। न कैम्प लगाया और न योजना बनायी।

पिछले वर्ष रूरल स्पोर्ट्स के नाम से बानसी में स्पोर्ट्स रखे गये थे। बड़ी सादगी से जो माननीय सदस्य आते हैं उनके गांव में ये रखे गये थे। इसके बाद आपने कहा कि काम नहीं हुआ।

मुझे स्पोर्ट्स कौंसिल की तरफ से बताया गया है कि 73–74 में 16 खेल संघों की राष्ट्रीय प्रतियोगिता हुई। एथलेट्स में 20 स्वर्ण पदक मिले हैं। तैराकी में 2 स्वर्ण पदक मिले हैं। 2 रजत पदक मिले हैं। क्रिकेट में द्वितीय स्थान रहा है।

(व्यवधान) (अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : (माननीय सदस्यों के आपस में वार्तालाप करने के कारण) आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज। सुनिये, माननीय मंत्री महोदय को।

श्री खेतसिंह : अच्छे खिलाड़ी हैं उनको अवार्ड देते हैं।

यह जो स्पोर्ट्स कौंसिल बनी हुई है उसका टेन्योर मई तक का ही है। मई में नयी स्पोर्ट्स कौंसिल को रिग्रोर्गेनाइज करेंगे, उस समय और अच्छे व्यक्ति लाये जायं जिनको स्पोर्ट्स का ज्ञान हो और हमारी मंशा है कि ग्रामीण खेल कूद में रुचि लेकर गांवों से निकले हुए खिलाड़ियों को आगे लायें, उसमें हम प्रयास करेंगे।

श्री रामकिशन : काक साहब के खिलाफ आप कार्यवाही कर सकेंगे? टिकिट कौन देगा?

श्री खेतसिंह : सारी स्पोर्ट्स कौंसिल को रिग्रार्गेनाइज करेंगे। काक साहब का काम अच्छा है तो रहेंगे, नहीं तो जावेंगे। कुल मिला कर स्पोर्ट्स कौंसिल के कार्यों के बारे में निवेदन कर दिया।

एक माननीय सदस्य : माननीय मंत्रीजी···

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, I will not allow any question during the reply of the hon. Minister.

श्री खेतसिंह : हवा महल से आने वाले माननीय सदस्य ने हिन्दी भाषा के बारे में जोर दिया। उन्होंने कहा कि भाषा विभाग अलग से खुला हुआ है। फिर भी अंग्रेजी में आम तौर पर सेक्रेटेरियेट में काम होता है। प्रगति तो निश्चित रूप से हुई, हां, आप यह जरूर कह सकते हैं कि जितनी प्रगति होनी चाहिये उतनी नहीं हुई है। उसका कारण है हमारी सारी सर्विसेज हिन्दी भाषी प्रान्तों की नहीं है। उन लोगों की आदत अंग्रेजी में लिखने की है, हमारी ओर से बराबर प्रयास रहा है कि हिन्दी में ही काम हो, इसके लिये सरकुलर भेजे हैं, माननीय मुख्य मंत्रीजी की ओर से विभागों के मंत्रियों को लेटर्स भेजे गये हैं। सरल हिन्दी में काम हो। यह जरूरी नहीं है कि क्लिष्ट हिन्दी में काम हो सरल हिन्दी हो, नोटिंग उसी में करना चाहिये और कार्यवाही करनी चाहिये। इस ओर प्रगति हुई है।

उच्च न्यायालय की बात ही ले लीजिये। चीफ जस्टिस बेरी थे, अब वे रिटायर हो गये हैं, उस समय काज लिस्ट हिन्दी में साया होनी चाहिये यह किया गया। हिन्दी में आर्गूमेन्ट्स हो सकते हैं, हिन्दी में आर्गूमेन्ट्स सुनते हैं। जजमेन्ट के लिये भी कहा तो कहा कि हाईकोर्ट के जजमेन्ट हिन्दी में नहीं हो सकते हैं, किन्तु मातहत कोर्ट्स के लिये ओर्डर दिया था। डिक्सनरी वगैरा ला डिपार्टमेन्ट की ओर से देने का प्रयास किया गया है। ला डिपार्टमेन्ट में विधि सूचना विभाग अलग से बना रहा है और जितने कानून हैं उनका हिन्दीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। विष्णुदत्तजी शर्मा वगैहरा जैसे लोगों को उसमें लगाया गया है। 47 कानूनों का हिन्दीकरण हो चुका है। इस तरह से इस ओर प्रयास कर रहे हैं।

श्री रामकिशन : हिन्दीकरण या हिन्दी अनुवाद?

श्री खेतसिंह : ज्यादा से ज्यादा हिन्दी का प्रचार हो और सारा नोटिंग और कार्यवाही हिन्दी में ही हो यह प्रयास किया है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : पत्र हिन्दी में भिजवाओ सैक्रेटेरियेट से।

श्री खेतसिंह : हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य ने हिन्दी ग्रन्थ अकादमी में नियुक्ति के बारे में कहा। विज्ञापन निकाले गये हैं। क्वालिफिकेशन्स लेडडाउन की हैं, जिनकी जिनकी आवेगी उसमें सलेक्ट हो जावेंगे। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है।

आपने रवीन्द्र रंगमंच के बारे में कहा। मैं उसमें भी निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक रवीन्द्र रंगमंच का प्रश्न है, आपसे छिपी हुई बात नहीं है, छत गिर रही थी, इसके लिये पैसा मंजूर कर दिया है 31 मार्च तक, इन्जीनियर्स ने बताया है, रवीन्द्र मंच की छत की मरम्मत कर दी जावेगी। और चालू हो सकेगा और आपने जो समस्या बतायी उसका समाधान हो जावेगा। माननीय सदस्य कार्य-क्रम रखना चाहें आपत्ति नहीं होगी और दिक्कत नहीं होगी।

श्री श्रीराम गोटेवाला : ठेके लेना चाहते थे, उसका क्या हुआ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : कर्मचारियों का क्या होगा?

श्री खेतसिंह : माननीय सदस्य ठेकेदार बनते हैं तो सोचेंगे।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : कर्मचारियों की बकाया तनख्वाह के लिये बतायें...

श्री खेतसिंह : 50 हजार रुपये की सैंक्शन कर दी है। सारे कर्मचारियों को रखना जरूरी नहीं है। जितने भी रवीन्द्र रंगमंच पर कर्मचारी हैं उन सबको रखने की आवश्यकता नहीं है। नौकर ज्यादा है और कम कर देना चाहिये, तब हमने कहा कि स्क्रीनिंग कर देना चाहिये और आज तक जो नौकर रहे हैं उनको तनख्वाह दे दी जाय। स्क्रीनिंग होने के बाद जो योग्य हों, उनको रखा जाय और बाकी को घर भेज दिया जाय। यह कोई जुर्म नहीं किया है यदि यह किया है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : 11 कर्मचारी थे।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : 11 के 11 रहने चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री खेतसिंह : उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि 50) 60) रु. प्रति के हिसाब से 1 लाख का आर्डर दे दिया। उनके पास यह जानकारी थी। लेकिन सुमनेश जोशी ने एक "स्वतन्त्रता सेनानी" नामक पुस्तक लिखी थी। उसकी प्रतियां खरीदने के लिये उनकी ओर से प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत हुआ था। मुख्य मंत्री जी के पास दिया था। उन्होंने मुझे भेजा था। हमने कहा कि पब्लिक लायब्रेरी में एक किताब खरीदी जा सकती है इससे अधिक नहीं खरीदी जा सकती है। न पैसा था कि एक साथ खरीद लेते। न तो एक लाख की खरीदी गयी और जो उनके पास इन्फोर्मेशन है वह गलत है।

किशनपोल बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि पुरातत्व विभाग में

(श्री खेतसिंह)

पुराने मैन्यूस्क्रिप्ट पड़े हुए हैं उनका उपयोग होना चाहिये। मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि यह बिल्कुल सही है। मुगल एज के बाद में अपने यहां जितने मैन्यूस्क्रिप्ट आ चुके हैं, क्योंकि देशी राज्यों में सबसे अच्छा इसका कलेक्शन था, उसमें अनुसंधान के लिये अपने राज्य के ही नहीं एवं भारतवर्ष के ही नहीं किन्तु विदेशों से विद्यार्थी भी आते हैं और बीकानेर में 40 विद्यार्थियों ने शोध का कार्य किया है। जहां तक उनको रखने करने का सवाल है, गवर्नमेन्ट सतर्क है और ध्यान रख रही है।

रिकेटेगोराइजेशन की बात कही। यह प्रयास किया है। 11 साल हो गये, जितनी स्वयं सेवी संस्थायें राजस्थान में चलती हैं, जो टोटल में 1200 हैं उनका रिकेटेगोराइजेशन नहीं हुआ था। जिस वक्त पहले केटेगराइजेशन किया गया था, उसको ग्यारह साल का समय गुजर चुका है और इन ग्यारह साल में कई ऐसी संस्थाएं हैं जिनका स्टेन्डर्ड बहुत ऊंचा था और आज उनका रिजल्ट गिर गया है। उनकी पढ़ाई का वह वातावरण और स्टेन्डर्ड नहीं रहा जो पहले था। आमतौर पर ऐसी संस्थाएं वहां के प्रधानाध्यापक और व्यवस्थापक पर चलती हैं क्योंकि एक ही आदमी ऐसी संस्थाओं का सर्वस्व होता है और तभी ये संस्थाएं कामयाब होती हैं। ऐसी संस्थाओं को जिनको कि पहले 'ए' श्रेणी में केटेगोराइज किया था उनको 80/90 प्रतिशत ग्रान्ट–इन–एड मिलती है जबकि आज की स्थिति में इनको 50/60 प्रतिशत ग्रान्ट-इन-एड दी जानी चाहिए। आज ऐसी भी संस्थाएं हैं जिन्होंने इस दरम्यान तरक्की की है और आज वे 90 प्रतिशत ग्रान्ट-इन-एड पाने की हकदार हैं। इसके लिए हम ने अलग-अलग कमेटियां बनायी हैं और उस कमेटी ने जांच करके अपनी रिपोर्ट मुकम्मिल कर दी है। मैं समझता हूं कि मार्च के अन्त तक या 15 अप्रैल तक निश्चित तौर से स्वयं सेवी संस्थाओं के मैं रिकेटेगोराइजेशन की घोषणा कर दूंगा। साथ ही यहां पर रूल्स के बारे में जिक्र किया था। किशनपोल से आने वाले माननीय सदस्य को मैं यह निवेदन करना चाहता हूं रूल्स का सिम्पलीफिकेशन कर दिया गया है और रूल्स फाइनेन्स डिपार्टमेंट में भेज दिये हैं और मैं समझता हूं कि ये रूल्स 8/10 दिन में फाइनल हो जाएंगे। आम तौर पर स्वयं सेवी संस्थाओं को जो दिक्कत आती है, वह दूर की जा रही है और जब भी वे विभागों में जाएंगे उनको बाकायदा इज्जत दी जाएगी।

संस्कृत शिक्षा के बारे में भी कहा गया है। इसके बारे में यह निवेदन करना चाहूंगा और आपको यह जानकर खुशी होगी कि हमारा राज्य वह पहला राज्य है जिसने संस्कृत शिक्षा के अन्दर बी.एस.टी.सी. ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूशन खोली है। आम तौर पर संस्कृत के अध्यापक अनट्रेन्ड होते हैं। उनकी भी ट्रेनिंग हो जानी चाहिए इसको ध्यान में रखते हुए हमने एक ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूशन महापुरा में खोल दी है। इस साल ट्रेनिंग प्रारम्भ कर दी है और मुझे यह बतलाते हुए खुशी है कि यह इन्स्टीट्यूशन हमारे यहां पर अच्छी तरह चल रही है। साथ ही यह निवेदन करना चाहता हूं कि संस्कृत के विद्यालयों के अन्दर हमारे यहां पर 28 हजार छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनमें से 2400 छात्र अनुसूचित जाति एवं जनजाति

(श्री खेतसिंह)

के हैं और संस्कृत जो देव वाणी कही जाती है। इस परिवर्तनशील युग में यह जन-जन की भाषा बन रही है। इस वर्ष हमने दो संस्थाओं में नये विषय खोले हैं। हम संस्कृत शिक्षा को प्रोत्साहन देना चाहते हैं और इस ओर हम प्रयास कर रहे हैं।

पाठ्य पुस्तकों के बारे में यहां पर सभी ने तारीफ की है। मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि आगामी वर्ष में भी हमारा प्रयास यह होगा और हम सोचते हैं कि गर्मियों में ही कुछ पाठ्य पुस्तकें और कुछ किताबें उपलब्ध करा दें और स्कूल खोलने के समय तक करीब-करीब सभी पुस्तकें विद्यार्थियों को मुहैया करा दें और इस सम्बन्ध में पाठ्य पुस्तकों के बारे में कोई तकलीफ नहीं होगी।

और भी कई बातें कहनी हैं। परन्तु मेरे पास बैठने वाले माननीय सदस्य कह रहे हैं काफी हो गया है तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने भाषण को समाप्त करता हूं।....

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। Let him finish first.

श्री श्रीराम गोठेवाला : म्यूजियम के बारे में ?

श्री खेतसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किशनपोल से आने वाले माननीय सदस्य ने एक और सुझाव दिया था। राजस्थान के जितने म्यूजियम हैं, वे अच्छे हैं। तब क्यों नहीं जिस प्रकार हैदराबाद का सालारजंग म्यूजियम है और सारे हिन्दुस्तान में मशहूर है उसी प्रकार का म्यूजियम जयपुर में हो। यहां विदेशी पर्यटक भी आते हैं। वे भी इसको देखें और इसका लाभ उठावें। इसलिए हम भी इस म्यूजियम को योग्य बनावें। मैं इस सुझाव पर निश्चित तौर पर विचार करूंगा। परन्तु दूसरे म्यूजियम से चीजें इस म्यूजियम में लाना आसान नहीं है। हर शहर का अपना अलग अलग स्थान होता है। किशनपोल से आने वाले माननीय सदस्य ने इतना आक्रोश व्यक्त किया तो म्यूजियम दूसरी जगह से लाना तो बड़ी चीज है और यह करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी आपका जो सुझाव है, जयपुर राजस्थान की राजधानी है, यहां पर विदेशी पर्यटक आते हैं तो जयपुर का म्यूजियम निश्चित तौर से अच्छा होना चाहिए। इस ओर हम प्रयास करेंगे।

अन्त में मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि....

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : लाल बहादुर शास्त्री कालेज के लिए कमेटी का निर्माण किया गया, उसके बारे में आपने क्या विचार किया है, क्या सोचा है ?

श्री खेतसिंह : मान्यवर, सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि इसके लिए एक कक्कड़ कमेटी बनी थी। उसने जांच की है और जांच रिपोर्ट गवर्नमेंट के पास आ गयी है और गवर्नमेन्ट उस पर विचार कर रही है। मैं समझता हूं कि एक महीने के अन्दर-अन्दर हम फैसला कर देंगे। उसमें दो तीन बातें हैं। मैं समझता हूं कि महीने भर

(श्री खेतसिंह)

में फैसला कर के आपको बता देंगे । कोई दिक्कत नहीं है ।

अन्त में मैं सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने अमूल्य सुझाव दिये । आपसे निवेदन है कि मैंने जो मांग संख्या 24 प्रस्तुत की है कृपा पूर्वक उसको पास कर दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष : राज्य मंत्री महोदय ।

श्री माननीय सदस्य : इनका भाषण पढ़ा हुआ मान लिया जाये ।

श्री बनवारीलाल (राज्य मंत्री, जेल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय जेल विभाग से संबंधित कटौती प्रस्ताव करीब 50 थे और जिसमें करीबन 10 सदस्यों ने बहस में भाग लिया । मैं उनका आभारी हूं कि उन्होंने कृपा पूर्वक अपने सुझाव दिए हैं ।

माननीय उपाध्यक्ष जी, क्रिमोनोली और और पेनोलोजी का इतिहास बहुत लम्बा है । मैं इसके विगत में जाना उचित नहीं समझता हूं । परन्तु यह जरूरी होगा कि इस विषय में थोड़ा बहुत कहा जाये । आदिम काल से लगा कर एक दम आधुनिकतम काल का जो वक्त गुजर रहा है, दुनिया के हर मुल्क ने, वहां के समाज ने, वहां के राज्य ने अपने आपको जीवित रखने के लिए, कुछ कानून कायदे बनाये और उनमें व्यवधान करने वाले को, उसको नहीं मानने वाले को, जो भी व्यक्ति सामने आया उसको इन कानून कायदे के नजरिये से देखा है और इसके लिए उन्होंने कुछ सजाए, पनिशमेन्ट का भी प्रावधान किया । भारत के अन्दर भी मनु-स्मृति से लगा कर इस काल तक कई कोडिफिकेशन ऐसे हुए हैं जिनमें इन सजाओं का प्रावधान रखा गया है ।

अलग-अलग वक्तों के अन्दर अलग-अलग तरीकों की सजाओं की तजबीज रही है । पहले वक्तों के अन्दर बहुत सख्त सजायें बहुत सख्त पनिशमेंट्स दी जाती रही हैं, और दुनियां के अन्दर जितने इस तरह के हुए हैं उनमें सीवियर किस्म की सजायें तजवीज की गई हैं । मिडिवियल भारत और यूरोप दोनों को हम देखते हैं तो तकरीबन 250 या 300 ऐसे जुर्म थे जिनमें सजा-ए-मौत दी जाती थी । लेकिन दुनियां में नवजागरण आया तो उन्होंने इस प्रकार के विचार संसार के सामने रखे कि जिनकी वजह से उन तमाम चीजों के अन्दर बहुत जबरदस्त तब्दीली आई है । उसके अन्दर सबसे बड़े स्मार्क, बोदम, फ्यूल आदि हुए हैं, उनके वक्त में सजाओं के अन्दर काफी कमी आई है । हमारे देश के अन्दर काफी परिवर्तन हुए, और खास तौर से इसमें परिवर्तन जो हुए हैं वह हमारी आजादी के बाद हुए ।

राजस्थान का जहां तक प्रश्न है यहां बहुत सारे राजे-रजवाड़े थे उन सबको मिला कर एक स्टेट बनी । हर स्टेट का हर रजवाड़े के तौर-तरीके अलग-अलग थे, सजायें अलग-अलग थीं, उनकी जेलें अलग-अलग थीं । उन सबका एकीकरण यहां पर किया गया जब राजस्थान के अन्दर एक तरीके की जेलें रखी हैं, एक तरह की सजायें तजवीज की हैं । इस समय राजस्थान के अन्दर 3 सैन्ट्रल जेलें हैं, 2 डिस्ट्रिक्ट जेल्स हैं, दो डिस्ट्रिक्ट जेल बी श्रेणी की हैं, दो 'सी' श्रेणी की हैं और 70 सब-जेल्स हैं । उनके अन्दर दो

(श्री बनवारी लाल)

रिफार्मेट्रीज हैं। लेडीज के लिए अजमेर जिले में हैं। कुल मिलाकर 5-6 हजार कैदियों के बीच अन्दर इन जेलों में रहते हैं।

इस समय जिस तरीके से वहां के कैदियों के साथ बरताव किया जाता है उसके बारे में कुछ माननीय सदस्यों के कटौती-प्रस्ताव आये थे उन्होंने उसमें कहा। लेकिन मैं, माननीय उपाध्यक्ष, आपके माध्यम से सब माननीय सदस्यों ने यह बात कही है कि इस समय जेल के अन्दर काफी अच्छा व्यवहार कैदियों के साथ किया जाता है, और जहां तक संभव होता है, और जहां तक कानून इजाजत देता है उनको सहूलियत उसके अन्दर दिया जाता है। इन सबके बावजूद अगर कोई यह बात सामने आती है कि दुर्व्यवहार हो रहा है, कहीं कोई ज्यादती हो रही है, तो उसके लिए फौरन एक्शन लिया जाता है। उसके अन्दर किसी को भी बख्शा नहीं जाता है।

जहां तक भोजन का प्रश्न है हमारे मुल्क के अन्दर जो भी प्रेस्काइब्ड भोजन है उसके अन्दर किसी किस्म की कमी नहीं की जाती है। इसमें 582 ग्राम आटा तकरीबन 53 ग्राम दाल और 30।। ग्राम सब्जी, इस तरह का प्रावधान आर्ज सामान्य कैदी के लिए निर्धारित होता है। मैं इसलिए कहता हूं कि मैं कई जेलों में व्यक्तिगत रूप से गया हूं और कैदियों से पूछा है कि आपको खाना मिलता है, और मैंने स्वयं ने खाना देखा है वह अच्छा है उस बारे में वहां पर किसी किस्म की शिकायत मेरे सामने नहीं थी। इसलिए मैं यह मानता हूं कि जो कुछ भी इसमें खाना दिया जा रहा है वह ऐसा नहीं कह सकते कि नाकाफी हो।

इसके अलावा वहां पर हम इन कैदियों के लिए प्रौढ़ शिक्षा चालू कर रहे हैं। प्रौढ़ शिक्षा सेन्ट्रल जेल में और डिस्ट्रिक्ट जेल में चालू है, और जहां कहीं भी उपलब्ध हो पढ़ाने वाले कैदियों के अन्दर तो सब-जेलों के अन्दर भी चालू कर रखा है। इनको पत्रिकाएं भी देते हैं। पत्र भी बड़ी बड़ी सब जेलों के अन्दर व्यवस्था की गई है। जैसे डेली पेपर्स और कई वीकली पेपर्स हैं वह वहां पर पहुंच जाते हैं। नवभारत टाइम्स पहुंच जाता है। राजस्थान के लोकल पेपर्स पहुंच जाते हैं। यह नहीं कहा जा सकता है कि हम उस तरफ ध्यान नहीं कर रहे हैं।

इसके साथ ही और भी कई ऐसी सुविधाएं हमने दे रखी हैं, मसलन, जैसे यहां पर चार ओपन एयर कैम्प्स चल रहे हैं, एक सांगानेर में, एक दुर्गापुरा में, एक सूरतगढ़ में एक अजमेर में। इनमें इस प्रकार की व्यवस्था होती है कि जितने कैदी आधे से ज्यादा सजा काट चुके हैं उनको भेजा जाता है। उनमें या तो काम दिया जाता है या वह वहां ऐसे ही रहते हैं। सब प्रिजनर्स होते हैं केवल उनकी देखभाल के लिए एक अफसर रहता है जो कि सादे लिबास में रहता है। ये सब सादे लिबास में रहते हैं ताकि बाहर से देखकर कोई इनको शनाख्त नहीं कर सकता है कि यह कैदी हैं। उनमें यह खुशी की बात है कि अभी तक एक या दो ऐसे वाकयात सामने आये हैं इस बात के कि वहां से कैदी चल दिये हों लेकिन वह भी मेन्टली डिस्टर्ब्ड होने से चल दिये। बाद में यह उदाहरण सामने नहीं आया कि यहां से कोई कैदी चला गया हो।

(श्री बनवारी लाल)

उसके साथ में एक और सुधार हमने किया है कि पेरोल पर कैदियों को बीच के अन्दर छोड़ते हैं। यह बहुत ही मानवीय दृष्टिकोण को सामने रखकर इस बात को तय किया है। अगर घर के अन्दर किसी किस्म की बात खड़ी हो गई हो, यानि कोई बीमार हो, किसी की डेथ हो गई हो या और ऐसी बात अगर हो सकती है कि जिसके बिना उसके काम नहीं चल सके तो अगर मुनासिब समझते हैं तो पेरोल पर छोड़ते हैं। इन सब बातों से इस नतीजे पर पहुंचा जा सकता है कि वहां पर इन लोगों को इस तरह का बनाते हैं कि समाज के अन्दर यहां से निकलकर सभ्य नागरिक की तरह से रह सकें और अपना जीवन-यापन कर सकें।

जहां तक इनको काम सिखाने का प्रश्न है तो इनको दरियां बनाना, पट्टियां बनाना कारपेट बनाना है, उसके साथ टेबल कुर्सियां बनाना है, उनकी मरम्मत करना यह सब सिखाया जाता है। कुछ जगहों पर अभी हमने चालू किया है स्कूटर्स, मोटर साइकिल और साइकलों की मरम्मत का काम सिखाना भी ताकि अकेला आदमी बाहर निकले, और क्योंकि कोई विशेष स्थिति नहीं है तो ऐसा न हो कि वह बेरोजगार हो जाय और अपने आपको पशोपेश में पाये। जब उसको मालूम होगा तो कुछ न कुछ काम करने की सोचेगा। ओपन एयर कैम्पस के अन्दर एक नया सुधार और किया है कि जो कैदी वहां पर रहते हैं उनको बैंकों से कर्जा दिलाकर उनसे धन्धा करवाते हैं उससे उनके पास जो पैसा आयेगा उसका आधा पैसा बैंक में जमा करायेगा और आधा अपने पास रखेगा। जस दिन वह रिहा होगा उस दिन पूरा पैसा उसको चुका देते हैं। उससे इस प्रकार की व्यवस्था हो जाती है...

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : अच्छा काम किया है।

श्री बनवारीलाल : माननीय सदस्यों की ओर से कुछ जेलों की मरम्मत के और नई जेलों की तामीर के बारे में भी सवाल आये हैं। माननीय उपाध्यक्ष, कई जेलें बहुत पुरानी हैं और उनमें वह सुविधाएं जो हम देना चाहते हैं वह वहां पर उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन हमारी वित्तीय स्थिति शायद माननीय सदस्यों से किसी तरह से छिपी नहीं है, और एक बिल्डिंग बनाने के लिए काफी सर्फा होता है। ज्यों ज्यों हमारा बजट एलाऊ करता उसके लिए तो कोशिश करते हैं कि तामीर भी करा दें और मरम्मत भी करा दें। कुछ माननीय सदस्यों की तरफ से यह प्रश्न भी आया कि नई जेलें बनाई जायं, क्योंकि पिछले साल जुडीशियरी की तरफ से जो रिकन्स्टीट्यूशन हो रहा है उसके हिसाब से कुछ जेलों के अन्दर अदालतें खोली गई हैं जिनकी वजह से वहां पर कैदियों के रहने की व्यवस्था इस प्रकार बदल गई है, लेकिन ज्यों-ज्यों उसके अन्दर टाइम आ रहा है खोलने का विचार किया जा रहा है। जहां जहां संभव हो सकेगा जहां तुरन्त बिल्डिंग मिल सकेंगी वहां पर खोलने की कोशिश की जायगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतना सब करने के बावजूद भी हमने कहा था कि इसकी रिपोर्ट हमारे पास गालिबन आजायेगी। उस पर और विचार करके और सुविधाओं की इनफार्मेशन्स दिये जाने का सवाल है। जहां तक वहां के कार्यों का प्रश्न है, कुछ और बातें

(श्री बनवारी लाल)

सामने आई हैं। कुछ मांगें सामने आई हैं। इसके लिए जल्दी ही विचार कर रहे हैं। विचार करके जल्दी ही निर्णय लिये जायेंगे।

एक माननीय सदस्य ने सवाल उठाया था, जेलों के अन्दर बिस्तरों और कम्बलों की बड़ी खराब हालत है। माननीय अध्यक्ष जी (उपाध्यक्ष) मैं यह तो दावा नहीं कर सकता कि कम्बल नये हैं। जैसे जैसे पुराने होते जाते हैं, उन्हें बदला जाता है। पिछले वर्ष तकरीबन एक हजार कम्बलों की व्यवस्था की है। इस साल और भी कर रहे हैं। ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। और भी बहुत सी बातें माननीय सदस्यों की ओर से आई हैं। क्योंकि जब शिक्षा मन्त्री जी बोल रहे थे तो पीछे से कुछ आवाजें आ रही मेरा निवेदन है कि जिनके जवाबात नहीं कर पाया हूं उनको लिखकर भजवा दूंगा। इसके बाद अब उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूं, कि मांग संख्या 17, एक करोड़ 22 लाख 15 हजार रु, उसको पास करने का कष्ट करें।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या 24 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 74,04,17,000 रु. तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या 24 स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 17 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय, को 1,22,15,000 रु. तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या 17 स्वीकार की गई।

सदन की कार्यवाही दिनांक 12 मार्च, 1975 के प्रातः 11-00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 8-43 बजे बुधवार दिनांक 12 मार्च, 1975 के प्रातः 11-00 बजे तक स्थगित हुई।)

188

शुद्धि-पत्र

शनिवार, दिनांक 8 मार्च, 1975

क्रम सं.	स्तम्भ सं.	पंक्ति सं.	अशुद्ध	शुद्ध
1.	3	नीचे से 5	बट्टूवर	अक्टूबर
2.	8	,, 8	कास्ट्स	ट्राईब्स
3.	13	,, 12	की	भी
4.	17	ऊपर से 3	की	के
5.	26	,, 8	हो	ही
6.	54	नीचे से 8	7	17
f.	57	,, 16	चचा	चर्चा
8.	73	,, 10	अनदान	अनुदान
9.	92	,, 7	चाहेते	चाहते
10.	108	,, 1	अव्ययस्था	अव्यवस्था
11.	111	ऊपर से 7	किताब	की किताब
12.	115	,, 4	विद्यथियो	विद्यार्थियों
13.	119	नीचे से 7	मननीय	माननीय
14.	146	,, 1	एकाकरण	एकीकरण
15.	161	,, 5	फस्टंईयर	फस्टईयर
16.	198	ऊपर से 14	हमको	उनको
17.	223	नीचे से 1	प	कप
18.	322	,, 7	यान	यानि
18	338	,, 7	गहोदय	महोदय
20.	372	पेज नं.	382	372
21.	372	नीचे से 6	मननीय	माननीय
22.	373	,, 7	भजवा	भिजवा
23.	373	,, 1	की	को